# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या : 12

**शुक्रवार**

**16 मार्च, 2007**

**राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे**

**विधान सभा भवन जयपुर, में प्रारम्भ हुई।**

**(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

**(श्री मंगलाराम गोदारा व डा. श्रीगोपाल बाहेती द्वारा सदन कूप में धरना व अनशन)**

**श्री अध्यक्षः** अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल पर बैठे रहने वाले माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वार्ता चल रही है, अच्छा है, आप इस समय यदि अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं तो ज्यादा उचित रहेगा। मैं, चूंकि संख्या भी बहुत क्षीण है...।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जिन माननीय सदस्यों के सवाल लगे हुए हैं, वे सवाल पूछना भी चाहते हैं और संख्या भी पूरी है।

**श्री अध्यक्षः** उचित रहेगा, अभी वार्ता चल रही है, मैं समझती हूं उचित रहेगा आधे घण्टे के लिये...।

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): क्वेश्चन-ऑवर चलने दें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): 5 दिन से लगातार, सारे राजस्थान के लोगों के क्वेशचंस हैं। और क्वेश्चन-ऑवर चले तो कोई दिक्कत नहीं है। वार्ता चले, बैठ जाएं, रास्ता निकाल लें। हम सब उनके, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी आपसे कह चुकी हैं। क्वेश्चन-ऑवर, मेरी तो आपसे प्रार्थना है, बाकी तो जैसा आप निर्णय लें। बाकी क्वेश्चन ऑवर तो चलना ही चाहिए।

**श्री अध्यक्षः** इसीलिये मैं कह रही हूं कि आधा घण्टे के लिये, 11.30 तक के लिये विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 11.02 बजे, 11.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई)**

**(समय : 11.30 बजे)**

**(पुनः समवेत् होने पर)**

**(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

**(श्री मंगलाराम गोदारा व डा. श्रीगोपाल बाहेती द्वारा सदन कूप में धरना व अनशन)**

**श्री अध्यक्ष:** सदन की कार्यवाही एक घंटे, अर्थात् 12 बज कर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 11.30 बजे 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

**(समय : 12.30 बजे)**

**(पुन: समवेत् होने पर)**

**(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

**(श्री मंगलाराम गोदारा एवं डा. श्रीगोपाल बाहेती, माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)**

**श्री अध्यक्ष :** आमरण अनशन पर हो, हाथ तो जोड़ लिया करो। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : हाथ तो दोनों ही जोड़ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मुख्य मंत्रीजी, डेडलॉक तोड़ने के लिये कुछ फरमायें आप।

## शासकीय वक्तव्य

### ओलावृष्टि से हुए नुकसान बाबत

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई है राजस्थान के अंदर और जगह-जगह पर पकी हुई खड़ी फसल नष्ट हुई है। हमने सोचा था कि इस सदन में इसके बारे में अच्छी चर्चा होगी, बहुत सारे सुझाव निकल कर आयेंगे, जिनको हम आगे चलकर अपनी क्रियान्विति में भी जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। पर दुर्भाग्यवश वह चर्चा नहीं हुई। इस भयंकर तबाही के अंदर मेरी सरकार की ओर से मैं आप सबको यह आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम लोग कोई कमी या कोई कोर-कसर उनको मदद करने में नहीं छोड़ेंगे। इस भयंकर त्रासदी के अंदर जितनी मदद हमारी सरकार की ओर से हो सकती है, उसमें मैं फिर कहती हूं कि किसी किस्म की कमी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि पहले दिन मैं खुद दौरा कर चुकी हूं। दो जगह मैं खुद होकर आई हूं। साथ में जो राज्य मंत्री थे, उनको तीन दिन के दौरे पर तुरन्त ही भेज दिया था, वह आज ही सब अपने क्षेत्र से वापस लौटेंगे। कलक्टर्स को भी दिशा-निर्देश कर दिये गये हैं कि वह भी जायें और सब इन्फोर्मेशन कलेक्ट करें। 17, 18 व 19 तारीख को तो आपने भी सब माननीय सदस्यों को उस दिन छुट्टी दी है ताकि हम लोग

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जाकर क्षेत्र के अंदर किसानों की डायरेक्ट बातचीत करके खुद इनके क्षेत्र में जाकर, देख कर इस विषय के ऊपर जितनी भी जानकारी ला सकते हैं, वह यहां ले आयें। मैं समझती हूं कि 20-21 तारीख तक पूरी जानकारी हमारे पास आ जायेगी और उसको देखते हुए जो बेस्ट से बेस्ट हम अपने किसानों के लिये कर सकते हैं उसमें जैसे मैंने आपको कहा है हम कोई कमी छोड़ेंगे नहीं । मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर आप कम्पेरिजन करें पिछले तीन सालों के अंदर तो हम लोगों ने जो पैसा दिया है, करीबन 33 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा दिया। और इन तीन-चार दिन के अंदर आलरेडी 13 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिये उसी से इंटेंशन जाहिर हो जाता है। किसानों के ऊपर किसी तरीके से मुसीबत आये, वह हम लोग पूरी तरीके से वहन करेंगे। हमारी सरकार किसानों की सरकार है और इसलिए यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनकी मुसीबत के अंदर हम लोग पूरी तरह से दृढ़-संकल्पित होकर उनकी मदद करें।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय नेता प्रतिपक्ष।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, पिछले दिनों राजस्थान के अंदर 3-4 दिन में भयंकर नुकसान किसानों का हुआ। ऐसा नुकसान राजस्थान में पहले कभी देखने को नहीं मिला था, यह प्रथम बार है। नेचुरल कैलेमिटी है। नेचुरल कैलेमिटी को मीट करने के लिये राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये हमें भी अनप्लीजेंट कठोर कदम उठाना पडा। हमारी पार्टी के दो माननीय सदस्यों को हमें बैठाना पडा कि आपका ध्यान आकर्षित हो। आप द्रवित हों और द्रवित होकर किसानों को मदद पहुंचाने के लिये वादा करें। हमने यह तो कहा ही नहीं, आप अभी किसानों को दे दीजिये। हम तो बात ही चाहते थे। आपने यह घोषणा की है कि आप आपके खजाने के सारे किवाड़ खोल देंगी और मुक्त हाथ से, मुक्त मन से उनकी आप भरपूर मदद करेंगी। यह आपका आश्वासन ही हम चाहते थे और कोई बात थी नहीं। यह जब आप कह रही हैं तो गेन आपको मिल रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा । हम तो उनके लिये संघर्ष कर रहे हैं और आप आश्वासन दे रहे हो । उस आश्वासन के मुताबिक किसानों को दे देंगी तो आप गेनर हो जायेंगे, हम तो इस मायने में लूजर रहेंगे। लूजर इस मायने में रहेंगे कि हमने संघर्ष किया, जब आप मानी हैं। हमने संघर्ष किया। (व्यवधान)

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें क्लियर करना चाह रही हूं कि यहां अच्छी चर्चा होती तो बहुत अच्छा होता, परन्तु जहां तक सरकार का सवाल है वह पहले दिन से ही हम सब लोग चाहे मंत्री महोदय हों, चाहे पूरे हमारे माननीय सदस्य हों, सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना काम करने के लिये निकले हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं हमारी ड्यूटी हमें बताने के लिये। हमारी जो ड्यूटी है उसको हम पूरी तरह से करेंगे। पहले भी किया है, फिर करेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** नहीं-नहीं, अब कुछ नहीं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चार दिन पहले लगातार किसानों की फसल नष्ट हुई है..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है ..(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): चार दिन के बाद भी सरकार कोई बात सुनने के लिये तैयार नहीं है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, अब कुछ नहीं। (व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) कह दिया नेता प्रतिपक्ष ..(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** इनकी तो कल मीटिंग हुई है 200 .. (व्यवधान) इनका तो काम ही यह है ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** क्या कहना चाहते हैं आप ? (व्यवधान) क्या तरीका है?

**श्री अमराराम** (धोद): मैं तो मेरी बात कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो भंयकर त्रासदी हुई है, 100 प्रतिशत फसल नष्ट हुई है। चार दिन के प्रतिवाद के बाद भी सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, इसलिए मैं सदन से बहिर्गमन कर रहा हूं।

**(श्री अमराराम (धोद), माननीय सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)**

**श्री अध्यक्ष:** माननीय नेता प्रतिपक्ष, बात यह हुई थी कि आप यह भी माननीय सदस्यों को, जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आप उनसे आग्रह करते कि बात हो गयी है, मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है कि वह कोई कसर नहीं रखेंगी किसानों को सहायता पहुंचाने में, अब आप कृपया इनको कह दीजिये कि अपने-अपने स्थान पर चले जायें। माननीय सदस्य, अपने स्थानों पर चले जायें।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे आपने बोलने नहीं दिया न । मुख्य मंत्रीजी के ठीक बाद में मैं यही रिक्वेस्ट करने वाला था और ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** अनशन तो तुड़ाते बाहर अपने स्थान पर जाकर, यहां थोड़ी टूटेगा।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी को मेरी बात थोड़ी कड़वी लगी। मैंने कड़वी बात कोई दुर्भावना से नहीं कही है।

**श्री अध्यक्ष:** अब मीठी कह दो। अब मीठी कह दीजिये।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आपको उससे ठेस पहुंची हो..(व्यवधान)

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): आपकी बात तो हमेशा अच्छी लगती है हम सबको। हमें आपकी बात कभी कड़्वी नहीं लगी है और जहां तक किसानों की राहत का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो पहले ही जो पैकेज दिया, हमारे रिलीफ मंत्रीजी ने अच्छी तरह से बता भी दिया था कि हमने 12 तारीख से पहले वाला जो नुकसान हुआ, ओलावृष्टि के अंदर दिया है उसको हमने अन्तरिम पैकेज मानकर ..(व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): Don’t put it. Don’t misquote it. Madam I am sorry.

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): हमने उसको अन्तरिम मानकर दिया हुआ है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** सदन की नेता को समाप्त तो करने दें। (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): The spirit we have to maintain it. If it is not in right spirit then what is this.

**श्री अध्यक्ष:** सदन की नेता को समाप्त तो कर लेने दें। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैंने तो मुख्य मंत्रीजी से कल भी निवेदन किया था, आज भी किया है और यह मानीं, इससे मुझे खुशी है, मेरी पार्टी को भी खुशी है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं और आपको बताऊं चौधरी कुम्भारामजी एक बार रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे। उनके पास एक फाइल गयी। कुम्भारामजी ने उस पर जो आदेश दिया था, उसकी टिप्पणी नीचे से प्रतिकूल आई। बोले, यह नियमों में है ही नहीं। कुम्भारामजी ने उस फाइल पर लिखा ऐसा नियमों में नहीं है तो वह नियम बदल दिया जाये।

(श्री रामनारायण चौधरी)

यह मैंने आपसे भी कहा। मैंने आपसे भी कहा है, ऐसे नियमों को आप बदल दें और जहां नियम नहीं हैं वो नियम किसानों के बना दो। अध्यक्ष महोदय, हम आपके साथ हैं इस मामले में।

**श्री अध्यक्ष:** आप बीच में क्यों बोलते हैं? चर्चा सदन की नेता प्रतिपक्ष के नेता के बीच की है, आप क्यों बोलते हैं?

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): जीरा, धनिया, प्याज, टमाटर, ईसबगोल सब किसानों की चीज हैं, मान्यवर। अब टमाटर तो साफ हो गया बेचारे का, तो इन सब को आप लीजिए और हम आपका आभार मानेंगे, किसान खुश होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को, जिनको हमने बैठाया था, मैं अनुरोध करूंगा हमारे पी.सी.सी. प्रेसिडेंट से, शिवचरणजी माथुर साहब वहां जायेंगे और इनको, इनसे प्रार्थना करेंगे कि सीट पर बैठाएं इनको।

**एक माननीय सदस्य:** जूस पिलाएं।

**श्री अध्यक्ष:** सदन में नहीं पिलाया जायेगा, सदन से बाहर जाकर के आप इनका अनशन तुड़वाएं, जूस पिलाइये और जो कुछ करिये लेकिन आप सदन से बाहर जाकर के करें यह काम।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): धन्यवाद दे दें आप।

## धरना-समाप्ति

**(श्री मंगालाराम गोदारा एवं डा. श्रीगोपाल बाहेती द्वारा धरना समाप्त)**

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप भी बता दो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): बजा देंगे।

**श्री अध्यक्ष:** बजा दी न, बजा तो दी।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे दल के दो माननीय सदस्यों को हमने बैठाया था, कड़वी घूट थी, कदम बहुत सख्त था लेकिन आपने भी बात मानी तो फिर इन्होंने भी बात मानी। मैं आपका और मेरी पार्टी का, दोनों माननीय सदस्यों का और मेरी पार्टी का मैं आभार मानता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** और आसन का आभार बिलकुल नहीं मानेंगे आप?

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आसन ने, अध्यक्ष महोदय, आपने जो सहृदयता दिखायी, अनेक बार गतिरोध पैदा हो गया फिर भी आप लगी रहीं। प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष ने माना या नहीं माना मैं कह नहीं सकता लेकिन हमने तो मान लिया था और मुख्य मंत्रीजी अड़ी नहीं कहीं भी लेकिन उनके सलाहकार जो थे, उनके जो सलाहकार थे, बुरा मत मान जाना, एक साल पहले इसी सभा के अन्दर, इसी बजट सत्र में कहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके सलाहकार जो बैठे हैं आपके आगे और पीछे और बराबर मैं, इनसे आप सावधान रहो, यही आपको डुबो देंगे। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सावधान रहें। (व्यवधान)

## स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री अध्यक्ष:** मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:-

श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से राज्य में विधि सचिव के पद पर पदस्थापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

वैसे भी इस मामले को मैंने राज्य सरकार को भेजा है टिप्पणी के लिए कि उनकी क्या टिप्पणी आती है और इसके अलावा बीस तारीख को जो न्याय प्रशासन की मांग है, उस पर भी माननीय सदस्य को यह प्रश्न उठाने की अनुमति होगी इसलिए मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से जिला पाली में पारम्परिक तरीके से ईंट कजावा व मिट्टी के बर्तन तैयार करने वालों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
2. श्री हीरालाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सम्पर्क एवं लिंक सड़कों का निर्माण करने के सम्बन्ध में।
3. श्री जालमसिंह रावलोत, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर एवं

जैसलमेर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में।

4. श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 स्थित रींगस कस्बे में ट्रोमा अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में।

**(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

माननीय सदस्य, चूंकि आज इसमें से एक-दो तो ऐसे ही हैं इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण मांग है जिस पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे।

पर्ची तो बाद में, अभी थोड़ी। हां, चूंकि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया इसलिए मैं चाहूंगी कि जिन चार सदस्यों की पर्ची है उनको मैं चार मिनट का समय दूंगी एक-एक को बोलने के लिए क्योंकि इसके बाद हम प्रारम्भ करना चाहेंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य की मांग को।

श्री अर्जुनलाल मीणा। कृपया बोलें आप।

## पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

### मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आरक्षण विषयक

**श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** इसके बारे में आपने प्रश्न जब पूछा था, उठाया गया था प्रश्न तो माननीय मंत्रीजी ने कह दिया था कि वो साक्षात्कार रोक दिये हैं। वही प्रश्न तो है आपका।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): नहीं, अध्यक्ष महोदय, नहीं रोके।

**श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सदन में जो आश्वासन दिया था उसके तहत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर के पदोन्नति में जो साक्षात्कार हो रहे हैं उनको रोका नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 13.03.2007 से होने वाले प्राध्यापकों की पदोन्नति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आरक्षण प्रावधानों की अवहेलना हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 45 पदों में से

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

एक भी पद एस.टी. केन्डीडेट नहीं है और पिछले 2001 में जो विश्वविद्यालय में भर्ती हुई थी उसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एक भी केन्डीडेट को भर्ती में नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइड लाइन के आधार पर यू.जी.सी. की जो गाइड लाइन 2006 के बिंदु संख्या 8 (ए) (4) में एस.सी., एस.टी. के आरक्षण के आरक्षण का प्रावधान है उसमें यह भी प्रावधान है कि जो बोर्ड, चयन करने का जो बोर्ड बनेगा उसमें एस.सी., एस.टी. का भी एक प्रतिनिधि होगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो भर्ती हो रही है उसमें एक भी केन्डीडेट, एक भी प्रतिनिधि एस.सी., एस.टी. वर्ग का शायद नहीं लिया है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर अपना जवाब दें।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्रीजी, इसका जवाब देंगे जिस दिन शिक्षा की मांग होगी। आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजियेगा आप।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): प्रमोशन तो अभी हो रहा है, इन्टरव्यू चल रहे हैं ... (व्यवधान) कालेज खुल जायेंगे उसके बाद क्या होगा?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, उसमें सलेक्शन कमेटी में जोधपुर यूनिवर्सिटी के एक्स वाईस चान्सलर प्रोफेसर श्यामलाल हैं उसमें जो शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। उसके अन्दर हैं वो। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो प्रकार के, पहले माननीय सदस्य ने उठाया था, 12 तारीख को जो साक्षात्कार हो रहे थे उनमें एस.सी., एस.टी. का बैकलोग नहीं था। यह सब्जैक्ट आपने उठाया था, उसको मैंने आपकी अनुमति से रोक दिया था।

यह जो है यह सी.एस. स्कीम के अन्तर्गत यह कार्यवाही हो रही है लेकिन इसमें भी मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो-जो अहर्ताएं हैं और जो आवश्यकताएं हैं उसके अन्तर्गत यह कार्यवाही होगी। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि हम यह निर्देश उनको भेज रहे हैं कि साक्षात्कार के बाद लिफाफे बंद रखेंगे और उनसे सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद में जो-जो मापदण्ड तय किये गये हैं, उन्हीं के आधार पर होगा। शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी, अपने सज्जन जो हैं वो उसमें साक्षात्कार में हैं और इसलिए जो भी प्रावधान होगा उस प्रावधान का पूरा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पालन किया जायेगा, किसी प्रकार से एस.सी., एस.टी. के साथ अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): एक ही निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय। जो इन्टरव्यू ले रहा है वह खुद ही एप्लीकेन्ट है। जज कभी खुद का फैसला देता है ... (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): यह आदेश दे दिया है कि वो नहीं बैठेगा। रोक दिया है उसको।

**श्री अध्यक्ष:** श्री तगाराम चौधरी, बाड़मेर रिफाइनरी के सम्बन्ध में।

(अनुपस्थित) श्री हरीसिंह रावत।

## उदयपुर में आई.आई.टी. की स्थापना करने विषयक

**श्री हरीसिंह रावत** (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे उदयपुर सम्भाग में इण्डियन टैक्नोलोजी आफ साइंस और आई.आई.टी. के बारे में कुछ मेरे सुझाव रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विश्व में हमारा प्रदेश, हमारा देश चाहे चिकित्सा हो, चाहे टैक्नोलोजी हो, चाहे इन्जीनियरिंग हो, हरेक में अग्रिम रहा है और इसका लोहा अमरीका के राष्ट्रपति मिस्टर बुश ने भी माना है और कहा है कि अमरीकियों, जागो, नहीं तो भारतीय आ जायेगें।

इसी के अन्तर्गत आज हमारे देश में भी आई आई टी खुलने के आसार हुए हैं जिसके अन्तर्गत मैं चाहता हूं कि आई आई टी हमारे उदयपुर में खुले। इसके कारण कि हमारे उदयपुर संभाग में कहीं भी कोई भी ऐसा बड़ा इन्स्टीट्यूट नहीं है। आज अगर हम देखें तो जोधपुर में एम्स या लॉ यूनिवर्सिटी है, जयपुर में एम एन आई टी एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी, कोटा में टैक्निकल यूनिवर्सिटी एवं ओपन यूनिवर्सिटी तथा अजमेर में लोक सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसी राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं लेकिन उदयपुर में हमारी ऐसी कोई संस्था नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आई आई टी का यह प्रावधान जो है हमारे उदयपुर में रखा जाए। इसके कई हमारे बिंदु हैं, हमारे यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दो हाई वेज हमारे यहां क्रास करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अहम भूमिका जो हम देंगे वह है जमीन की, हमारे पास चार जगह

(श्री हरीसिंह रावत)

ऐसी जमीन है जो पांच सौ हैक्टेअर से भी अधिक है। जितनी भी जमीन चाहिएगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद भी अगर पैसों की जरुरत पड़ेगी तो हमारे पूरे संभाग के जितने भी हम विधायक और सांसद हैं हमारे फण्ड से देकर जो भी कमी होगी, हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे।

अत: आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आई आई टी हमारे उदयपुर में स्थापित हो। इस सन्दर्भ में हमारे चपलोत साहब भी कुछ बोलना चाहेंगे। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमती वंदना मीणा।

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी बारे में पर्ची दी है और यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने पहली बार पर्ची दी और खुली नहीं। आई आई टी उदयपुर में होना नितान्त आवश्यक है। राजस्थान को एक आई आई टी केन्द्र सरकार ने दी है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** पर्ची के माध्यम से उसी को इजाजत दी जाती है जिसने पर्ची डाली हो। (व्यवधान)

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): एक मिनट की बात है मेरी ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): जोधपुर सबसे बढ़िया जगह है, जोधपुर में आई आई टी ...(व्यवधान) जोधपुर में सबसे बढ़िया जगह है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): जोधपुर ठीक है और हर दृष्टि से जोधपुर में आवश्यक है। (व्यवधान) जोधपुर सबसे उत्तम जगह है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है, ...(व्यवधान) आसन पांवों पर है, ...(व्यवधान) आसन पांवों पर है ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): xxx

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): xxx

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): xxx

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): xxx

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): xxx

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (नोखा): xxx

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): xxx

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): xxx

**श्री अध्यक्षः** कृपया स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण कर लें, नो, नो, स्थान ग्रहण करें, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, जिसकी पर्ची होती है केवल वही बोलता है, यह गलत परम्पराएं आप डाल रहे हैं, उचित नहीं है। श्रीमती वंदना मीणा।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना गतिरोध हाउस में हुआ है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि आई आई टी जो सीपेज वाला क्षेत्र है ग्रामीण बड़ोप्पल टेन प्लस टू का भवन ही उपलब्ध नहीं है वहां बनाओ।

**श्री अध्यक्षः** स्थान ग्रहण करें, श्रीमती वंदना मीणा।

## पंचायतों को पट्टे जारी करने का अधिकार देने विषयक

**श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे उदयपुर ग्रामीण में सत्रह पटवार मण्डल व इक्कीस पंचायतें हैं और इन पंचायतों में 67 गांव जो पैराफेरी में आते हैं, यह जो गांव पहले पंचायतों में थे और उसके बाद पैराफेरी में आने की वजह से इन गांवों में करीबन बारह हजार परिवार लाभान्वित होते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि इन परिवारों को न तो पंचायत पट्टे दे सकती है क्योंकि यह पैराफेरी में आने की वजह से पंचायत कहती है कि यह पैराफेरी में हैं इस वजह से हम पट्टे नहीं दे सकते हैं, यह नगर विकास प्रन्यास के द्वारा दिए जायेंगे। यह रोक पंचायतों ने लगा रखी है। उन पंचायतों में सभी मध्यम वर्ग के व गरीब परिवार रहते हैं।

मेरा अनुरोध है कि इन पंचायतों द्वारा इन परिवारों को पट्टे दिए जाएं और उसके साथ-साथ नगर विकास प्रन्यास से विकास कार्य भी करवाए जाएं क्योंकि वहां पर चाहे स्कूल भवन हो, चाहे आंगनबाड़ी भवन हो वह पंचायत भी नहीं बना सकती है जब तक यू. आई. टी. एन. ओ. सी. नहीं देगी तब तक वहां भवन का निर्माण नहीं होगा। ऐसी पंचायतों में सरपंच जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं वह तो काफी चक्कर लगाकर एन.ओ.सी. लाते हैं तब जाकर उसका निर्माण होता है बाकी सीधे-सादे सरपंच होते हैं उनके जूते तक टूट जाते हैं, वहां के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती वन्दना मीणा)

ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदयजी, इन पंचायतों को, जो पैराफेरी के अन्तर्गत आती हैं, उनकी समस्या का समाधान करें। कहीं न कहीं इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। यह बारह हजार परिवार आपको हमेशा के लिए याद करेंगे। इसी आशा के साथ मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री तगाराम। हालांकि आपको समय पर आने की आदत डालनी चाहिए लेकिन चूंकि यह रिफाइनरी का मामला है इसलिए मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूं।

## बाड़मेर में तेल रिफाइनरी लगाने विषयक

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैंने आपकी आज्ञा से पर्ची के माध्यम से बाड़मेर में तेल की रिफाइनरी लगे, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री से और सदन से निवेदन करना चाहूंगा, जब से तेल निकला है बाड़मेर में तब से लेकर के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत प्रयत्न किया है रिफाइनरी के लिए, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। सर्वदलीय बैठकें बुलाईं, संकल्प पारित किए और सभी ने एकजुट होकर के बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगाने का तय किया था और बड़ी खुशी थी कि बाड़मेर में ही लगेगी। बीच में यहां से दल भी गए अधिकारियों के और वहां पर देखा गया किस जगह उपयुक्त है, क्या है।

मेरी तो उसमें मांग थी धौलपाडिया खाली जमीन पड़ी थी उसमें लगाने की, लीलाडा, जादुओ की ढाणी और बायतु में तय कर दिया था टीम ने और उसके कुछ ही समय बाद में भारत सरकार से भी हरी झण्डी मिल गई थी और रिफाइनरी लगना तय हो गया था। वहां पर राजनीतिक कारण से कुछ प्रतिपक्ष के नेताओं के इशारे पर कहो, वहां के बाड़मेर के उन्होंने वहां कुछ वाद विवाद भी उठाया था, टी.वी. में भी कई बार आया था, इस तरह की बातें भी हुई उसके उपरांत मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। फिर बाद में भारत के पैट्रोलियम मंत्रीजी बदल गये और अभी जो वर्तमान में मंत्रीजी हैं वह या किसी कारण से यह जो मांग उठी है दुबारा इतनी रियायत देने की, बड़ी भारी रियायत देने की, यह समझ में नहीं आ रही है। जब तेल निकाला, किसानों ने अपनी जमीन दी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे को आदेश फरमाया

(श्री तगाराम चौधरी)

था मंगला-1 के लोकार्पण के दिन कि यह जमीन देनी है और आप काश्तकारों का मन बनाओ और यह देश के भले का मामला है, राजस्थान के भले का मामला है, इससे ज्यादा कोई अवसर हो नहीं सकता बाड़मेर के लिए कि बाड़मेर में रिफाइनरी खुले तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उद्योगपतियों को उद्योग लगाने का अवसर मिलेगा। गाड़ी वालों को तेल की ढुलाई का अवसर मिलेगा और कई तरह के फायदे होंगे। राजस्थान अकेले को ही नहीं भारत को भी फायदा है। फिर यह रिफाइनरी आगे से आगे सरक रही है जिससे तेल का दोहन बीच में कई बार इस तरह से घोषणाएं भी हुई कि तेल का दोहन 2005 में कर दिया जायेगा। फिर 2006 भी निकल गया, 2007 भी निकल गया। अब वहां पर केयर्न की मीटिंग कलक्टर साहब की अध्यक्षता में हुई थी। केयर्न वाले कह रहे हैं 2009 में हम करेंगे। तो दिन-प्रतिदिन वह दोहन भी अभी बंद पड़ा है एक प्रकार से। गाड़ियों से, ट्रकों से यदि लोडिंग करके कच्चा तेल बाहर भी ले जाते तो बहुत गाड़ी वालों को फायदा होता। आज के दिन जो ट्रक युवा बेरोजगार चलाते हैं उनको काम मिलता नहीं है, बहुत काम मिलता, वहां पर भी रोजी लगती और यह फायदा ही फायदा है। मुझे बहुत ही विश्वास है माननीय मुख्य मंत्री महोदया पर और पूरे सदन पर कि यह काम आप करवायेंगे। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से भी.

**श्री अध्यक्ष:** वह जो गयीं।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): कि आप अपना पूरा प्रभाव काम में ले करके यह रिफाइनरी बाड़मेर में ही लगवाएं। यह मेरी प्रार्थना है पूरे सदन से। पुरजोर मांग है यह रिफाइनरी नहीं खुलती है तो मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा और यह रिफाइनरी खुलनी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष:** पुरजोर मांग ही मत करो। आप सदन से यह कहो कि सदन इस सम्बन्ध में संकल्प पारित करके भेजे।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): मैं आपके माध्यम से...

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर विषय है और हम सब तगारामजी के साथ हैं। बाड़मेर में ही रिफाइनरी खुलनी चाहिये। जहां पर माल पैदा हो, वहां नहीं खोल करके दूसरी जगह जो षड्यंत्र किये जा रहे हैं यह राजस्थान की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

राजस्थान में ही खुलेगी और बाड़मेर में ही रिफाइनरी खुलनी चाहिये ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): मैं आपकी आज्ञानुसार...

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में रिफाइनरी नहीं हो इसके लिये पूरे प्रयत्न हो रहे हैं। जो शर्तें रखी जा रही हैं 26,000 करोड़ की शर्त वह निश्चित रूप से एक ऐसी शर्त है जो कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती जबकि अटल बिहारी वाजपेयीजी ने मध्य प्रदेश में और पंजाब में रिफाइनरी खोलने के लिये केवल 1500 सौ करोड़ रुपये की शर्त रखी थी और वहां रिफाइनरी चालू हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, इसमें नयी बात यह है मैं माननीय सदस्य तगारामजी से कहना चाहता हूं..

**श्री अध्यक्ष:** पर्ची तो उनकी है, बोल रहे हैं आप।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): कि वहां तेल भी नहीं है। जहां तेल नहीं है वहां रिफाइनरी चालू हो गयी है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा होता यहां मुख्य मंत्री और सरकार अभिभाषण और बजट में इस पर कोई बात कहतीं। पूरे अभिभाषण और बजट में एक शब्द भी नहीं कहा रिफाइनरी के लिये। यह सरकार रिफाइनरी के प्रति कितनी गंभीर है यह इससे ही मालूम पड़ जाता है।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): जहां तेल है, कच्चा तेल है वहां रिफाइनरी नहीं हो इसके लिये +++ राजस्थान के बाड़मेर जिले में रिफाइनरी नहीं हो यह केवल +++ आप उसे रोकें। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहता हूं उनका प्रयत्न पूरा चल रहा है लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय नेताजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने प्रयत्न से केन्द्र सरकार को समझाएं रिफाइनरी बाड़मेर में ही होनी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आपकी पर्ची नहीं है। मिस्टर रावलोत, कृपया विराज जाएं। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया विराजें। आपको इस पर्ची पर अनुमति नहीं है। स्थान ग्रहण करें। तगारामजी, काफी बोल लिये आप तो। बात कह दी ना आपने अपनी।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पूरे सदन से और विशेष तौर से मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन

(श्री तगाराम चौधरी)

करना चाहता हूं कि पुनः पूरा सदन इस बहुत ही जन कल्याणकारी राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये और यहां के बेरोजगारों को रोजगार मिले, उद्योग मिले। बाड़मेर पिछड़ा हुआ रहा है बरसों से तो वहां पर उद्योग खुलें। इस तरह का बहुत ही अच्छा काम होगा इसके लिये संकल्प व्यक्त किया जाए सर्व सम्मति से। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री टीकम चन्द कान्त** (सिवाना): हम भी उम्मीद करते हैं कि सदन यह संकल्प पारित करेगा कि बाड़मेर में ही रिफाइनरी खुलनी चाहिये।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस मामले को उठाया, पर्ची के द्वारा सरकार से संबंधित जानकारी लेने के बारे में ही चीज उठायी जाती है लेकिन तगारामजी ने तो प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप लगा दिया कि हम तो कर रहे हैं लेकिन प्रतिपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं..

**श्री अध्यक्ष:** यह किसने कहा है ?

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): कहा है।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): ऐसा बीच में हुआ। मान्यवर, ऐसा बीच में वहां पर हुआ था।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उस पर्ची के तहत उन्होंने जो आरोप लगाया है उसको हटा दिया जाए कार्यवाही से।

**श्री अध्यक्ष:** हटा देंगे। ऐसा कहा है तो हटा देंगे। अब मंत्री कुछ कह रहे हैं। मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तगारामजी ने यह बात कही सदन की नेता हाउस में उपस्थित थीं। अगर वह पहल करतीं और संकल्प लाने की कोई बात करतीं तो कोई बात बनती।

**श्री अध्यक्ष:** संकल्प वैसे भी आ सकता है। आ सकता है संकल्प।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी बैठे हैं तो फिर संकल्प, यह सही है राजस्थान में लगनी चाहिये। बाड़मेर में लगनी चाहिये इसमें किसी को इल्तजा, किसी को इंकार नहीं है। पहल करिये आप। इल्जाम लगाने से क्या होता है कि यह नहीं कर रहे हैं, वह नहीं कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्री खड़े हैं। कुछ बोलना चाह रहे हैं।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य का आभार प्रकट करना चाहता हूं पर्ची के माध्यम से राजस्थान की साढ़े पाँच करोड़ जनता की धड़कन की आवाज है, जो मांग है उसके बारे में उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, इसके लिये मैं इनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक ऐसा पिछड़ा प्रदेश है जिसमें पिछले सौ साल में चालीस साल तो अकाल पड़ा। राजस्थान में पेयजल की समस्या, अकाल की समस्या है। राजस्थान में पहली बार प्रकृति मेहरबान हुई पश्चिमी राजस्थान में यहां पर पैट्रोलियम के अथाह भण्डार मिले। पिछले तीन साल के कार्यकाल में 138 कुओं के छिद्रण का कार्यक्रम हुआ जिसमें 380 मिलियन टन पैट्रोलियम के डिपाजिट प्राप्त हुए। पिछले 45-50 साल के कार्यकाल में 111 कुओं के छिद्रण का कार्यक्रम हुआ और मात्र 20 मिलियन टन डिपाजिट प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 2004 में रिफाइनरी की स्थापना के लिये तेल कम्पनीज की एक मीटिंग मैंने आयोजित की थी जिसमें ओ एन जी सी और तमाम कम्पनीज थीं। उनसे आग्रह किया था कि कर्नाटक की तर्ज के आधार पर सेज, कर्नाटक की तर्ज के आधार पर रिफाइनरी पैट्रो केमिकल्स काम्पलेक्स आदि की स्थापना राजस्थान में की जानी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की कम्पनी ने रिफाइनरी के लिये अपनी सहमति दी थी और मीटिंग के अन्दर यह प्रस्ताव हुआ था। उसके बाद एम ओ यू साइन होना था। एच पी सी एल और राजस्थान सरकार के बीच में एम ओ यू साइन होना था परन्तु केन्द्र सरकार के दखल के कारण 98 के अन्दर यह एम ओ यू साइन नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैंने राजस्थान के तमाम सांसदों को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि रिफाइनरी की स्थापना के लिये भारत सरकार से आग्रह किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 मई, 2005 को राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने भारत के प्रधानमंत्री को राजस्थान में रिफाइनरी लगाने के लिये पत्र प्रेषित किया और अक्टूबर, 2005 में राजस्थान प्रवास के दौरान ओ एन जी सी के चेयरमैन सुधीर रॉ जो एम ओ यू साइन होना धौलपुर पावर प्लांट के गैस आपूर्ति के समझौते में उसमें यहां के चेयरमैन सुधीर रॉ ने यह स्वीकार किया था कि राजस्थान में रिफाइनरी लगाने के लिये प्रोपर जगह है और इकोनोमिकली वायबल है। यह बात ओ एन जी सी के चेयरमैन सुधीर रॉ ने स्वीकार की थी। यहां पर उन्होंने यह भी विश्वास

दिलाया था कि राजस्थान में अगर परिस्थिति अनुकूल रही तो 36 और 40 माह के बीच के अन्दर रिफाइनरी का कार्य कम्पलीट कर दिया जायेगा उसके बाद..

**श्री अध्यक्ष:** आप तो यह बताओ कोई उम्मीद है कि नहीं ?

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ओ एन जी सी द्वारा चाही गयी आधारभूत सुविधाओं, ओ एन जी सी के अधिकारियों के साथ चर्चा के लिये 30.11.2005 को एक मीटिंग आयोजित की उसमें आर के मदान एसोसियेट प्रोफेसरान और बिजनेस डवलपमेंट और एच पी एस आहूजा यह थे। मैं सभी चीज अभी आपको बता दूंगा। मुख्य मंत्री द्वारा तेल कुओं के फील्ड डवलपमेंट प्लांट की स्वीकृति के लिये रिफाइनरी की स्थापना हेतु केन्द्रीय पैट्रोलियम मिनिस्टर को पत्र प्रेषित किया ... (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी का गुणगान तो थोड़ी देर बाद सब कर लेंगे। अगर आज करना है तो अध्यक्षजी ने यह निर्देश दिया, आसन ने यह निर्देश दिया है कि आप लगाना चाहते हैं कि नहीं? आपका सरप्लस बजट है। पैसा देना है कि नहीं? आप एक बात कह दो। पत्र प्रेषित...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक भेदभाव के आधार पर यह रिफाइनरी राजस्थान में नहीं लगाना चाहते ... (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): जितनी आपको, मुख्य मंत्रीजी ... (व्यवधान) राजस्थान में किसान ... (व्यवधान) अब तो कृपा करें नाटक बंद... (व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): इनकी नीयत साफ है। सरप्लस बजट कोई रिफाइनरी लगती है क्या ... (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): रिफाइनरी लगाते हैं क्या, आपकी मंशा भी नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप तो कृपया करके नाटक बंद करें ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण आसन का काम आप नहीं किया करें ...(व्यवधान) आपसे कह रही हूं आसन अपना काम करेगा, आप नहीं किया करें ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): हमें पता है सब, आप गुणगान करके राजस्थान का भट्ठा बैठा रहे हैं और यह तरीका ठीक नहीं है ...(व्यवधान) जनता सब जानती है और हम सब जानते हैं ...(व्यवधान)

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): आसन का कहना नहीं मान रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहा है राज्य सरकार का ...(व्यवधान) यह कहना नहीं मान रहे हैं, बीच में ही ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप आसन का काम करने लगते हैं ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रश्न भी नहीं पूछने देना चाहते हैं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** मंत्रीजी, आसन खड़ा हो तो आपको भी स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए ...(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के उप नेता ने जिस तरह से बात पेश की, आज राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने पक्ष और प्रतिपक्ष की सर्वदलीय बैठक आयोजित की, यह प्रश्न राजस्थान के तमाम साढ़े पांच करोड़ जनता के हक की बात का है, ना तो प्रतिपक्ष और ना पक्ष अगर यह बात है तो सामूहिक रूप से एक निर्णय किया जाये। भारत सरकार से इस प्रकार से आग्रह किया जाये कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहजी ने आंध्र प्रदेश के काकानाड़ी के अंदर, वहां पर ओ.एन.जी.सी. ने कहा था कि इकोनोमिकल वाइबल वहां रिफाइनरी के लिए नहीं है लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करके वापिस इस मामले को पुर्नविचार के लिए आग्रह किया।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने 15.01.2007 को रिफाइनरी की स्थापना के लिए केन्द्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर को पत्र लिखा। मैं आज प्रतिपक्ष पर या किसी सरकार पर आरोप-प्रत्योराप नहीं करना चाहता। मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सकारात्मक तरीका आप अपनाकर राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान की साढ़े पांच करोड़ जनता के लिए राजस्थान में रिफाइनरी लगवायें। इसमें पक्ष और प्रतिपक्ष सामूहिक रूप से एक साथ होकर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पेट्रोलियम मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा। जहां जिस क्षेत्र में पेट्रोल निकला, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोल निकला, बाम्बे हाई में पेट्रोल निकला वहां रिफाइनरी लगी, गुजरात में पेट्रोल निकला तो

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

गुजरात में रिफाइनरी लगी, आसाम में पेट्रोल निकला तो आसाम में रिफाइनरी लगी तो राजस्थान की तमाम जनता का अधिकार बनता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है कि जिस पश्चिमी राजस्थान में, जिस रेगिस्तान में पेयजल की समस्या है, अकाल की समस्या है, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है तो रिफाइनरी के लिए अगर कोई न्यायोचित स्थान है तो राजस्थान है। राजस्थान भारत सरकार से आग्रह करता है। मुझे भारत के प्रधानमंत्रीजी से मिलने का मौका मिला, मैंने उनसे भी आग्रह किया और पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पूर्व मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर को जिन्होंने मुख्य मंत्री जी को आग्रह किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। यह राजस्थान के हित की बात है। राजस्थान के अधिकार की बात है, इसलिए राजस्थान के तमाम दो सौ विधायक सभी मिलकर के एक राय से रिफाइनरी राजस्थान में कैसे लगे, राजस्थान में दस हजार करोड़ का इनवेस्टमेंट कैसे लगे, इस बात पर आज चर्चा करनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** लायें तो आप संकल्प, कौन ना कर रहा है ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, आप शर्तें मान लो, भाषण नहीं, वह तो वोट के टाइम आप कर लेना ...(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैं अभी बताता हूं ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप शर्तें मान लीजिये ...(व्यवधान) बहुत दु:खी हैं ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): आपने मानी है क्या ...(व्यवधान) आंध्र प्रदेश में मानी है, गुजरात में मानी है कि पंजाब में मानी है, जो हम मान लें ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): हैलीकॉप्टर आपके काम आता है, एयरोप्लेन आपके काम आता है, आप जाइये बात करिये ...(व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): 26 हजार करोड़ की शर्तें नहीं मान सकते हैं ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): हम भी अख़बार पढ़ते हैं ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): इस प्रकार की अव्यावहारिक शर्तें लगाकर के राजस्थान में रिफाइनरी नहीं ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप इस प्रकार से राजस्थान का भला नहीं कर सकते ...(व्यवधान) आप बैठिये ...(व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): राजस्थान को विकसित राज्य बनाना हमारी सरकार का संकल्प है। राजस्थान अभी विकासशील है ...(व्यवधान) 26 हजार करोड़ संभव नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मैं तो लंबी बात नहीं करूंगा, एक ही बात कहूंगा कि शर्तें बैठकर के नेगोसिएट करें, राजस्थान का भला करो, कहीं दूसरी जगह चली जायेगी। आई.आई.टी. आप नहीं दे रहे। दूसरे प्रांत में चली जायेगी। आपकी जो कार्य शैली है उसको ठीक करो, गति लाओ। लोगों से मिलना-जुलना शुरू करो और चिट्ठी-पत्री की बात कम करो और प्रेक्टिकल बात ज्यादा करो ...(व्यवधान)

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, शर्तें पहले तो थी ही नहीं, जिस समय हरी झंडी मिली थी दिल्ली से, उस समय शर्तें थी ही नहीं। अब शर्तें कहां से आयी ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप तो एनर्जेटिक हो। आप हर बात के लिए उधर क्यों देख रहे हो? आप बोलो हम चलेंगे, बात करेंगे लेकिन शर्तें तो माननी पड़ेंगी। अगर आप राजस्थान का भला चाहते हैं तो ...(व्यवधान) आप बैठकर सुनिये, जब हम बोल रहे हैं ...(व्यवधान) आपको थोड़ा सीखना चाहिए ...(व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता जब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो आप बार-बार क्यों उठ रहे हैं? ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): यह क्या है, यह आप भाषण सुना रहे हैं? ...(व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): माननीय मंत्रीजी पूरा चित्रण कर रहे हैं, आपकी काली करतूतें खोल रहे हैं। कांग्रेस राजस्थान में, बाड़मेर में रिफाइनरी खोलना नहीं चाहती है। शिवचरणजी माथुर जरूर लेते हैं ...(व्यवधान) लेकिन अशोकजी गहलोत नहीं आने दे रहे हैं यह मेरा आरोप है ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मंत्रीजी, आप तो कृपया करके शर्तें

(श्री रामनारायण मीणा)

मान लो और जो कंडीशन हैं, हम दिल्ली बात करते हैं फिर चलेंगे ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** आप बैठ तो जायें, भाषण नहीं ...(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 27 अक्टूबर, 2006 को ओ.एन.जी.सी. ने रिफाइनरी स्थापना हेतु इंसेंटिव की मांग की थी। 15 जनवरी, 2007 को माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा पेट्रोलियम मंत्री जी को पत्र लिखा गया और इस रिफाइनरी के अंदर दखल का आग्रह किया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 10 हजार का इनवेस्टमेंट रिफाइनरी का और 26 हजार करोड़ रुपये का इंसेंटिव, हमारे खान सचिव ने ओ.एन.जी.सी. के चेयरमैन को मांग की, खुलासा के लिए पत्र प्रेषित किया और मांग की कि एस.बी.आई. कैप के अंतर्गत फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है, वह हमें प्रेषित की जाये।

अध्यक्ष महोदय, ओ.एन.जी.सी. ने जो मांगा है, वह सुपरिभाषित नहीं है और जो मांग का पैकेज पेश किया है, वह बहुत अधिक है। जो उन्होंने पत्र लिखा है, जो इंसेंटिव उन्होंने मांगा है उसमें सूचनाओं का पूरा अभाव था और छूटों की राशि 26 हजार करोड़ या इससे अधिक की मांग थी। राज्य सरकार जानना चाहती है कि 10 हजार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट और 26 हजार करोड़ की छूट मांगना कहां तक न्यायोचित है। इसके साथ में मांग की कि एस.बी.आई. कैप के द्वारा की गयी स्टेडी के आधार पर उसकी प्रति भी हमें उपलब्ध की जाये। उसका जो सर्वे किया है उसकी प्रति हमें दी जाये ताकि हम उसका जवाब दे सकें। इसके साथ में वैक्स क्रूड की प्राइज नॉन वैक्स क्रूड के बराबर है या नहीं है इसके बारे में भी हमें जानकारी दी जाये। यह भी बताया जाये कि ट्रांसपोर्टेशन की कुल राशि ओ.एन.जी.सी. वहन करे। रिफाइनरी का प्रोडेक्ट प्रोफाइल बताया जाये।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आई एम आन पाइंट आफ आर्डर...(व्यवधान) मेरा निवेदन था कि या तो सरकार अलग से चर्चा करा ले, आप मर्जी से, यह सदन तो तय करेगा नहीं, तय करना है राजस्थान सरकार को और केन्द्र सरकार को तो वहीं जाकर के बात करें। इसमें सदन की क्या उपयोगिता हो सकती या तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से अलग से रखे। आज पर्ची के माध्यम से चर्चा कराना उचित नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लें ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आपने कठिनाई तो बता दी लेकिन आसन ने आपसे पूछा था कि अब भी कोई उम्मीद है कि नहीं ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): इसके बारे में निश्चित रूप से राज्य सरकार को बताना चाहिए ...(व्यवधान)

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने एक पर्ची के द्वारा तगारामजी को यहां पर बोलने की बात कही। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी बात को बहुत प्रभावी तरीके से उठा दिया। जहां तक सवाल रिफाइनरी का है ...(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माथुर साहब, अब आपकी ही बात कर रहा हूं। जो आपने चिट्ठी लिखी है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप सुन लें पहले ...(व्यवधान)

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): आप बैठें तो सही ...(व्यवधान) किसी को कोई एतराज नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप माथुर साहब को सुन लें, फिर आप दे दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): किसी को कोई एतराज नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो इसके लिए कमिटेड हूं और मैंने तो मुख्य मंत्रीजी से एक बार नहीं कई बार कहा। अभी यहां पर बहस इन्होंने छेड़ दी। ओ.एन.जी.सी. लगाने वाली पार्टी थी उसने कुछ मांग की। इसका मतलब यह नहीं है कि उन मांगों पर आप बात नहीं करें, मैंने तो अभी रिसेंटली एक पत्र मुख्य मंत्रीजी को लिखा है और मैंने कहा है उनसे कि आप आठ हजार करोड़ रुपया इस रिफाइनरी के माध्यम से राजस्थान में पैदा कर सकती हैं और इस राजस्थान को टैक्स-फ्री स्टेट बना सकती हैं।

**श्री अध्यक्ष:** टैक्स-फ्री स्टेट बना सकती हैं।

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): यह मैंने कहा है। केवल भावना से बात नहीं कहता हूं। मैं तो इसके लिये आपके राम नाइकजी ...(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैं आपका जिक्र करूंगा ...(व्यवधान)

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): सुनिये तो सही। आज बहस हो रही है क्या इस पर?

**श्री अध्यक्ष:** आप बोलने दें उन्हें। आप बोलने दें उन्हें ...(व्यवधान)

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): बहस हो रही है क्या यह ...(व्यवधान) आपने ऐसे तथ्य यहां पर प्रस्तुत किये ...(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैं इनकी चिट्ठी का ही हवाला करूंगा ...(व्यवधान) अच्छी बात है, स्वागत करता हूं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप बोलने दें उन्हें ...(व्यवधान) पहले बोलने दें ...(व्यवधान)

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): आप मुझसे बहस कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माथुर साहब, आप तो अपनी बात पर आयें ...(व्यवधान)

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): मैं तो राम नाइक का भी कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) वह एन.डी.ए. के मिनिस्टर थे और जिस अच्छी तरह से उन्होंने व्यवहार किया। वहीं से मैं इस बात को शुरू करना चाहता हूं। आप भारत सरकार पर दोष लगा रहे हैं।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): नहीं लगाया है।

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): लगाया है आपने। दोष लगाने से क्या होगा।

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): दोष लगाने से आपकी क्या रिफाइनरी लग जायेगी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं? सुन लें उनको।

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): मणिशंकरजी अय्यर को मैंने तैयार किया। मैंने कहा लोक सभा में जब इस प्रकार की बात उठाई जा रही है, मेहरबानी करके आप इसमें निर्णय कीजिए। भारत सरकार रिफाइनरी नहीं लगा रही है, ओ एन जी सी एक कॉमर्शियल पार्टी है, उसने कुछ शर्तें, कुछ बातें रखी हैं, उन पर चर्चा कीजिए, वह शर्तें आपको सूट नहीं करती हैं तो हिन्दुस्तान के अंदर दूसरे प्लेयर्स भी हैं उनको आप इन्वाइट कीजिए। जरूरी थोड़े है कि आप ओ एन जी सी से ही इसमें बात करें, आज बड़े-बड़े कंसर्न हैं, ऐसे कंसर्न हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में एक बड़ी पार्टी की तरह कई स्टील प्लांट खरीद रहे हैं, उनसे आप बात कीजिए। आप केवल ओ एन जी सी को

(श्री शिवचरण माथुर)

लेकर भारत सरकार को दोष देने की बात करें कि उन्होंने 26 हजार करोड़ का पैकेज आपके सामने रख दिया है। मैं समझता हूं कि आप क्या वातावरण पैदा कर रहे हैं रिफाइनरी लगाने का?

मैंने तो कल भी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि इसमें किटंग अक्रोस द पार्टी लाइन, आपको विश्वास दिला कर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के आज के मंत्री मुरली देवड़ाजी, उनसे भी मैंने चर्चा की है, कहीं पर भी उनका कोई विरोध नहीं है। आप मुझे माफ करें मंत्री महोदय, पता नहीं यह कहां तक सच है लेकिन आपने तो एक बार यह भी कहा था कि भटिण्डा से निकलने वाली पाइप लाइन है, मैं इसको नहीं निकलने दूंगा, उसको ब्लास्ट कर दूंगा। आप कैसे ब्लास्ट कर देंगे? आपने नहीं कहा होगा लेकिन यह अखबारों में आया था। (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैंने नहीं कहा था।

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): अगर नहीं कहा था तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह अखबारों में छपा था।

**श्री अध्यक्ष:** अखबारों में आया था।

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): अखबारों में छपा था। रिफाइनरी लगाने का यह कोई तरीका नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ... (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): एच पी सी एल और आई ओ सी की लाइन निकल रही है राजस्थान से होकर, यह हमारा अधिकार बनता है, पहले एच पी सी एल ने आवेदन किया था, ओ एन जी सी ने भी इसको टर्न डाउन कर दिया और अपनी खुद की मांग रख दी थी।

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): भटिण्डा की पाइप लाइन से आपको फायदा है। अगर 10 हजार करोड़ रुपए लगाकर 10 मिलियन टन की फैक्ट्री यहां पर लगाना चाहते हैं और यदि उसकी कैपेसिटी आपको बढ़ानी है तो भटिण्डा पाइप लाइन से आप तेल ले सकते हैं। आपको तो उसका स्वागत करना चाहिए। आपने कहा कि मैं उसको ब्लास्ट कर दूंगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ...(व्यवधान) आप ब्लास्ट शब्द निकालें, वह किस समाचार पत्र में, किसी स्थान पर यह बात नहीं

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

आई है, यह कोई आप मन से पैदा कर रहे हैं। यह ब्लास्ट की बात, कोई आतंकवादी थोड़े हैं जो ब्लास्ट की बात कर रहे हो? स्टेट के इण्टरेस्ट में, जो राज्य के हित में होगा, राजस्थान सरकार रिफाइनरी लगाने के लिए कृत संकल्प है।

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, 21 तारीख को मुख्य मंत्रीजी ने एक मीटिंग बुलाई। विरोधी पक्ष के नेता रामनारायणजी चौधरी, मैं और कल्लाजी कांग्रेस की तरफ से गए थे। दूसरी सभी पार्टियों के लोग भी वहां पर आए थे। एक राय से हमने मुख्य मंत्रीजी को कहा कि हम आपको अधिकृत करते हैं, इसमें आप जो कुछ भी हमारा सहयोग लेना चाहते हैं वह लीजिए, कहीं दो राय नहीं है, इसमें कहां मतभेद है, लेकिन उसके तरीके होते हैं। आप भारत सरकार को गाली देने में लगे हैं, उसकी आलोचना करने में लगे हैं। मुरली देवड़ाजी ने कहा कि कहां हमारी तरफ से इन्कारी है, बैठें तो सही।

कल मुख्य मंत्रीजी कह रही थीं कि मुरली देवड़ाजी से मेरी बात हो गई है, तय हो गया है, हम बैठ कर बात करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से भी मैं जितना भी हमारा इसमें सहयोग होगा, हम रिफाइनरी बाड़मेर में लगाकर रहेंगे, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के द्वारा इस मामले को उठवा कर सदन के अन्दर एक नई बहस करवा रहे हैं और माननीय मंत्रीजी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, यह बॉल को अपने यहां से केन्द्र में फेंकना चाहते हैं, जब बॉल आपकी साइड में है इसलिए है कि ओ एन जी सी ने जो शर्तें रखी....।

**श्री अध्यक्ष:** इन्होंने तो आपके पाले में फेंक दी, केन्द्र को कहां भेजी? आपके पाले में डाल दी।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं इनके पाले में है। आप बैठकर बात क्यों नहीं करते, जैसा माथुर साहब ने कहा है, आपको रियायतें देनी पड़ेंगी, आपको रियायतें देनी पड़ेंगी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप बीच में न बोलें। विराजिए।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): अभी जैसे जौहरी बाजार से

(श्री रामनारायण चौधरी)

आने वाले माननीय सदस्य उछल रहे थे, भाई ऐसे थोड़े काम चलेगा। आप तो व्यापारी आदमी हो और ओ एन जी सी भी व्यापारी है, वह निगोशिएशन करना चाहता है सरकार के साथ, अगर उसके साथ आपका नहीं बैठता है तो आप भारत सरकार से बात करें, भारत सरकार इन्टरवीन करेगी, हम भी मिलकर कोशिश करेंगे, ऐसे मत कहो कि हमारे मंत्रीजी ने लिख दिया, प्रधान मंत्रीजी को लिख दिया, चीफ मिनिस्टर साहब ने यह लिख दिया, हम यह कहां पूछ रहे हैं कि आपने क्या फर्ज किया और चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या फर्ज किया, हमने तो कहीं पूछा नहीं, आपकी ही पार्टी के मैम्बर ने पूछा है तो आप यह साबित करना चाहते हैं कि आप तो पूरी चेष्टा कर रहे हैं लेकिन भारत सरकार नहीं लगा रही है, ऐसा मत करो। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप बोल लेना बाद में, आप तो जवाब भी देंगे।

**श्री अध्यक्ष:** आप प्रश्न पूछ लें, वैसे पर्ची पर ऐसा होता नहीं लेकिन आप पूछ लें प्रश्न। मैं ना नहीं कर रही, आप भी पूछ लीजिए।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की लाइफ लाइन है। जिस इलाके के अंदर अकाल पड़ता है और जहां पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, अगर यह रिफाइनरी लग गई तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति की दिशा और दशा बदल देगी। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से तेल निकालने के मामले में कुछ कम्पनियों को हमने एकाधिकार दिया हुआ था और वर्षों तक दिया हुआ रहा और मिडल ईस्ट के दबाव में वे कम्पनियां पाकिस्तान में तेल निकालती रही, बाकी जगह तेल निकालती रही और हिन्दुस्तान के बाड़मेर में तेल नहीं निकाल सकी जानबूझकर। तो एक ओ एन जी सी ही नहीं है। मैं माथुर साहब की बात से सहमत हूं। एक ओ एन जी सी ही नहीं है, इस समय वर्ल्ड में ओपन मार्केट हो गया है, इसलिए आप अन्य मल्टी नेशनल कम्पनीज से भी चर्चा कीजिए, चर्चा करके जो भी हमारे राजस्थान के हित में हो, जो फायदा हो, उनसे बात करके रिफाइनरी लगाने की बात क्यों नहीं करते? हमारी पार्टी और सरकार, हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि रिफाइनरी राजस्थान में लगे, यह हमारी पार्टी का कमिटमेंट भी है लेकिन, मंत्री महोदय, इस मामले में हमें सतर्कता बरतनी होगी कि एक ही पार्टी के साथ, अगर उस पार्टी ने कोई शर्त लगा दी, उन शर्तों को लेकर हम

(डा. एन. एस. गुर्जर)

इसमें डिले करें, मैंने तो समाचार पत्रों में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, मुझे मालूम नहीं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारियों के पास फाइल बहुत दिनों तक पड़ी रही। उन्होंने देखा तक नहीं। मुझे मालूम नहीं है, यह सही है या गलत है, अगर सही है तो यह बहुत गम्भीर बात है, सरकार को इस बात को देखना चाहिए, इतने सेंसेटिव इश्यू जो राजस्थान के हित से जुड़ा हुआ है, उसमें भी अधिकारी इस तरह की टालमटोल करे या उसको लाइट वे में लें तो यह उचित नहीं है राजस्थान के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो भी कर सकें, प्रतिपक्ष से बात करें, भारत सरकार से बात करें, जितनी भी मल्टी नेशनल्स हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं उनसे आप चर्चा करें और कोशिश यह करें कि जैसा आपने कहा टैक्स फ्री, आप भी यह मानते हैं कि टैक्स फ्री हो सकता है, टैक्स फ्री ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर रिफाइनरी लग गई तो टैक्स फ्री ही नहीं, हमारी इनकम इतनी बड़ी हो जाएगी ... (व्यवधान)

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): किसानों की जमीन ओ एन जी सी के नाम से अलॉट हो रही है।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल टैक्स फ्री ही नहीं मैं इससे भी आगे की बात करना चाहता हूं कि यदि यह रिफाइनरी लग गई तो उसके बाद राजस्थान हिन्दुस्तान के जो विकसित प्रदेश हैं उनकी श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा हो जाएगा कुछ सालों के अंदर और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला गम्भीर है, मंत्री महोदय, आप इसे गम्भीरता से लीजिए और इसमें जवाब तो जैसा आप अपने अधिकारियों से डिस्कस करके आए हैं वह दे दीजिए लेकिन इस विषय को गम्भीरता से लीजिए और रिफाइनरी राजस्थान में लगे इसका प्रयास कीजिए, धन्यवाद। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप जवाब मत दो, आप सीधी बात बता दो।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माथुर साहब को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि इन्होंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा, सोशल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट के कार्यक्रम में मणि शंकरजी अय्यर, तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्रीजी आए थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि राजस्थान के अंदर रिफाइनरी लगाने के लिए पर्याप्त माकूल

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

परिस्थितियां हैं। मैं आपको यह भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा। टेक्नो इकोनोमिक स्टडी जो केयर्न एनर्जी के साथ हुई है उसमें 9 हजार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की आपने बात बताई, इसके साथ आपने 7.5 एम एम टी पी ए की रिफाइनरी जो 15-20 साल तक चल सकती है अपने प्रोडक्शन के हिसाब से, डिपोजिट के हिसाब से, उसके साथ ही मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने स्वयं ने इस बात को इस पत्र में जो माननीय मुख्य मंत्रीजी को प्रेषित किया है उसमें इस बात को स्वीकारा है कि जो इन्सेंटिव ओ एन जी सी ने मांगे हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं, जितने हैं उसकी लागत के 50 प्रतिशत तक होने चाहिए। अगर 9 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका आधा 50 प्रतिशत इन्सेंटिव मांगे जाने चाहिए। जब 10 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 9 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 26 हजार करोड़ रुपए के इन्सेंटिव मांगे जा रहे हैं तो इसको जस्टिफाइड आप भी नहीं माना इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल को इतने दिन रखा। इतनी बड़ी मांग उन्होंने की है उसको जस्टीफाई करने में और उसका आकलन करने में समय लगता है। हमारे खान सचिव ने फरवरी, 2007 में चिट्ठी लिखी थी...।

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो इस पर पूरा दिन बहस रख लीजिए। पर्ची के आधार पर इस तरह के मामले को उठा रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** अब मैं क्या करूं? इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मैं आपको नहीं रोक सकी तो दूसरों को भी नहीं रोक सकती।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 12 मार्च, 2007 को ओ एन जी सी के चेयरमैन ने मीटिंग करने के लिए पत्र लिखा है तो इस पर बैठकर चर्चा करेंगे। हमने जो अपनी बात है उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने जो इन्सेंटिव मांगे हैं उन पर बैठकर चर्चा की जाएगी। यह हमारी साढ़े पांच करोड़ जनता के अधिकारों का प्रश्न है।

राजस्थान में रिफाइनरी लगेगी उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष और संपूर्ण राजस्थान की 5.5 करोड़ जनता इस मामले में साथ है और भारत सरकार से

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

पूरा आग्रह है कि जिस हिसाब से यहां पर पेट्रोलियम के डिपोजिट लगातार मिलते जा रहे हैं इसलिए इकोनोमिकल वायबिलिटी के हिसाब से परीक्षण के बाद में जो पत्र हमारे खान सचिव ने लिखा है उसके आधार पर इनका रिप्लाई आने के बाद में बैठक करने के बाद निश्चित रूप से आगे निर्णय किया जाएगा, मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** श्री कालीचरण सर्राफ।

## नसीराबाद में छात्र-छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विद्यालय, नसीराबाद की छात्राओं के साथ जो यौन उत्पीड़न की घटना हुई और उसको वहां की प्रिंसिपल ने उजागर किया उसका तबादला पंजाब कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उस प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन का जांच दल आया है वह पीडि़त छात्राओं के बयान बदलने की भी कोशिश कर रहा है। मेरा यह कहना है कि इससे राजस्थान में ही नहीं, नसीराबाद, अजमेर जिला और राजस्थान के लोगों में आक्रोश है और महिलाओं में विशेष रूप से इस बात को लेकर आक्रोश है कि इस प्रकार के यौन उत्पीड़न को उजागर करने वाली महिला को इस प्रकार से स्थानान्तरित कर दिया जाए, उसको दण्डित करने का प्रयास किया जाए और जो पीडि़त छात्राएं हैं उनके बयान बदलने की कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से इसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और दोषी लोग इसमें बचे नहीं इस बात के लिए राज्य सरकार को सदन को आश्वस्त करना चाहिए यह मेरा कहना है।

**श्री अध्यक्ष:** गृह मंत्री तो हैं नहीं। शिक्षा मंत्रीजी, आप हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे। (व्यवधान) अब आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर): पाइंट ऑफ इंफार्मेशन।

**श्री अध्यक्ष:** नो पाइंट ऑफ इंफार्मेशन। पाइंट आफ आर्डर की व्यवस्था है, जवाब दे रहे हैं, मैं कह रही हूं, प्लीज सिट डाउन।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया, वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक तो मैं बता दूं केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्थानांतरण का काम भारत सरकार का नहीं है, उनके कमिश्नर का है, वे उनके स्थानांतरण का काम करते हैं। दूसरी बात, पुलिस में जो मामला दर्ज है उसमें मुस्तैदी से कार्यवाही हो रही है और मैं गृह मंत्रीजी को कहूंगा उसमें किसी भी प्रकार से हम बयान नहीं बदलने देंगे और जो भी संरक्षण दे सकते हैं सबको देंगे। साथ ही, आज सुबह जो न्यूज आई थी, मैंने हमारे प्रमुख शासन सचिव श्री सुधीर भार्गव को कहा है कि वे केन्द्रीय विद्यालय संगठन के जो कमिश्नर हैं उनसे इस संबंध में बातचीत करें और आवश्यकता हुई तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मुझे बात करना आवश्यक हुआ और पत्र लिखना हुआ तो मैं आपकी भावनाओं को भी और सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहूंगा कि निश्चित्त रूप से एक महिला प्रधानाचार्य ने हिम्मत जुटाकर यह काम किया और इसको उजागर किया है उसको वास्तव में पुरस्कृत किया जाना चाहिए था उसकी बजाय उनको तिरस्कृत किया जा रहा है, इन भावनाओं से मैं निश्चित रूप से उनको अवगत कराऊंगा।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): जान से मारने की धमकी दी जा रही है उनको।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): जहां तक जान से मारने की धमकी की बात है मैं गृह मंत्रीजी से कहूंगा कि जिस प्रकार की सुरक्षा की बात है उनसे पूछ लेंगे, बातचीत कर लेंगे, जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, राज्य सरकार निश्चित रूप से उठाएगी और इस काण्ड को किसी भी प्रकार से कोई दबाया नहीं जाएगा, कानूनी कार्यवाही उसमें की जाएगी और विद्यालयों में इस प्रकार का वातावरण नहीं बने चाहे वो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के हों, चाहे प्राइवेट विद्यालय हों, चाहे सरकारी या अनुदानित हों, इसमें इस प्रकार का वातावरण नहीं बने, इसके लिए हमने पहले कई कदम उठाये थे, मोबाइल पर प्रतिबंध लगाना, अश्लील एसएमएस आते थे उसके कारण से बारहवीं तक की सभी कक्षाओं में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन हमारे प्रतिबंध केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने नहीं माने और मोबाइल के माध्यम से यह सारी कार्यवाही प्रारंभ हुई है। अब हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में जितने भी विद्यालय कार्यरत हैं चाहे वे केन्द्रीय विद्यालय हैं, चाहे प्राइवेट विद्यालय हैं, चाहे अनुदानित हैं, सरकारी हैं, बारहवीं तक की सभी कक्षाओं में मोबाइल छात्र-छात्राओं को लेकर आने का प्रतिबंध हम कठोरता से लागू करेंगे ताकि इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रकार के कदम आइंदा कम होने की स्थिति में आयें, यह मैं आश्वस्त कर सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्रीजी ..(व्यवधान)

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** स्थान ग्रहण करें। आसन पांवों पर। माननीय मंत्रीजी, मैं चाहूंगी कि यदि आवश्यकता हो तो इस बारे में आप मानव संसाधन मंत्रीजी को भी पत्र लिखें और इस प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण इन परिस्थितियों में यहां से नहीं होना चाहिए और इसके अलावा, इस बात की व्यवस्था की जाए उनके जान-माल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इस बात की पूरी व्यवस्था की जाए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन मंत्रीजी से व्यक्तिगत बात कर लूंगा और आपकी भावना के आधार पर उनको पत्र भी लिख दूंगा और कमिश्नर से भी बात करेंगे और गृह मंत्रीजी से कहूंगा उनकी सुरक्षा के बारे में चिन्ता करें।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इंफार्मेशन। हम विधायकों को आपके सचिवालय द्वारा इस सदन का सदस्य नहीं माना गया है। एक परिपत्र इस विषय में आपके सचिव महोदय ने निकाला है इसमें यह लिखा है आप अपनी नेमप्लेट के आगे ..(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सचिवालय के बारे में यहां चर्चा नहीं होती है।

**श्री अध्यक्ष:** मेरी बात सुनिए। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। मेरी बात सुनिए आप।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर): इसमें यह लिखा हुआ है हम सदन के सदस्य नहीं होते ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** मैं कहती हूं स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर): मैं तो बैठ जाऊंगा मैडम, आपका आदर करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें, मुझे सुनें, उसके बाद आप बैठें प्लीज। ऐसा है कि हमारे नियम

(श्री अध्यक्ष)

और परम्परा व प्रक्रिया है कि विधान सभा अध्यक्ष और विधान सभा सचिवालय के बारे में किसी को भी कोई शिकायत हो तो मेरे चैंम्बर में आकर मुझसे मिलें, मुझे बताएं क्या है, क्या नहीं है। सदन में चर्चा नहीं की जा सकती, यह नियम है। इसलिए स्थान ग्रहण करें। बैठे रहें और आकर मेरे चेम्बर में मुझसे मिल लीजिएगा।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर): मेरा मामला नहीं है, पक्ष, विपक्ष के सभी सदस्यों का मामला है किस तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं आपके यहां से। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है।

**श्री अध्यक्ष:** बता दिया। (व्यवधान) नो, नो, अंकित नहीं हो। अंकित नहीं होगा।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर): xxx

**श्री अध्यक्ष:** आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं, आप आसन की अवमानना कर रहे हैं। स्थान ग्रहण कर लें। नेता प्रतिपक्ष, इन्हें स्थान ग्रहण करवाएं।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** अब आपकी क्या सूचना हो गई?

## सूचना

### पीलीबंगा नगरपालिका क्षेत्र में तोड़फोड़ होने की सम्भावना

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका, पीलीबंगा के अंदर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से बहुत ही गंभीर तोड़फोड़ होने वाली है।

**श्री अध्यक्ष:** कल उठा देना यह प्रश्न।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): लोगों में हाकाकार मचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के पास न तो कोई साधन है और जो तोड़फोड़ होगी, रोड नई बनानी पड़ेगी, नालियां बनानी पड़ेंगी और जो लोग इससे प्रभावित होंगे, गरीब लोग हैं उनको दूसरे स्थान पर बसाने के लिए सरकार कोई प्रयास करे। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, लोगों में बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है।

**श्री अध्यक्ष:** संपूर्ण राजस्थान में अतिक्रमण हटाये जा रहे हैं।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): मैं यह नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय के आदेश की पालना होनी चाहिए मैं इस बात को जानता हूं और पालना करनी पड़ेगी।

**श्री अध्यक्ष:** आप क्या चाह्ते हो कि अतिक्रमियों को प्रोत्साह्न दिया जाए।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कह रहा हूं उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करने के लिए नगरपालिका के पास संसाधन उपलब्ध नहीं हैं और नालियां टूट जाएंगी, सड़कें टूट जाएंगी, लोगों का आना-जाना रुक जाएगा और जो लोग प्रभावित होते हैं उनको मैं प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग वाकई में गरीब हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, अगर नगरपालिका के पास जगह उपलब्ध है तो उनको दूसरे स्थान पर रियायती दर पर जगह उपलब्ध करा दे, मैं कोई मुफ्त में नहीं दिलवा रहा हूं। यह मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बहुत ही गंभीर विषय है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है।

**श्री अध्यक्ष:** आप वहां करें, आप सवयं भी तो नगरपालिका के सदस्य हो, वहां फैसला करो।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार से पैसे की मांग कर रहे हैं, लोगों को व्यवस्थित रूप से बसाने के लिए निवेदन कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** याचिका का उपस्थापन। श्री जोगाराम पटेल।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप तो कहते रहते हैं पैसे की कमी नहीं है, खजाना भरा पडा है, अब क्या जरूरत पड़ गई मांगने की। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): मैं न तो खजाने का मालिक हूं और न मैंने कभी ऐसा कहा।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी, अब श्री जोगाराम पटेल याचिका का उपस्थापन कर रहे हैं।

## याचिकाओं का उपस्थापन

### जोधपुर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय खोलने बाबत

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा

(श्री जोगाराम पटेल)

क्षेत्र लूणी (जोधपुर) के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय खुलवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

## लूणी में सड़कों का रिनेवल और नयी सड़कों के निर्माण बाबत

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी (जोधपुर) में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों का रिनेवल कराने व मण्डी समिति द्वारा नई डामर सड़कों के निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

## लूणी एवं झंवर में (जोधपुर) तहसील भवनों के निर्माण बाबत

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणी (जोधपुर) की तहसील लूणी व उप तहसील झंवर के भवनों का निर्माण करवाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

## लूणी (जोधपुर) के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान आदि संकाय खुलवाने एवं भवन निर्माण विषयक

(4) विधान सभा क्षेत्र लूणी (जोधपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग खुलवाने तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी के जर्जर भवन की मरम्मत करवाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** श्री हीरालाल।

## मूंडिया से भगतरापुरा तक मिसिंक लिंक सड़क का निर्माण विषयक

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवाई उपखण्ड के मूंडिया से भगतरामपुरा पंचायत सेदरिया तक मिसिंग लिंक रोड द्वारा ग्राम भगतरामपुरा को जोड़ने बाबत, एवं

## अरनिया चुराड़ा निवाई से बड़ा गांव देवडूंगरी तक सड़क निर्माण विषयक

निवाई उपखण्ड के ग्राम पंचायत मुख्यालय अरनिया चुराड़ा निवाई से रामचन्द्रपुरा की ढाणी गुजरान को बड़ागांव देवडूंगरी तक सड़क निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

## ढाणी जाटावाला रड़ा से ढाणी डाब्डाला तक सड़क निर्माण विषयक

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम राजनौता

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

(कोटपूतली) में ढाणी जाटावाला रड़ा से ढाणी डाब्डाला तक ग्रेवल सड़क का निर्माण कराने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** श्री दाताराम गुर्जर।

## खेतड़ी राजकीय महाविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानन्द के नाम पर करने बाबत

**श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी का नाम स्वामी विवेकानन्द के नाम पर करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** श्री वीरेन्द्र मीणा। अनुपूरक अनुदान की मांग।

# अनुपूरक अनुदान वर्ष 2006-07 की मांगों का उपस्थापन

**श्री वीरेन्द्र मीणा** (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष, 2006-07 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि अनुदान की मांगों पर विचार जब किया जाता है तो जिन माननीय सदस्यों के कटौती के प्रस्ताव यहां दिये जाने पर सदन में मान लिये जाते हैं और जिन माननीय सदस्यों के विभिन्न दलों के सचेतक महोदय नाम लिख कर भेजते हैं उनको बोलने में प्राथमिकता दी जाती है और उसके बाद में जब समय रहता है तो बाकी माननीय सदस्यों को भी दिया जाता है समय इसलिए और जिन माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं वह एक साथ उन्हें सदन के अन्दर पेश कर दें ताकि बहस के दौरान माननीय मंत्री उनका जवाब दे सकें। समय का अभाव है। इसलिए मैं उसी हिसाब से जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण यहां पर उत्तर नहीं मिल सकेगा उनको लिखित उत्तर भेज दिया जाएगा। यह इस सदन की परम्परा रही है।

श्री दिगम्बर सिंहजी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अनुदान की मांग रखें।

# अनुदान की मांग

## मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14 अरब, 54 करोड़ 61 लाख 55 हजार तक की राशि प्रदान की जाए।

**श्री अध्यक्ष:** श्री मदन दिलावर।

## मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना की प्रस्तुति

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3 अरब 4 करोड़, 83 लाख, 43 हजार तक की राशि प्रदान की जाए।

**(मांग संख्या 26 एवं 51 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)**

# मांग संख्या 26 व 51 पर विचार

**श्री अध्यक्ष:** श्री कालीचरण सर्राफ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई और मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विभिन्न संगठक योजनाओं पर चर्चा हो रही है।

मैं मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी उपलब्धियां इस सरकार ने पिछले 3 साल में हासिल की हैं उतनी उपलब्धियां पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में हासिल नहीं की, यदि मैं यह कहूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च की गई राशि का सवाल हो, चाहे नये

(श्री कालीचरण सर्राफ)

चिकित्सालय खोले जाने की बात हो, चाहे हास्पिटल के भवन निर्माण कराये जाने की बात हो, चाहे पदों को सृजित कर नियुक्तियां दिये जाने का सवाल हो, चाहे चिकित्सा सुविधा सहायता दिये जाने की बात हो, चाहे चिकित्साकर्मियों के आवास बनाये जाने के लिए राशि की स्वीकृति का सवाल हो, स्वास्थ्य सूचकांक में वृद्धि की बात हो, चाहे तकनीकी सुविधाओं के विस्तार की बात हो, चाहे औषधियों की उपलब्धता का सवाल हो, औषधि निर्यात में वृद्धि की बात हो और चाहे परिवार नियोजन का सवाल हो, हर बात में हमारी सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, पिछले तीन सालों में व पिछली सरकार की तुलना में कहीं ज्यादा हैं।

**(समय : 13.46 बजे)**

**(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)**

माननीय सभापति महोदय, मैं तुलनात्मक आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूंगा। चिकित्सा सुविधाओं पर समग्र व्यय, पिछली सरकार ने दो हजार 52 करोड़ रुपये पांच साल में खर्च किये और हमने 2424 करोड़ रुपये तीन साल में खर्च किये। राजस्थान हैल्थ सिस्टम योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य और दवाइयों हेतु हमने 285 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जब कि पिछली सरकार ने एक नये पैसे का भी प्रावधान नहीं हुआ। चिकित्सालयों की संख्या, हमने 138 चिकित्सालय नये खोले।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय सदस्य, इतनी असत्य बात तो नहीं कहें कि एक पैसे का भी काम नहीं हुआ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): बैठिए, बैठिए, बिराजिए आप, अपना नम्बर आए जब बोलना।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): कि एक पैसा ही खर्च नहीं हुआ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): मैं बता रहा हूं, आंकड़े दे रहा हूं, बैठिए प्लीज।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): क्या यह हो सकता है कि किसी मांग पर एक वित्तीय वर्ष में एक पैसा खर्च नहीं हुआ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): नहीं हुआ, बैठिए।

अस्पताल में शैय्याओं के लिए आपके राज में 283 शैय्याओं की वृद्धि की पांच साल में और हमने 2349 शैय्याओं की तीन साल में । इसी प्रकार से

(श्री कालीचरण सर्राफ)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का सवाल है, आपने अपने पांच साल के कार्यकाल में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना नहीं की। हमने 51 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की। इसी प्रकार से ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आपने केवल 13 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की और हमने तीन साल में 62 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की। इसी प्रकार से, उप स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण, आपके समय में एक का भी नहीं हुआ, हमने 8 का किया, उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, आपके राज में 75 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई पांच साल में और हमने 686 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की तीन साल में। आपने अपने राज में एक भी ब्लड बैंक की स्थापना नहीं की। हमने 3 ब्लड बैंकों की स्थापना की। आपने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित जिला चिकित्सालय पर इमरजेंसी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एक में भी नहीं किया, हमने भरतपुर और सीकर दो जगह किया। इसी प्रकार से, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, आपने एक भी नहीं किया, हमने 6 का किया। जुबेर खानजी, सुनिए। इसी प्रकार से, आपने पांच साल में एक भी एम्बूलेंस उपलब्ध नहीं कराई, हमने 25 हास्पिटल्स में एम्बूलेंस उपलब्ध करवाई। सिटी-स्केन मशीन आपने पांच साल में एक भी उपलब्ध नहीं कराई, हमने 10 जगह उपलब्ध कराई। इसी प्रकार से, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का निर्माण, आपके समय में 16 भवनों का निर्माण हुआ, हमने 44 में किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का निर्माण आपके समय में एक भी नहीं हुआ, हमने 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का निर्माण किया। इसी प्रकार से उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण, आपके समय में 75 और हमारे समय में 454, चिकित्सकों के लिए आवास गृहों के भवनों का निर्माण, आपने एक का नहीं किया, हमने 40 का किया और नर्सिंग आवास गृहों के भवन का निर्माण, आपके समय में एक नहीं, हमारे समय में 42, ब्लड बैंक के भवन का निर्माण, आपके समय में जीरो और हमारे समय में दो और पदों के सृजन का जहां तक सवाल है, वरिष्ठ विशेषज्ञ, आपके समय में एक पद का सृजन किया गया और हमने 26 का किया। कनिष्ठ विशेषज्ञों के आपके समय में केवल चार पद सृजित हुए और हमने 162 किये। चिकित्सा अधिकारी स्नातकोत्तर निश्चेतन, नेत्र चिकित्सा, हड्डी रोग विशेषज्ञ आपके समय में एक भी पद का सृजन नहीं

हुआ और हमने 94 किये। चिकित्सा अधिकारी का आपके समय में एक भी पद का सृजन नहीं हुआ, हमने 2457 पदों का सृजन किया। नेत्र सहायकों के पद आपके समय में जीरो, हमारे समय में 47, लेब टेक्नीशियन के आपके समय में जीरो, हमारे समय में 96, मेडिकल रिलीफ सोसायटियों का गठन आपके समय में केवल 328 और हमारे समय में 1825, नोट कर लीजिये।

इसी प्रकार से, चिकित्सा सुविधा सहायता की बात सुन लीजिये। मुख्य मंत्री रक्षा सहायता कोष से व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा आपके समय में पांच साल में 3090 और हमारे समय में 3594, मुख्य मंत्री सहायता कोष से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या आपके समय में पांच साल में 5970 और हमारे तीन साल में 7041 की संख्या रही। हर चीज में हम आपसे अव्वल हैं।

इसी प्रकार से, बी. पी. एल. परिवारों को नि:शुल्क सहायता आपके समय में 28 लाख 67 हजार को दी और हमारे समय में 38 लाख को दी। राज्य में ग्रामीण एवं गरीब तबके के रोगियों तथा आपातकालीन मरीजों के लिए दवाइयां आपके समय में 78 करोड़ पांच साल में और हमारे तीन साल में 71 करोड़। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेलिफोनिक सुविधा आपके समय में जीरो और हमने 1488 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दूरभाष की सुविधा से जोड़ा।

इसी प्रकार से, आयुर्वेद का मामला ले लीजिये। नये औषधालय आपके समय में जीरो खोले गये और हमारे समय में 114 खोले गये। होम्योपैथिक औषधालय आपके समय में जीरो, हमारे समय में 14, स्पेशियलिटी क्लिनिक की स्थापना आपके समय में जीरो, हमारे समय में दो। एक छत के नीचे सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं आपके समय में जीरो और हमारे समय में 255 की गईं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के औषधालयों में औषधियों की आपूर्ति के लिए आपने एक करोड़ रुपया खर्च किया और हमारे समय में 13.03 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): आपके समय में रुपया जाता कहां था? यह तो बता दो।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): क्या पता कहां जाता था। इसी प्रकार से, आपके समय में 'ब' श्रेणी से 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत हास्पिटल की संख्या जीरो और हमारे समय में 22 रही।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): तिवाड़ीजी, वो ही बता सकते हैं जो थे। (व्यवधान)

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): सुनो। इसी प्रकार से, आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्तियों का सवाल है, आपके समय में पांच साल में 142 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति की गई और हमारे तीन साल में, नेता प्रतिपक्ष, 357 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। इसी प्रकार से नये प्रशिक्षण केन्द्र आपके समय में जीरो प्रारम्भ किये और हमारे समय में 23 प्रारम्भ किये। आयुर्वेदिक कालेज आपके समय में एक भी नहीं खोला गया और हमारे समय में दो खोले गये। होम्योपैथिक कालेज आपके समय में जीरो, हमारे समय में पांच खोले गये। यूनानी कालेज आपके समय में जीरो, हमारे समय में दो और नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र आपके समय में जीरो और हमारे समय में 14 खोले गये।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, चिकित्साकर्मियों के लिए आवास का जहां तक सवाल है, हमने चिकित्सा अधिकारियों के 818 आवासों का निर्माण किया, नर्सिंगकर्मियों के लिए 840 आवासों का निर्माण किया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 82 आवासों का निर्माण किया, यानि हमने कुल 1840 आवासों का निर्माण किया और आपके समय में बिल्कुल जीरो, एक भी आवास का निर्माण नहीं हुआ।

इसी प्रकार से, स्वास्थ्य सूचकांकों का सवाल है, शिशु मृत्यु दर 75 प्रति हजार से घटाकर हमारे समय में 67 प्रति हजार हुई यानि 10.67 की कमी की गई। मातृ मृत्यु दर 677 प्रति लाख थी आपके समय में और हमने उसको घटकर के 445 प्रति लाख हमारे राज में की यानि 34 प्रतिशत की कमी की। जन्म दर आपके समय में 30.4 थी और हमारे समय में केवल 29 प्रति हजार यानि 4.29 की हमने इसमें कमी की। मृत्यु दर आपके समय में 7.6 थी और वह आज 7 हो गई यानि राष्ट्रीय औसत से भी कम है, इसमें 7.89 प्रतिशत की कमी की है।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): ये पेपर टेबल पर रख दो, बताने की जरूरत नहीं है।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): मैं बता रहा हूं, आप सुनिये। बताने की कैसे जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, राजस्थान के इतिहास में पहली बार कई सालों से मांग की जा रही थी कि राजस्थान में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। इनके राज में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई और हमारा राज आने के बाद हमारे राज में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): ये किनको कह रहे हो?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): अब आप तो सुनो साहब। आप बुजुर्ग आदमी हो, आपको क्या कहूं, आपका मैं आदर करता हूं। कृपया टोका-टाकी न करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): कालीचरणजी, टोका-टाकी होती है वह वृद्धावस्था में ज्यादा होती है इस बात का ध्यान कर लेना आप।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): इतना ही नहीं, इस बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सामान्य जनता तक ले जाने के लिए 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक हमने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य चेतना अभियान चलाया और इस स्वास्थ्य चेतना अभियान में 9205 कैम्पों का आयोजन किया, 53 लाख 21 हजार लोगों ने इस अभियान में भाग लिया और 31 लाख 5 हजार लोग इससे लाभान्वित हुए और 2 लाख 85 हजार लोगों की इस अभियान के दौरान नि:शुल्क जांच की गई।

इसी प्रकार मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह जो 2007-08 का बजट पेश किया उसमें भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वास्थ्य और चिकित्सा से सम्बन्धित की गईं। इस वर्ष 365 संस्थाओं में डाक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, उपकरण और आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था की है और 24 घंटे खोले जाने की व्यवस्था की जाएगी। बड़े शहरों में ओल्ड-एज होम की स्थापना की जाएगी। 7502 ए एन एम, जी एन एम की नियुक्तियों की घोषणा की गई है। प्रदेश में हास्पिटल्स में मरीजों को लाने-ले जाने के लिए 100 एम्बुलेंसेज की व्यवस्था इस साल में की जाएगी। प्रदेश में ऐसे गांव जहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी संभागीय केन्द्रों पर मोबाइल सर्जिकल यूनिट की घोषणा की गई है। 130 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले

(श्री कालीचरण सर्राफ)

जाएंगे, 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा, 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की है। पांच जिला स्तरीय चिकित्सालयों और 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निजी दानदाताओं के सहयोग से खोलकर शैय्याओं में बढ़ोतरी किये जाने की बात की गई है। पांच जिलों हनुमानगढ़, राजसमंद, दौसा, बारां, धौलपुर में ए एन एम प्रशिक्षण कॉलेज खोलने की घोषणा, पैरा मेडिकल काउन्सिल के गठन की घोषणा, हास्पिटल के पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो ट्रोमा हास्पिटल की स्थापना की घोषणा की गई है। सभापित महोदय, मैं यह कहूं, इतना काम, इतनी घोषणाएं की गई हैं कि यदि मैं पूरी का वर्णन करूं तो पूरी रात हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार जयपुर में स्थित चारों सैटेलाइट हास्पिटल को सुदृढ़ किये जाने का काम भी राज्य सरकार इस साल हाथ में लेगी। मानसरोवर में एक नये हास्पिटल का निर्माण किया जाएगा और बॉम्बे हास्पिटल के सहयोग से उसका संचालन किया जाएगा। इस बजट में 30 आयुर्वेदिक, 30 होम्योपैथिक और 10 यूनानी हास्पिटल खोले जाने की भी बात की गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं की हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, वह नये आयाम स्थापित करेंगे और प्रदेश के नागरिकों को सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध होगा, निश्चित रूप से इसमें ये बजट के प्रावधान सहायता प्रदान करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कुछ जो व्यावहारिक कठिनाइयां चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आती हैं उनके बारे में भी कुछ जिक्र करना चाहूंगा।

चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो और चाहे अन्य किसी पार्टी की हो, हर सरकार की यह मंशा रहती है कि राजस्थान का 80 प्रतिशत व्यक्ति गांवों में निवास करता है इसलिए गांवों में अधिक से अधिक अस्पताल खोले जायें, अधिक से अधिक डाक्टर्स वहां भेजे जायें और अधिक से अधिक ग्रामीण जनता को चिकित्सा की सुविधा मुहैया हो और इसी बात को ध्यान में रखकर इस बार भी राज्य सरकार ने कई अस्पताल गांवों में खोले जाने की घोषणा की है परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि हर सरकार सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में

(श्री कालीचरण सर्राफ)

अस्पताल खोलती है, डाक्टर्स की वहां नियुक्ति करती है पर डाक्टर्स जिस दिन उसकी ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति होती है, उसी दिन से वह शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से वह अपना ट्रांसफर करवाये, इस जुगाड़ में लग जाता है। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, यह भी देखने में आया है कि वह केवल महीने में एक दिन गांव के अन्दर जाता है और अपने अधीनस्थ कर्मचारी को हर तारीख की अलग-अलग सी.एल. दे देता है और जब कोई यहां से इंसपैक्टर जाता है या कोई बड़ा अधिकारी जाता है तो उस दिन की सी.एल. वह अधीनस्थ कर्मचारी उनके सामने रख देता है और कह देता है कि डाक्टर साहब छुट्टी पर हैं। इस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर्स अधिक से अधिक संख्या में जायें, इसके लिए मैं कुछ सुझाव माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को देना चाहूंगा। मेरे दो-तीन सुझाव हैं। पहला सुझाव है, हर अस्पताल में एक रजिस्टर मेन्टेन किया जाये और उसमें डाक्टर रोज अटेंडेंस करे और जिस दिन वह छुट्टी पर जाता है, उसके पहले दिन वह सी.एल. के लिए उसमें नोट लगा दे कि कल मैं छुट्टी पर रहूंगा। यदि यह हमने किया तो वह एप्लीकेशन पेश कर देता है, वह नहीं हो पायेगा।

इसी प्रकार से, जब डाक्टर्स से बात होती है तो वह यह कह देता है कि हमें गांवों में जाने में कोई तकलीफ नहीं है परन्तु गांवों में कोई रेजिडेंशियल फेसेलिटी नहीं है इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी गांव में अस्पताल खोले जाने की घोषणा करें, उसके साथ ही साथ यह भी प्रबन्ध करें कि वहां अस्पताल के साथ-साथ उस डाक्टर्स के रहने के लिए रेजिडेंशियल फेसेलिटी भी हो। यदि हम रेजिडेंशियल फेसेलिटी औषधालय में मुहैया करायेंगे तो मुझे लगता है कि डाक्टर वहां जाकर रहने की कोशिश करेगा।

इसी प्रकार से, आज यह व्यवस्था है कि शहरों में डाक्टर्स लगते हैं उनको भत्ता मिलता है। मैं कहना चाहूंगा कि डाक्टर गांवों की ओर आकर्षित हो, इसके लिए आप इस प्रकार से व्यवस्था करें कि जो शहर में डाक्टर अपोइंट होगा, उसको कोई भत्ता नहीं और जो गांवों में जायेगा, उसको ग्रामीण भत्ता देने की यदि हम घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से डाक्टर गांवों में जाने के लिए आकर्षित होगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि डाक्टर जो गांवों में जाते हैं, उनको यह चिंता रहती है कि उनके बच्चे, अच्छी स्कूल क्योंकि गांवों में नहीं होती है, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे तो इसके लिए मैं यह भी

(श्री कालीचरण सर्राफ)

कहना चाहूंगा, हर संभागीय केन्द्र पर कम से कम डाक्टर्स और जो मेडिकल डिपार्टमेंट का स्टाफ है, उनके लिए यदि हम होस्टल्स की व्यवस्था करें, जिन डाक्टर्स की नियुक्ति गांवों में हुई हैं उनके लिए, उनके बच्चे होस्टल्स में रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें तो निश्चित रूप से इसमें इजाफा होगा और गांवों की ओर डाक्टर्स आकर्षित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक दूसरी समस्या जो बड़ा गम्भीर रूप प्रदेश में धारण किये हुए है, अल्ट्रासाउण्ड के माध्यम से जो लिंग परीक्षण किया जा रहा है, आज पूरे प्रदेश में लगभग 1000 मशीनें इस प्रकार से लगी हुई हैं और जिस तरीके से लड़के और लड़कियों का अनुपात निरन्तर कम होता जा रहा है, 1991 में जहां 1000 लड़कों पर 909 लड़कियां थीं राजस्थान में, आज उनकी संख्या घटकर 1000 पर 886 हो गई। सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के माध्यम से यदि पता लग जाता है कि लड़की है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को गम्भीरता से इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि कड़ा कानून इसके लिए बनाया जाना चाहिए और जो दोषी डाक्टर्स इसमें मिले हुए हैं, उनके साथ कोई रियायत नहीं हो। अभी पिछले दिनों सरकार ने कार्यवाही की थी और 63 डाक्टर्स इसमें दोषी पाये गये थे। यदि मैं गलत होऊं तो मुझे करेक्ट करेंगे, परन्तु अभी तक उन 63 डाक्टर्स के खिलाफ कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई कि जिससे कि और डाक्टर्स में इसका मैसेज जाये। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ...

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

अभी तो मैंने शुरू किया है, शुरू-शुरू के वक्ता को तो कम से कम आधा घंटा देओ साहब। तो सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि कड़े से कड़ा दण्ड इस प्रकार के भ्रूण हत्यारों को दिया जाना चाहिए चाहे वह कितना ही एप्रोच वाला व्यक्ति हो, यदि हम कड़े कानून के द्वारा इसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तो यह नहीं रूकेगा।

एक बात और कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जब सड़क दुर्घटनाओं में कोई व्यक्ति की मौत होती है तो उसके लिए पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है। अब एक तो किसी व्यक्ति की मौत हुई और उस पर उसका पोस्टमार्टम अनिवार्य हो। सड़क दुर्घटना में जिसकी मौत हो गई, उसके

(श्री कालीचरण सर्राफ)

पोस्टमार्टम की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार से कानून में संशोधन किया जाना चाहिए कि सीआर.पी.सी. की धारा 174 के अन्तर्गत, जो पोस्टमार्टम की अनिवार्यता की धारा है, उसको हटाया जाना चाहिए और सड़क दुर्घटना में जो लोग मरते हैं, उनके पोस्टमार्टम की अनिवार्यता यदि समाप्त होगी तो इससे कई लोगों को राहत मिलेगी।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, इसमें एक निवेदन है, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह सही कह रहे हैं लेकिन आलरेडी यह प्रावधान है और लॉ सेक्रेटरी के यहां से चिट्ठी भी चली गई है कि दुर्घटना में जो मृत्यु होती है और अगर वह नहीं चाहते हैं तो पोस्टमार्टम नहीं कराया जाये लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानती है इसलिए इसको कड़ाई से लागू कराने की बात है। आज ही एस.एम.एस. में यह बात आई कि पुलिस नहीं मानती है जबकि डाक्टर्स सहमत हैं, परिवार सहमत है और नियम यह कहता है लेकिन यहां की जो पुलिस है, वह अपने चक्कर में कि वह चक्कर में नहीं पड़ती, जांच कैसे करेंगे कि यह कैसे दुर्घटना हुई, किसकी गलती रही इसलिए पोस्टमार्टम कराती है, इसलिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय सदस्य आम आदमी की पीड़ा कह रहे हैं।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, यदि वह एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ...

**श्री सभापति:** बिराजिये। आपका नम्बर आयेगा, तब आप बोल लेना। अब आप बिराजिये।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): ...उसकी जांच करना आवश्यक होगा कि किसी के द्वारा या किसी ने कोई कुछ खिलाकर मारकर, डाल तो नहीं गया, कोई जान-बूझकर एक्सीडेंट तो नहीं किया गया। इसमें यह पोस्टमार्टम तो आवश्यक रहना चाहिए। उसको कोई कष्ट नहीं हो, परिवार को कोई कष्ट नहीं हो। यह जब तक पूरी जांच नहीं हो जाये, तब तक यह पोस्टमार्टम तो होना आवश्यक है।

**श्री सभापति:** ठीक है, आप बिराजिये।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): पोस्टमार्टम की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए क्योंकि इसमें किस कारण से मौत हुई, इसको बताये जाने

की जरूरत नहीं पड़ती। उसका कोई कारण नहीं है इसलिए पोस्टमार्टम, जिसकी एक्सीडेंट से मौत हो, उनके लिए पोस्टमार्टम की अनिवार्यता बिलकुल समाप्त कर दी जानी चाहिए।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): नहीं, यह एक्सीडेंटल क्लेम में एक मेजर एविडेंस है, इसलिए कोई वैसे ही नहीं होगी, जब तक कानून के प्रावधानों में दुर्घटनाओं के मामले में परिवर्तन नहीं करोगे, वैसे ही नहीं होगी यह।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): इसलिए मैं कह रहा हूं कि कानून में संशोधन किया जाये, यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में और विशेषकर बड़े शहरों में निजी अस्पताल चलते हैं, प्राइवेट अस्पताल हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश में मिल जायेंगे और इसी प्रकार से प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेन्टर्स भी आज जगह-जगह खुल रहे हैं परन्तु इनकी फीस कि ये कितनी फीस गरीब जनता से वसूल कर रहे हैं, इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार के प्राइवेट अस्पताल हैं, जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेन्टर्स हैं, उनके बारे में एक अलग से कानून बनाया जाये कि उनकी फीस कितनी हो, कितनी फीस वह मरीजों से लें, इस प्रकार का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए जिससे कि खुली लूट इन लोगों ने मचा रखी है, उससे गरीब जनता को निजात मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूगा, जयपुर शहर में एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, कांवटिया अस्पताल है और वह जयपुर के उत्तर में शास्त्री नगर में स्थित है। आज जिस तरीके से जयपुर शहर की पापुलेशन बढ रही है, यहां इस बात की आवश्यकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र में और हो। मेरे इलाके में जयपुर अस्पताल बना हुआ है। अभी वह सेटेलाइट अस्पताल है। वहां अभी जो वर्तमान स्थिति है। 7.5 एकड़ जमीन पर यह अस्पताल बना हुआ है और इसमें 10594.47 वर्गमीटर कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसमें दो डाक्टर्स के क्वार्टर्स और दो स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए हैं, 27 डाक्टर्स इस समय वहां पोस्टेड हैं और 59 नर्सिंग और अदर पैरा मेडिकल वर्कर्स वहां पर पोस्टेड हैं और वहां इस समय जनरल सर्जरी, मेडिसिन, गायनोकॉलॉजी, आप्थामोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, पीडिएट्रिक्स,

एनेस्थेसेसिया, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और ई.एन.टी. का काम हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, वहां के यदि पेशेंट्स की स्थिति देखी जाय, रोगियों की, तो 2004 में जहां टोटल 1 लाख 47 हजार 792 रोगी वहां पर आये उसकी संख्या बढ़कर 2005 में 1 लाख 52 हजार 562 हो गई और 2006 में यह बढ़ कर 1 लाख 71 हजार 497 हो गई। इसी प्रकार से वहां यदि इनडोर पेशेंट्स की स्थिति देखें तो 2004 में जहां 3521 थे, 2005 में 3584 हुए और 2006 में वह 5638 हुए। माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां हर चीज में वृद्धि हुई है। आपरेशंस का जहां तक सवाल है, 2004 में जहां 2847 आपरेशन हुए, 2005 में 3733 और 2006 में 9918 आपरेशन वहां पर किये गये। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, यदि इसे डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल बनाया जाय तो दक्षिण क्षेत्र की जनता को इससे सुविधा मिलेगी और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जयपुरियाजी ने, जिन्होंने इस हास्पीटल का निर्माण कराया था उनसे भी मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि यदि सरकार इसको डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल बनाती है तो जितनी उसके लिए आवश्यकता होगी भवन बनाने की, वह भवन अपने पैसे से बनाकर सरकार को देने के लिए तैयार हैं, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आयेगी। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में यह मांग करना चाहता हूं कि जयपुर शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जिस प्रकार जयपुर के उत्तर में कांवटिया हास्पीटल है उसी प्रकार से जयपुर के दक्षिण में जयपुरिया हास्पीटल को डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल के रूप में क्रमोन्नत किया जाय। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं दो-तीन मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आप घंटी मत बजायें, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

**श्री सभापति:** अब आधा घंटे से ज्यादा हो गया है माननीय सदस्य। करीब पचास माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

**श्री कालीचरण सर्राफ:** एक-दो मिनट। मालवीय नगर सेक्टर 6 में हाउसिंग बोर्ड ने डिस्पेंसरी तो बनाकर दे दी है और उसमें अभी डाक्टर्स भी लगा रखे हैं परंतु अभी वह डेपुटेशन पर हैं, वह डिस्पेंसरी स्वीकृत नहीं है इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि इस साल के बजट में मालवीय नगर की डिस्पेंसरी 6 नम्बर की, उसको भी शामिल किया जाय। इसी प्रकार से, मेरे क्षेत्र में माडल टाउन और झालाना बाईजी की कोठी में लेडीज डाक्टर नहीं है, डिस्पेंसरी में, उसकी सुविधा, इस प्रकार की व्यवस्था भी

(श्री कालीचरण सर्राफ)

निश्चित रूप से करनी चाहिए। दो सुझाव मैं और देना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश में डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स, नर्सेज, रेडियोग्राफर, लेब असिस्टेंट, यह पिछली सरकार के समय से ही कांट्रेक्ट पर चल रहे हैं, वह अपना मन लगाकर काम नहीं कर सकते। मेरी मांग है कि इस प्रकार जो कांट्रेक्ट पर पूरे प्रदेश में डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स, नर्सेज, रेडियोग्राफर, लेब असिस्टेंट्स लगे हुए हैं उनको नियमित करने की कार्यवाही भी निश्चित रूप से प्रारम्भ की जानी चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि सरकारी हास्पीटल्स में कापरेटिव की दुकानें नहीं होने के कारण सरकारी कर्मचारियों को बहुत दिक्क्त होती है, उनको दवाइयां समय पर नहीं मिल पाती हैं, इसलिए मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि इस बात को देखे सरकार और इस प्रकार की व्यवस्था करे कि प्रदेश के हर हास्पीटल में कापरेटिव की दुकान निश्चित रूप से हो। इस प्रकार की यदि व्यवस्था की तो निश्चित रूप से उसका फायदा भी प्रदेश की जनता को मिलेगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

**श्री सभापति:** धन्यवाद।

**श्री संयम लोढ़ा:** ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर की कलेक्ट्री में जो शराब के दौर चले थे और जो नृत्यांगनाओं के नृत्य हुए थे और यह मामला विधान सभा में हमारी ओर से उठाया गया था, तब माननीय गृह मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि सात दिन के भीतर संभागीय आयुक्त से जांच करवाकर रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी। माननीय सभापति महोदय, दस दिन हो गये उस बात को और संभागीय आयुक्त ने जांच रिपोर्ट भी दे दी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश प्रदान करें कि वह रिपोर्ट को टेबल करे।

**श्री सभापति:** माननीय गृह मंत्रीजी आ जायेंगे अभी, बात करेंगे। माननीय श्री मोहनलाल गुप्ता (अनुपस्थित)। माननीय श्री नवरतन राजौरिया (अनुपस्थित) । माननीय श्री बीरू सिंह।

**डा. सी. पी. जोशी :** माननीय सभापतिजी, पहले कालीचरणजी को बुला दिया इसलिए मोहनलालजी एबसेंट रह गये।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 26 पर मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

यह बताना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क राजस्थान का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है जिसमें 5 लाख 8 हजार मतदाता, नगर निगम के 70 में से 20 वार्ड, लगभग 10 हजार कालोनियां, 40 कच्ची बस्तियां, 12 गांव और 40 ढाणियां हैं। इतने बड़े विधान सभा क्षेत्र में, इसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई थी तो आज इस सदन के माध्यम से अब तक यहां पर जितने भी विधायक रहे हैं और उन्होंने चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए जितने-जितने प्रयास किये हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अधिकांश विधायक यहां पर कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, बीजेपी से यहां पर अब तक केवल दो ही विधायक रहे हैं। सबसे पहले इस सदन के माध्यम से मेरे जो महाध्यक्ष हैं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, इनका मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जे.के. लॉन अस्पताल, एस.एम.एस. अस्पताल और जयपुरिया, यह जो चार....

**श्री सभापति :** एक मिनट माननीय सदस्य। गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कलेक्ट्री के परिसर की बात कही, वह रिपोर्ट प्राप्त हो गई, मैं लगातार तीन दिन से हाउस में इस तैयारी के साथ आ रहा हूं, जब भी आप समय तय करें, मैं उसके बारे में स्टेटमेंट सदन में देने को तैयार हूं।

**डा. सी. पी. जोशी :** रिपोर्ट ले कर दें, जो पढ़ लेंगे, फिर पूछ लेंगे। जब रिपोर्ट आपके पास आ ही गई है तो सदन में ले कर लें, उसको पढ़ लेंगे।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** सामान्यत: आपने भी, इतने साल देखा है हमने, रिपोर्ट का परपज यह है कि उसमें किस का दोष बनता है, किसका नहीं, उस पर सरकार का क्या वह है उसको रखने का, मैं सोचता हूं उसके एक-एक बिंदु को लेकर के यहां कोई उसका पोस्टमार्टम करने के लिए क्या किसी का दोष है कि नहीं, इस बात को निर्धारित करने के लिए संभागीय आयुक्त को तय किया और उसके आधार पर जो भी स्टेटमेंट है, मैं रख दूंगा, उसमें आप और कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं जरूर उसमें से बात बताऊंगा, बाकी यहां रिपोर्ट रख करके उसके एक-एक बिंदु को लेकर के उस पर चर्चा करना, मैं सोचता हूं कि जिस भावना से अपन ने काम किया, वह उचित नहीं होगा। आप चाहेंगे तो मैं रख दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन फिर उसमें बहुत डिटेल कई

चीजें हैं उनके बारे में कई प्रकार के सवालों पर घंटों अपन उसमें चलेंगे, जिस परपज से हमने जांच कराई उसमें दोषी के खिलाफ अगर कोई एक्शन हो जाता है और हम लोग संतुष्ट होते हैं तो ठीक है। उसमें कोई सवाल आपके खड़े होंगे तो मैं उसके अनुसार जवाब देने को तैयार हूं, आप जो भी समय तय करें, मैं उस समय दे दूंगा।

**श्री सभापति:** चार बजे दे दें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** चार बजे।

**श्री सभापति:** ठीक है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय सभापति महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय गृह मंत्रीजी से संबंधित है, मैं एक मिनट में निवेदन कर रहा हूं।

**श्री सभापति:** अब ऐसा है माननीय सदस्य....

## सूचना

### शास्त्री नगर कब्रिस्तान, जयपुर बचाओ कमेटी के सदस्यों का धरना

**मोहम्मद माहिर आजाद:** जयपुर के शास्त्री नगर कब्रिस्तान बचाओ कमेटी के लोग आठ दिन से धरने पर बैठे हैं, पहले भी वहां छह-सात लोगों की मृत्यु हो गई थी, वह खाली कराना चाहते हैं कब्रिस्तान अतिक्रमियों से, गृह मंत्रीजी से वह मिले थे, माननीय गृह मंत्रीजी ने जिला प्रशासन को निर्देश भी दे दिये थे लेकिन...

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, यह मामला दूसरा है।

**मोहम्मद माहिर आजाद:** मैं वही आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि वह यहां आये हुए हैं चाहे गृह मंत्रीजी अपने कक्ष में उनसे बात कर लें, इसका समाधान हो, पहले जैसी अनहोनी घटना नहीं हो जाय, पहले छह-सात लोगों की वहां पर पुलिस की गोली से मृत्यु हुई थी, जस्टिस राजेन्द्र सक्सेना आयोग बना, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है, आज मुर्दों के रहने की जगह जिंदा लोग रह रहे हैं, आपसे मिले भी हैं, आपने निर्देश भी दिये हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है आज आठ दिन होने के बावजूद भी, यह स्थिति बनी हुई है।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

**मोहम्मद माहिर आजाद :** दूसरा एक प्रतिनिधि मण्डल तोपखाना हजूरी में जो बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वह भी आये हैं, तो सरकार को चाहिए कि उसकी जांच करा कर मुआवजा जो आपको देना है, वह दें, आप खुद बड़े संवेदनशील हैं...

**श्री सभापति :** जानकारी में आ गया गृह मंत्रीजी के, अब आप विराजें।

**मोहम्मद माहिर आजाद :** मैं तो गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से यही निवेदन कर रहा हूं कि आपने खुद ने जो निर्देश दिये हैं, कम से कम वह तो एग्जीक्यूट हों। हमको कहने की जरूरत ही नहीं होती अगर यह स्थिति होती तो।

**श्री सभापति :** माननीय मंत्री महोदय के जानकारी में ला दिया आपने।

**मोहम्मद माहिर आजाद :** सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं, आपको खुद को पता है कि पहले किस तरीके के हालात हुए थे और कितने लोगों की उसमें मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हुए थे, मेरा मकसद तो केवल इतना सा ही है कि पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की नहीं हो, समय रहते हुए उसके ऊपर जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए।

**श्री सभापति:** ठीक है, कह दी आपने। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान:** गृह मंत्रीजी इसमें सक्षम हैं, कमीशन की जो रिकमण्डेशन आई हैं, आपने स्वयं ने स्वीकारा है और उनको आप लागू करवाइये, यह जो शास्त्रीनगर कब्रिस्तान है जो जयपुर में है इसके ऊपर जब गोलाबारी हुई, गोली चली थी, लोग मरे थे, सक्सेना कमीशन बैठा उसने रिपोर्ट दे दी और मैं मानता हूं कि आपकी जानकारी है उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए और सक्सेना कमीशन...

**श्री सभापति:** अब आप विराजे।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसको आप लागू कराइए।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, इसमें एक चीज और जो सदन में नहीं आई है, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा..

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदय, ये बड़ी योजना से जो नये विधायक हैं उनकी भ्रूण हत्या कर रहे हैं ये लोग (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय गृहमंत्रीजी इसमें कोर्ट ने भी (व्यवधान) कोर्ट के डायरेक्शन को आप फुलफिल कर दें और जो कब्जे वहां पर हैं, उनको हटाकर के (व्यवधान) और कब्रिस्तान को अतिक्रमण से बचाएं।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले तीन साल से देख रहा हूं कि बड़ी योजना से जो नये विधायक बोलते हैं, योजना बनाकर के उनकी भ्रूण हत्या करते हैं ये लोग, यह उचित बात नहीं है (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): (व्यवधान) आपको एन्क्रेज कर रहे हैं आप बोलिए लेकिन यह एक समस्या ऐसी है लोग आये हुए हैं (व्यवधान)

**श्री सभापति:** अब आप विराजे।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): जब मैं बोलता हूं तब ही आपको सारी बातें याद क्यों आती है, मेरी समझ में नहीं आया (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): जब गृहमंत्रीजी थे नहीं, गृहमंत्रीजी के आते ही हमने अपनी बात उनको कह दी (व्यवधान)

**श्री सभापति:** अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): xxx

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): xxx

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य बीरूसिंहजी।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): xxx

**श्री सभापति:** मांग पर चर्चा करें।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): xxx

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): xxx

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): इसमें ऐसा है कि एकदम तुरन्त मैं आपके सामने सारा विषय रख पाऊंगा यह तो नहीं है, आपने विषय मेरे सामने रखा है, मैं उसकी आवश्यक सामग्री को मंगाने के बाद क्या उसमें मुझे आपको जवाब देना है, मैं तैयार करके अगर आप चाहोगे तो कल मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूं (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप नियमों में आइए ना, नियमों और प्रक्रियाओं के तहत आप नोटिस देकर के आइए, यहां थोड़े ही अचानक पोइन्ट आफ आर्डर में उसको उठा दिया (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं में चलता है, माननीय सदस्य (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कोई तरीका थोड़े ही हुआ (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नोटिस देकर के आइए ना (व्यवधान) पर आप डिसक्शन ओपन नहीं कर सकते, आप डिसक्शन ओपन नहीं कर सकते, यह थोड़े ही है कि पोइन्ट आफ आर्डर में उठा दिया (व्यवधान) एक सदस्य खड़े हैं, दूसरे सदस्य खड़े हो रहे हैं, यह थोड़े ही होगा।

**श्री सभापति:** ठीक है, माननीय सदस्य।

## मांग संख्या 26 एवं 51 पर विचार

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था इस सदन के माध्यम से मैं घनश्यामजी तिवाड़ी, चिकित्सा मंत्री दिगम्बरसिंहजी और राजस्थान की माननीय वसुंधराजी का, उनका विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित जो महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट है, जे.के. लोन अस्पताल है, एस.एम.एस. और जयपुर अस्पताल है 1967 से लेकर 2003 तक बिलकुल नाम मात्र के इन अस्पताल में विकास के काम हुए हैं और पिछले तीन साल में इन सभी के सहयोग से एग्जेक्ट तो मेरे पास आंकड़ा नहीं है लगभग 300 करोड़ के काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन चार अस्पताल में कराये गये हैं और आप किसी भी एजेन्सी से सर्वे करा लें तो आज की तारीख में जो चार अस्पताल हैं उनका बिलकुल काया-पलट हो गया है। इसलिए विशेष तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी और घनश्यामजी तिवाड़ी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में 22 डिसपेंसरी हैं, 15 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

और 8 हमारे हौम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अस्पताल हैं इनमें कई प्रकार की कमियां हैं, अनेक प्रकार के उपकरण यहां पर नहीं है, अगर सरकार इस नये बजट से जितने भी डिसपेंसरीज हैं इनके अंदर भी नये उपकरण लगाए जाएं तो आसपास के इलाके को इसके अंदर फायदा हो जाएगा और माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी का मैं पुन: आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क का जो वार्ड नम्बर-13 है मानसरोवर वहां पर 50 करोड़ की लागत से एस.एम.एस. के पैटर्न पर एक नया चिकित्सालय बन रहा है लगभग 300 बैड का यह चिकित्सालय है और लगभग इसकी बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई है तो इसके लिए भी माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी का मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरी दो या तीन ही डिमाण्ड्स हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में झोटवाड़ा है वहां पर पंचायत समिति की सात बीघा जमीन है और 1984 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हीरालालजी देवपुरा ने यहां पर एक सैटेलाईट अस्पताल का उदघाटन हुआ किया था और उनका पत्थर भी वहां पर लगा हुआ है और वर्तमान में जो हमारा झोटवाड़ा क्षेत्र है इसमें मेरे विधान सभा के वार्ड नम्बर-1, वार्ड नम्बर- 8, वार्ड नम्बर-9, वार्ड नम्बर-10, वार्ड नम्बर आपका 7, वार्ड नम्बर-2 इसी प्रकार आपका 70, 68, 69 है इनको मैं उपनगर के नाम से पुकारता हूं और लगभग यहां पर तीन लाख की आबादी है और यहां पर मौटे तौर पर गरीब आदमी रहते हैं, मुसलिम समाज के लोग भी रहते हैं, एस.सी. के लोग भी रहते हैं, एस.टी. के लोग भी रहते हैं। मैं पिछले तीन साल से प्रयास कर रहा हूं हर साल सरकार के माध्यम से एक पत्र आ जाता है कि सरकार के पास इस समय पैसा उपलब्ध नहीं है इसलिए यहां पर सैटेलाइट अस्पताल खोल नहीं सकते। इसलिए मेरी आपसे डिमाण्ड है, एक ही डिमाण्ड है यहां झोटवाड़ा के अंदर एक सैटेलाइट अस्पताल खोल दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय दिगम्बर सिंहजी लगातार 15 साल तक जीतेंगे। नमस्कार, भारत माता की जय।

**श्री सभापति:** धन्यवाद। माननीय श्री महादेवसिंह खंडेला।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): (व्यवधान) यह क्या तरीका निकाला है, इसलिए क्या अच्छा तरीका है, राजेन्द्रजी, अस्पताल तो खुला हुआ है जयपुर में और जीतोगे कुम्हेर से, आप भी कोई तरीका निकालें कुछ (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य:** बिलकुल लैटेस्ट टेकनीक मैंने डवलप की है साहब।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): अस्पताल की नींव के पहले ही कांस्टीटुएन्सी खतम हो गई है आप ध्यान रखना (व्यवधान)

**श्री सभापति:** आप बैठे-बैठे बात नहीं करें।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खंडेला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है इसमें लगातार तीन साल से पूरे डाक्टर भी नहीं है और वहां जो भवन बना हुआ है वह भी बहुत ही खराब स्थिति में है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खंडेला जो कि नगरपालिका क्षेत्र है और वहां की आबादी करीबन 30-35 हजार के करीब है, गरीब लोग निवास करते हैं, वहां भवनों का निर्माण करवाकर सारे डाक्टर पदस्थापित करवायें जिससे वहां के लोगों को चिकित्सा का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। विधान सभा क्षेत्र खंडेला में ही गवाला में सामुदायिक केन्द्र है जिसमें केवल दो डॉक्टर काम कर रहे हैं, गवाला के आसपास में गांव है, ढाणियां हैं और गांव और ढाणियों के लोग सीकर तक जो कि वहां से करीबन 50 कि.मी. पड़ता है, नीम का थाना वहां से करीबन 30 कि.मी. पड़ता है वहां वे जा नहीं सकते, आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल तो दिया है लेकिन डाक्टरों की कमी होने की वजह से वहां के लोग चिकित्सा के लिए लाभान्वित नहीं हो सकते। हमारे इलाके में पहले तो गांवों के अंदर अब भी बच्चा जन्मता था दाईयां काम करती थीं लेकिन अब दाईयां तो हैं नहीं इसलिए बड़े-बड़े गांव हैं, ढाणियां हैं तो एएनएम वगैरह हैं, कम संख्या में एएनएम्स है और जहां कहीं भी आपने उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोल रखे हैं उन उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में भी सब जगह एएनएम्स नहीं हैं इसलिए वहां आज भी एएनएम्स के रिक्त पद पड़े हैं, उनको भरने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, गांवों में, मेरे खुद के गांव हौद में आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है आज तक वहां कोई डाक्टर नहीं है, सारा भवन भी, मतलब डाक्टर के अभाव में वहां कोई मरीज नहीं आता है और जब मरीज नहीं आता है, डाक्टर नहीं है, हास्पिटल खुलता नहीं है तो वह सारा हास्पिटल बर्बाद हो गया है और जो डाक्टर के रहने का मकान था वह मकान भी टूट गया है

(श्री महादेव सिंह)

इसलिए मेरा निवेदन है कि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हौद पंचायत समिति खंडेला में डाक्टर पदस्थापित किया जावे और वहां के उस भवन के पुनर्निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि दी जाए जिससे यहां के आसपास के गावों में, बाहर के गांवों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधा मिल सके। धन्यवाद, जयहिन्द।

**श्री सभापति:** माननीय श्री सुंदरलालजी अनुपस्थित। माननीय श्री हीरालाल रैगर।

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग की मांग संख्या-26 पर मैं अपने क्षेत्र की समस्याएं, वैसे उपलब्धियां तो हमारे माननीय कालीचरणजी सर्राफ ने सारी दी हैं, निवाई जयपुर रोड एन.एच.-12 पर स्थित है, आये दिन वहां ऐक्सीडेंट होते हैं। मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि निवाई में एक ट्रोमा हास्पिटल स्वीकृत किया जाए, दुर्घटनाओं की यह स्थिति है टोंक और निवाई के बीच में दस-दस मौतें एक-एक साथ हो जाती हैं तो मैं पुरजोर शब्दों में चिकित्सा मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि निवाई में ट्रोमा हास्पिटल खोला जाए। मेरे यहां होस्पिटल में पैरा मेडिकल स्टॉफ और एक चिकित्सक, एक वरिष्ठ चिकित्सक का पद रिक्त हे वह भरा जाए। दतवास एवं जिलाई जो पीएचसी हैं उनको सामुदायिक चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाए साथ सिरोही, नटवाड़ा एवं खरवाड़ा बुजुड में पीएचसी खोली जाए। आपने मुझे समय दिया धन्यवाद।

**श्री सभापति:** धन्यवाद। माननीय श्री भागीरथ चौधरी।

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 26 के जरिये निवेदन करना चाहता हूं वैसे तो मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे कार्य हुए हैं जो पिछले 56 वर्ष में कभी नहीं हुए। मेरे किशनगढ़ का जो यगनाम हास्पिटल है वह सौ बैड का था उसको डेढ़ सौ बेड में क्रमोन्नत कर दिया गया है और ट्रोमा यूनिट भी मेरे वहां खोली गयी है उससे जो हमारे किशनगढ़ में जो मार्बल मंडी है जो विश्वविख्यात है उसमें हम सबको बहुत ही इस सरकार ने जो यह तोहफा दिया है इससे हमारे किशनगढ़ की जनता इतनी प्रभावित है, खुश है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, हर क्षेत्र में परन्तु सभापति महोदय, जो देता है उससे ही मांगी जाती है जो हम मांगे और मांग पूरी करे उन्हीं से ही मांगी

(श्री भागीरथ चौधरी)

जाती है। सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से मेरे किशनगढ़ स्थित ट्रोम यूनिट के नवीन भवन निर्माण एवं उसके सुचारू संचालन की आवश्यकता के लिए मैं राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर किशनगढ़ स्थित है जिसमें गंभीर सड़क दुर्घटनाओं हेतु आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं दिलाने हेतु हमारे यहां तीन वर्ष पूर्व सितम्बर, 2004 में 6 स्थानों पर ट्रोमा यूनिट की स्थापना की गयी थी इनमें भीम, सोजत, देवली, महुआ, शाहपुरा, जयपुर एवं किशनगढ़ का चयन किया गया इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हाइवे पर होने वाली गम्भीर दुर्घटनाओं में घायल रोगियों को शीघ्र उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना था। मान्यवर सभापति महोदय, मेरे किशनगढ़ स्थित यगनाम चिकित्सालय में भी ट्रोमा यूनिट की स्थापना की गयी थी और केन्द्र सरकार द्वारा बजट आबंटन पश्चात् राज्य सरकार ने बीस लाख रुपये उपकरण एवं एंबुलेंस के लिए चिकित्सालय को दिये गये लेकिन इस ट्रोमा यूनिट के नवीन भवन निर्माण की प्रस्तावित लागत राशि साठ लाख रुपये की स्वीकृति आज तक प्राप्त नहीं हुई है जिससे यहां पर ट्रोमा यूनिट का सुचारू संचालन करने में काफी कठिनाई आ रही है जबकि इस चिकित्सालय परिसर में इस हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और पर्याप्त चिकित्सक स्टाफ भी उपलब्ध है लेकिन नर्सिंग स्टाफ की कमी है अत: आपसे निवेदन है कि आप बजट आबंटन वर्ष 2007-08 में किशनगढ़ स्थित ट्रोमा यूनिट के नवीन भवन निर्माण की राशि स्वीकृत करायें। सभापति महोदय, साथ ही इसके सफल एवं सुचारू संचालन में मदद करने हेतु आवश्यक मापदंडानुसार नर्सिंग स्टाफ एवं नवीन उपकरण की स्वीकृति जारी करावें ताकि असहाय दुर्घटनाग्रस्त लोगों को उपचार की सुविधा मिल सके। सभापति महोदय, मेरे किशनगढ़ स्थित वायन अस्पताल में आईसीयू की स्वीकृति की आवश्यकता है। मान्यवर, किशनगढ़ अजमेर जिले का सबसे बड़ा उपखंड है यहां पर स्थित जैसा मैंने आपको बताया सौ बैड से डेढ़ सौ बैड किया गया यहां पर आसपास के विधान सभा क्षेत्र जैसे परबतसर, पुष्कर, नसीराबाद, भिनाय, मालपुरा एवं दूदू के ग्रामीण जन अपना इलाज कराने हेतु आते जाते रहते हैं लेकिन आज वर्तमान में काफी संख्या में मरीज हार्ट पेशेंट होते हैं जिन्हें अपना इलाज कराने में काफी कठिनाई आती है। किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र पर स्थित होने एवं किशनगढ़ भीलवाड़ा मार्ग, किशनगढ़ मालपुरा मार्ग, किशनगढ़ डीडवाना मार्ग

(श्री भागीरथ चौधरी)

एवं काफी आवागमन होने से काफी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे रोगियों के लिए काफी असुविधा होती है अत: किशनगढ़ स्थित वायन अस्पताल में आईसीयू की आवश्यकता के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2007-08 में इसकी सक्षम स्वीकृति प्रदान करावें ताकि हार्ट पेशेंट मरीजों व दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के इलाज की पूर्ण सुविधा उपलब्ध हो सके। आईसीयू के भवन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान में यहां पर आरएचएसडीपी योजना में नवीन भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है लेकिन आईसीयू के साथ संचालनार्थ आवश्यक उपकरण एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायें। सभापति महोदय, मेरे किशनगढ़ सिटी डिस्पेंसरी में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र एवं महिला चिकित्सक के नये पद की भी आवश्यकता है अत: सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे किशनगढ़ स्थित डिस्पेंसरी में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र एवं महिला चिकित्सक का नया पद सृजित करने की कृपा करें क्योंकि जहां चालीस-पैंतीस हजार की आबादी है मेरे इस शहर में वहां पर चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में केवल राजकीय सिटी डिस्पेंसरी संचालित है जिसमें केवल दो चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुराने शहर में महिलाओं की चिकित्सा सुविधाओं हेतु न तो कोई राजकीय चिकित्सालय है न ही निजी चिकित्सालय है जिससे महिलाओं को अपने इलाज, प्रसव कार्य आदि हेतु तीन चार किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इसी प्रकार शहर के आसपास दस पन्द्रह किलोमीटर दूर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत पाटन, सरगांव, डीडवाना, मालियों की बाड़ी, टीकावड़ा, वरना, मुंडोला, सिलोरा आदि के गांव, ढाणी, मजरों के लोगों, महिलाओं को भी अपना इलाज कराने आना पड़ता है इसके लिए पुराने शहर में जरूर यह व्यवस्था हो जाए तो चालीस-पैंतालीस हजार की जो आबादी है उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सभापति महोदय, आखिर में मैं किशनगढ़ स्थित वायन अस्पताल में चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ के आवास रिपेयर एवं नये आवास निर्माण की आवश्यकता के लिए भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इसकी समुचित व्यवस्था हो जाए तो हमारी जनता को बहुत राहत मिलेगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** धन्यवाद। माननीय श्रीमती ममता शर्मा। (अनुपस्थित) माननीय श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): सभापति महोदय, आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर प्रस्तुत मांग के संदर्भ में आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था के लिए राज्य का हर वर्ग सरकार पर और सरकार द्वारा स्थापित चिकित्सालयों पर मुख्य रूप से आश्रित है। यह बात अलग है कि अनेकों ऐसे अस्पताल बड़े-बड़े नाम के साथ में भी हमारे राज्य में अलग-अलग जगहों पर स्थापित हुए हैं जहां पर इलाज के आधुनिकतम उपकरणों के साथ साथ एक बड़ी टीम सेवा में लगी है लेकिन फिर भी आज एसएमएस अस्पताल की अगर बात की जाए जिसको हम सुपर स्पेशियलिटी के नाम पर डवलप कर रहे हैं इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता लेकिन समय-समय पर देखते हैं कि उपकरणों के व्यवस्थित रूप से काम नहीं करने का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है और अनेकों बार मौतें तक हुई हैं मरीजों की। आज सरकार द्वारा चाहे वो केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से हो या राज्य के अपने स्रोत हों, राशि का स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा किया जा रहा है और अस्पतालों की बेहतर व्यवस्था बनायी जा रही है लेकिन फिर भी हमारे को आज के समय में आवश्यकता है जयपुर शहर में एसएमएस अस्पताल पर बढ़ते हुए और इससे संबद्ध चिकित्सालयों में बढ़ते हुए बोझ को देखते हुए हम और जो अस्पताल हैं जैसे हमारे रेफरल होस्पिटल हैं कांवटिया और जयपुरिया होस्पिटल हैं इन अस्पतालों को भी अगर हम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध करें यहां पर रेजीडेंट डॉक्टर्स को उनकी सेवाएं वहां पर भी दें तो उन अस्पतालों के मरीज जो जा रहे हैं उनको पूरी सुविधा मिल पाएगी। यह मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है। इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे आसपास का जो क्षेत्र है इसके लिए बार-बार मरीजों का यहां तक आने उनको इलाज सही डॉक्टरों के माध्यम से मिले इसकी भी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को और सरलीकृत किया जाना चाहिए। आज पर्टीकूलर डॉक्टर्स से कोई पेशेंट इलाज कराना चाहता है तो उसको उस डॉक्टर तक अप्रोच करने का माध्यम अस्पताल न होकर उसके घर से होता है और घर पर पहले मरीज अप्रोज करे तो निश्चित रूप से उसको कुछ डॉक्टर को व्यक्तिगत उसकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ती है तभी उसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है यह गरीब के इलाज के नाम पर बहुत तकलीफ दायक है । अनेकों जिलों के उदाहरण हमारे सामने हैं। मैं बात को कम शब्दों में करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले समय पर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

हमारे यहां पर महामारी का प्रकोप रहा । डेंगू, चिकनगुनिया जैसा रोग हमारे पूरे राज्य छा गया और इसके चलते अनेकों लोगों की मौत हुई, अनेकों लोगों ने कष्ट भोगे वह अलग है। लेकिन वह व्यवस्थाएं एकदम से ना बन पाने के कारण यहां पर मरीजों की एक लंबी कतार लग गई। मेडिकल कालेज और भी हैं हमारे राज्य में लेकिन उन मेडिकल कालेज में इलाज की व्यवस्था नहीं रही। हालांकि उदाहरण दिये जाते हैं मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा संभागीय मुख्यालय बीकानेर वहां पर पीबीएम अस्पताल है। वह अस्पताल कभी अपने नाम के लिये जाना जाता था और आज का वक्त यह है कि वहां पर मरीज अगर इलाज के लिये आते हैं तो उनको महज प्रताड़ना के अलावा और कुछ नहीं मिलता । पिछले समय में जब डेंगू का प्रकोप फैला, सभापति महोदय, हमारे वहां के प्रिंसिपल, हमारे वहां के सुपरिंटेंडेंट और हमारे वहां के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट विदेश यात्रा कर रहे थे, मरीज दर-दर भटक रहे थे और उनको अपनी विदेश यात्रा से लौटकर उनके इलाज की व्यवस्था करने की कोई सोच नहीं, वहीं दूसरी ओर मरीजों को भर्ती करने के नाम पर अस्पताल में कोई प्रक्रिया नहीं थी । मरीजों को सीधा रास्ता दिखलाया जा रहा था कि आप जयपुर जायें। कारण कि वहां पर हमारे पास इलाज की माकूल व्यवस्था नहीं है और माकूल व्यवस्था के नाम पर उनको आवश्यकता थी महज एक सैल अपरेटर की। जो मरीज डेंगू रोग से पीडित है उसको प्लेटलेट की जरूरत होती है एक सैल अपेरेटर जो वहां वर्षों से खरीदा हुआ था उसको उस अस्पताल में व्यवस्थित तरीके से लगाया नहीं जा सका और नहीं लगाये जाने के कारण यह थे कि जो विभागीय कमी-पूर्ति करनी थी उसके प्रति वहां का प्रशासन घोर अनदेखी कर रहा था। दो वर्ष पूर्व 2004 में उसके लिये राशि आबंटित हुई । 26 लाख रुपया सांसद निधि से उसको दिया गया। उसके एक डेढ वर्ष बाद फिर विभाग को याद आता है कि यह राशि कम पड़ती है 13 लाख की और मांग की जाती है। लेकिन समय-समय पर उसको जो इंस्टाल करने की कार्यवाही करनी थी उस कार्यवाही की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं उसके बाद जब कभी भी टीम आने की बात आती है कि इसके लिये किसी स्थान से कोई जांच समिति आयेगी तो वहां पर स्टाफ की अनुपलब्धता बताई जाती है। आज के समय वह स्टाफ आप सीएमएचओ से डेपुटेशन पर लाकर कर रहें हैं तो आपने उस समय क्यों नहीं वह व्यवस्था की? क्या गरीब को यहां तक भेज कर, एक-एक मरीज का हजारों रुपया खर्च कराकर न जाने कितनों ने अपनी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

अकाल मौत का सामना किया है कौनसा यश कमाना चाहती है हमारी यह सरकार? यह बात मेरी समझ से बाहर है ।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा समय-समय पर वहां पर प्रशासनिक अकर्मण्यता के चलते अस्पताल में आये दिन धरने और प्रदर्शन, आये दिन मरीजों की मौत यह घटनाएं वहां पर आम हो चुकी हैं। अधीक्षक का पद लंबे समय से फोर-ए-ग्रांट चल रहा है। आज के समय में पुन: एक आदेश जारी होता है उस आदेश के तहत फिर यह कह दिया जाता है कि इंडेफिनेट पीरियड के लिये यही अधीक्षक काम करेंगे । क्या हमारे इतने बडे अस्पताल में एक अधीक्षक भी हमारे को नहीं मिल सकता है? सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं अनेकों बार आये दिन वहां पर मरीजों को और उनके अटेंडेंट को खुद इधर-उधर मशक्कत करनी पडती है। वार्ड की हालत यह है कि वार्ड के आस पास के टायलेट की हालत यह है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी उनका उपयोग कर ले तो वह खुद बीमार हो जाये । आज वहां पर जो हमारे बेहतरीन डाक्टर अपने आप को बताते हैं उनके इलाज की बानगी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । वर्ष 2003 में एक अबोध बालिका इलाज के लिये पीबीएम अस्पताल में आती है । घडसाना से वह चलती है घडसाना का डाक्टर उसको रेफर करता है एक जांच के लिये सरीन लेबोरेट्री के नाम पर । उस लेबोरेट्री में जांच के लिये वह व्यक्ति अपनी पुत्री को लेकर जाता है । उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट वहां से दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि उस बच्ची को कैंसर है । सभापति महोदय, पुन: वह व्यक्ति यह रिपोर्ट लेकर घडसाना के डाक्टर सोनी के पास जाता है । डाक्टर सोनी रेफर करता है पीबीएम अस्पताल के बहुत बडे चिकित्सक के नाम पर जो कि वर्तमान में भी वहां पर प्रिंसिपल के पद पर पदस्थापित है । वह उस प्राइवेट जांच रिपोर्ट के आधार पर उस बच्ची का इलाज शुरू कर देते हैं। कीमोथैरेपी उसको दे दी जाती है और वह बच्ची बेहोश हो जाती है। उसकी तबीयत बिगडने पर वह गरीब व्यक्ति वापस एप्रोच करता है कि मेरी बच्ची को क्या हो गया । दूसरे कोई व्यक्ति बताते हैं कि इसको यह बीमारी नहीं है । आप इसकी जांच पुन: करवाइए । दूसरे चिकित्सालय से वह जांच कराने की कोशिश करते हैं कहीं पार नहीं पडती । फिर उनको बताया जाता है कि आप दिल्ली के अस्पताल से जांच करा कर लाइए । वह दिल्ली की लाल लेबोरेट्री से जांच कराते हैं जिसमें पाया जाता है कि बच्ची को कैंसर नहीं है । सभापति

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

महोदय, उस रिपोर्ट के आधार पर वही डाक्टर रेफर करता है दूसरे डाक्टर को और वह दूसरा डाक्टर पीबीएम अस्पताल में ही एसपी मेडिकल कालेज में उसकी जांच करता है और जांच में फिर पाया जाता है कि उस बच्ची को कैंसर नहीं है । एक ऐसी बच्ची जिसको डाक्टर की लापरवाही के कारण, ऐसा इलाज करने के कारण आज तक वह जिंदगी और मौत से झूझ रही है । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज हमारा इतना बड़ा अस्पताल ऐसे डाक्टरों के हाथों में है जिन डाक्टरों की अकर्मण्यता का यह उदाहरण है । क्या होगा ऐसे अस्पतालों का, क्या होगा ऐसे मरीजों का। आज हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं । हमें उपकरण देने के नाम पर हम अच्छे से अच्छे उपकरण दे सकते हैं लेकिन जब तक उनको उपयोग में लेने वाले हाथ उचित नहीं होंगे तब तक मरीज का हित होने वाला नहीं है । समय-समय पर अस्पतालों में मशीनों की खराबी की दुहाई दी जाती है । कारण जो इसकी आड़ में समझ में आता है वह एक ही समझ में आता है कि प्राइवेट हास्पिटल में पेशेंट जाये और वहां पर इलाज कराये । तो उन सरकारी अस्पतालों का क्या होगा? आज करोडों रुपये की मशीनें वहां पर लाई जा रही हैं लेकिन उन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है । सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इन तथ्यों की गहराई में जायेंगे, क्या हो रहा है इसको देखेंगे । गरीब को इलाज कराने के नाम पर जो सरकार अपनी सोच लेकर चल रही है इस सोच को वास्तविक रूप से हम लागू कर पायेंगे ऐसा शायद आने वाले दिनों में संभव हो, सभापति महोदय, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं स्थानांतरण का दौर चल रहा है हालत यह है कि अनेक सीएचसी हैं जहां पर डाक्टर के 75 प्रतिशत पद रिक्त चल रहे हैं । वहां पर डाक्टरों का दूर-दूर तक पता नहीं है । मैं उदाहरण देना चाहूंगा हमारी सीएचसी लूणकरणसर का । वहां पर 6 पद स्वीकृत हैं जूनियर स्पेशलिस्ट के, वर्तमान में 3 पद रिक्त हैं । एक एसएमओ का पद है उस पर पद स्थापित हैं, एमओ का पद रिक्त है । एक डाक्टर वहां पर डेपुटेशन पर चल रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ वहां पर डेपुटेशन पर चल रहा है । आज हमने पद स्थापित कर रखा है वहां पर उस अस्पताल से अनेक डाक्टर डेपुटेशन के नाम पर तनख्वाह भी उठा रहे हैं लेकिन वहां के लोगों को व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं । एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी वह सुविधाएं दे सकता है, खांसी जुकाम की दवा तो वह भी दे सकता है वहां पर इतने डाक्टर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

पद स्थापित करने का कारण क्या रह गया? इतना बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, नेशनल हाई-वे पर अस्पताल है लेकिन वहां पर एंबुलेंस की सुविधा नहीं है । ठीक इसी तरीके की स्थिति हमारे बीकानेर जिले के नापासर कस्बे की आती है। वहां पर भी एक बहुत बड़ा अस्फ्ताल है। अनेकों पर आपने वहां पर दे रखे हैं लेकिन उन पदों पर डाक्टर पद स्थापित नहीं है । महज दो डाक्टर अपना वहां पर काम चला रहे हैं । जबकि उस अस्पताल को वहां पर स्थापित करने का उद्देश्य था कि पीबीएम अस्पताल के ऊपर सीधा लोड ना पड़े, आसपास के गांव के लोग वहां पर इलाज कराने के लिये जायें। यह इस बात को जाहिर करता है कि वास्तव में हम व्यवस्था तो करना चाह रहे हैं लेकिन उस व्यवस्था की क्रियान्विति ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। सभापति महोदय, एक तरफ अभी हमने बजट में अनेकों नये सामुदायिक केन्द्र खोलने की बात कर ली । एंबुलेंस देने की बात कर ली, संभागीय मुख्यालय पर हम मोबाइल डिसपेंसरी चला देंगे, यह सब हमने बात की । मोबाइल डिसपेंसरी समय-समय पर चलती रही है, आज भी हम किसी भी सीएमएचओ के अंडर में देख लें वहां उनके पास लंबी चौड़ी गाड़ियों की लाइन खडी है लेकिन उनके पास डाक्टर नहीं हैं। जब तक हम डाक्टर का पद स्थापित नहीं करेंगे, जब तक उनके लिये पद सृजित नहीं करेंगे, नई नियुक्तियां नहीं करेंगे तब तक उन अस्पतालों का क्या करेंगे यह बात मेरी समझ से बाहर है । सभापति महोदय, सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि हम डाक्टर को पद स्थापित करें, पैरा-मैडिकल स्टाफ को पद स्थापित करें । आज गांवों में इलाज की हम बात कर रहे हैं, गांवों में इलाज की सुविधा नहीं है यह बात सही है मैं भी यह मांग करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये लेकिन जब आपके पास डाक्टर नहीं है, डाक्टर गांव में टिकना नहीं चाहता है तो उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्या किया जायेगा? इस व्यवस्था को सुधारा जाये कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से चिकित्सकों का और स्टाफ का ठहराव हो। इसके लिये हम उनको क्या बेहतरीन सुविधा दे सकते हैं। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने भी सुझाव दिया था कि हम डाक्टरों को चाहे उनके हाउस-रेंट-अलाउंस के नाम पर या और दूसरे अलाउंस दें जो शहरों की तुलना में अगर कहीं ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से वहां पर आदमी के रुकने का विचार होगा। आज यह एक नियम तो है कि हर राजकीय कर्मचारी और अधिकारी जो वहां पद स्थापित है अपने मुख्यालय पर उसका रात्रि ठहराव

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

होना चाहिये लेकिन इसकी तरफ कोई भी नहीं देखता। रात्रि ठहराव नहीं करने वालों के ऊपर कभी कोई कार्यवाही नहीं होती। डाक्टर मैक्सिमम अप-डाउन करते हैं। सुबह वह अपने नजदीकी जिले से या नजदीकी कस्बे से चलते हैं, अस्पताल तक पहुंचते हैं जब तक आधा आउटडोर का समय निकल जाता है और दो-तीन घंटे रूककर वापिस चले जाते हैं। यह आपस में उन्होंने अपनी बारी बांध रखी है, एक दिन अगर यह सीएसी की कहानी कर ले तो दो डाक्टर एक दिन आ जाएंगे, दो डाक्टर एक दिन आ जाएंगे, इस तरीके की व्यवस्था चलती है तो फिर पद का क्या लाभ है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धन की कमी नहीं होने के बावजूद भी जब कभी कोई आवश्यकता बतलाई जाती है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा भी जो राशि दी जाती है उस राशि का समुचित उपयोग, आज के समय में व्यवस्थाओं के नाम पर कह लीजिए या अकर्मण्यता के नाम पर कह लीजिए उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है इस बात को भी माननीय मंत्री महोदय को दृष्टिगत रखना चाहिये।

इसके साथ-साथ, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अस्पताल के अंदर समय-समय पर जो रिक्त पदों की बात की जाती है, इसको भरना चाहिये। लम्बे समय से पीबीएम अस्पताल के अंदर जो लाइफ सैविग मेडीकल स्टोर है वह बंद था, बंद का कारण क्या था महज एक दस बाई दस के कमरे की मरम्मत कराना, उस मरम्मत को कराने में महीनों लग गए। दर-दर मरीजों को भटकना पड़ा दवाओं के लिए। उस स्टोर की स्थापना का उद्देश्य क्या था, इस बात को हम भूल गए। उचित दर पर दवा मिले, उचित स्थान पर दवा मिले, हर समय दवा मिले इसकी तरफ देखना किसी ने मंजूर नहीं किया। इसका अगर हम दूसरा पक्ष देखना चाहें तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने व्यवस्था नहीं बनने दी शायद उनके अपने कुछ व्यापारिक हित रहे होंगे जिनके चलते हुए यह देखते रहे हो कि आस-पास के मेडीकल स्टोर पर अगर आम मरीज जाएंगे दवा के लिए तो शायद उनके हितों की ज्यादा पूर्ति होगी, इन सब बातों का ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और उसके साथ यह कहना चाहता हूं, पूर्व में हमारा पीबीएम अस्पताल, कैंसर के रोगी वहां पंजाब और हरियाणा तक

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

से आया करते थे। कैंसर का बहुत बड़ा सेंटर था और रीजनल कैंसर सेंटर नाम से भी जाना जाता है। वहां पर आज के समय में भी स्थिति यह है कि इलाज कराने के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है तो सीधा जाता है वहां पर अधिकांश अगर पोस्टिंग है तो रेडिएशन ओनकोलोजिस्ट की, जबकि एक मरीज को अगर इलाज के लिए जाना है तो सबसे पहले उसको, मेरी जानकारी कहती है, हो सकता है वह गलत भी हो क्योंकि अगर मेडीकल ओनकोलोजिस्ट के पास में जाएगा वह ही उसको बताएगा कि उसको फर्दर कोई सर्जरी की जरूरत है, किस तरीके की थैरेपी की जरूरत है और कोई ऐसी आवश्यकता है या महज दवा से उसका काम चल सकता है, तो यह पदों को बढ़ाया जाना चाहिये। आज के समय में केवल एक पद है वहां मेडीकल ओनकोलोजिस्ट जबकि रेडीएशन ओनकोलोजिस्ट के वहां पर सात पद हैं।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर पूर्व के अंदर हमने यह देखा कि जो वहां पर सीसीओ था उसकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। आईसीयू वहां पर लम्बे समय से बंद रहा, इलाज के अभाव में। लगभग दो साल तक आईसीयू बंद रहने के बाद, मरम्मत का पैसा आ जाने के बाद जब यह मरम्मत हो गई तो यह पाया गया कि उसके अंदर स्टाफ नहीं है इसके कारण हम इसको नहीं चला पाए। दो बैड का एक आईसीयू वहां चलता रहा। राशि आने के बावजूद भी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह बानगी मैं एक सम्भागीय मुख्यालय बीकानेर की न देते हुए मैं आपको पूरे राज्य की बताना चाहता हूं, अधिकांश स्थानों पर यही स्थिति है चाहे हम कोटा के मेडीकल अस्पताल की स्थिति ले लें चाहे हम जोधपुर के मेडीकल कालेज की स्थिति ले लें, उससे सम्बद्ध अस्पताल की स्थिति ले लें। आये दिन मरीजों को इसीलिए, एक गरीब तबके का बड़ी आशा के साथ वहां इलाज कराने आता है, जब उसकी आशा की पूर्ति नहीं होती...

**श्री सभापति:** आप वाइंडेप करें।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): तो उसके मन का आक्रोश वहां पर सामने आता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राज के, प्रावधान वर्तमान में किए उन प्रावधानों का उपयोग शायद तभी हो पाएगा जब हम इसके लिए सही पद स्थापित कर पाएंगे। सही डाक्टरों की टीम को वहां पर ले पाएंगे, उनकी वह इच्छा जाग्रत कर पाएंगे जिस सेवा की भावना से उन्होंने इस प्रोफेशन में आने की बात की है, उन्होंने डिग्री को हासिल किया है, उनकी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

भावना वहां पर पूरी उस तरीके से रहे जिस प्रकार उन्होंने शिक्षा लेते हुए की। आशा करता हूं कि आने वाले समय में सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी और इसी के अनुरूप कार्य करेगी। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्रीमती प्रतिभा सिंह।

(अनुपस्थित) श्री हेमराज मीणा।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): सभापति महोदय, आज मांग संख्या-51 सामाजिक न्याय और मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई दूंगा जिन्होंने सामाजिक न्याय में, बहुत दिनों से हमारी जबरदस्त मांग चल रही थी 2008 तक सारा बैकलाग पूरा होगा। जब से मैं विधायक बना हूं, हमारे सारे एस.सी,एस.टी. के विधायक हैं, सारे आफिसर हैं सबका बार-बार यह निरंतर यह दवाब रहता आया है कि चालीस हजार का हमारा बैकलाग है लेकिन वह बैकलाग, बार-बार यह सवाल उठता था कोई जवाब नहीं मिलता था, मुख्य मंत्री को बधाई दूंगा उन्होंने हमारी इस बात को स्वीकार किया, बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान का सबसे बड़ा काम हुआ है। इतना बड़ा काम आज दिन तक इसका कोई नहीं कर पाया। कांग्रेस का भी राज रहा, कांग्रेस वालों ने भी केवल आश्वासन दिया। केवल रिजर्वेशन के नाम पर वोट लिये लेकिन काम किसी ने नहीं किया। 2008 तक हमारे जो चालीस हजार कर्मचारियों का बैकलाग है वह शून्य हो जाएगा इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, सरकार को, समाज कल्याण मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। हमारा बहुत बड़ा काम हुआ है। सभापति महोदय थोड़ी अड़चन हमारे बीच में है। (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): बकाया है, बैकलाग बाकी है उसको पूरा करवा दो बधाई सब की स्वीकार कर लेना। ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** आप बिराजिए।

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): अभी तो आधे से ज्यादा बैकलाग बाकी है साहब ...(व्यवधान) बधाई देने से कोई फायदा नहीं है।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): 2008 तक शून्य हो जाएगा यह आपके सामने बजट की किताब में आ गया। (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): वाह-वाही मत करो। क्षेत्र में जाना है लोगों के बीच में जवाब देना है।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): तीन वर्ष संघर्ष के बाद मुख्य मंत्री ने जो सबकी बात सुनी और बहुत बड़ा काम कर दिया कोई नहीं कर सका आज दिन तक। सभापति महोदय, मेरा थोड़ा-सा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि इसमें हमें दिक्कत सी महसूस होती है मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, जोन आफ कंसीड्रेशन के नाम पर जब बैकलाग की बारी आती है तो एक से पांच, अगर एक अफसर को लेना होगा तो पांच को बुलाएंगे, अगर छठा-सातवां नम्बर है तो उसको नहीं बुलाएंगे, यह सबसे बड़ी अड़चन है। अगर उपलब्ध है तो जोन आफ कंसीड्रेशन का ध्यान न रखते हुए उन अधिकारियों को आमंत्रित किया जाना चाहिये, तो यह बैकलाग निश्चित रूप से भरेगा। हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक लोग हैं, संस्थाएं हैं, हमारे जो एमएलएज हैं, सारी जनता में इतना अच्छा मैसेज जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा काम मुख्य मंत्री ने किया है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा अनुसूचित जनजाति के जो गरीब लोग हैं, छोटी बस्तियों में रहते हैं, एस.सी के लोग हैं, बैरवा, मेघवाल हैं, सकड़ी गलियों में रहते हैं उन लोगों के पास जो रिहायशी मकान है, जो गांव में मकान बने हुए हैं, किसी के टापरी है, किसी के झौंपड़ी है, ऐसे छोटे-छोटे मकान बने हुए हैं लेकिन उनके पास अभी तक उनके पट्टे नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि गांव में जो छोटे-छोटे मकान बने हुए हैं अगर उनको पंचायत समिति के द्वारा अगर नि:शुल्क भू-आबंटन किया जाए या पट्टे जारी कर दिये जाएं तो निश्चित रूप से उनको मालिकाना हक मिलेगा। मालिकाना हक मिलने से वह बैक से ऋण ले सकते हैं, बैंक से और सुविधाएं मिल सकती हैं। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा यह बहुत महत्वपूर्ण बात है इसको माननीय मंत्रीजी सम्मिलित करेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, बैकलाग के बारे में मेरा एक बिन्दु छूट गया। कह रहा था, चालीस हजार बैकलाग है, मैं कहना चाहूंगा कि बैकलाग भरने के लिए जोन आफ कंसीड्रेशन को ध्यान में रखने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है, इसको रिव्यू करने की एक कमेटी बने।

(श्री हेमराज मीणा)

कमेटी में पांच आदमी हों। पांच आदमी में एक एस.सी. का हो, एक एस.टी. का हो और तीन अन्य के हो सकते हैं। तीन सामान्य के भी हों ताकि न एस.सी., एस.टी. का नुकसान होगा न सामान्य वर्ग का नुकसान होगा तब जाकर यह कमेटी लगातार रिव्यू करेगी, जब जाकर निश्चित रूप से यह 2008-09 तक पूरा भरा जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सामाजिक न्याय के द्वारा कई सारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन आज योजनाएं सरकार बना रही है, सरकार पैसा भी दे रही है लेकिन उन योजनाओं पर सुपरवीजन के लिए हमारे पास अधिकारियों की आवश्यकता है, समाज कल्याण में एक डिप्टी डायरेक्टर बैठता है हमारा पूरा जिला खाली हैं, तो मैं चाहता हूं कि सुपरवीजन के लिए जो तहसीलदार, एसडीओ हैं इनको भी यह अधिकार दिया जाए ताकि हमारी जो अनुसूचित जाति की योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं का यह सुपरवीजन कर सकें, देख सकें ताकि वह योजनाएं क्रियान्वित हों। जनता को उन योजनाओं का लाभ मिले। अधिकृत रूप से वैसे तो तहसीलदार, एसडीएम जाकर देखते हैं लेकिन उनको समाज कल्याण, हमारे सामाजिक न्याय विभाग की ओर से, सरकार की ओर से भी निर्देश हो ताकि उन एस.सी की योजनाओं पर सुपरवीजन करके उसका छोटे गरीब तबके तक उसका लाभ पहुंचे। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा एसडीएम, एडीएम ये सब वहां मौजूद हैं उनको यह दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेडीकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, इनमें छात्रावास, हमारे को इनमें छात्रवृति मिलती है लेकिन इंजीनियरिंग कालेज में छात्रवृति मिलने का प्रावधान है प्रतिमाह का है। लेकिन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग में छात्रवृत्ति मिलने का प्रावधान प्रतिमाह का है। छात्रवृत्ति के माध्यम से हर महीने उनको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि उनको प्रतिमाह नहीं मिलती है। साल में एक बार मिल जाए तो गनीमत है। तो बजट का जो केन्द्र सरकार का आता ही नहीं है, समय पर ग्राण्ट नहीं आती, उसके कारण से आज इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के छात्र पढ़ रहे हैं उन छात्रों को बहुत दिक्कत पैदा होती है। मंत्रीजी, इस सम्बन्ध में आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्रयास करें, राज्य सरकार की ओर से ताकि सेण्ट्रल गवर्नमेंट से बजट समय से आये और इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं

(श्री हेमराज मीणा)

उनको छात्रवृत्ति समय से मिले ताकि उनको आर्थिक अभाव नजर नहीं आये। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज जो प्राइवेट सहभागिता के अनुसार चल रहे हैं, निजी स्तर पर चल रहे हैं, आज उनमें एस.सी., एस.टी. के जो विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। यानि उनकी जो काउंसिलिंग होती है, काउंसिलिंग के बाद मेरिट के आधार पर उनको काउंसिलिंग में इंजीनियरिंग और मेडिकल में कालेजों में भेजा जाता है। काउंसिलिंग के आधार पर तो कई बार जब देखते हैं तो उनकी फीस इतनी तगड़ी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उसको वहन करने में बहुत मुश्किल आती है। तो सरकार की ओर से प्रयास हो, माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से भी यह प्रयास हो कि जितने भी मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज हैं जिनमें प्राइवेट कालेजों में लड़के पढ़ते हैं, काउंसिलिंग के बाद जाते हैं, उनकी 2-2 लाख रुपया फीस है और सामान्य कालेज की फीस 3 हजार रुपया है तो बहुत अन्तर है, तो उसमें भी कुछ रिलेक्सेशन हो, ताकि गरीब और छोटे तबकों को इसका लाभ मिल सके। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे सामाजिक न्याय विभाग की एक योजना है, एस.सी. कारपोरेशन। एस.सी. कारपोरेशन के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों को वाहन दिलाना, व्हीकल्स दिलाना या रोजगार के साधन तैयार करने के लिये वाहन दिये जाते हैं। लेकिन मैं एक बात देखता हूं कि जब उनका साक्षात्कार होगा तो लोग आयेंगे 200-300 और टारगेट 2 या 3 होंगे, तो ऊंट के मुंह में जीरा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंत्रीजी सेण्ट्रल गवर्नमेंट से बात करें। बात करके इनके टारगेट बढ़ें ताकि लोगों को रोजगार के साधन मिलें। रोजगार के साधन मिलेंगे तो उनकी माली हालत सुधरेगी। और उनका आर्थिक आधार ठीक होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय विभाग, समाज कल्याण विभाग के हास्टल चलते हैं और रेजीडेंशियल कालेज भी हैं, स्कूल भी हैं। अब हम देखते हैं कि साधारणतया इन होस्टलों में वार्डनों के पद बहुत सारे खाली हैं। चूंकि मंत्रीजी मेरे जिले के हैं, सभापति महोदय, तो मैंने कई बार इनसे बात की कि खाली पद भरें। लेकिन समस्या यह आ गयी सभापति महोदय कि फाइनेंस का नया अड़ंगा। मैंने मंत्रीजी से बात की तो कहा कि फाइनेंस में फाइल चल रही है। सभापति महोदय, आज हमारे होस्टल हैं, हम लगातार

(श्री हेमराज मीणा)

होस्टल खोलते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एस.सी; एस.टी; के लड़के ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इनको हम सरकार की कुछ अच्छी सुविधा दें। लेकिन समस्या आज यह आ गयी कि हमारे कई होस्टलों में एक वार्डन के पास 4-4 होस्टलों का जिम्मा है। उनको वह सम्भालने में उनकी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और कई होस्टल तो हमारे ऐसे हैं जो चपरासी और चौकीदार के भरोसे चलते हैं।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

मैं चाहूंगा, सभापति महोदय कि मंत्रीजी इसकी भर्ती करें ताकि सरकार के पैसों का सदुपयोग हो और सरकार के पैसे के सदुपयोग का लाभ अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को मिले। सभापति महोदय, आप घण्टी बजा रहे हैं। अभी तो मैं एक ही डिमाण्ड पर बोल रहा हूं। अभी तो शुरू ही किया है मैंने।

**श्री सभापति:** टाइम पूरा हो गया।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): सभापति महोदय, आज छात्रावासों में 550 रुपया, छात्रावासों में 550 रुपया एक विद्यार्थी को एक महीने के लिये देते हैं। मैं समझता हूं, यह बहुत कम है। चाय-नाश्ता उसमें, खाना भी उसमें, सुबह का खाना भी उसमें। साबुन भी उसमें, तेल भी उसमें। तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस राशि को बढ़ाकर 550 की जगह 700, मैं तो चाहता हूं कि हजार करें लेकिन 700 तो आप निश्चित रूप से करें ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके। उनकी पढ़ाई ठीक प्रकार से हो सके।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा सामाजिक न्याय में। सभापति महोदय, कई सारे हमारे, जो रेजीडेंशियल कालेज हैं, रेजीडेंशियल स्कूल हैं और कुछ छात्रावास हैं जिनमें टेम्परेरी रूप से रसोइया, चौकीदार संविदा पर रख रखे हैं। ऐसे लोग हमने संविदा पर रख रखे हैं। लेकिन उनको 5-5 साल हो गये हैं। आज दिन तक उनको स्थाई नहीं किया गया। एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ कि जो संविदा में कर्मचारी काम कर रहे हैं वर्षों से, उनको स्थाई किया जाना चाहिए। तो सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि संविदा में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप निश्चित रूप से स्थाई करें ताकि वह मन लगाकर काम करें। उन रसाइयों की और जो चौकीदार का काम

(श्री हेमराज मीणा)

कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है। इतनी कम है कि वह तो नि:शुल्क सेवा ही कर रहे हैं। वह गरीब आदमी का, वह इस आस में काम कर रहा है कि चलो कभी तो मेरी नौकरी बन ही जायेगी, कभी तो मुझे पैसा मिलेगा ही। मेरा रोजगार इससे चल रहा है, उस हिसाब से वह काम करता है तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो गया, हमारे मंत्रीजी इस बारे में गहराई से विचार करें। गहराई से विचार करके इसका मानदेय भी बढ़ायें और उनको स्थाई करने के बारे में भी विचार करें।

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-26 के बारे में भी थोड़ा सा निवेदन करुंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा।

**श्री सभापति:** एक मिनट में पूरा करें।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): सभापति महोदय, मांग संख्या-26 में चिकित्सा में जितना किया गया, मैंने देखा है, मैं पिछली बार भी एम.एल.ए. था लेकिन 3 सालों में जितना काम हुआ है, रिकार्ड तोड़ सारे राजस्थान में काम हुआ है। और मेरे सहरिया एरिये में तो सबसे ज्यादा काम हुआ है। काम की कोई कमी नहीं है चिकित्सा के क्षेत्र में। आज मैं कह सकता हूं कि जो राजस्थान हैल्थ डवलपमेंट सिस्टम जो राजस्थान में, उसके माध्यम से जो पैसा आया है, ऐसा लगता है कि शाहबाद में भी ऐसा हास्पिटल बना है, बारां जैसा लगता है कि बारां जैसा हास्पिटल शाहबाद में बन गया। तो इतना बड़ा काम चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ है। सभापति महोदय, इसमें कोई कमी नहीं रही है। स्वास्थ्य चेतना यात्रा, कई सारी योजनाएं हमने निकालीं। लेकिन स्वास्थ्य चेतना यात्रा की विशेष बात यह रही है कि बीमारी के बारे में जनजागृति होना। यह तो एक प्राथमिक काम है लेकिन स्वास्थ्य चेतना योजना जिस दिन गांव में आई उसी दिन वहां पर मेडिकल कैम्प भी आयोजित किया। बीमारों को भी देखा और बीमारों को नि:शुल्क दवाई भी दी। उनका इलाज भी किया। ऐसा कोई अभियान आज दिन तक नहीं चला जिसका तुरत-फुरत लाभ जनता को मिला हो। मैं इसके लिये भी बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी ने मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। आर.एच.डी.सी., राजस्थान हैल्थ डवलपमेंट सिस्टम द्वारा पैसा लग रहा है, काया-कल्प ही हो गया। कभी यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि सब सेण्टर में पैसा लगेगा।

(श्री हेमराज मीणा)

कभी यह नहीं लगता था कि सी.एच.सी., जो ऊपर से बिलकुल नीचे गिरने की स्थिति थी, उसकी मरम्मत हो जाएगी। आज सी.एच.सी., पी.एच.सी., सब सेण्टर, ऐसे नये चमाचम दिखने लग गये, जैसे कोई पहले कभी किसी ने इसके बारे में विचार ही नहीं किया। सभापति महोदय, मेडिकल का बहुत बड़ा काम हुआ। औजारों के लिये भी पैसा दिया। आज नये-नये हास्पिटल खुले हैं। नई-नई तकनीक से चिकित्सा प्राप्त हो रही है। सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा मंत्रीजी को मैं तो एक सुझाव देना चाहता हूं, 2-3 सुझाव हैं मेरे। सभापति महोदय, ट्राइबल के एरिये से मैं आता हूं। ट्राइबल सब प्लान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, उसके साथ ही यह सहरिया एरिया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भर्ती भी खूब कर रहे हैं, लोगों को नौकरी भी खूब दे रहे हैं। ए.एन.एम. की नौकरी भी दे रहे हैं, कम्पाउण्डर की भी दे रहे हैं, डाक्टर की भी दे रहे हैं। परमोशन भी कर रहे हैं लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि आप या तो भर्ती करें तो हमारे इलाके से वह बाहर नहीं जाए। हमारे सामने समस्या यह है कि आपने हमारे यहां पोस्टिंग तो कर दी, पोस्टिंग करने के बाद में वह अपनी जुगत इस बात में लगाता है कि जिस दिन पोस्टिंग लेता है कि मैं कैसे तबादला करवाकर के शाहबाद से चला जाऊं। वह यह कोशिश करता है। तो आप यह तय करें कि या तो हमारे जिले में, वहीं के लोगों को अपोइण्टमेंट दें और जिले से बाहर उनका तबादला न हो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मेरे यहां पर जो ट्रांसफर हुए, 11 ट्रांसफर हुए और वही किसी न किसी एम.एल.ए. की डिजायर करवा लेते हैं और वह अपने इच्छित स्थान पर चले जाते हैं। हमारे 11 का ट्रांसफर हुआ और 3 आये, सारी पी.एच.सी. खाली। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई ऐसी पाबन्दी लगाइये आप। एक मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में आप भर्ती करें तो या तो उनको स्पेशल ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का भत्ता दें ताकि वह उस लालच से वहां रुकें।

आज सहरिया एरिये में अगर कोई पी.एच.सी. बंद है, कल को कोई केजुअलटी हो गयी, कोई सहरिया की डेथ हो गयी तो कांग्रेसी तो बैठे हैं उठाने के लिए कि भूख से मौत हो गयी। अब आदमी बीमारी से मरेगा और भूख से मौत बताएंगे यह। जैसे इनके राज में हुआ। अशोक गहलोतजी के टाइम पर यह मेरे इलाके में 22 डेथ हुई, भूख से हुई, शुद्ध रूप से भूख से हुई लेकिन उसका इन्तजाम मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा किया कि अब उस इलाके में भूख से

(श्री हेमराज मीणा)

मौत हो ही नहीं सकती इसलिए नहीं हो सकती कि 35 किलो गेहूं मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, काम कर रहे हैं और मेडिकल की इतनी तुरत-फुरत व्यवस्था हो गयी कि आज मैं समझता हूं कि मैंने कभी नहीं देखा तो मैं जो यह कमी भर्ती की है इसको कैसे भी करके आप पूरा करें, यह मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, संविदा की ... (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, धन्यवाद। श्री ज्ञानचन्द पारख।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, यह पैसे दे-देकर सहरियों से बुलवाते हो आप लोग कि यह कहो कि हमें 35 किलो गेहूं मिल रहा है, यह मिल रहा है और उसके बाद वहां से एस.डी.ओ., पटवारी सब गायब हो जाते हैं। पहले आप लोग पैसे दिलवाते हो। मैं गयी हूं तीन बार आपके वहां पर ... (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): इसका जवाब तो मैं आपको दे दूंगा अभी। आप बैठो तो सही। ...(व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): क्या जवाब दोगे आप? ...(व्यवधान) आपके टाइम पर जितनी मौतें हुई हैं। ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): इनके कांग्रेस के महा मंत्री गये हैं, अश्क अली टांक। अब मैं यहां खोलता हूं पोल इनकी। इनके राज में ... (व्यवधान) हमारे राज में ... (व्यवधान) एक पोल खोल देता हूं। अश्क अलीजी टांक, जो इनके प्रदेश के महा मंत्री हैं, अब वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता हैं तो मैं आपको बताऊं ... (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): तो मैं आपको बताऊं कि वे एक गांव में गये मेरे यहां पर पिजना में। पिजना में एक लड़की को बुखार आ रहा था। उससे कहा, वह बैठी हुई थी। क्या हाल है तेरा? साहब, मैं बीमार हूं। तू तो यह कहना कि तू तो मरने की स्थिति में है। जबरदस्ती अश्क अली टांक ने खाट पर उठाकर उसको डाला और फिर अपना फोटो खिंचवाया, वीडियोग्राफी करवायी कि साहब, मैं तो मरने की स्थिति में हूं। भूखे मर रही हूं। यह मेरे पास वीडियो कैसेट है, मैं टेबल कर सकता हूं। मेरे पास वीडियोग्राफी की एक

कॉपी है। मैं टेबल कर सकता हूं। करूंगा। करूंगा। वह वीडियोग्राफी की मेरे पास कैसेट है। ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): टेबल करो न। माननीय सभापति महोदय, मनगढ़ंत आरोप लगाकर यह सदन को गुमराह करना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): कोई सी.डी. हो, सबूत हो तो आप दीजिए न। हम तैयार हैं देखने के लिए ... (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): फिर भी बी.जे.पी. वाले आपको शामिल नहीं कर रहे हैं। आप कितना भी इनका कर लो ... (व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): फिर भी कोई मतलब नहीं है। आप ज्यादा बटरिंग मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सहरिया आदिवासी लोग भूख से मरे हैं। ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): जवाब देना पड़ेगा क्षेत्र में। ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, सहरिया आदिवासी भूख से मरे हैं। मैं खुद देखकर आया हूं वहां पर, भूख से मरे हैं। ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** आदिवासियों के हिमायती हो? ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके शासन में क्या हुआ था? आपके शासन में क्या हुआ था? भूल गये क्या आप? ...(व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह कह सकता हूं कि मंगलवार के दिन ... (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमारे शासन में कुछ नहीं हुआ था। ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जब आप यहां पर विराजते थे तो आपके शासन में क्या हुआ था?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमारे मुख्य मंत्रीजी थे तब ... (व्यवधान) शासन में हुआ था तो आप ... (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): मंगलवार को जिस दिन सदन चलेगा, मैं वह सी.डी. टेबल कर दूंगा।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी ने ... (व्यवधान) वहां जाकर ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके शासन में 30 से ज्यादा लोग मरे हैं। ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपके राज में तो सहरिया आदिवासी इतने मरे हैं कि ... (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आपको तो भूख से मरने वालों से सम्पर्क तक नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): और रिकार्ड में आपका नाम लिखा गया ... (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): भूख से मरने के साथ-साथ आपने तो 17 लोगों को पुलिस थाने में भी बंद कर दिया। ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** अंकित नहीं हो।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): xxx

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): xxx

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): xxx

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): इनके लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूं। यह सोचे कि भूख से मरे हैं पर 2003 से पहले मरे हैं। ....(व्यवधान) भूख से 2003 से पहले मरे हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): xxx

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): xxx

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): हरिमोहनजी, यह भी आपकी खुशी के लिए किया है इन्होंने। ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** अब आप वाइण्ड-अप करिये।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में ही खतम कर दूंगा। दो मिनट चाहिए मेरे को।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): xxx

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): xxx

**श्री सभापति:** आपने काफी समय ले लिया। आपका समय समाप्त। माननीय सदस्य।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): xxx

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं मंगलवार के दिन इनके प्रदेश महा मंत्रीजी की सी.डी. आपके यहां टेबल करके दूंगा। मेरे पास सी.डी. रखी हुई है कि यह क्या बयान दे रहे थे उसमें। ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** अब आप विराजिये। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ। ...(व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सहरियों की भूख से मौतें 2003 में हुई थी। उसके बीच में हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा इन्तजाम किया है कि सहरिया कभी भूख से मर नहीं सकता। घर बैठे-बैठे ही वह दो रुपये किलो गेहूं, वह गेहूं भी उसको मिल रहा है और खूब खा रहा है और खूब खुश हो रहा है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): यह गेहूं दिल्ली से आ रहा है। अपने फण्ड से नहीं दे रहे हो, वह दिल्ली से आ रहा है। ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप बार-बार टोकते क्यों हैं बीच में? ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): हरिमोहनजी पैदा थोड़े ही कर रहे हैं। राजस्थान का काश्तकार पैदा कर रहा है। ...(व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बिन्दु और निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मेडिकल स्टाफ के रूप में संविदा पर बहुत सारे कर्मचारी आपने लिये थे। वे काम कर रहे हैं। गरीब आदमी हैं। तनख्वाह उनको बहुत कम मिलती है और संविदा पर लिया हुआ कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। ए.एन.एम. है, टेक्निशियन है, रेडियोग्राफर है। मैं चाहूंगा कि माननीय सभापति महोदय, उनका आप, मैंने सुना है कि उनको नौकरी से निकाल रहे हैं, नौकरी से निकालने की बात तो आप छोड़ दीजिए लेकिन मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप उनको स्थाई रूप से नौकरी में लें ताकि उनको रोजगार मिले, इनके परिवार की माली हालत सुधरे, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद।

**श्री सभापति:** माननीय श्री ज्ञानचन्द पारख।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय सभापति महोदय, यह तो सबको

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पता है कि हमारी वर्तमान सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** आप बैठे-बैठे बातें नहीं करें। ...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): इस क्षेत्र की जो आवश्यकता थी, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने वह आवश्यकता पूरी करने का अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। चाहे नये अस्पताल खोलने हो तो उसमें भी अपना रिकार्ड कायम किया। चाहे उप केन्द्र खोलने हो और चाहे नये उपकरण, चाहे सीटी स्केन मशीन सहित बड़े-बड़े कीमती उपकरण, जिनकी आवश्यकता आज हर जिला मुख्यालय पर प्रतीत होती है, हमारे चिकित्सा मंत्री ने बड़ी उदारता से उन उपकरणों की पूर्ति वहां पर की और आज मरीज को वहां बहुत बड़ा लाभ भी उन उपकरणों से मिल रहा है। चाहे रक्त जांच के उपकरण हो, वह भी बहुत उपलब्ध कराये और उससे भी बढ़कर जो हमारे प्रदेश के जो भी चिकित्सालय हैं, अस्पताल हैं, उनके भवन जो बहुत जर्जर अवस्था में हो गये थे, उनके पुनर्निर्माण और उनके नवीनीकरण के लिए करोड़ों रुपये उपलब्ध करवाये। आज जाएं तो लगता है कि कोई अस्पताल है वरना तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई खंडहर में आ गये। मरीज को भय भी कि पता नहीं कब छत गिर जाए। छत से बरसात के दिन पानी भी टपके लेकिन एक के बाद एक अस्पतालों के नवीनीकरण का एक जो काम चल रहा है उससे सरकारी अस्पताल की पैठ बहुत बढ़ी लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने सड़क के क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगायी है। आज सड़क के मामले में हम हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें भी बहुत बड़ी छलांग। गांव-गांव में शिक्षा की व्यवस्था हो गयी अगर कोई पढ़ना चाहे तो नजदीकी स्कूल तैयार पड़ी है। चाहे उच्च प्राथमिक है, प्राथमिक है, शिक्षा वह आसानी से ले सकता है और चाहे जल संसाधन का क्षेत्र हो तो एक के बाद एक करोड़ों रुपये की योजनाएं लगातार स्वीकार हो रही हैं और उस पर काम चल रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में भी उतनी लम्बी छलांग लगाने की आवश्यकता आज महसूस हो रही है। हमने बहुत किया है, यह बात सही है पर आज आवश्यकता कितनी है और उसके मुकाबले में हमारे पास संसाधन कितने हैं अगर दोनों पर दृष्टि डालेंगे तो उसमें बहुत बड़ा अन्तर स्पष्ट नजर आ जाएगा कि हमारी आवश्यकता तो इतनी है परन्तु हमारे पास संसाधन इतने कम। मेरा चिकित्सा मंत्री से बिलकुल आग्रह

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

रहेगा कि उस अन्तर को कम कैसे किया जाए। अन्तर को पाटा कैसे जाए और उस दिशा में जो भी करना पड़े क्योंकि यह लोक महत्व का विषय है चिकित्सा, सब की आवश्यकता है चिकित्सा। उस अन्तर को कैसे पाटा जाए, उस दिशा में जितना ज्यादा कार्य हो सके वह करना हमें पड़ेगा। आज गुजरात देख लें, महाराष्ट्र देख लें और कर्नाटक देख लें और वहां से हमारी तुलना करें तो हम थोड़े पीछे महसूस होते हैं। उसका कारण यह नहीं है कि हमने कोई कमी रख दी। पहले जिनका शासन था यदि उस समय वे उतना प्रयास करते जो हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने प्रयास किया तो शायद यह अन्तर कुछ कम होता। उन्होंने काम नहीं किया इसलिए हमें ज्यादा काम करने की आवश्यकता आज महसूस होती है और वह हमें करनी चाहिए। आज हालत क्या है? प्रदेश के दस हजार लोगों की बाई-पास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी प्रतिवर्ष राजस्थान के लोगों की होती है और पूरे राजस्थान में हमारे पास संसाधन है मात्र 600 ओपन हार्ट सर्जरी करने के। इतना बड़ा अन्तर। जिनके पास पैसा है, बॉम्बे जाकर करा आये, दिल्ली जाकर करा आये, थोड़ा कम पैसा है, राजस्थान के किसी प्राइवेट अस्पताल में करा आये लेकिन जो वास्तव में गरीब है और उसको कोई गम्भीर हृदय रोग हो गया और आपरेशन की आवश्यकता है। वह पूरे राजस्थान में एकमात्र सवाई मानसिंह अस्पताल की कार्डिक यूनिट सर्जरी ही उसका आपरेशन कर सकती है क्योंकि बहुत कम खर्चे में वहां आपरेशन हो जाता है और मरीज का नहीं के बराबर पैसा लगता है। मेरा उच्च शिक्षा मंत्रीजी से बिलकुल आग्रह रहेगा कि राजस्थान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, दस हजार रोगी जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता है और संसाधन 600, और उसमें जो गरीब व्यक्ति हैं तो कम से कम संसाधन की वजह से चाहते हुए भी वर्षों तक अपना आपरेशन नहीं करवा सकता। मेरा आग्रह रहेगा उनसे कि कार्डिक सर्जरी यूनिट को इतना बजट दें कि कम से कम प्रतिवर्ष दो हजार आपरेशन आसानी से यहां जो व्यक्ति कराना चाहें, उतना तो हो ही जाये। कम से कम दो हजार, उसके बिना आपकी यूनिट चल नहीं सकती।

साथ ही आज जितने वाहन बढ़े, उससे दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गयी। जितने भी नेशनल हाइवे पर अस्पताल हैं उसमें ट्रोमा वार्ड की आवश्यकता आज हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं और हमारे ट्रोमा वार्ड की संख्या अभी भी कम है। मरीज चाहे तो भी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

राजस्थान के अस्पताल में आपरेशन करवाने के लिये उसे कई बार बहुत असुविधा होती है और आज भी हमारे आर्थोपैडिक के जो कैसेज हैं, उनकी पहली प्राथमिकता अहमदाबाद या गुजरात रहती है। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध रहेगा, बहुत बड़ा काम नहीं है, जो भी एन.एच. पर अस्पताल है वहां पर्याप्त मात्रा में आर्थोपैडिक सर्जन हो जाये और जो हमारी ट्रोमा यूनिट है, वह भी इतनी सुदृढ़ हो जाये कि हमारे यहां के किसी मरीज को चिकित्सा के अभाव में राजस्थान से गुजरात की ओर मुंह देखना नहीं पड़े, इस बात का प्रयास करना चाहिये। आज इसकी बहुत आवश्यकता हो गयी है।

साथ ही मैं जो टी.बी. के हमारे रोगी हैं, टी.बी. ऐसी बीमारी हैं जिसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, बिलकुल ठीक हो सकता है अगर मरीज को सही इलाज मिल जाये और उसके लिये प्रयास भी किये। डाट कार्यक्रम हम राजस्थान में लाये। राजस्थान के हर टी.बी. अस्पताल में डाट कार्यक्रम लागू भी हो गया पर एक बार डाट कार्यक्रम के जो परिणाम हैं उस पर भी ईमानदारी से नजर डालें तो आसानी से हम सहज कह सकते हैं कि डाट कार्यक्रम के उतने अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं। शायद उसमें पर्याप्त मेडिसिन नहीं है या जितने दिन लेने की आवश्यकता है, उतने दिन वह दवाई नहीं ली जाती और हमारे कई टी.बी. के मरीज एम.डी.आर. में तब्दील हो रहे हैं, उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं। मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि एक बार डाट कार्यक्रम को पुन: दिखवायें। आप देखिये, इसके क्या परिणाम आ रहे हैं ? कितने मरीजों का डाट कार्यक्रम में इलाज किया और उसमें कुल कितने पूरे ठीक हो गये ? कितने बाद में सैकण्ड कैटेगिरी में चले गये? कितने बाद में एम.डी.आर. में चले गये ? अगर ईमानदारी से परिणामों को देखें तो शायद इसमें हमको कोई नई पद्धति लागू करने की आवश्यकता निश्चित रूप से महसूस होगी वरना कई गरीब व्यक्ति टी.बी. के पर्याप्त इलाज के अभाव में अभी भी मर रहे हैं, यह हमारी सरकार के लिये ठीक बात नहीं है। जब हम इतना अच्छा काम करें, इतने अच्छे प्रयास करें, हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और ऐसी बीमारी में मर जाये जिसमें इलाज सम्भव है, इसलिए मेरा बिलकुल आग्रह रहेगा कि इसको आप देखिये।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

मैं चिकित्सा मंत्रीजी की जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा कि जो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

ए.आर.वी. कुत्ते काटने के इंजेक्शन हैं, वैक्सीन है, यह पहले सरकारी अस्पतालों में सारी वैक्सीन नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाते थे। गरीब आदमी को कुत्ता काट गया, बड़ा दर्द भी होता था लेकिन पेट में किसी प्रकार 14 इंजेक्शन वह लगवा लेता था और भारत की एकमात्र फैक्टरी में वह इंजेक्शन बनता था, उसकी पूरे हिन्दुस्तान में सप्लाई होती थी। लेकिन पिछले एक डेढ़ वर्ष से वह फैक्टरी बंद हो गयी। किसी भी सरकारी अस्पताल में कुत्ते काटने के नि:शुल्क इंजेक्शन आज की तारीख में उपलब्ध नहीं होते। मात्र बी.पी.एल. के जो केसेज हैं उनको सरकार हमारी ओर से करवाती है, वह अलग बात है। लेकिन जो बी.पी.एल. के ऊपर की श्रेणी का व्यक्ति है, अगर उसको कुत्ता काट जाये तो उसके लिये बहुत भारी काम हो जाता है क्योंकि एक इंजेक्शन कुत्ता काटने का 300 रुपये का आता है और उसके कम से कम 6 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि कुत्ता काटने की जो वैक्सीन है, ए.आर.वी. की, वह सरकारी अस्पतालों में किसी प्रकार से नि:शुल्क या बहुत ही रियायती दर पर उपलब्ध हो जाये ताकि जो एक गम्भीर समस्या है उससे हमारी मरीजों को थोड़ी मुक्ति मिल सके।

साथ ही अस्पतालों में सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, आज एक आम आदमी की सोच हो गयी कि यह सारे लूट के केन्द्र हो गये। चाहे जांच हो इसमें भी कमीशन, चाहे दवाई लिखनी हो, उसमें भी कमीशन। सरकारी अस्पतालों में मरीज जाता है इलाज कराने के लिये, लेकिन कई बार ऐसे चिकित्सक के हत्थे चढ़ जाता है जो इलाज के बहाने अनावश्यक जांचें करवाकर या ऐसी कमीशन वाली दवाइयां लिखकर उस मरीज को तो जरूर ठीक कर देते हैं लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। इस लूट को रोकने के लिये भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। आज जनता महसूस कर रही है कि किसी प्रकार यह लूट कम हो जाये, बिलकुल बंद हो जाये। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा अधिकांश मरीज जो आउट डोर या भर्ती के मरीज हैं, वह एक बार सरकारी अस्पतालों में आ गया तो उसकी सारी जांचों की सुविधा वहीं पर मिल जाये, वहीं पर करवा दें और भर्ती करने के बाद भी कोई डाक्टर बाहर की जांचें लिखता है तो कोई न कोई ऐसा प्रावधान करें आप कानून में कि उस डाक्टर के खिलाफ भी कोई कठोर कार्यवाही हो सके। साथ ही सही दवाई मिल जाये, बिना कमीशन वाली दवाई मिल जाये और उसके लिये हमने मेडिकल रिलीफ सोसायटी अस्पताल में खोल

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

रखी है, उसकी दुकान है जहां दवाइयां मिलती हैं। पर उन दवाइयों की संख्या थोड़ी है। हर प्रकार की दवाई वहां नहीं मिलती। इसके लिये भी हम हमारी जो मेडिकल रिलीफ सोसायटी की दुकानें हैं दवाइयों की, उनको थोड़ा मजबूत करें, थोड़ा सुदृढ़ करें। उससे कमीशन की जो लूट होती है, उससे काफी हद तक हमको मुक्ति मिल सकती है। मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि हम जितने भी प्रयास कर सकें, बीमारी होने के बाद उसको ठीक करने के लिये और वह हमने किया है, हमारे मंत्रीजी और प्रयास करेंगे। लेकिन साथ-साथ बीमारी की रोकथाम के लिये जितने प्रयास हो सकें, उसको भी करने की आवश्यकता है। अगर पहले ही रोकथाम का अपन प्रयास कर लें, वैसे हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया, जो भी हमारे प्राथमिक स्कूल हैं, उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, वहां बच्चों की मेडिकल जांच होती हैं, बच्चों को आइरन व विटामिन की गोलियां समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं, उनकी आंखों का टैस्ट भी होता है और भी बीमारियों की जांच होती है, लेकिन उसके अलावा भी आज लाखों की संख्या में मात्र जांच के अभाव में परेशान हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि उनको शुगर है, बहुत बाद में पता लगता है उसको जब तक उसका शरीर खोखला हो जाता है। कई मरीजों को पता नहीं कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जांच कराने के बाद ही पता होता है। एक जन जागृति अभियान चाहे इसमें सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेना पड़े, हम बीमारी की रोकथाम के लिये पहले जितने प्रयास कर लें, हो सकता है उसके बाद में हमारे अस्पतालों पर बोझ कम पड़े वरना आज ऐसे किस्से सुनने में आते हैं । बैठा था आदमी हार्ट अटैक हुआ, मर गया, पता ही नहीं लगा कि उसे यह बीमारी थी। अगर पहले से ही पता लग जाता ...

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

**श्री सभापति :** अब आप वाइंड-अप करें।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): इसको शुगर है, इसको हार्ट अटैक हो गया, दूसरी बीमारी है तो उस दिशा में भी सरकार की ओर से कोई न कोई प्रयास हो।

बीमारी रोकने के लिये जो आज टीकाकरण की आवश्यकता है, टीकाकरण करें। जहां पूर्व की जाचं की कोई आवश्यकता है, आप जांच करें और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस बार जगह-जगह मेडिकल कैम्प, मेडिकल मोबाइल

यूनिटों की स्थापना की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मोबाइल यूनिट के जरिये हम काफी हद तक इस रोकथाम की दिशा में अच्छा प्रयास कर सकते हैं। फिर सरकार से बिलकुल अंत में वापस यही बात कहूंगा कि जितनी आवश्यकता है उसके मुकाबले में संसाधन उपलब्ध हो जाएं, उस दिशा में जितनी तेज छलांग आप लगा सको वह लगाने का दोनों माननीय चिकित्सा मंत्रियों से आग्रह है मेरा।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** धन्यवाद। श्री राकेश मेघवाल।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**(समय : 15.30 बजे)**

**(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी, श्रीमती वसुंधरा राजे के राज में सभी विभाग राजस्थान को प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जिस तरह राजस्थान में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में राजस्थान की यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने स्कूल खोल कर भवन बना कर शिक्षा जगत में राजस्थान को ए श्रेणी में लाने का प्रयास किया है उसी प्रकार सभी गांवों को सड़कों से जोड़ कर राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, बधाई के पात्र हैं और राजस्थान में ग्यारहवां स्थान परबतसर विधान सभा क्षेत्र का आया है। (व्यवधान)

सुन लो खरी-खरी बात, आपके समय में तो खड्डे ही नहीं बुरे थे।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय सदस्य, राठौड़ साहब में और स्वास्थ्य मंत्रीजी में कोई अन्तर नहीं समझते हैं, चाहे उनको धन्यवाद दो तो भी मान लोगे।

**श्री अध्यक्ष:** बीच में व्यवधान नहीं डालें, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): वह आप नहीं समझोगे, आप उस राज में नहीं थे जब राजेन्द्र सिंहजी चिकित्सा मंत्री थे, आज पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर हैं और आज यह चिकित्सा मंत्री बन गये हैं दिगम्बर सिंहजी। फर्क इतना ही है कि वो उधर बैठते थे यह इधर बैठते हैं। (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): हैल्थ मिनिस्टर वो ही हैं आज भी, डी-जूरे, डी-फैक्टो है, हैल्थ मिनिस्टर वो ही हैं। यह मालूम है कि नहीं, आपको।

**श्री अध्यक्ष:** यह इनको पहले बताओ डी-जूरे और डी-फैक्टो का अन्तर बताओ। (व्यवधान) ऐसे ही कह दिया डी-फैक्टो।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): हां, यह ठीक है। गलती हो गयी, साहब। गलती हो गयी।

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर): डी-जूरे भी यही हैं डी-फैक्टो भी यही हैं।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): आपको लेट समझ में आयी है, पहले बोल देना चाहिए था।

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर): मेरे को समझ है। माननीय सदस्य, मुझे इसकी पूरी जानकारी है डी-फैक्टो की डी-जूरे की।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): अध्यक्षजी के पहले ही बोल देते न।

**श्री अध्यक्ष:** डी-जूरे है। जूरे है, जीरो नहीं।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): आप ऐसा करो, दोनों अध्यक्षजी के चैम्बर में जाकर बात कर लेना, मेरा समय क्यों नष्ट कर रहे हो। आप मेरे पुराने दोस्त हो, सी.पी. जोशी साहब। और जुबेर खानजी वैसे ही नहीं बोलेंगे क्योंकि जुबेर खानजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मैं जीतता हूं जब ही जुबेर खानजी जीतते हैं और मैं हारता हूं तो जुबेर खानजी हारते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, बहुत आब्जैक्शनेबल बात है कि आपने डी-फैक्टो कहा किसी को। गलत बात है।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): इसलिए जुबेर खानजी तो भारतीय जनता पार्टी की खुद मन्न्त मांगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आये और जुबेर खानजी जीतें।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप क्या चाहते हो मैं अगली बार जीतूं कि हारूं?

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): अपन दोनों आयेंगे जीत के। (व्यवधान) यह मन्नत मांगना ख्वाजा साहब की दरगाह में कि राज हमारा बने और आप विपक्ष में, इस तरह बैठे अच्छे लगते रहें।

**श्री अध्यक्ष:** पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, आपकी अनुपस्थिति में नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको डी-फैक्टो मुख्य मंत्री कहा है। (व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): वो भी मेरे भाषण में।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य के कहां का दर्द कहां होता है, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं, पूरे राजस्थान के लोग जानते हैं कि हमारी मुख्य मंत्री न-केवल सक्षम हैं बल्कि इन्हीं मुख्य मंत्री ने परिवर्तन रथ पर आरूढ़ हुए तो इन सब का ऐसा सफाया किया, ऐसा सफाया किया।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): किसने कही यह बात, मैंने तो यह बात नहीं कही। आपके लिए तो मैंने तो यह बात नहीं कही। अध्यक्षजी, मैंने तो हैल्थ मिनिस्टर डी-फैक्टो, डी-जूरे की बात कही थी, आप कह रहे हो सी.एम. की ...(व्यवधान)

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आपने अपनी भावना अभिव्यक्त कर दी, मैंने हैल्थ मिनिस्टर के लिए बोला था। ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जो स्वयं चिकित्सक हैं ...(व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): अब आप को करेक्ट कर दो, माननीय डिप्टी चीफ व्हिप, करेक्ट कर दो इनको। ...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो यह कहा था राजेन्द्र सिंहजी और दिगम्बर सिंहजी दो बदन एक जान हैं।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): यह बात कही थी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यही बात कही थी क्या आपने।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): आपको सी.एम. बनने की लगी हुई है, क्या बात कर रहे हो। ...(व्यवधान) मेरे पास इलाज नहीं है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, इनको हमारी दोस्ती पर एतराज है क्या।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): यह आपकी अनकांशस में है। अनकांशस में जो आपका दिमाग काम कर रहा है वो रिफलैक्ट कर रहा है। ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): इनकी तो मिनिस्टरी में ही दिक्कत आ रही है, आप चीफ मिनिस्टर की बात कह रहे हो। मिनिस्टर में ही दिक्कत है।

**श्री अध्यक्ष:** नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य तीन दिन से कुंठित थे, बोल नहीं पा रहे थे, कुछ न कुछ बोलना था इसलिए बोल दिया।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): आज बहुत खुश हैं।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): मेरी कुंठा को आपने, अध्यक्षजी, पहचाना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरों का उत्साह मत बढ़ाओ। डी-फैक्टो और डी-जूरे चीफ मिनिस्टर, राजस्थान का नुकसान हो जायेगा। मेरी कुंठा की तो मैं कर दूंगा पर राजस्थान की क्या?

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आपकी कुंठा से मैं चिंतित रहती हूं।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): बहुत अच्छा, मुझे खुशी है पर राजस्थान की बी.जे.पी. इनकी बहुत बड़ी महत्वकांक्षा से कुंठित है, इनका ध्यान कौन रखेगा कि वर्चुली डी-फैक्टो और डी-जूरे को चीफ मिनिस्टर की लड़ाई चल रही है वहां पर। तो इसका उत्तर है कुछ।

**श्री अध्यक्ष:** विराजो आप।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): जोशी साहब, आप विराजो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): विराजो। इसका उत्तर आप ही दे दो।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): मेरा उत्तर है ...(व्यवधान) घनश्यामजी खड़े हुए न दिलावर साहब खड़े हुए, समझ गये, नमस्कार। ना घनश्यामजी खड़े हुए ना दिलावरजी खड़े हुए। नमस्कार।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): सी.पी. जोशी साहब, जब मेघवाल बोलता है और भोला मेघवाल हूं मैं राजस्थान में तो बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** अब आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): और जब मेघ गरजता है तो बादल बरसते हैं इसलिए आप थोड़ा शांति धारण कर लीजिए धारीवालजी, जोशीजी साहब।

**एक माननीय सदस्य:** जोशी को धारीवाल बना रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** अब मेघ बरस रहे हैं।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): इनमें और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों दोस्त हैं। वैसे सी.पी. साहब तो मेरे पुराने दोस्त हैं, हम एक ही उपक्रम समिति में हैं। इनके अच्छे हैं और बाहर से तो तारीफ करते हैं राठौड़ साहब की अन्दर पता नहीं क्या इनके हो रहा है। बाहर तो चिकित्सा मंत्रीजी की भी तारीफ करते हैं। हमारी उपक्रम समिति में सब हमारी सरकार की तारीफ करते हैं।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): चेयरमैन रहे हुए हैं।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): हां, अपने चेयरमैन रहे हुए हैं इसलिए तारीफ करते हैं।

मैंने यह कहा था, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में सड़कों के मामले में अगर राजस्थान पूरे राजस्थान में प्रथम आया है तो मुझे भी इस बात का गर्व है कि राजस्थान में ग्यारहवां नम्बर परबतसर विधान सभा क्षेत्र का आया है इसलिए इनको यह बात बुरी लग गयी। अब इनको मैं खरी बात कहूं तो डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें हमने 1998 में भैरोंसिंहजी शेखावत साहब जब मुख्य मंत्री थे, डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें आप छोड़ कर गये थे वो डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें पांच साल में नहीं बनायीं, वो भी डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों को डामरीकरण के लिए हमने किया है। तो आपने तो पांच साल में सड़कों को खड्डे कर-कर के ही तोड़ा है।

मैं एक बात यह कह रहा था कि चिकित्सा मंत्री जब राजेन्द्र सिंहजी थे, उस पर सी.पी. जोशी साहब बोले, उस समय नर्सों की भर्ती हुई थी और इन्होंने ही नर्सों की भर्ती करी थी। आपके पांच साल के कार्यकाल में एक भी इतिहास बता दो कि भर्ती की थी क्या आपने।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनके राज में बरसात हुई नहीं तो सड़कें टूटी नहीं।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): सड़कें तो उन्होंने तोड़ दी न।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बरसात हुई नहीं, टूटी नहीं इनकी तो।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): इन्होंने गडारें डाल-डाल के तोड़ीं।

**श्री अध्यक्ष:** आज तो मेडिकल हैल्थ की डिमाण्ड है, सड़कों की भी नहीं है और शिक्षा की भी नहीं है।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): वो उन्होंने याद दिला दी, साहब। मेघवाल बोलते हैं जब बीच में ज्यादा बोलते हैं इसलिए मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राजस्थान का भोला मेघवाल एक राकेश मेघवाल बोलता है तो बीच में टोका-टाकी नहीं करें।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): नर्सों के साथ राजेन्द्र सिंहजी का नाम लेकर आप क्या कहना चाह रहे हो।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): भर्ती इन्होंने की थी, राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत थे और यह चिकित्सा मंत्री थे। ...(व्यवधान) आपने क्या किया।

आज मांग संख्या 26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर जो मांग है पर मैं राजस्थान के यशस्वी माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा और राजस्थान की यशस्वी, लोकप्रिय मुख्य मंत्री, जो पहली मातृ शक्ति मुख्य मंत्री हैं देश में, देश आजाद होने के बाद में।

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): क्या?

**श्री अध्यक्ष:** बीच में नहीं बोलें।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): क्यों आप महिलाओं के खिलाफ हैं क्या। पहली मातृ शक्ति बनी हैं मुख्य मंत्री, आपने आज तक बनने दिया क्या।

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप राजस्थान की बात करिये, हिन्दुस्तान में तो कई बनी हैं।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): मैं तो राजस्थान विधान सभा में राजस्थान की ही बात कर रहा हूं। बुरा लग रहा है क्या।

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): देश की कर रहे हैं।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): और पहली मातृ शक्ति विधान सभा की अध्यक्ष बनी हैं और पहली महामहिम प्रतिभाजी पाटिल हैं, तो आपने तो उनका भी सम्मान नहीं किया, आप एक महिला होकर के महिलाओं का सम्मान करना सीखो।

2007-08 में 5502 ए.एन.एम की भर्ती, जी.एन.एल. की भर्ती, यह

पहली बार एक साथ हुआ है। 130 उप-स्वास्थ्य केन्द्र एक साथ पहली बार खोले जा रहे हैं। 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जा रहा है। पांच जिला स्तरीय जो अस्पताल हैं उनको क्रमोन्नत किया जा रहा है। 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शैयाओं में क्रमोन्नत किया जा रहा है। यह राजस्थान के माननीय मंत्री दिगम्बर सिंहजी की बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्य मंत्रीजी के सहयोग से।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (अलवर): अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं इतने कर दिये हैं, यहां तो हजारों लोग तो इकट्ठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, मर रहे हैं और इनके बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे हैं कि हम कितनी करेंगे भर्ती। उनको तो सब को निकलवा दो, उनको सब की सेवा समाप्त करने के लिए ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप तो जो कटौती का प्रस्ताव है उसी पर बोलेंगे।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): आप जिसका कटौती प्रस्ताव लगा है न उसी पर बोलो, यह आम भाषण नहीं है, आम बजट नहीं है।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (अलवर): मैं तो आपसे कह रहा हूं। ...(व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): तीन साल में तीन लाख लोगों को रोजगार दिया है, यह राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजे ने दिया, आपने तीन को नौकरी नहीं दी। ...(व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र सिंह** (अलवर): सत्य बातें बोल दिया करो।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): आपके समय तो हमेशा एक ही बात कहते थे कि खजाना खाली है, राज्य की माली हालत खराब है। उस भाषा में कहूंगा जिसमें आप बोलते थे, वो कहूंगा तो फिर कहोगे, हां, ठीक नहीं है।

क्या किया, नव-युवकों को नौकरी देने का आपने वादा किया था, दी क्या एक भी नौकरी ...(व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र सिंह** (अलवर): आपने बहुत अच्छा काम किया है, यह सब बहुत अच्छी बात है लेकिन ...(व्यवधान) उनको भी भर्ती करवा दो।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): उनकी तारीफ तो करो।

(श्री राकेश मेघवाल)

इनकी तारीफ तो करो ताकि दुबारा और बजट बढ़ाया जाए, तीन लाख लोगों को तीन साल में नौकरी दी है।

**श्री अध्यक्ष:** आप भोले मेघवाल को बार-बार डिस्टर्ब नहीं करें वह कई बार कह चुके हैं कि भोले मेघवाल को टोको मत।

**एक माननीय सदस्य:** बिलकुल नहीं टोकेंगे।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): आप यह बताइये एक साथ सौ एम्बुलैंस दी हैं, अगर आप पिछले कार्यकाल में सौ दे देते तो अभी हमको दो सौ देनी पड़ती। आपने एक भी एम्बुलैंस नहीं दी। सभी अस्पतालों में एम्बुलैंस नहीं है और पिछले कार्यकाल में जब चिकित्सा मंत्री राजेन्द्रजी राठौड़ थे तो मेरे परबतसर अकेले हास्पिटल में दो दी थीं। आपने क्या किया पांच साल में? नई योजना चालू की जो चिकित्सा चेतना यात्रा, उसमें गरीब को गणेश मानकर एक-एक गांव ढाणी जाकर चिकित्सा विभाग ने लोगों की सेवा की है यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । उसके साथ-साथ ही एक नई योजना और अभी लागू की है जो प्रत्येक गांव, ढाणी तक डाक्टर एक मोबाइल सेवा जो चालू की है वह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।

**श्री अध्यक्ष**: आप जो भाषण दे रहे हो वह मंत्रीजी का जवाब होना चाहिए। आप अपने कट मोशन पर बोलो। आपका कोई कट मोशन हो उस पर बोलो आप।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): मेरे कटमोशन पर बोल रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष:** क्या कट मोशन है?

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): कटमोशन तो सारे कट हो गये, मोशन रह गये। ...(व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): यह उप स्वास्थ्य केन्द्र में ...(व्यवधान) मौसम बहुत अच्छा है ना इसलिए कटमोशन कट कर दिया। हर चीज का आप बोलते हो क्या अपनी बात पर, आप भी तो कभी पूरब में और कभी पश्चिम में चले जाते हो तो हम तो उत्तर-दक्षिण में ही जा रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप अपने स्थान पर भी नहीं हैं और बैठे हुए बोल रहे हैं।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ जब चिकित्सा मंत्री थे....

**श्री अध्यक्ष:** आप नाम नहीं लें। यहां नाम नहीं लिया जाता किसी का।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री उस समय चिकित्सा मंत्री थे तो एक बेसरोली में हास्पिटल खोला था, बीस लाख रुपए की लागत लगाई थी वह बीस लाख रुपये की लागत से अस्पताल बना था वह मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में है, उसमें कुछ काम बाकी रह गया था और एक कोई ....

**श्री अध्यक्ष:** तो आज थोड़े ही डिमांड है यह, सड़क की डिमांड आज थोड़े ही है?

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): सड़क की नहीं, मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र...

**श्री अध्यक्ष:** तो आप तो राजेन्द्र राठौड़, राजेन्द्र राठौड़ गा रहे हो ...(व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा गौर से सुनें, आपका ध्यान सी.पी. जोशी की तरफ है। मैं यह बोल रहा हूं राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेसरोली...

**श्री अध्यक्ष:** यह कब की, दस वर्ष पहले की बात है।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): यह उन्होंने बनवाया था, अधूरा रह गया, उसको पूरा करने के लिए मांग कर रहा हूं। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आप क्यों +++ कर रहे हो?

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ...(व्यवधान) नाराज हैं क्योंकि ससुराल में खुलवा दीं।

**श्री अध्यक्ष:** +++ असंसदीय शब्द है।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): +++ का तो खानदानी धंधा आपका है, हमारा नहीं है...(व्यवधान) हम तो मेघवाल हैं +++ नहीं करते हैं। हम चाहे जिसको राज कराते हैं, +++ का काम मेघवालों का नहीं है। राजा महाराजाओं को राज करवाया मेघवालों ने और आज भी सदन में राज करवा रहे हैं मेघवाल इसलिए +++ आपका काम है। मैं जो बात कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस लाइन पर बात कर रहा हूं....

**श्री अध्यक्ष:** आप तो इनकी बातों का जवाब मत दो, आप तो कट मोशन पर बोलो।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेसरोली, विधान सभा क्षेत्र परबतसर 1996-97 में बीस लाख रुपए सैंक्शन हुए थे, उसका कार्य अधूरा है जो माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह बिल्डिंग हैण्ड ओवर, टेकन ओवर करके उसमें पांच लाख रुपये और कम पड़ रहे हैं। वह देकर उसको पूरा करवाया जाए। यह कहना चाहता हूं मैं तो।

**श्री अध्यक्ष:** यह ठीक बात है।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): यही कह रहा हूं मैं तो, क्या है कि आपका ध्यान उधर चला गया माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उधर प्रतिपक्ष वालों को नहीं देखें। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो संविदा पर डाक्टर, कम्पाउण्डर, ए.एन.एम. लिए गए हैं उनको परमानैंट किया जाए ताकि चिकित्सा स्वास्थ्य में सुधार होगा और उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें सुलभ काम्पलैक्स और लैट्रीन बाथरुम की सुविधा नहीं है। जर्जर अवस्था में जो पहले के उप स्वास्थ्य केन्द्र बने हैं, मैंने पच्चीस लाख रुपए एम.एल.ए. कोटे के देकर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र में बीस हजार, पचास हजार देकर उनको मरम्मत करवाया है। सरकार से भी पैसा मिला उनमें मरम्मत का बीस-बीस हजार रुपए। मैं यह चाहता हूं प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र में लैट्रीन, बाथरूम की सुविधा हो और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो हैं वहां सुलभ काम्पलैक्स हो क्योंकि यहां गांवों में इस तरह की बहुत आवश्यकता है और उसी से साफ-सुथरा हास्पिटल रह सकता है और गरीबों को और मरीजों को उसमें सुविधा मिल सकती है।

एक हमने जिस तरह से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में स्कूलें खोलीं उसी पैटर्न पर क्यों नहीं प्रत्येक गांव में और छोटी ढाणी है उसमें भी उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए जिससे ए.एन.एम. वहां की आस पास की दस ढाणियां रहती हैं और राजस्व गांव है उस लेवल पर भी उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। पंचायत मुख्यालय पर उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र होगा तो आसपास की ढाणियों में ए.एन.एम. जा सकती हैं, गांवों में जा सकती हैं और वह वहां का जो कम्पाउण्डर है पंचायत मुख्यालय पर बैठकर सुविधा दे सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** बस आप समाप्त करें।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): अभी तो बोलना ही शुरु किया है अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष:** आपको बोलते हो गए हैं तेरह मिनट।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): तेरह मिनट में सात मिनट तो विपक्ष ने ले लिए हैं, सी. पी. जोशी साहब ने ले लिए।

**श्री अध्यक्ष:** आप कोई ऐसी बात कहोगे तो विपक्ष तो लेगा। आप बात ही ऐसी कहते हो।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): वह मेरे गिनती नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को मैं मेरे क्षेत्र में ले गया था 20 जनवरी को और बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, पच्चीस हजार की भीड़ थी।

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): क्वालिस में।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): हां, क्वालिस में ले गया, हैलीकाप्टर में ले गया, आपके पास क्वालिस है नहीं, हम तो खानदानी करोड़पति, अरबपति हैं।

**श्री अध्यक्ष:** बीच में व्यवधान नहीं डालें कृपया।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): हिन्दुस्तान की सब गाड़िया हैं आप तो ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप जरूरी नहीं है कि उनकी बात का जवाब दो, आप अपना कहो।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आदमी अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखे, अब इनके पास गाड़ी नहीं है मोटर साइकिल है तो उसका इलाज मैं क्या करूं। मैं खानदानी करोड़पति हूं, इन्कम टैक्स सबसे ज्यादा देता हूं, सब गाड़ियां हैं मेरे पास, हैलीकाप्टर लाने की कोशिश कर रहा हूं। अमेरिका और लंदन से सौ लोग आए थे उस कार्यक्रम में और जिस दानदाता ने पच्चीस लाख रुपए की लागत से बहुत बड़ा भवन बनवाया था, पांच सौ लोग मुम्बई से आए थे तो इसलिए जितने प्रवासी राजस्थान से बाहर रहते थे, अमेरिका, यू.एस.ए. और लंदन और मुम्बई में उनके बीच में पच्चीस हजार की जनसंख्या, बहुत बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ में माननीय मंत्री महोदय से श्रीमती खेलीबाई जाजोरिया अस्पताल का लोकार्पण करवाया था ...(व्यवधान) उस अस्पताल की माननीय मंत्री महोदय ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसी बजट में आपकी घोषणा की क्रियान्विति करते हुए

(श्री राकेश मेघवाल)

उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेलीबाई जाजोरिया राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य बाजवास को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए।

दूसरा नवीन स्वास्थ्य केन्द्र जितने भी खोले हैं उनमें ए.एन.एम. की भर्ती की जाए और ए.एन.एम. लगाई जाएं। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उसी दिन परबतसर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसको भी क्रमोन्नत करने की माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की थी उसको क्रमोन्नत किया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को काहे में करेंगे क्रमोन्नत ?

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): रेफरल में कर देंगे, सौ शैय्याओं में कर देंगे, सैटेलाइट से जोड़ देंगे।

**श्री अध्यक्ष:** सैटेलाइट छोड़ देंगे।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): आपका आशीर्वाद रहेगा तो आप जो कहोगे उसी में क्रमोन्नत कर देंगे लेकिन क्रमोन्नत आप करवा देना मेहरबानी करके। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आप साक्षी हो गये। एक माननीय अध्यक्ष महोदय,

**श्री अध्यक्ष:** अब आप कन्क्लूड करें।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): अब माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग में इनकी एक पोल तो और खोल दूं साहब मैं 1997-98 में माननीय मदनजी दिलावर, समाज कल्याण मंत्री उस समय थे और मैं एम एल ए था और माननीय मुख्यमंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत थे, समाज कल्याण छात्रावास खोला था और चालीस लाख रुपए दिए थे 1998 में चुनाव हार गया और 1998 में छात्रावास का ट्रांसफर हो गया। आपने देखा मास्टर का ट्रांसफर होते देखा, जे.ईएन, ए. ईएन का ट्रांसफर होते देखा लेकिन इन कांग्रेस के लोगों ने गहलोतजी के राज में मेरे उस छात्रावास का ही ट्रांसफर कर दिया। मैं वापस 2003 में आया तो छात्रावास नहीं मिला फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन किया तो वापिस समाज कल्याण छात्रावास गच्छीपुरा में खोला और 42 लाख रुपए की लागत से बिल्डिंग दी उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

एक ओ.बी.सी. छात्रावास जो ग्राम भडू में उसमें भी 42 लाख रुपए का भवन दिया, उसके लिए भी माननीय मंत्रीजी को और माननीय मुख्य

मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए जो साढ़े पांच सौ रुपए हैं वह बहुत कम हैं, ऊंट के मुंह में जीरा है, कम से कम हजार रुपए होना चाहिए। गरीब बच्चा है उसको साफ सुथरा रहने के लिए, खाने के लिए अच्छा भोजन मिल सके इसके लिए हजार रुपए करने की मेहरबानी करें। समाज कल्याण विभाग ने जो छात्रावास अभी सौ छात्रावास पिछले साल खोले थे, इस बजट में बिलकुल नहीं दिए इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा इस वर्ष कम से कम पचास समाज कल्याण छात्रावास देने की मेहरबानी करावें और बजट में समाज कल्याण विभाग को और बजट दिया जाए। बालिका समाज कल्याण छात्रावास परबतसर शहर में नया खोला जाए यह माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग का ढांचा खराब है। पुराने जमाने की आयुर्वेद की जो पद्धति थी आप और हम जब आयुर्वेद विभाग से दवाई लेते थे। आजकल आयुर्वेद विभाग के दरवाजे पर कोई जाना भी नहीं पसन्द करते ..

**श्री अध्यक्ष:** अब आप कृपया समाप्त करें।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): इसलिये उस ढांचे में सुधार करने के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा और माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक अभियान चलाकर आयुर्वेद विभाग के इस पूरे सिस्टम को सुधारने की कृपा करावें, मेहरबानी करावें ताकि राजस्थान की परम्परागत जो आयुर्वेद पद्धति है उसको बढ़ावा मिले और आयुर्वेद पद्धति लागू की जावे।

ए एन एम, डाक्टर और कम्पाउंडर सब अप-डाउन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा परबतसर विधान सभा क्षेत्र पुष्कर और अजमेर की सीमा से लगता है ...

**श्री अध्यक्ष:** अब आप बस समाप्त करें प्लीज।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): तो इन सबका वहां अप-डाउन बंद करावे और मुख्यालय पर रहने के आदेश प्रदान करावें ताकि गरीब और हर वर्ग का इलाज हो सके। नहीं तो शाम को तीन बजते ही अजमेर और सुबह ग्यारह बजे से पहले आना नहीं पुष्कर से। मैंने कहा पुष्कर में पुष्कर सरोवर

(श्री राकेश मेघवाल)

में अगर नहाना है तो नहा कर आ जाओ लेकिन रहो तो कम से कम परबतसर विधान सभा क्षेत्र में ही। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री रामलाल शर्मा।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की मांग पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सरकार ने पिछले तीन वर्षों के अन्दर चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये हैं और उनका जिक्र सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने शब्दों में किया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान सरकार की मुख्य मंत्री महोदया और चिकित्सा मंत्री महोदय को कि इन्होंने राजस्थान में 2003 में जब सरकार बनी उस समय चिकित्सा में अनेकों पद रिक्त थे और लगभग 731 पदों की भर्ती करके, लगभग 1400 चिकित्सकों की पदोन्नति करके, लगभग 2500 पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती करके राजस्थान के अन्दर एक इतिहास कायम करने का काम किया है इसके लिये मैं चिकित्सा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूं। दो-तीन बातें चिकित्सा के सन्दर्भ में निवेदन करना है।

चिकित्सा का क्षेत्र एक बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र है। हर सरकार का प्रयास रहता है कि मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहे और इसके लिये ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर चिकित्सा की सुविधाएं दिला सकें ऐसा प्रयास सरकारें करती हैं। निश्चित रूप से विगत तीन साल के अन्दर सरकार ने अच्छे काम करके चिकित्सा के क्षेत्र में जिन पी एच सी के भवन नहीं थे, जिन सब सेण्टर्स पर बिल्डिंग बनी हुई नहीं थी या बिल्डिंग बनी हुई थी तो वह जर्जर अवस्था में थी उनको सुधारने का काम किया है। जिन सी एच सी के अन्दर चिकित्सकों के आवास बने हुए नहीं थे उन चिकित्सकों के आवास बनाने का काम सरकार ने किया है। मात्र तीन-चार सुझाव आज की मांग पर मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मेरा सुझाव है कि जब भी नेशनल हाईवे रोड्स पर दुर्घटनाएं घटित होती हैं तो सबसे पहले सूचना पुलिस के पास आती है। सरकार ने इस बजट

(श्री रामलाल शर्मा)

के अन्दर सौ एम्बुलेंस देने की जो घोषणा की है मेरा निवेदन है कि इन एम्बुलेंसेज का उपयोग यदि पुलिस के माध्यम से चिकित्सा विभाग करे तो उससे कई लाभ हैं। जहां दुर्घटना घटित होती है लोग आक्रोशित होते हैं, रास्ता जाम करने का प्रयास करते हैं, रास्ता जाम करने के बाद में एम्बुलेंस की यदि तुरन्त सुविधा उन्हें मिलती है तो प्राथमिक उपचार के आधार पर उस घायल अवस्था में व्यक्ति के प्राण बचाये जा सकते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि क्या चिकित्सा विभाग इन एम्बुलेंसेज का उपयोग नेशनल हाईवे रोड्स के ऊपर दुर्घटना के समय कर सकता है ?

दूसरा सुझाव मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने जिन मापदंडों के आधार पर प्रसव के बाद जो सहायता दी जाती थी उस सहायता के बारे में कभी राशन कार्ड, कभी कहते हैं कि आपका रेफरल कार्ड बना हुआ नहीं है और कभी उनको कहा जाता है कि आपके टीके सही समय पर नहीं लगे इस आधार पर, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक मात्र मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र में आज भी अप्रैल, 2006 से लेकर फरवरी, 2007 तक लगभग 1500 प्रसव महिलाओं को अभी तक भुगतान नहीं मिला। कभी उनको कहते हैं कि आपका राशन कार्ड दूसरी तहसील का बना हुआ है हम आपका भुगतान नहीं करेंगे। कभी कहते हैं कि आपका रेफरल कार्ड बना हुआ नहीं है इसलिये हम आपको भुगतान नहीं करेंगे। कभी उनको कहा जाता है आपके टीके ठीक समय पर नहीं लगाये इसलिये आपका भुगतान नहीं करेंगे। जिस हास्पिटल के अन्दर डिलीवरी हुई है, जिस हास्पिटल के अन्दर प्रसव हुआ है उससे बड़ा प्रमाण कोई हो नहीं सकता चाहे वह किसी भी विधान सभा क्षेत्र की रहने वाली हो, किसी भी तहसील की रहने वाली हो यदि उस चिकित्सालय के अन्दर उसको डिलीवरी हुई है तो उसको जननी सुरक्षा योजना के तहत सहायता मिलनी चाहिये।

मेरा सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर सबसे ज्यादा दवाब सवाई मानसिंह हास्पिटल के अन्दर रहता है। क्या इस दवाब को कम करने के लिये जयपुर जिले के आस-पास 30 किलोमीटर की परिधि के अन्दर पड़ने वाली सी एच सी को यदि हम सुविधायुक्त बनाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जयपुर के एस एम एस हास्पिटल का दवाब भी कम होगा और उन 30 किलोमीटर की परिधि में आस-पास के पड़ने वाले गांवों के अन्दर एक अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रह सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात अभी माननीय सदस्य ने अपनी रखी थी चिकित्सकों के द्वारा प्राइवेट जांचें करवाना या प्राइवेट जांचों के बाद अनियमितता कहूं या कोई खुद के स्वार्थों की बात कहूं यह एक बहुत गंभीर बात है। आज सरकार के द्वारा जितनी भी सी एच सी, पी एच सी हैं वहां दवाइयों के अपार भण्डार भरे हुए हैं। वह दवाइयां खराब हो जाती हैं लेकिन उनका वितरण नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव है कि इसकी भी एक मानीटरिंग कमेटी बना कर उन दवाइयों का सही उपयोग हो सके इसके लिये भी हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है।

चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने किये हैं ज्यादा कुछ निवेदन नहीं करना चाहता। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किशनपुरा जो सब सेण्टर है उस सब सेण्टर के अन्दर पी एच सी खुलना नितान्त आवश्यक है क्योंकि लगभग उसके 15 किलोमीटर की परिधि के अन्दर कोई दूसरी सी एच सी नहीं है। हमारा चौमूं का जो सी एच सी हास्पिटल है उस चिकित्सालय को भी क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वह हास्पिटल है। अब की बार सरकार ने इस बजट सत्र में जो घोषणा की है कि सभी चिकित्सालयों में 24 घण्टे डाक्टर उपलब्ध रहेंगे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर इस घोषणा का असर पड़ेगा और आपात काल में, इमरजेंसी के अन्दर जिन सुविधाओं की आवश्यकता रहती है उनको सुविधा निश्चित रूप से मिलेगी।

एक बार पुन: चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय काम किये हैं उनके लिये और आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र में और भी अधिक हम अब मिलकर काम कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मौका दिया।

**श्री अध्यक्ष:** थैंक यू।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आसन से व्यवस्था दी गयी थी कि जयपुर के संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में 4.00 बजे गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

**श्री अध्यक्ष:** दी गयी थी ?

## शासकीय वक्तव्य

## जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित डांस पार्टी

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

2.3.2007 को कलेक्ट्रेट, जयपुर परिसर में होली स्नेह मिलन के अवसर पर आयोजित विवादास्पद डांस पार्टी एवं दिनांक 5.3.2007 को कलेक्ट्रेट परिसर में मीडियाकर्मी एवं कर्मचारियों के मध्य मार-पीट की घटना की संभागीय आयुक्त, जयपुर से जांच करायी गयी। जांच में निम्न तथ्य सामने आये:-

दिनांक 2.3.2007 को कलेक्ट्रेट परिसर में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ था जिसमें आर्केस्ट्रा पार्टी, पेशेवर नर्तिकाएं भी थी। आर्केस्ट्रा पार्टी विभागीय समिति द्वारा बुलायी गयी थी। कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट कर्मचारी, अधिवक्ता, जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय, सहायक कलक्टर, जयपुर एवं उप खंड अधिकारी, जयपुर ने भाग लिया। पेशेवर महिलाओं के कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु बुलाने से विवादास्पद स्थिति बनी एवं इसमें कलेक्ट्रेट परिसर की छवि भी दुष्प्रभावित हुई है। आर्केस्ट्रा पार्टी का आयोजन करना एवं महिलाओं को बुलाये जाने में विभागीय समिति के अध्यक्ष श्री रामावतार भारद्वाज एवं कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारी श्रीमती गौरी देवी की मुख्य भूमिका रही। उसके अलावा श्री अनिल जैन, कनिष्ठ लिपिक का आचरण भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य रहा। दिनांक 3.3.2007 को समाचार पत्र में प्रकाशित दृश्यों में जिन चार कर्मचारियों श्री विजय कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक, श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ लिपिक, श्री मुन्ना लाल, वाहन चालक और श्री दामोदर मीणा, वाहन चालक भी पाये गये इनके विरुद्ध जिला कलक्टर द्वारा अनैतिक आचरण सम्बन्धी कार्यवाही 16 सी सी ए का नोटिस दिया गया। जिला कलक्टर द्वारा श्री रामावतार भारद्वाज, श्री अनिल जैन और श्रीमती गौरी देवी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी। सभी सातों कर्मचारी जो घटना में किसी न किसी प्रकार से लिप्त पाये गये हैं।

इनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त उन्हें तत्काल जयपुर से बाहर स्थानांतरित किया जायेगा। जिला कलक्टर जयपुर ने विभागीय समिति के अध्यक्ष एवं कर्मचारियों के आग्रह पर कुछ समय के लिए कार्यक्रम में भाग लिया था। जिला कलक्टर को यह अवगत नहीं कराया गया था कि होली के कार्यक्रम में नाच-गाने वाली महिला नृत्यंगनाओं को भी बुलाया गया है। उनकी उपस्थिति में कोई अभद्रता या अश्लील हरकत नहीं हुई थी। फोटो में श्री मुन्नालाल, वाहन चालक को शराब की बोतल कमीज के अंदर से निकालते हुए दिखाया गया है। यह फोटो कलक्टर परिसर के दूसरे चौक की है जिस पर बैडमिंटन दिखाई दे रहा है। होली मिलन समारोह में शराब पीने वाले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसी अन्य कर्मचारी की पहचान नहीं हुई। संभवतया: जान-बूझकर के वाहन चालक के फोटो को समारोह से जोड़कर समाचार में दर्शाया गया है। समारोह स्थल पर शराब आदि पीने के संबंध में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। मदिरा सेवन के बारे में आभास यह है कि कुछ लोगों ने अलग से जाकर के मदिरा का सेवन किया था।

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5.3.2007 को कर्मचारियों द्वारा समाचार-पत्रों में होली मिलन समारोह के आयोजन के संबंध में प्रकाशित आपत्तिजनक समाचारों के स्वरूप मध्यान्ह अवकाश समय मीटिंग आयोजित की गयी थी जिसमें मीडिया कर्मियों द्वारा फोटो खींचे जाने पर कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों के बीच झगड़ा और विवाद उत्पन्न हुआ। इस संदर्भ में तीन प्रकरण थाना बनीपार्क में दर्ज किये हैं। एक प्रकरण श्री प्रमोद शर्मा, प्रेस फोटोग्राफर, दैनिक नवज्योति द्वारा, दूसरा प्रकरण श्री रामावतार भारद्वाज, अध्यक्ष, विभागीय समिति कलेक्ट्रेट जयपुर द्वारा और तीसरा प्रकरण श्री जितेन्द्र भारद्वाज, एडवोकेट पुत्र श्री रामावतार भारद्वाज द्वारा दर्ज कराया गया। तीनों प्रकरण दिनांक 5.3.2007 की घटना से संबंधित हैं। इसमें अनुसंधान की कार्यवाही जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसकी कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ गवाहों के बयान हो चुके हैं, कुछ अनुसंधान अभी अधूरा है परन्तु अनुसंधान होने के बाद पुलिस कार्यवाही की जायेगी।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2 तारीख को कार्यक्रम हुआ उसकी पूरी सी.डी. मौजूद है। यह कार्यक्रम साढ़े तीन बजे शुरू हुआ। आपके जिला कलक्टर 3 बजकर 45 मिनट पर उस कार्यक्रम में गये और 4 बजकर 40 मिनट तक उस कार्यक्रम में बैठे रहे। 6 गाने नृत्यांगनाओं ने उनकी मौजूदगी में पेश किया है और यह सब सी.डी. में मौजूद है, नम्बर एक। नम्बर दो, उसके बाद खबर अखबारों में साया हुई और फिर 5 तारीख को कलेक्ट्रेट के उसी परिसर में कर्मचारियों की सभा हुई। भडकाऊ भाषण दिये गये। कर्मचारियों द्वारा मारपीट करने की बात की गयी। यहां तक कि राजस्थान पत्रिका के फोटोग्राफर या कौनसे का है, मुकेश शर्मा, उसने कलक्टर के चैम्बर में घुसकर अपनी जान बचाई है। इस सब के बावजूद कलक्टर की कोई रेस्पोंसिबिलिटी नहीं है। 45 मिनट तक नृत्यांगनाओं के नृत्य होते रहे और होली के अवसर पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना भी चाहते हैं तो कर्मचारी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कार्यक्रम पेश करें। पेशेवर नृत्यांगनाओं का कलेक्ट्रेट में क्या औचित्य है और खाली कलक्टर ही नहीं, आपका ए.डी.एम. वहां बैठा हुआ, आपका एस.डी.एम. वहां बैठा हुआ। अब सरकार कौनसी संस्कृति विकसित करना चाहती है वह तो आपको तय करना है। आज हमारी दृष्टि में ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): इस तरह से आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इस ढंग से आप आरोप लगा रहे हो ...(व्यवधान) सरे आम मनगढंत बात कर रहे हैं सदन के अंदर, गलत बात कर रहे हैं सदन में ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हमारी दृष्टि में जो कुछ हुआ है वह किसी भी रूप में गृह मंत्रीजी, जिस सांस्कृतिक परिवेश से आप आते हैं ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): संस्कृति आपसे सीखें हम ...(व्यवधान) आप खुद संस्कृति देखकर के फिर बात करना ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): जिस संस्कृति का आपने निर्माण किया है ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): यह सी.डी. गलत बनाकर के पेश कर रहे हैं आप सदन में ...(व्यवधान) काहे की सी.डी. पेश की है सदन में ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह ठीक नहीं है, एक मिनट भी जयपुर का जिला कलक्टर अपने पर कंटीन्यु करे ...(व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, भारत की संसद ने कुछ एम.पी. को टी.वी. पर चैनल में आने के बाद कि क्वेश्चन के लिए उन्होंने पैसे लिये उनको डिसक्वालिफाई किया और उनकी जगह चुनाव हुए। एक तरफ हमारी संसद अपनी गरिमा बनाने के लिए उन सांसदों को जिन्होंने टी.वी. के चैनल के माध्यम से जब यह समाचार आया कि इस तरह की घटना हुई उस पर एक्शन लिया। माननीय गृह मंत्रीजी आपके स्वयं के कथन के अनुसार आप यह मानते हैं कि वहां पेशेवर नृत्य हुआ। इसमें कोई डिसप्यूट नहीं है। यह भी कोई डिसप्यूट नहीं है कि विभागीय समिति ने होली मिलन का कार्यक्रम रखा और यह भी कोई डिसप्यूट नहीं है कि कलक्टर से लेकर के नीचे लेवल तक के अधिकारी वहां मौजूद थे। कलक्टर की मौजूदगी में यह घटना हो जाये। कलक्टर को जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन कलक्टर की मौजूदगी में यह

(डा. सी. पी. जोशी)

घटना हो गयी, टी.वी. पर आ गयी, मैंने स्वयं ने ई टी.वी. पर कमिश्नर का, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना तब तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार ने कार्यवाही की विधान सभा में चर्चा करने के बाद। विधान सभा चल रही है, विधान सभा के सदस्य यहां पर मौजूद हैं, ऐसा कृत्य, जिस कृत्य में मैं नहीं कहता कि कलक्टर इनवाल्व है। लेकिन यह बात तो सत्य है कि 5 बजे तक कलक्टर की डयूटी है। जब कलक्टर की डयूटी में कोई घटना हो जाये तब जिम्मेदारी किसकी बनती है। मैं समझता हूं कि हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए I don't want to question about the credential of the Collector but simultaneously I am concerned about this कि यदि आपने इस तरह की चीजों को एग्जम्पलरी पनिशमेंट देकर नहीं मैसेज दिया तो ना आपके हित में है, ना हम सब के हित में है। जब विधान सभा चल रही है, इलेक्ट्रानिक मीडिया में यह चीज आ जाये। आप और हम सब यह कहें कि यह चौथा स्तंभ है और उसके बाद भी हम कार्यवाही नहीं करें तो मैं उसकी मेरिट में नहीं जाना चाहता हूं । यह मैं आप पर छोड़ता हूं। उस दिन भी मैंने यह बात कही थी आपसे, फिर रिपीट कर रहा हूं कि 5 बजे के पहले यदि कलक्टर मौजूद है तो कलक्टर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। आप मुझे यह बता दें कि कौन से नियमों के अंतर्गत कलक्टर सरकारी काम में, एक लिबरल तरीके से एक प्रोग्राम कराये, वहां तक तो समझ में आता है लेकिन जब आप खुद गृह मंत्री की हैसियत से यह मान रहे हैं कि वहां पेशेवर नृत्य हुआ, 5 बजे के पहले कलक्टर मौजूद था तो मुझे बता दें कि कौन से कानून में कलक्टर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं इसमें डिसप्यूट भी नहीं करना चाहता। आप खड़े होकर के यह कह दें स्वविवेक कि क्या हम सबकी गरिमा के लिए, इलेक्ट्रानिक मीडिया जो पीपुल वाच का काम करता है, प्रिंट मीडिया जो लोगों को जानकारी देता है। यदि उनकी क्रेडिबिलिटी को भी हम खतम कर देंगे तो इस विधान सभा को बंद कर देना चाहिए। यदि हम यह मैसेज भी नहीं देना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उस कलक्टर की कांपिटेंस पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं कि सरकार इस चीज को टोलरेट कैसे कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप खड़े होकर सदन में आश्वस्त करें कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। फिर आप भावनाओं में बह जायेंगे क्योंकि आपकी भावना जब शुरू

(डा. सी. पी. जोशी)

होती है तो रूकती नहीं है। अब तो हमारा कोई दबाव नहीं है। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप स्वविवेक से खड़े होकर के कह दें कि अपनी भावना से, मन से कह रहे हैं कि कलक्टर यहीं रहना चाहिए, कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। सरकार ठीक कर रही है। यदि हम एक शब्द नहीं बोलेंगे और यदि आपका मन यह कहता है कि कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है तो कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी में एक्शन नहीं लेने में आप भी पार्टी होंगे You can not search the responsibility that I was not responsible as a Minister. कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी में मिस्टर गुलाब चन्द कटारिया हू प्रोफेस कि मेरे संस्कार हैं जो प्रोफेस करते हैं कि मैं संस्कार के कारण राजनीति में हूं। यदि वह टोलरेट करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह इतिहास आपको भी माफ नहीं करेगा। कटारियाजी, इसलिए मैं आशा करता हूं कि हम इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में ब्युरोक्रेसी ही काम करती है। वही आपका अंग होती है, हमारा, सब का अंग होती है। हम यह भी नहीं चाहते हैं लेकिन साइमलदेनियसली हमने इन चीजों को नहीं रोका तो हम ठीक काम नहीं करेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप खड़े होकर सदन को आश्वस्त करेंगे। जब सदन चल रहा है तो सदन की गरिमा बनी रहे, चौथे स्तंभ की गरिमा बनी रहे। राजस्थान की जनता इस बात के लिए आश्वस्त रहे कि यह सरकार इस तरह के एक्शन को पसंद नहीं करती है और लाउड लेवल पर यह मैसेज जाना चाहिए कि यदि आफिस आवर में यह काम होता है तो उसके बारे में सरकार सख्त कदम उठाती है। यह हम आपसे आशा करते हैं। आप कृपया इस पर एक्शन के संबंध में अपनी बात कहें। मैं आपसे सानुरोध निवेदन करना चाहता हूं कि फिर भावनाओं में नहीं बहें क्योंकि भावनाओं में बहने के बाद हम दो बात कहेंगे आप भावना में आयेंगे फिर आप निर्णय ले लेंगे कि मैं भावना में, दबाव में काम नहीं करता हूं। सात दिन हो गये, दबाव किसी का नहीं है। आपका स्वयं का यह जो स्टेटमेंट है कि यह पेशेवर नृत्य था, आपका स्वयं का यह कनफेक्शन है कि कलक्टर वहां मौजूद था। आप स्वयं भी डिनाई करने की स्थिति में नहीं हैं। पांच बजे बाद यह घटना नहीं हुई है। आप स्वयं डिनाई करने की स्थिति में नहीं हैं कि उस दिन छुट्टी नहीं थी। आप स्वयं डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कलक्टर की सुपरविजन नेग्लीजेंस नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यदि यह सत्य बात है तो मैं आपसे आशा करता हूं कि इस चैप्टर को अभी बंद कर दें। हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम डिबेट नहीं

(डा. सी. पी. जोशी)

करना चाहते क्योंकि चार दिन तक हाउस नहीं चला। हम एक्सट्रीम स्टैप लें, फिर आप कहेंगे कि आप हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं। हम आप पर छोड़ते हैं। आप यदि यह निर्णय कर दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पर निर्णय करें लेकिन यदि एक्शन नहीं होता है तो हमारा प्रोटेस्ट बहुत स्ट्रोंग प्रोटेस्ट होगा। फिर आप हमको मत कहना कि सदन चलाने के लिए आप बात नहीं कर रहे हैं, ठीक भी नहीं रहेगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): नहीं, नहीं जिन कर्मचारियों को आपने 16 सी सी ए के नोटिस दिए...

**श्री अध्यक्ष**: बात तो आ गई पूरी।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): जिन कर्मचारियों को इन्होंने 16 सी सी ए के नोटिस दिए, दोषी माना, कम से कम उनको सस्पैण्ड तो करो, आप तो उनको दोषी भी मान रहे हो और कार्यवाही भी नहीं कर रहे हो। ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** 16 सी सी ए का नोटिस कोई कम थोड़े होता है? ...(व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अन्य सदस्यों को बोलने का मौका दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर से सम्बन्धित मामला है, मैं दो मिनट में अपने विचार रखना चाहता हूं।

**श्री अमराराम** (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने 5 तारीख को इसी हाउस में कहा था कि 5 बजे तक यदि घटना हुई है ...(व्यवधान)।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे समय दिया है। आप तो बोलते रहते हैं। आप विराजें।

**श्री अमराराम** (धोद): मेरा तो एक ही सवाल है, उसके बाद आप बोल लेना।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है, आप इन माननीय सदस्य को बैठाएं। यह काफी डिस्टरबेंस करते रहते हैं और बार-बार बोलते रहते हैं, अन्य लोगों को बोलने का मौका देते नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): गृह मंत्रीजी ने 5 तारीख को इसी हाउस में यह

(श्री अमराराम)

स्टेटमेंट दिया था कि ऑफिस टाइम में 5 बजे तक अगर प्रोग्राम हुआ, उसमें कलक्टर शामिल हुआ है तो हम उस कलक्टर पर कार्यवाही करेंगे। मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी ने इसी हाउस में यह शब्द कहे थे, अगर उन पर वे कायम हैं तो निश्चित रूप से कलक्टर जिसने जिम्मेदार पद पर रहते हुए यह कृत्य किया है उसके लिए उनको सज़ा की यहां घोषणा करनी चाहिए, अगर वह अपने शब्दों पर कायम हैं तो। ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** बस ठीक है, अब आप पूछ लीजिए।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, होली का त्यौहार सभी दफ्तरों में मनाते हैं, सभी गली मौहल्लों में मनाते हैं। ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप बीच में क्यों खड़े हो गए? बोलने दीजिए उनको।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): यह जो होली का त्यौहार है, वह सब जगह मनता है लेकिन इसमें भी एक मर्यादा होती है और मर्यादाओं का पालन निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों को करना चाहिए। हम अपने को सभ्य समाज कहते हैं और कलेक्ट्रेट एक पावन स्थल है, निश्चित रूप से होली खेलते समय मर्यादाओं का पालन होना चाहिए, चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे वह अधिकारी हो। आखिर हर चीज की एक मर्यादा होती है और मर्यादाओं के अंदर ही हम सब काम करते हैं, सारे पर्व मनाते हैं। आजकल तो रंग फेंकने या विभिन्न प्रकार के मजाक करने को भी सभ्य समाज में ठीक नहीं माना जाता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि जिन भी कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस प्रकार का कार्यक्रम किया, मीडिया ने उसको दर्शाया, शराब बाहर पी हो लेकिन किसी कर्मचारी के हाथ में, उसकी जेब में शराब की बोतल भी पाई गई। निश्चित रूप से यह अशोभनीय कृत्य है। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से जो-जो लोग भी उसमें दोषी हैं, सरकार को उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। हमें उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए। कलक्टर वहां मौजूद थे, वह डाइरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी उनकी बनती है, सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें डिफेंड नहीं करना चाहिए और जब एक छोटे से छोटे कर्मचारी को उसकी सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी के नाम पर या कोई छोटी सी गलती के नाम पर उसको प्रताड़ित कर सकते हैं तो निश्चित रूप से बड़े से बड़े अधिकारी भी

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जिस प्रकार की सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी के लिए दोषी है, ठीक है, सीधे-सीधे उन्होंने नृत्यांगना नहीं बुलाई, कर्मचारी संघ के माध्यम से बुलाई लेकिन उनके व्यवहार से, उनके आचरण से जनता को यह मैसेज जाना चाहिए था कि जयपुर शहर के वह कलक्टर हैं, उनका आचरण एक मर्यादित आचरण है, उनका व्यवहार एक मर्यादित व्यवहार है, यह जयपुर शहर की जनता को ही नहीं बल्कि राजस्थान की जनता को भी यह मैसेज जाना चाहिए। निश्चित रूप से कोई कार्यवाही करें या न करें, इस बारे में बात नहीं है लेकिन जयपुर शहर की जनता में एक मैसेज जाना चाहिए और प्रेस ने जिस प्रकार इस कृत्य को उजागर किया है, कृत्य के बारे में जनता को जानकारी दी है उसके लिए मैं प्रेस को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ माननीय गृह मंत्री महोदय के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हो, इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि कार्यवाही करे। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (टोडारायसिंह): एक सवाल गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** बात तो पूरी आ गई, अब क्या कहना चाहते हैं?

**डा. एन. एस. गुर्जर** (टोडारायसिंह): माननीय गृह मंत्री महोदय, क्या मीडिया की तरफ से आपको कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है? यदि हां तो उस पर आपने क्या कार्यवाही की है? क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण के बारे में तो सबने बता दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता लेकिन मीडिया का फर्ज है कि किसी भी चीज की कमी को जनता तक पहुंचाए, मीडिया हमेशा जनता की आवाज हुआ करता है इसलिए मीडिया के साथ जो हुआ उस सम्बन्ध में क्या मीडिया ने आपको कोई ज्ञापन दिया है और ज्ञापन दिया है तो उसमें क्या मांग की गई है और उस पर आपने क्या कार्यवाही की है, इसकी भी सदन को जानकारी दे दें।

**श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (बल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, अब बीच में नहीं, अब नहीं, सारी बात तो आ गई।

**श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (बल्लभनगर): यह मर्यादा का पाठ पढ़ाने वालों के उस राज में भी होली आई थी और इनके गृह मंत्री के गृह जिले के

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

गृह थाने में कालबेलिया नाच हुआ था, उनको भी पैसा दिया गया था और उस सी आई को प्रमोट करके इन्होंने डीवाई एस पी बनाया। उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): कालबेलिया डांस के लिए तो मुख्य मंत्रीजी एक स्कूल खुलवा रही हैं। (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): हमने करवाया तो बंद करवाओ। ...(व्यवधान) यह आपका राज है, हमने करवाया इसलिए आप भी करवाएंगे क्या? (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): कालबेलिया नृत्य सिखाने के लिए तो आपकी सरकार स्कूल खोल रही है। यह राजस्थान की संस्कृति है। ...(व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, आप उस समय हाउस में नहीं थे। माननीय गृह मंत्रीजी हाउस में थे। उस प्रकरण में कटारियाजी ने एक घण्टा भाषण दिया। आप उनसे बात करिए, उन्होंने जो बात कही वह हमें आज भी याद है। शायद उनको याद नहीं है। ...(व्यवधान) मुझे तो याद है। आपने उस कृत्य को उस समय कंडेम किया था, आपने जब सदस्य के रूप में कंडेम किया तो एक मंत्री के रूप में आपसे अधिक अपेक्षा की जाती है।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति के अनुसार मामला नहीं है पर होली का समय है इसलिए इस बात को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। मामला गम्भीर है, कलक्टर दोषी है इसमें कोई दो राय नहीं है पर इतनी बात तो सोचे कि होली ही थी, गलती हो गई। ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस घटनाक्रम में कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की है। जैसे ही आपने विषय उठाया, मैंने दो मिनट में कहा कि संभागीय आयुक्त से जांच करवा लेते हैं। आपने जितना कहा सात दिन के समय में जांच करवाई, जांच की रिपोर्ट जो उन्होंने दी, उन सारी बातों को मैंने समाहित करते हुए आपके सामने रखीं न तो इसमें जो पेशेवर नृत्यांगनाएं आई उसको ना नहीं कहा, न मैंने कलक्टर की उपस्थिति नहीं है ऐसा भी नहीं कहा, कलक्टर की उपस्थिति वहां है, जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बात अमरारामजी ने कही, समय साढ़े चार और पांच के बीच है, निश्चित रूप से है, वह भी उसमें वेरीफाई हुआ है और जो उनकी उपस्थिति और कलेक्ट्रेट परिसर में घटना घटी है, निश्चित रूप से कलक्टर भी उसमें नेग्लीजेंसी के लिए जिम्मेदार अवश्य है, इसमें कहीं भी किसी चीज को कोई छुपाने का कारण नहीं है। जब हम कोई चीज जनता के बीच में लेकर जाना चाहते हैं तो वह ठीक ढंग से जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो यह हमारा मकसद रहा है और मैं निश्चित रूप से आपकी भावना सम्बन्धित सी एम तक पहुंचा कर जो भी कलक्टर के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है वह उसके खिलाफ भी हो, इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमती ममता शर्मा। ...(व्यवधान) डिमाण्ड शुरू, डिमाण्ड शुरू।

**श्री अमराराम** (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी की भावनाओं को तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन मुख्य मंत्रीजी ही उनको बचा रही हैं, वरना तो मैं समझता हूं कि आज 14 तारीख हो गई, जिस कलक्टर को मुख्य मंत्री बचा रही हैं, गृह मंत्रीजी की भावनाएं....

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): ऐसी बात करके आप सदन में तनाव पैदा करते हैं। कहां से मुख्य मंत्रीजी उसका बचाव कर रही हैं। मुख्य मंत्रीजी कहां बचाव कर रही हैं? आप अनावश्यक तनाव पैदा कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): गृह मंत्रीजी की भावनाओं से हम सब सहमत हैं। ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): जयपुर राजधानी है उसमें इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार भी उतनी ही दोषी है। सरकार ऐसे मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन दे रही है। ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, आप हर बात पर खड़े हो जाते हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन इस घटना के बारे में मैंने एक घण्टे भाषण दिया उस पर उस अधिकारी के खिलाफ एक रत्ती भर की कार्यवाही नहीं हुई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उल्टा उसको परमोशन दिया। मैंने कम से कम आपकी भावनाओं की इज्जत करते हुए जो भी कुछ घटना हुई, मैंने उसको किसी तरह से कम ज्यादा नहीं किया और मैंने यह भी कहा था कि अगर घटनाक्रम पांच बजे से पहले आएगा। और कलक्टर की उस परिसर में समय की सीमा में है तो निश्चित रूप से उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने यहां राजनीति खेलने का प्रयास नहीं किया, मैं आपको कहूं, लेकिन आपके दल के अध्यक्ष ने यह कहा कि हम ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** बैठे-बैठे नहीं बोलें धोद से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): मैं यहां एक घण्टे के लिए चिल्लाया था उस कालबेलिया घटना में, एक गरीब की मौत हुई, आपके गृह मंत्री होते हुए भी उसका बाल बांका नहीं किया और उसको प्रमोशन दिया। अफसोस है। ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ब्यावर में एक आदमी की झौपड़ी जल गई थी ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** अब कोई नहीं। अंकित नहीं हो।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): xxx

**श्री अध्यक्ष:** अब कोई वाद-विवाद नहीं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): xxx

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): xxx

**श्री अध्यक्ष:** कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अपनी सरकार की जन्म-पत्री पढ़ लो और अपने कारनामों को पढ़ लो और अपने द्वारा दिये हुए नियमों को पढ़ लो, अगर चाहो तो उसी बात पर बहस हो जाए कि आपने क्या किया, हमने क्या किया?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): xxx

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): इतना ईमानदारी से, आज दिन तक किसी सरकार ने ऐसा ईमानदारी से निर्णय नहीं लिया, मैं 30 साल से इस विधान सभा में हूं केवल आपके कह देने से नहीं होगा। सरकार ने कितनी सहृदयता से और आप कह रहे थे मुख्य मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जितनी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तत्परता से कार्यवाही होनी चाहिए उसी आधार पर मैंने क्या किया? क्या बात करते हो आप। कलक्टर को सीएम द्वारा ..(व्यवधान) क्या बात करते हो आप? …(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): xxx

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): चिल्लाने से नहीं होगा, आप उस समय कहां चले गये थे जब मैं एक घंटे तक चिल्लाया था। एक गरीब की बेटी की मौत हो गई थी, कोई आपका वहां नाच करने के लिए ले गया था। उस समय आपने कुछ भी कार्यवाही नहीं की, उसके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ और यहां बोलने के लिए खड़े हो जाते हो। क्या बात करते हो। हम जो बात करते हैं वह सही बात करते हैं। सही बात को गलत साबित करने की कोशिश करते हो। यह इस तरह से बोलने से नहीं होगा, कुछ आचरण भी करना सीखो। आचरण करके सीखो, फिर बोलना सीखो। आचरण तो करते हो गंदा और बोलते हो अच्छा, आदर्श की बातें करते हो ऐसा नहीं चलता है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): xxx

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): क्या कार्यवाही की है?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): xxx

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): xxx

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण कर लें। …(व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): xxx

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, जो सामने खड़े हैं ..(व्यवधान) राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ..(व्यवधान) नाम से पुकारूंगी। अब मैं नाम से पुकारूंगी। मैं आपका नाम पुकारूंगी। कृपया स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण कराओ। उप मुख्य सचेतकजी, जाओ उनके पास, उनसे स्थान ग्रहण करवाओ। स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें। …(व्यवधान) आप इतने उत्तेजित होकर और जो मर्जी आये सो बोलने लग जाते हो। यह आपकी बहुत गलत बात है। ममता शर्मा।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): xxx

**श्री अध्यक्ष:** कृपया स्थान ग्रहण करें। आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है। मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, अब आप बीच में क्यों खड़े हो गये? ममता शर्मा ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): xxx

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): xxx

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक): xxx

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): xxx

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): xxx

**श्री अध्यक्ष:** राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। ममता शर्मा।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): xxx

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमान् बंशीलालजी, मुझे आपको नाम से पुकारना पड़ रहा है। आप जानते हैं सदन का नियम, माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, इतना उत्तेजित होकर और किसी भी माननीय सदस्य को इस प्रकार से आप चाहे जो कुछ कहने लग जाते हैं। यह ठीक नहीं है, नियमों के विपरीत है, थोड़ा ध्यान रखा करें नियमों का। श्रीमती ममता शर्मा।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): xxx (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** क्या चर्चा है, इनकी क्या चर्चा है। चर्चा आपकी है, आप खामख्वाह में खडे हो जाते हो।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): xxx

**श्री अध्यक्ष:** क्या कहना चाहते हो? अंकित नहीं हो।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): xxx

**श्री अध्यक्ष:** इनके मंत्री ने कुछ भी किया होगा, यह विषय नहीं है। नहीं, गलत बात है। नो, गलत बात है। ...(व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): xxx

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): xxx

**श्री अध्यक्ष:** बैठें आप। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। नहीं, कुछ नहीं, स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें। श्रीमती ममता शर्मा।

# मांग संख्या-26 एवं 51 पर विचार

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 पर आज चर्चा चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है चिकित्सा का, सफाई और चिकित्सा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि सरकार की मंशा ऐसी लगती है कि वह बहुत ज्यादा रिफोर्म्स मेडिकल में लाना चाह रही है, ज्यादा क्रांतिकारी कदम उठाना चाह रही है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सारी कुछ थाली परोसकर एक जगह दे दी गई है। पिछले दिनों एसएमएस अस्पताल भी देखा और एसएमएस अस्पताल में करीब 200 करोड़ रुपये सरकार द्वारा दिया गया। वहां काम भी बहुत हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह तो एक सफेद हाथी है और इतना बड़ा जहाज है कि जिसमें आप जितना भी देंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पब्लिक को नहीं मिल पाएंगी उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आपका कांवटिया होस्पिटल भी है, आपका सैटेलाइट होस्पिटल भी है अगर आप इसमें स्पेशलाइजेशन करके और अलग-अलग पैसा देते हैं किसी को हार्ट होस्पिटल बना दें, किसी को न्यूरोलोजी का बना दें, जयपुर इतना बड़ा हो गया है, जैसे चंडीगढ़ में हुआ है और ऐसे ही लखनऊ, यू.पी. में किया गया है अगर इस तरह का आप करते तो शायद आम पब्लिक है, जो मीलों दूर रहती है, अजमेर रोड की तरफ इतना बढ़ गया, टोंक रोड की तरफ बढ़ गया, दिल्ली की तरफ जयपुर इतना बढ़ गया तो एसएमएस में जब वे लोग आते हैं तो आप कुछ भी कहें वे सुविधाएं आज भी नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि स्पेशलाइजेशन है ही नहीं, स्पेशलिस्ट है ही नहीं और जब तक यह नहीं होगा तब तक आपने जो पैसा दिया है मेरा मानना है कि इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर आप इस पैसे को डिवाइड करते हैं और दूसरे स्टेट्स के पैटर्न पर चलते तो शायद हमारी पब्लिक को ये सुविधाएं मिल सकती थी। जयपुर की पैराफेरी में जितने हास्पिटल हैं उनको आपको देना चाहिए था।

दूसरी बात यह है कि आज पार्किंग प्रोब्लम है, आज स्टाफ की प्रोब्लम है, बड़े हास्पिटल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टाफ की भर्ती नहीं कर रहे हैं तो जो भी आदमी आता है, अगर आप यह सोचते हैं कि यहां मध्यमवर्गीय, उच्च वर्गीय लोग आ रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है तो आप यह भूल जाएं यह बिलकुल नहीं हो रहा है। जो प्राइवेट होस्पिटल हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो पैसा अच्छी तरह दे सकते हैं वे प्राइवेट होस्पिटल में जा रहे हैं

(श्रीमती ममता शर्मा)

तो आप क्यों नहीं प्राइवेट होस्पिटल से पब्लिक रिलेशनशिप बढ़ाकर उनको अपने साथ करते, क्यों नहीं उनसे बात की जाए। जिस तरह से आंध्रा में हुआ है और जिस तरह से कर्नाटक में हुआ है, कर्नाटक भी आलरेडी कर चुका है। मेरा मानना यह है कि हमारी राज्य सरकार है, माननीय मंत्री महोदय यहां नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो कम से कम इस बात पर विचार करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। एक बात मुझे और कहनी है और यह विडम्बना ही है कि छोटे-छोटे नर्सिंग होम, जो प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, जो बहुत बड़े नहीं हैं उनको मान्यता मिल चुकी है और यह जो मान्यता मिली है, यह अहमदाबाद में मिल चुकी है, दिल्ली में मिल चुकी और दुर्भाग्य इतना जबरदस्त है कि हमारे जो एम्प्लायज हैं, जब वह बीमार होते हैं तो आप एम्स के लिए रेफर कर देते हैं, एस्कोर्ट में जब वह जाते हैं तो उनको पैसा मिल जाता है लेकिन राजस्थान में इतने बड़े हास्पिटल खुलने के बाद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वह सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है और आपके स्टेट का पैसा दूसरे स्टेट्स में जा रहा है। अगर यह सुविधाएं आप दें, जैसा उदयपुर में अमेरिकन हास्पिटल खोला है, दो साल से वह खुला हुआ है लेकिन वहां पर अगर आप यह सोचें कि यह बहुत अच्छा चल रहा है तो वह नहीं चल रहा है। हमारे जयपुर में ही एस्कोर्ट भी खोला गया, एस.के. सोनी भी है, दुर्लभजी भी है, इनमें सारी सुविधाएं हैं, बाहर से डाक्टर्स आ रहे हैं, सब हो रहा है लेकिन अगर आप सच पूछें तो इलाज कराने आज भी हमारा पेशेंट बाहर जाता है, वह इसलिए जा रहा है कि आप लोग उसको पैसा नहीं देते हैं, हमारी गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है, वह हम उनको नहीं देते यहां उनको, दिल्ली जाएंगे तो ले जाएंगे व अहमदाबाद जाएंगे तो ले जाएंगे लेकिन अगर वह जयपुर में चाह रहे हैं कि वह प्राइवेट हास्पिटल में करा लें तो वह नहीं कर पा रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हमारे जो प्राइवेट हास्पिटल्स हैं अगर उनको फैसिलिटी दी जाएगी तो मेरा मानना यह है कि हमारे जो सरकारी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो जाते हैं जिनको आप पैसा देते हैं या बी.पी.एल. हैं उनके आने जाने के खर्चे में उनमें बहुत ज्यादा बचत होगी। यह भी एक बहुत सोचने वाला मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय से कि मेडिकल पर बहुत बड़ा इनवेस्टमेंट हमने करना चाहा और किया भी और मेडिकल ट्यूरिज्म की भी हमने बात की, सारा कुछ हुआ लेकिन मंत्री

(श्रीमती ममता शर्मा)

महोदय, आप मुझे यह बताएं कि आपने आज तक इसको टैक्स फ्री किया क्या, कितने साल हो गये जो प्राइवेट हास्पिटल्स को आप ट्यूरिज्म की बात कर रहे हैं। ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और हास्पिटल को सब कुछ मिल जाए तो यह जितने भी हास्पिटल हैं इनको आपने कभी टैक्स फ्री किया है ? सच पूछिए तो यह मैं पूछना चाहती हूं कि मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर ट्यूरिस्ट को यहां कुछ मिला है या ट्यूरिस्ट जब भी कुछ होता है, जो ट्यूरिस्ट और मेडिकल दोनों और सच पूछिए तो इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है तो इसको बंद करेंगे, ये कागजी जो घोषणाएं हैं हमारी सरकार की, यह कृपया बंद करें और अगर घोषणा करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने का भी पूरा-पूरा प्रयास करें। तभी हमें कुछ मिल पाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो संविदा पर लगे हुए कर्मचारी हैं वह करीब 115 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपके पास लिखित में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह संविदा पर हैं, सह कांट्रेक्ट पर हैं, किस बेसिस पर हैं और जो कांट्रेक्ट बेसिस पर होता है उनका ट्रांसफर नहीं होता लेकिन उनके लगातार ट्रांसफर भी हो रहे हैं तो आखिर राज्य सरकार क्या चाहती है ? कल से वह भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं और स्टेट मिनिस्टर माननीय जोशी साहब भी है, कम से कम कोई आदमी आपका जाकर उनकी बात तो करे और यह तो पूछे कि आपके हाल क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, उनको आपने नोटिस दे दिया 31 मार्च को आप सब को हटा दिया जाएगा। और आप यहां बजट में घोषणाएं ये कर रहे हैं, हम नये कर्मचारी रखेंगे, नये नर्सिंग स्टाफ रखें, आखिर जो हैं उनका क्या है ? सात साल से वह आपके पास काम कर रहे हैं, सात साल से सरकार को सेवाएं दे रहे हैं तो कम से कम ...(व्यवधान) आप कृपया आपके बाहर की बात है इसलिए थोड़ा सा बैठ जाइए।

**श्री अध्यक्ष:** आप संविदा को छोड़ कर अपने कट-मोशन पर आइए।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): तो मैं यह कहना चाह रही हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई गलत नहीं है, इसमें महिलाएं और पुरूष दोनों हैं, जो 115 कर्मचारी छोटे-छोटे बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर तो मैं इतना कहना चाह रही हूं कि उन्हें कोई जाकर उनको किस बेसिस पर आप निकाल रहे हैं 31 मार्च को जो नोटिस दिया है, कम से कम उनको यह तो कहें और आप नई घोषणाएं करते जा रहे हैं कि हम और ले रहे हैं।

(श्रीमती ममता शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, मेरे बूंदी की भी बात करना चाहूंगी कि बूंदी हास्पिटल जिला हैड क्वार्टर का एक बहुत बड़ा हास्पिटल है और चूंकि बूंदी नेशनल हाई-वे 12 पर है और ट्यूरिस्ट बहुत ज्यादा आता है वहां लेकिन जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है उसको कोटा रेफर किया जाता है या जयपुर रेफर किया जाता है तो ट्रोमा यूनिट नहीं होने की वजह से, कोई हार्ट यूनिट नहीं होने की वजह से वहां प्रोब्लम यह होती है, पेशेंट या तो कोटा जाते-जाते दम तोड़ देता है या जयपुर आते-आते दम तोड़ देता है तो हम एक तरफ ट्यूरिज्म की बात कर रहे हैं, अब रोज एक्सीडेंट होते हैं, मेरे ख्याल से आल्टरनेटिव डे एक न एक एक्सीडेंट जरूर होता है और जब हड्डी टूट जाती है या ब्रेन एंजरी होती है तो पेशेंट को दम ही तोड़ना होता है, कोई मुश्किल से 10 परसेंट केसेज ऐसे होते होंगे जो सरवाइव कर पाते हैं तो माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी कि स्टाफ की कमियां, इतनी स्टाफ की कमी है, जहां 37 लोगों का होना चाहिए वहां केवल इस वक्त 22 लोगों का स्टाफ बूंदी में काम कर रहा है। दूसरी बात गाइनोकोलोजिस्ट नहीं है, कितने महीने से नहीं हैं, हमने अवगत कराया, नैनवां में तो पता नहीं कितने सालों से नहीं हैं, बूंदी जिला का जो नैनवां है वहां तो पता नहीं कितने सालों से गाइनोकोलोजिस्ट नहीं है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इन छोटी-छोटी बातों पर वह जरूर ध्यान दें और सफाई का जहां तक सवाल है।

**श्री अध्यक्ष:** आप इतना ध्यान दिला रही हैं, मंत्रीजी तो हैं ही नहीं। ...(व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): दूसरे मंत्रीजी बैठे हुए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और मंत्रीजी से कहना है लेकिन कहना तो आपके माध्यम से ही है। हास्पिटल की सफाई की जो हालत है वह इतनी खराब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। माननीय मंत्री महोदय एक बार खुद जाकर उसका अवलोकन करें तो उनको पता लगेगा कि चारों तरफ गंदगी है और हम बहुत प्रयास भी करते हैं और एनजीओ के जरिए ही प्रयास करते हैं, सब करते हैं लेकिन बावजूद उसके आपके जो स्टाफ की लापरवाहियां हैं, खास तौर से जनाना हास्पिटल की अगर आप हालत देख लें तो उन महिलाओं पर दया आती है। आसपास कोई बाउण्डरी नहीं होने की वजह से एक दो बार तो ऐसे केसेज भी हुए हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं, न्यू बोर्न बेबी, उनको सूअर घसीट कर ले गये। इससे बड़ी और क्या बात होगी ? तो मैं यह चाहती हूं कि हास्पिटल को ए-ग्रेड अगर

आप बनाते हैं तो उसमें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और नेशनल हाई-वे 12 पर हैं और गांवों की जो दशा है, गांवों में भी मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी तरह से गांवों में डाक्टर्स और नर्सेज स्टाफ पूरा करिए क्योंकि गांवों में मृत्यु हो जाती है लोगों को पता ही नहीं चलता है, बेचारे किस तकलीफ में लोग मर रहे हैं तो हमारी संवेदनशीलता की बात करने वाली सरकार को मैं इतना सा निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि इसमें भी पूरा-पूरा ध्यान दें।

दूसरी जो मांग संख्या-51 है उसमें एस.सी. के लिए, भगवा कपड़े पहनते हैं मंत्री महोदय तो भगवा रंग छोड़कर थोड़ा सा एस.सी. की तरफ भी देखें आप। बहुत बुरे हालात हैं एस.सी. हास्टल्स के ।

**श्री अध्यक्ष:** भगवा कहां पहन रखें हैं, उन्होंने तो पिंक पहन रखे हैं।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा दुर्भाग्य मान लीजिए कि वह केसरिया कपड़ों में नहीं आए हैं।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भगवा कपड़ों से क्या है ? समाज कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जा सकता ?

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): बाकी तो वह रोज केसरिया में ही आते हैं।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसमें कपड़ों का क्या लेना देना है? ...(व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): और एस.सी. के छात्रावासों में छात्रवृत्ति पूरी नहीं मिल रही है।

**श्री अध्यक्ष:** आप कपड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया करें।

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): ये मेरी दादी मां हैं, मेरा सारा ध्यान रखती हैं।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): उसका कारण मैं यह बता दूं यह दादी मां इसलिए कहते हैं कि या तो आप बाल रंग लो नहीं तो मैं दादी मां कहूंगा।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, महिलाएं कपड़ों का ध्यान नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा ध्यान ? बताइए।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): मैंने कहा कि दादी मां नहीं, आप परदादी मां कहो। ...(व्यवधान) लेकिन बाल नहीं रंगूंगी। ...(व्यवधान)

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): ये इनकी पसंद के कपड़े पहनें ? ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** तीन दिन में टेंशन के वातावरण के बाद आज सदन में बहुत अच्छा वातावरण है।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): तो मंत्री महोदय, जो आपके छात्रावास हैं एस.सी. के हम चाहते हैं उनको आप हैड क्वार्टर्स पर कम से कम भवन तो दें, वह जब कि किराये पर चल रहे हैं और उनके बच्चों की भी इतनी बुरी हालत है तो उन बच्चों पर भी दया करें और बड़े-बड़े जो कस्बे हैं उनमें भी हमने जो दो कस्बों में बड़े-बड़े भवन बनाये थे उसके बाद आपने एक भी स्वीकृति नहीं दी तो मैं चाहता हूं कि एक दो स्वीकृतियां आपकी तरफ से आएं और खास तौर पर बूंदी शहर के लिए एक तो छात्रावास होना चाहिए क्योंकि अब जो जागृति आ रही है, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से या प्रेस मीडिया के माध्यम से तो बहुत ज्यादा लोगों में छोटे बच्चों में बहुत जागृति है और वह यह चाहते हैं कि हम पढ़ें लेकिन उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाने की वजह से इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा सा इसमें करें। जहां तक थोड़े बहुत भ्रष्टाचार की बात है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जरूर कहूंगी कि नर्सिंग स्टाफ पर जरूर आप रोक लगायें। डाक्टर्स पर भी लगायें, नर्सिंग स्टाफ पर भी लगायें क्योंकि कई बार ऐसे फोन आते हैं कि साहब, पैसे नहीं दे रहे हैं इसलिए हमको ऑपरेशन टेबल पर नहीं ले रहे हैं। कई बार ऐसे फोन आते हैं कि हास्पिटल का टाइम है लेकिन डाक्टर्स हास्पिटल में नहीं हैं और घर पर प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं। जब हम उनसे कहते हैं, ट्रांसफर की बात करते हैं, कुछ करते हैं तो वो रिजाइन करने को तैयार रहते हैं क्योंकि 4-4 मंजिल के हास्पिटल आलरेडी वो अपने बना चुके हैं। जिस सड़क पर हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य रहते हैं उसी सड़क पर करीब तीन हास्पिटल बड़े-बड़े बन चुके हैं 4-4, 5-5 मंजिल के। स्वायत्त शासन मंत्री महोदय नहीं हैं, इनसे भी पूछिये कि जिलों में भी बड़े-बड़े शहर जो हैं उनमें भी इजाजत लेने का तो कीजिये कि जिस तरह जे. डी. ए. से इजाजत ली जाती है उस तरह नगरपालिका से इजाजत लें कि कितनी मंजिल का भवन कितनी जमीन पर बन सकता है। ये सब बातें सोचने वाली

(श्रीमती ममता शर्मा)

हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा राजस्थान का ढांचा बदल दिया जाए तो वह तभी बदलेगा कि डाक्टर्स पर पूरी-पूरी लगाम आप लगाइये। टाइम पर नहीं जाते हैं, कई बार पेशेंट को बहुत ज्यादा इल-ट्रीट करते हैं। तो ये सब बातें हैं इन पर आप जरूर ध्यान देंगे। माननीय मंत्री महोदय को मेरे ख्याल से प्रोसीडिंग में मिल जाएगा कि मैंने 'अ' श्रेणी अस्पताल की डिमांड की है। मैं आपको पूरा धन्यवाद करूंगी, आप यह मत समझियेगा कि मैं सदन में धन्यवाद करने से चूकूंगी, मैं इसलिए नहीं चूकूंगी कि जो अच्छा काम करता है उसको अच्छे काम के लिए धन्यवाद जरूर देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप पूरे बूंदी हास्पिटल के लिए पूरे-पूरे संवेदनशील रहेंगे। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

**श्री अध्यक्ष:** थैंक्यू। श्री शिवजीराम मीणा (एबसेंट) श्री धर्मेन्द्र मोची।

**श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी के कुशल प्रबन्धन के कारण प्रदेश स्वास्थ्य में अग्रणी स्थान ले रहा है इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। जो बजट में मुख्य मंत्रीजी ने ग्रामीण क्षेत्र में ए एन एम के साथ-साथ एक अतिरिक्त ए एन एम और जी एन एम की घोषणा की है, मैं समझूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में उससे चिकित्सा का सुधार होगा।

इसके साथ-साथ ग्रामीण स्वास्थ्य चेतना यात्रा का आयोजन भी हुआ और 9250 कैम्प लगे तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों में खूब लाभ मिला और मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में भी ऐसे कैम्पों का आयोजन हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ मिले। सामुदायिक अस्पतालों में एम्बुलेंस की घोषणा, दूर-दराज के क्षेत्रों में निश्चित टाइम पर मोबाइल टीम की घोषणा के लिए भी मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका खूब लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के रावतसर कस्बे में सामुदायिक हास्पिटल है और एक बहुत बड़ा हास्पिटल है। इसके 100 ग्राम लगते हैं और दूर-दराज का एरिया भी इस क्षेत्र में आता है, यह मेगा हाइवे पर है तो इसको रेफरल हास्पिटल बना दिया जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को खूब लाभ मिलेगा।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

रावतसर एस डी एम हैडक्वार्टर है, नगरपालिका क्षेत्र है तो इसको रेफरल हास्पिटल बनाने की मांग करता हूं।

इसके साथ-साथ टिब्बी कस्बे में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। टिब्बी एस डी एम हैडक्वार्टर है, तहसील क्षेत्र है, 30 पंचायतें लगती हैं। दूर-दराज के एरिया के अन्दर दिक्कत आती है क्योंकि मात्र एक डाक्टर है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि टिब्बी हास्पिटल को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की स्वास्थ्य मंत्रीजी कृपा करें। इसके साथ-साथ तलवाड़ा, थालरका बड़े ग्राम हैं वहां मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की मांग करूंगा।

इसके साथ-साथ रावतसर में 30 लाख रुपये की लागत से एक बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग की बेकार पड़ी है तो मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि उस बिल्डिंग का उपयोग भी हो जाए और वहां पर आयुर्वेदिक हास्पिटल भी खुल जाए।

इसके साथ-साथ जिला हास्पिटल में सी टी स्केन की व्यवस्था नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक जिले के लिए आपने घोषणा भी की है तो हनुमानगढ़ जिले में भी सी टी स्केन की व्यवस्था हो। इसके साथ-साथ गंधेली ग्राम में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काफी दिनों से बिल्डिंग रहित पड़ा है और जगह-जगह इधर-उधर लगवा रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसकी बिल्डिंग के लिए पैसा उपलब्ध करायें। आपने 33 लाख रुपये रावतसर हास्पिटल के लिए दिये उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपने ही अपने पिछले कार्यकाल में टोपरिया में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिया, उसकी बिल्डिंग दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रावतसर के अन्दर एक्स-रे मशीन भी स्वीकृत पड़ी है, अभी तक नहीं लगी है वह लगवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष:** वैरी गुड। बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री लालचन्द मेघवाल।

**श्री लालचन्द मेघवाल** (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि आज से तीन वर्ष पूर्व प्रदेश में ओजस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने पद ग्रहण किया और तब से जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं, मैं कहना चाहूंगा कि

(श्री लालचन्द मेघवाल)

माननीय मंत्री महोदय, समय-समय पर जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में जन स्वास्थ्य चेतना यात्रा के माध्यम से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तो अगर हम उन केन्द्रों पर किस तरह एक उप स्वास्थ्य केन्द्र पर एक ए एन एम की पोस्ट होती है, अभी मुख्य मंत्री महोदया ने बजट के माध्यम से एक जी एन एम की पोस्ट और स्वीकृत की है। जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र को सुदृढ़ नहीं करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में नहीं देखेंगे तब तक इस देश का उद्धार नहीं होने वाला है क्योंकि आजकल हर व्यक्ति सोचता है कि मैं शहर में जाऊं, अच्छे डाक्टर के पास जाऊं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। 75 प्रतिशत पापुलेशन जहां ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी जो बिलकुल हिन्दुस्तान के डैड-लाइन पर है, पाकिस्तान से लगती हुई सीमा के पास है रायसिंहनगर क्षेत्र। रायसिंहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है और वहां जो डाक्टर्स की स्थिति है, मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि अब जो डाक्टरों की स्थिति है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनिक स्पेशलिस्ट, सर्जरी, मेडिसन, ये सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। आप समय-समय पर इस तरह की व्यवस्था करें ताकि जो बोर्डर के नजदीक ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र हैं उन हास्पिटल्स में डाक्टर्स की व्यवस्था रहे।

इसके साथ-साथ मैं विशेष तौर से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि अभी आपने मेरे रायसिंहनगर हास्पिटल के पुनर्निर्माण के लिए करीब 97 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं और पूरा हास्पिटल डिसमेंटल होकर नया बनेगा। मैं उसके लिए माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत शुक्र-गुजार हूं। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र के अन्दर कंवरपुरा है, खिंचिया है, 67 एनपी है, समरेजा है, मालसर है, भोमपुरा, रामजीवाला, इन सभी क्षेत्रों में ए एन एम की पोस्टें खाली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एक ए एन एम की पोस्ट होती है वह भी खाली होगी तो आमजन क्या सोचेगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरह उप खण्ड स्तर पर पांच मेल नर्स की पोस्टें खाली पड़ी हैं और जिस तरह लैब टेक्नीशियन की पोस्टें गंगवाला ग्रामीण, समरेजा, लक्खा, इस तरह के ग्रामीण क्षेत्र में जो पोस्टें रिक्त पड़ी हैं चाहे वह किसी भी कैडर की पोस्ट है, आप निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था करें कि जब भी आप नये डाक्टर्स की नियुक्ति करें तो उनको ग्रामीण

(श्री लालचन्द मेघवाल)

क्षेत्र में लगायें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वह वास्तविक रूप से मिले।

इसके साथ-साथ मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि मेरे क्षेत्र में विशेष तौर से इन्होंने 97 लाख का एक बहुत बड़ा समाज कल्याण का हास्टल था उसकी बिल्डिंग के लिए पैसे दिये। हमने जगह उपलब्ध करा दी, इन्होंने बिल्डिंग के लिए पैसे दिये। मैं इनका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। विशेष तौर से मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह समाज कल्याण विभाग में अभी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं और जिस तरह प्रति बच्चे पर जो पैसे दे रहे हैं अगर उनको हजार रुपये तक कर दें तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा में अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वास्तव में शिक्षित करना चाहते हैं तथा हम अपने दायित्व को निभाना चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि विशेष रूप से जहां बालिका विद्यालय है और जहां आवासीय विद्यालय है और जहां बालिकाओं के होस्टल्स हैं, उनमें भी आप बिल्डिंग के पैसे दें, बिल्डिंग बनायें सरकारी ताकि हमारा प्रदेश विकसित हो और प्रदेश विकसित तभी हो सकता है जब शिक्षा जिस प्रदेश में अग्रणी होगी, तभी प्रदेश का विकास सम्भव हो पायेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने पूरे प्रदेश में जहां भी जो जिस चीज की जरूरत है, चाहे मेडिकल के मामले को ले लें, चाहे एजुकेशन का मामला हो, जहां जिस चीज की जरूरत है, टीचर्स की हो तो निश्चित रूप से समय-समय पर पूरा करते हैं, ऐसी मेरी धारणा है। इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि हमारे इस गंगानगर जिले में, जो इसी बजट में, जो विशेष रूप से गंगानगर जिले का जो शुगर मिल का मुख्य मुद्दा था और जो शुगर मिल बाहर स्थापित करने की बात कही, विशेष रूप से गंगानगर जिले के हालात ऐसे थे अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति रात को सोता था तो सुबह जब वह उठता था तो दो-दो इंच तक उस पर राख जम जाती थी, तो बड़ी दिक्कत थी तो उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं मुख्य मंत्री महोदय का, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई एवं मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना के माननीय मंत्रीगणों के रिप्लाई तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

**श्री अध्यक्ष:** पारित तो आप 12 बजे तक कराओगे। कोई समय तो निश्चित होना चाहिए। 8-9 बजे, कुछ तो करो। आप तो ऐसे 12 बजे तक कर दोगे। (व्यवधान) पहले आप 7-8 बजे, कोई समय तो करो।

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना सम्भव होगा क्योंकि तीन दिन की छुट्टी है, जितना सम्भव होगा, जल्दी करवा देंगे। (व्यवधान) रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना। जितना जल्दी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई तक तो बढ़ाना ही पड़ेगा। जितना जल्दी होगा, करवा देंगे।

**श्री अध्यक्ष:** आप 7-8 बजे, जो कुछ चाहो, समय बढ़ाओ। फिर देख लेना।

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 बजे तक के लिए समय बढ़ाया जाये।

**श्री अध्यक्ष:** क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाये?

**(स्वीकृत)**

7 बजे तक समय बढ़ाया गया।

श्रीमती प्रतिभा सिंह।

# मांग संख्या-26 एवं 51 पर विचार

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे वक्त दिया।

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, आवश्यकता नहीं है धन्यवाद की, यह आपका राइट है। It is your right.

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): मैं अनुपस्थित थी उस समय, दुबारा

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूं। (व्यवधान) मैं मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर अपने विचार रखना चाहूंगी कि स्वास्थ्य को डब्ल्यू.एच.ओ. में इस तरह से परिभाषित किया है कि - "A state of complete physical, mental and social well being, and not merely an absence of disease or infirmity." यानी कि किसी भी राष्ट्र या राज्य के लोगों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सुधार के साथ ही बीमारियों की समाप्ति हेतु पूर्व सुधार करना चाहिए, यह एक मुख्य बात है। इसके लिए सामान्य विज्ञान वह है, जो बीमारियों के होने से पहले उसकी रोकथाम करे जबकि हम तब जागते हैं जब बीमारियां महामारी बन जाती हैं। इसको प्रिवेंटिक एंड सोशल-मेडिकल इपेटोमोलोजी कहते हैं, सरकार इस तरह कोई ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड स्टडी है, जो कि स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करना सिखाती है। महामारी जैसे येलो फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया और काफी अन्य हैं। ये महामारियां हर वर्ष फैलती हैं किन्तु उनकी रोकथाम के लिए चरणबद्ध योजना हमारी सरकार कभी भी हाथ में नहीं लेती है। जब यह एक महामारी, बहुत भयंकर समस्या बन जाती है, तब इस ओर हम कंट्रोल करने की तरफ अपने कदम रखते हैं। सरकार रथयात्राओं का तो आयोजन करती है, अभी किया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकिन जो अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनको अपनाकर रचनात्मक कार्य नहीं कर रही है ठोस, जिनके दूरगामी असर हो आने वाली पीढियों पर भी। जहां हमें जनसंख्या के नियंत्रण का काम सबसे पहले हाथ में लेना चाहिए। हमारी सारी योजनाएं वहां आकर फेल हो जाती हैं और रथयात्राओं के कैम्प हमने लगाये, उनकी जगह हम लोगों के अन्दर ऐसे कैम्प लगाते कि जो way of living हमें बताते और यह बताते कि हमें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार का फूड लेना चाहिए ताकि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें। डम्पिंग एरिया, कैचमेंट एरिया शहर और गांव से बाहर हो ताकि मच्छर नहीं पनपें और साथ ही जिस समय इनके लार्वा उत्पन्न हों, तभी फोगिंग करवाई जानी चाहिए टाइमली ताकि हम लोक स्वास्थ्य को बचा सकें, समय पर कारगर योजना बनाकर जन-धन हानि को काफी हद तक बचाया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी कि जेनेरिक आधार पर औषधियां लिखने की घोषणा अभी तक हमारे यहां कोरी कागजी रही हैं क्योंकि इनके मोनेटरिंग की कोई पर्याप्त व्यवस्था

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

हमारे सिस्टम के अन्दर नहीं हैं। जो भी दवाई डाक्टर पर्ची पर लिखता है, उसका इन्द्राज आउटडोर रजिस्टर में भी हो और उच्चाधिकारी के द्वारा पूरे राज्य के अन्दर, स्टेट के अन्दर समय-समय पर आउटडोर रजिस्टर की जांच की जाये ताकि जो डाक्टर्स जेनेरिक के अलावा अन्य दवाइयां लिखते हैं, उन पर कठोर कार्यवाहियां होनी चाहिए क्योंकि जेनेरिक आधार पर हम जब औषधि लिखते हैं तो उनकी कीमत आलमोस्ट 40 प्रतिशत कम आ जाती है इसलिए आम आदमी को, गरीब आदमी को इसकी सुविधा मिले, उसको लाभ पहुंचे, इसके लिए यह जेनेरिक औषधि लिखने के हमारे मोनेटरिंग सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथन करना चाहिए।

दूसरी चीज, मैं मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ जो मुख्यालय पर पदस्थापित है या गांव में है, वह वहां पर निवास नहीं करते हैं। इस कारण रोगी मजबूर होकर चाहे वह बड़ा शहर हो चाहे वह गांव हों, कस्बे हों, उनको प्राइवेट डाक्टर्स जो प्रेक्टिस करते हैं, उनके यहां पर मजबूर होकर जाना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी मंत्रीजी, हमें कन्या भ्रूण हत्या को भी रोका जाना चाहिए। नहीं तो आने वाले समाज में, आने वाले वक्त में हमारे यहां पर बहुत बड़ी सोशल प्रोब्लम होने वाली है कि लड़कों का जो जेण्डरवाइज हमारा रेशो कम आ रहा है कि लड़कों को विवाह के लिए पर्याप्त लड़कियां ही उपलब्ध नहीं होंगी तो समाज के अन्दर एक तरह से क्लेश उत्पन्न होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगी। नवलगढ़ क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोठड़ा एक ऐसी जगह है जहां पर डाक्टर का पद पिछले 4-5 महीनों से खाली पड़ा हुआ है और वहां अभी तक डाक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवलगढ़ की स्थिति भी बहुत दयनीय है। डाक्टर के बैठने की वहां पर कोई प्रोपर व्यवस्था नहीं है तो जब डाक्टर्स के लिए ही नहीं है तो रोगियों की तो आप छोड़िये। वहां बजट मिल चुका है लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है इसलिए उस अस्पताल को स्ट्रेंथन करने के लिए भी आप थोड़ा मंत्री महोदय से निवेदन है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जमीन की व्यवस्था आप करवा देंगे?

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): वह है नहीं टाउनशिप के अन्दर तो कहां करें। उसको डबल स्टोरी की मंजूरी दे दें आप वहां सिटी में तो जमीन के अभाव में वह हो नहीं पा रहा है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगी कि नवलगढ़ क्षेत्र के ग्राम कोलसिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम चारण की ढाणी, धायलों का बास, नेहरा की ढाणी, तुर्काणी ढाणी जोहड़ी, मिल नगर और ढूढियों के बास, मिठारवालों की ढाणी, पूनियों की ढाणी, खरीतों की ढाणी काफी दूर-दूर तक है और इसमें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, अतः यहां उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करें। एक जो हमारे बीपीएल की दवाइयां जाती हैं या और जो अन्य सरकारी दवाइयां जाती हैं उनमें जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है वह इतना, हमने अब भ्रष्टाचार को, समाज ने एक तरह से स्वीकार्य कर लिया है कि यह चीज तो असेंसियल है, यह तो जानी ही नहीं है। जैसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, किस तरह से भ्रष्टाचार हमारे समाज में स्थापित हुआ है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले किसी के यहां रिश्वत का रुपया आता था और उससे कोई चीज खरीद ली थी तो समाज में छिपाते थे कि भाई यह अलग से कहां से इनकम आई और दिखाने से डरते थे। आज लड़की का संबंध करते हैं और पूछते हैं कि लड़की का संबंध कहां करा, लड़का क्या कर रहा है तो कहते हैं कि फलां नौकरी में है, लेकिन नहीं-नहीं, वह तनख्वाह पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं, तनख्वाह नहीं, ऊपर की इनकम बहुत ज्यादा है। तो जब हम बेटी को, लड़की को भ्रष्टाचारी को देने से नहीं चूक रहे हैं तो इस तरीके से धीरे-धीरे समाज के अंदर भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, इस चीज को भी हमें देखना होगा। और एलोपैथी के साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय, हमें आयुर्वेद व यूनानी जो पद्धतियां हैं हमारी, उनका प्रचार-प्रसार भी करना चाहिए ताकि उनका भी लोगों को लाभ मिल सके। अब मैं माननीय मंत्री महोदय का संविदा के कर्मचारियों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि संविदा पर काफी संख्या में चिकित्साकर्मी कार्यरत हैं, इनकी नियुक्ति भी नियमित कर्मचारियों की जो प्रणाली है, जो एक सिस्टेमेटिक मेथड है उसी तरीके से हुई थी और जब इनको संविदा पर रखा तो इनके साथ कोई रिटन कांट्रेक्ट नहीं हुआ सरकार के पास और यह बराबर नियमित कर्मचारियों की तरह ही पिछले काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं, इनका स्थानांतरण इनके इच्छित स्थानों पर हम नहीं कर रहे हैं

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

और इन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे प्रसूति अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, चिकित्सा अवकाश आदि से वंचित किया जा रहा है जो मैं सोचती हूं कि सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, उसके प्रतिकूल है और राज्य सरकार यदि इनको नियमित करती है तो किसी प्रकार का वित्तीय भार भी सरकार पर नहीं आने वाला है क्योंकि यह जो संविदा पर कर्मचारी हैं इनकी वेतनवृद्धि हर वर्ष टेन परसेंट तो आटोमेटिकली हो रही है और ज्यादातर जो कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन ले रहे हैं और अपनी सेवाएं भी यह निष्ठापूर्वक दे रहे हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इनको नियमित करें, स्थानांतरण की सुविधा दें और जो एक जनरल सोसियल साइंस का जो नियम है, सामाजिक न्याय, उसके तहत इन्हें भी सुविधाएं प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु जो है उस पर अपने विचार रखना चाहूंगी कि हिन्दुस्तान के संविधान में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्यायिक, विचारों की स्वतंत्रता, आस्था, विश्वास, पूजा, अवसर की समानता के अधिकार दिये गये हैं। आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य में जो कमजोर वर्ग विशेषकर एससी और एसटी के लोगों की विशेष देखभाल करे, यह राज्यों का और राष्ट्र का कर्तव्य है और उनकी शिक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयास करने का कार्य राष्ट्र का और राज्य का आवश्यक रूप से है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 274, विशेष राशि की व्यवस्था केन्द्र और राज्यों के द्वारा की जाती है ताकि एससी.एसटी. वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाई जाएं। सरकार को चाहिए कि एससी और एसटी के कल्याण हेतु एक एडवाइजरी कौंसिल का गठन करे ताकि हम खाली दिखाने के लिए नहीं, निष्ठापूर्वक इन लोगों के लिए कार्य कर सकें। अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए कौन सी नई योजनाएं वह ला रही है जो इनके कल्याण के लिए प्रभावी हों। बीपीएल परिवारों के लिए, मैं एक विसंगति की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि बीपीएल परिवारों के लिए एसजीआरवाई की जो योजना है उसमें लाभ दिया जाता है और शर्त यह लगाते हैं कि उसके पास जमीन नहीं हो और दूसरी ओर व्यक्तिगत लाभ देने हेतु जब हम किसी बीपीएल परिवार के व्यक्ति को चयनित करते हैं कुआ गहरा कराने के लिए, तो

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि उसके पास जमीन नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कुआ काहे पर बनायेगा, जमीन पर ही बनायेगा, तो इस तरीके की जो विसंगतियां हमारे सिस्टम में है उसको हमें दूर करना चाहिए और इस बीपीएल की जो यह चीज है इसको पुनः परिभाषित करके करना चाहिए ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को लाभ मिले, इस हेतु हमें बीपीएल की सीलिंग को भी हटाना चाहिए कि भाई, इन्हीं लोगों को मिलेगा, बहुत से ऐसे लोग उसके अबोव रह जाते हैं जो वंचित रह जाते हैं और वह कमजोर आय वर्ग के व्यक्ति होते हैं। केन्द्र सरकार से अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशेष संगठक योजना है, जो बजट आबंटित किया जाता है हर राज्य सरकार को, वह राज्य सरकार द्वारा विभागों में जब....

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्या, पन्द्रह मिनट हो गये, अब कृपया आप कनक्लूड करें।

**श्रीमती प्रतिभा सिंह:** अध्यक्ष महोदय, दो मिनट, मैं बस कन्क्लूड ही कर रही हूं। वह राज्य सरकार द्वारा विभागों में जब आबंटित किया जाता है तब यह स्पष्ट आदेश नहीं होते हैं और इन नियमों की भी पालना नहीं होती कि योजना में प्राप्त यह राशि अनुसूचित जाति के लोगों को ही मिल रही है या अन्य लोगों को, यह सुनिश्चित नहीं है। जैसे हास्पीटल्स में है या पशुओं के हास्पीटल्स में है, जो बजट हम देते हैं, एक तो वह एससी.एसटी. के लोगों को ही मिले, ऐसा उसके अंदर क्लियर नहीं होता है तो इस ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। इन योजनाओं में रुपया सही खर्च हो, सदुपयोग हो तो इसके लिए कड़ाई से हमें इनकी मानीटरिंग करनी चाहिए, जितनी भी सरकारी योजनाएं ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही हैं उनमें एससी. और एसटी. के व्यक्तियों को लाभ मिले और रोजगार भी मिले, उनको इकोनोमिकली इन्डिपेंडेंस मिलनी बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि जिस क्षेत्र में हमें बहुत विशेष जरूरत है वह एससी और एसटी की महिलाओं की स्थिति है, वह वाकई में ही बहुत, वैसे तो पचास प्रतिशत महिलाओं की ओवरआल चाहे वह ओबीसी हो, मुसलिम हो या जनरल हो, सभी की दयनीय है लेकिन उसमें एससी और एसटी की तो जो है वह करेला और नीम चढ़ा हम कह सकते हैं, उन हेतु हमें विशेष प्रोग्राम्स बनाने चाहिए और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी मंत्री महोदय कि आप हर

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

डिपार्टमेंट में महिलाओं के लिए जेन्डर बजटिंग रखें और उस बजट को ईयरमार्क भी करें ताकि साल के अंदर हमें यह कनक्लूजन आ जाये कि महिलाओं के लिए कितना पैसा खर्च हुआ है और उसका सम्पूर्ण लाभ उन लोगों को मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे वक्त दिया, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** धन्यवाद आपको बहुत-बहुत। श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल। (व्यवधान) अब बैठी नहीं बोलेंगी आप, प्लीज। बैठी हुई नहीं बोलेंगी, बोल लिया काफी, सतरह मिनट बोल लीं।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या-26 चिकित्सा और लोक कल्याण और सफाई और मांग संख्या- 51 अनुसूचित जाति के कल्याण...

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठे-बैठे इतने जोर से न बोलें कि मैं भी डिस्टर्ब होऊं, वह भी डिस्टर्ब हों।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल:** हेतु विशिष्ठ संघटक योजना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान में वसुंधराजी ने राज सम्भाला था उस समय के पीरियड को और आज के समय को तीन वर्ष हो गये हैं, उन्होंने बारी-दर-बारी पहला बजट, दूसरा बजट, तीसरा बजट और चौथा बजट, इस प्रकार से बजट के माध्यम से उन्होंने एक पूरे राजस्थान को अच्छा करने को जो घोषणाएं बजट के माध्यम से पेश कीं, उसके अनुरूप काम हुआ। विपक्षी माननीय सदस्य जिनको सिर्फ विपक्ष में बोलना है उनकी नजरों में यह कागजों का पुलिंदा होगा मगर जो आज यह बजट मेरे सामने पडा है, चौथा बजट, इसमें भी कई अच्छी घोषणाएं हुई हैं और लास्ट में 82 पेज पर 188 का कालम हैं, ममताजी, सुनते जाइये।

आपने कहा कि ये कागजों का पुलिंदा है, हमारी वसुंधराजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैंने जो घोषणाएं की हैं ये केवल मात्र घोषणाएं नहीं हैं, इसके लिए मैंने अलग से प्रावधान कर लिए हैं और इसके लिए विशेष रूप से रखा है। इसका गवाह है पूरा राजस्थान, पूरे राजस्थान से आने वाले हम सभी विधायक, हम विधायकों के क्षेत्र में होने वाले काम, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लें, शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, चाहे सड़कों के क्षेत्र में देख लें, चाहे कोई भी आप सबजेक्ट उठा के देख लें, कोई क्षेत्र उठा के देख लें, आज ग्रामीण इलाकों में

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

वास्तविक रूप से विकास के मायने लोगों को समझ में आये हैं, वास्तविक रूप से इस सरकार को इस सत्ता में लाने के जो मायने थे वह समझ में आये हैं और सरकार को सभी धन्यवाद दे रहे हैं। बजट पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की क्योंकि बजट पर इनके पास बोलने को कुछ था ही नहीं, इतना अच्छा बजट पेश किया और चिकित्सा के मामले में मैं बताना चाहूंगी कि अभी कुछ दिनों पहले अप्रेल में बाढ़ आई थी उस समय भी सरकार की तरफ से इतने अच्छे और पुख्ता प्रबंध हुए थे, बाढ़ के समय पर जो चिकनगुनिया और जिस प्रकार की बाढ़जनित और वर्षाजनित बीमारियां हुई उसमें भी सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ में और चिकित्सा विभाग ने बहुत अच्छे तरीके से अपना सहयोग दिया और उसमें चाहे कोई भी जिला देख लो वहां पर सब जगह दवाइयों की व्यवस्था की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी वसुंधराजी को क्योंकि गांव में इसके लिए सभी धन्यवाद दे रहे हैं। जस्ट उसके बाद में, चिकित्सा स्वास्थ्य चेतना यात्रा चली, स्वास्थ्य चेतना यात्रा का वह समय भी सही चुना। जस्ट बाढ़ के बाद में ही वह समय था और उसमें जितने भी लोगों को लाभान्वित किया जाना था, उसमें वो लाभान्वित हुए और गांव, ढाणी, मगरी में बैठा हुआ आदमी उस चीज से लाभान्वित हुआ। चाहे सड़कों का देख लें, सड़कों के मामले में आज पाली जिला और राजस्थान की तो सब जगह प्रशंसा हो ही रही है, पाली जिले में तो बहुत जबरदस्त काम हुआ है। मैं मांग संख्या-26 जो आज का विषय है चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य, इसके बारे में आपके माध्यम से हमारे चिकित्सा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी साहिबा से कुछ निवेदन करना चाहती हूं कि वैसे तो पूरे राजस्थान में जो चिकित्सालयों की जर्जर अवस्था थी उसको सुधारने के लिए, डाक्टरों की व्यवस्था के लिए सभी जगह पर समान बजट दिया गया मगर मेरा इस मौके पर एक और निवेदन है कि नाडौल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है मेरे यहां पर, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करावें क्योंकि नाड़ौल की आबादी 15 हजार है और वर्तमान में वहां का आउटडोर 2004 में 14,286 था और 2005 में 14,896 था और 2006 में 17,273 था अगर यहां नाड़ौल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक केन्द्र में क्रमोन्नत कर दिया जाता है तो इससे, मैं कल माननीय वसुधंराजी, मुख्य मंत्रीजी से मिली और इससे पहले मैंने माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से भी इसके बारे में निवेदन किया था कि वहां पर हमारे दानदाता चिकित्सा के क्षेत्र में भवन बनाने के लिए भी तैयार है और

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

इससे हमारी 40 से 50 गांव, ढाणियां जो इससे जुड़ी हुई हैं इसमें 14 पंचायतें हैं, 14 पंचायतों में 40 से 50 गांव हैं जिसमें नाड़ौल पंचायत, सालरिया, कोटड़ी, आना, दादयी, ढलोन, किशनपुरा, सावलदा, निपल, देवली, पाबूजी, केसुलिन, नारलाई, बड़ौद, जीवनकलां ये 14 ग्राम पंचायते हैं। इन ग्राम पंचायतों में 50 से 60 गांव हैं, ये सभी गांव लाभान्वित होंगे और इसमें चारो तरफ आवागमन से तो एकदम सही स्थिति हो गई है मगर इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कर दिया जाता है तो वैसे भी सरकार ने इस बजट में निजी सहयोग को आमंत्रित किया है और निजी सहयोग करने के लिए हमारे दानदाता तैयार हैं। इसी प्रकार से मेरे सादड़ी में भी 30 बैड हैं और 30 बैड को 50 बैड करने की मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से और वसुंधराजी से मांग करती हूं। क्योंकि वहां पर भी भवन आलरेडी बना हुआ है और वहां पर भी जो आउटडोर वैसे आंकड़ें मंत्री महोदय मंगाये तो मिल सकते हैं 2004 में 57,534 था और इंडोर 1963, मेजर ऑपरेशन हुए 593, माइनर ऑपरेशन हुए 628, डिलेवरी हुई 204 और बैड यूटिलिटी थी 136.21 प्रतिशत, आप सोच सकते हैं और 30 बैड हैं और 30 बैड पर मरीजों को बिठाने, सुलाने के अलावा भी नीचे मरीजों को सुलाया जाता है। यह स्थिति है जो बैड यूटिलिटी थी। इसी प्रकार से 2005 में 62,552 आउटडोर और इंडोर 2,278, मेजर ऑपरेशन हुए 864, माइनर ऑपरेशन हुए 457, डिलीवरी 361 और बैड यूटिलिटी थी 159 प्रतिशत, 2006 में आउटडोर था 79,170, इंडोर था 2,890, मेजर ऑपरेशन हुए 837, माइनर ऑपरेशन हुए 704, डिलीवरियां हुई 561 और बैड यूटिलिटी थी 163.94 प्रतिशत। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब इतना अच्छा हो रहा है तो इस विभाग की तरफ से भी सादड़ी में जो 30 बैड है उसको 50 बनाने के लिए भी सारे प्रस्ताव विभाग के भी शायद आपके पास आ गये होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से है, चिकित्सा मंत्रीजी से है कि कृपया करके इसे सादड़ी में 30 से 50 बैड में क्रमोन्नत किया जाए। सादड़ी हमारे देसूरी का एक मैन स्थल है और यहां पर भी दानदाताओं के द्वारा भवन बना हुआ तैयार है सिर्फ आपको बैड क्रमोन्नत करने हैं और मैं इतना विश्वास दिलाती हूं कि दानदाताओं और निजी सहयोग का मैडम ने इसमें घोषणा कर दी है, इतना विश्वास दिलाती हूं कि जब भी आपको एक्स्ट्रा मेडिसंस की आवश्यकता होगी तब भी इसमें पूरा सहयोग हमारे दानदाता करने के लिए

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

तैयार रहेंगे। क्योंकि हमारे क्षेत्र का गोड़वाड का जो क्षेत्र कहा जाता है वहां के दानदाता पूरे बोम्बे की अर्थव्यवस्था पर कब्जा रखते हैं और जब भी किसी प्रकार की विपत्ति होती है चाहे कवास में हुई, चाहे पाली में अकाल पड़ा जब भी वो लोग आकर के अपनी तरफ से सहयोग करते हैं। इसलिए मेरा आग्रह आपके माध्यम से यही रहेगा कि सादड़ी में भी 50 बैड क्रमोन्नत किए जाएं। इसके साथ ही बिजौवा में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। इस गांव की आबादी आठ हजार के करीब है और वहां पर एक ए एन एम है और बिजौवा गांव भी एक आदर्श गांव है और वहां पर ए श्रेणी के आयुर्वेदिक हास्पिटल भी है, इसके साथ ही घाणेराव में भी मैं नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए आग्रह करूंगी। इस गांव की आबादी भी 7500 के करीब है, यहां पर भी केवल एक ए एन एम है और ए श्रेणी का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। यहां पर सैकण्डरी स्कूल है, यहां पर मिनी सहकारी बैंक है, घाणेराव में मुछला महावीर तीर्थ और पंच तीर्थ है जहां पर स्वयं गुलाबजी जो अपने गृहमंत्रीजी हैं, वह भी आकर के गये हैं और इससे जुडता ही आदिवासी इलाका पड़ता है। अत: यहां पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए ऐसा मेरा निवेदन है। इसके साथ ही मैडम ने जब इस बजट में हमारी माननीय वसुंधराजी ने जब इस बजट में 7502 ए एन एम की घोषणा की है, पहले भी कई ए एन एम को लगाया है, डॉक्टरों को लगाया है और इस बजट में भी इसकी घोषणा की है तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग करती हूं कि मेरे सावलदा जो कि खुद ग्राम पंचायत है, घाणा जो भी ग्राम पंचायत है, गिराली जहां पर तो दानदाताओं ने भवन भी बना दिया है और मैंने उसका उदघाटन भी इसी शर्त पर किया था और चिकित्सा मंत्रीजी से बात करके कि मैं उदघाटन उसी समय करती हूं भाई साहब, जब आप यहां पर ए एन एम लगाएंगे क्योंकि जब मैं गांव में जाऊंगी तो ए एन एम वो मांगेंग, इसलिए आप कहें तो मैं उसका उदघाटन तो कर दूं लेकिन लोग कह रहे हैं इन्होंने उस समय फोन पर कहा था कि आप कर दो, वहां पर ए एन एम आपके लिए जरूर, अवश्य ही ए एन एम ऑफिस खोल दूंगा। वहां पर भवन बना हुआ है सिर्फ पोस्ट क्रियेट करनी है। सभी पंचायत मुख्यालय और गिराली में जैसा कि मैंने निवेदन किया कि दानदाताओं ने चाहे मेरा कोई भी गांव उठा के देख लें दानदाता एडवांस में हमको सहयोग देने के लिए तैयार हैं, वो इसलिए कि राजस्थान की स्थिति सुधरी है। वसुंधराजी राजस्थान की पहचान

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

बहुत अच्छी बनाई है, जो पहचान पूर्व की सरकार ने बिगाड़ दी थी, जो खोखली हो गई है, यह हो गया है, वह हो गया है, इसलिए प्रवासी भी आकर्षित हो रहे हैं सहयोग करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं यह इसी का परिणाम है इसलिए आप इससे मुझको मत झुकाइये और दे ही दीजिये।

**श्री अध्यक्ष:** कृपया समाप्त करें।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): मैडम दो मिनट और।

**श्री अध्यक्ष:** आपने 5.08 बजे बोलना शुरू किया था 12 मिनट बोल लिये।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): दो मिनट और। मैं मांग संख्या-51 के संबंधी अनुसूचित जाति और कल्याण हेतु विशिष्ट संगठन योजना जो है इसके संबंध में भी कुछ अपने विचार रखना चाहूंगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पूरे राजस्थान के एससी/एसटी वर्ग के लोगों की तरफ से जिन्होंने अनुप्रति योजना जिसके माध्यम से सिविल परीक्षाओं में उनको सरकार ने कोचिंग करने के लिए जो सुविधा दी एक लाख की और पैंतालीस हजार की आईएएस के लिए और आरएएस के लिए अलग-अलग उसके लिए भी मैं वसुन्धराजी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मन से धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ ही अब के बजट में भी यह उन्होंने घोषणा की और करके दिखाया एससी/एसटी का बैकलॉग बीस हजार छोड़ गये थे वो दस हजार पूरा किया और आने वाले समय में भी वो पूरा किया जाएगा ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वसुन्धराजी ने जो भी राजस्थान की जनता के सामने जो भी घोषणा की निश्चित रूप से उनको पूरा किया है और इसी पूरा करने की प्रक्रिया से सभी का विश्वास प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जा रहा है। मैं एक बात के लिए और धन्यवाद देना चाहूंगी अम्बेडकर पीठ पार्क के निर्माण की जयपुर में जो घोषणा की गयी है निश्चित रूप से पूर्व की सरकार ने अपने नाम से भवन बनाये अशोक जी ने अपने नाम से अशोक उद्यान बनाया। बाहेती जी आपके अजमेर में भी बना हुआ है उधर से आती हूं तब देखती हूं जोधपुर में भी बना हुआ है। मगर मैं धन्यवाद देना चाहती हूं... (व्यवधान) वो नाम के सम्राट थे सम्राट तो ये हैं । सम्राट तो वो होते हैं जैसा गांव में भावना होती है कि सम्राट वो होता है जो जनता की आम जरूरतों का ध्यान रखती है उन्होंने आम जरूरतों का ध्यान नहीं रखा इसलिए आज वो क्या हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। सम्राट तो वसुन्धरा जी हैं।

**श्री अध्यक्ष:** सम्राट तो वो होते हैं जो दिल में समाये रहते हैं।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): मेरी नजर में सम्राट वसुन्धराजी हैं जिन्होंने प्रत्येक वर्ग का अब के बजट में ध्यान रखा, महिलाओं का ध्यान रखा, जेंडर बजटिंग पेश किया। महिलाओं का रेश्यो सभी विभागों में अच्छा रहे इसके लिए सब कुछ किया और सबसे बड़ी चीज एससी/एसटी वर्ग का पूरा ध्यान रखा जिस मुद्दे को आप लोग भी बहुत हवा देते रहे बेकलॉग पूरा करवाओ, बैकलॉग पूरा करवाओ। बेकलॉग पूरा करवा दिया और हमारे पास में बोलने को बहुत जगह है और हमारे समाज वाले हमारे एससी/एसटी वर्ग वाले इस सरकार के साथ में जुड़ेंगे और मजबूती के साथ जुड़ेंगे देखना आने वाले समय में आपको बतायेंगे आपने हम लोगों का मिसयूज किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना जरूर पड़ेगा। वर्षों-वर्षों तक भुगतना पड़ेगा। ये तो आपने बीच में टोक दिया।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): आप उनका जेंडर मत बदलो उनको साम्राज्ञी बोलो सम्राट मत बोलो।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): इसमें भी क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग थोड़े होता है सम्राट सम्राट होता है कोई हो। बजट इतना बढ़िया पेश किया इस पर कुछ आप बोले नहीं ।

**श्री अध्यक्ष:** अब आप समाप्त करें।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): एक मिनट जवाब तो दे दूं, नहीं तो ये समझेंगे कि बोलना नहीं आता महिलाओं को।

**श्री अध्यक्ष:** ऊट पटांग बातों का जवाब देना आवश्यक नहीं है।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): हुकुम आप विराजें हैं, आप भी सर्वोच्च पद पर विराजे हुए हैं कभी-कभी इनके मन में होता है कि महिलाएं आगे कहां पहुंच गयी हैं इसलिए जवाब देना आवश्यक है।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): देसूरी से आने वाली माननीय सदस्या, हम तो मानते हैं कि महिलाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि इस पूरे सदन में 6-7 ही हैं तो यह हमारी हालत है अगर अब तैंतीस प्रतिशत होंगी तो क्या हालत होगी हम जानते हैं।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): तैंतीस प्रतिशत तो आप कराओ। आप हमेशा महिला दिवस पर ...। ये तो मैं जवाब दे रही हूं इससे हटकर महिला दिवस पर आपने खूब रोना रोया कि महिलाओं की यह हो रही है वो हो रही है।

**श्री अध्यक्ष:** वो हाल तो हमने देखा है। वो हमने देखा है हाल दिन से। महिलाएं तो केवल दो थीं लेकिन पुरुष ने जो हंगामा किया तीन तक देख लिया हमने।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ एक ही महिला थी अगर 15-20 होतीं तो क्या हालत होती।

**श्री अध्यक्ष:** आपके साथ दो थीं।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): ये ढोंग तो यह रचते हैं कि हम महिलाओं के समर्थक हैं लेकिन ये सबसे बड़े विरोधी हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): आपके साथ महिला एक थी तो वो तो पुरुष थी बाकी आप सारा काम वो कर रहे थे।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): महाभारत और रामायण एक ही महिला ने करवाया था आप चिंता मत करो बहुत हैं।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित :** अध्यक्ष महोदय, ये तीन दिन का जो नजराना हुआ उसमें हरिमोहन जी को बेलन युद्ध सहन करना पड़ा घर पर कि वसुंधरा जी के विरोध में क्या कर रहे हो ये बेलन युद्ध हो गया उनके। यह उन्होंने कहा है मेरे को। हरिमोहन जी ने कहा है।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): इसीलिए ठंडे पड़े हैं आज।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): किसी भी पड़ोसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए और हमारी पड़ोसी बोल रही हैं तो मुझको तो ठंडा रहना ही है।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): ये इतना अच्छा माहौल बना रहे हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि सदन में आने की कुछ सार्थकता सिद्ध हुई नहीं तो इतने दिन से तो ऐसा लग रहा था कि सभी चर्चा कर रहे थे कि क्या हो रहा है करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा था और आप सबको देख-देख कर जो प्रशासनिक लॉबी है वो भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी इसलिए सुधर जाओ, सभी सुधर जाओ। सभी का इसी में फायदा है इसलिए ...

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): हम सुधरे हुए हैं इसमें भी शक है क्या आपको। कमाल करते हो।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): नहीं-नहीं, मैंने तो आपकी हां में हां मिलायी है।

**श्री अध्यक्ष:** देसूरी से आने वाली माननीय सदस्या, आज आपने अख़बार में नहीं पढ़ा क्या, ये नहीं सुधरेंगे।

**डा. एन.एस. गुर्जर** (टोडारायसिंह): हरिमोहन जी, इस उम्र में आकर सुधरे कि नहीं सुधरे बराबर है।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): धन्यवाद, मैडम।

**श्री अध्यक्ष:** श्री प्रहलाद गुंजल।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई की मांग संख्या-26 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठन योजना की मांग संख्या-51 पर चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा प्रारम्भ हुई और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा प्रारम्भ की और पिछले पाँच सालों की तुलना वर्तमान सरकार के तीन सालों से करते हुए सारा चित्रण सदन के सामने रखा। इतनी गम्भीर मांग पर चर्चा है लोक स्वास्थ्य राष्ट्र की धरोहर है और मनुष्य समाज व्यवस्था का वो घटक है कि उसकी कार्यक्षमता पर समाज की आर्थिक और सामाजिक उन्नति निर्भर करती है और इसलिए यह चिंतन केवल राजस्थान के स्तर पर नहीं है पिछले लंबे अर्से से विश्व के मानचित्र पर भी इसकी चर्चाएं हुई। चाहे वो अल्माटा घोषणा हो और अल्माटा घोषणा के बाद प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा का लाभ मिले इसलिए राष्ट्रीय चिकित्सा नीति भी बनी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि भारत सरकार ने जो 1982 में राष्ट्रीय चिकित्सा नीति बनायी राजस्थान में 1983 में उसका अनुसरण हुआ और उसका अनुसरण होने के बाद जिस सरकार के समय यह चिकित्सा नीति बनी 1983 से लेकर 1990 तक और 1998 से लेकर 2003 तक वो शासन में रही। आश्चर्य होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम चिंता कर रहे हैं कि हमारी चिकित्सा नीति इस प्रकार की है कि प्राथमिक चिकित्सा प्रत्येक व्यक्ति को गांव तक मिले और हमारी रफ्तार उसको चिकित्सा उपलब्ध कराने की कितनी बनी है यह आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं । वर्तमान सरकार के तीन वर्षों में खोले गये स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या और विगत सरकार के पाँच वर्षों में खोले गये स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या । उप स्वास्थ्य केन्द्र तीन साल में 686 और विगत सरकार के पांच सालों में 75 । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान सरकार में तीन साल में 51 और विगत सरकार के पाँच वर्षों में शून्य। यह चेहरा बताता है कि चिकित्सा आम ग्रामीण जन जीवन को मिले इसके बारे में इनका दृष्टिकोण, इनका नजरिया, इनकी नीति किस प्रकार की रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर दो-तीन बातों

(श्री प्रहलाद गुंजल)

की चर्चा करना चाहता हूं। पिछले दिनों राजस्थान में स्वास्थ्य चेतना यात्रा प्रारंभ की गई और एक महीने तक राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री जी के आह्वान पर पूरे राजस्थान के गांव-गांव तक स्वास्थ्य चेतना यात्रा गई। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज भी याद आता है कि मैंने कई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान पढ़े कि स्वास्थ्य चेतना यात्रा राजनीतिक यात्रा है। यह पोस्टर छपाओ प्रतियोगिता हो रही है और गांव गांव तक पोस्टर पहुंचाये जा रहे हैं । लेकिन आज इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी को, अध्यक्ष महोदय, मैं गांव से आता हूं और मुझे आज भी गांव के दूरस्थ इलाके में बैठे हुए व्यक्ति की तकलीफ की ठीक से जानकारी है जिसके मन में चिकित्सा स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस नहीं है और आज भी जिसके मन में यह कल्पना नहीं है कि वह जिस साधारण बीमारी से ग्रसित है सामान्य तरीके से उसका उपचार कराया जा सकता है । अगर कोई आदमी उम्र के पड़ाव पर बैठा हुआ बीमार होता है उससे जाकर तकलीफ पूछते हैं जवाब मिलता है कि यह सब उम्र की बीमारियां हैं अब यह साथ जाने वाली हैं । गांव के दूरस्थ इलाके में बैठा हुआ जो व्यक्ति जिसकी तकलीफ का इलाज संभव है, समाधान संभव है अवसर नहीं है उम्र की बीमारी के साथ जोड़ कर हताश होता है, समझौता करता है उस राजस्थान के गरीब व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर उसकी तकलीफ को दूर करने का पहली बार लोकतंत्र के इतिहास में एक अवसर राजस्थान की सरकार ने खड़ा किया है । अवसर खड़ा किया है राजस्थान सरकार ने जो गांव का व्यक्ति सामान्य बीमारी से ग्रसित है या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है उसका इलाज गांव में होगा और गांव में तुरंत उसकी बीमारी का इलाज संभव है तो वहां पर होगा अगर गंभीर बीमारी है जिसका इलाज जिला चिकित्सालय पर संभव नहीं है तो उसको उस बारे में मार्ग दर्शन दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, आप कल्पना करोगे, राजस्थान में एक प्रकार के वातावरण का निर्माण होगा कि एक के बाद एक पंचायत में जब चिकित्सा चेतना रथ जाने लगा तो होड़ लग गई मरीजों की और यह आंकड़े जो राजस्थान की सरकार ने प्रदर्शित किये हैं कि कोई 31 लाख लोगों ने आकर उसमें अपना इलाज कराया । मैं समझता हूं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं कि संख्या इससे भी ज्यादा बढ़ गई हो । अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो कार्यक्रम इन तीन सालों में हुआ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण का। कोई राजनीतिक बात कहे कोई तकलीफ नहीं है । हम बहुत ईमानदारी से जब

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं कोई भी देश समग्र और शक्तिशाली देश तब बन सकता है जब उसका लोक स्वास्थ्य सुदृढ़ हो । उसकी आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य मजबूत और सुदृढ़ हो । उसकी कार्य क्षमता में दो गुना, चार गुना इजाफा हो । स्वास्थ्य के आधार पर तब राष्ट्र की क्षमता नापी जाती है । केवल भौतिक आधार पर और अन्य तरीकों से कोई जीडीपी के आधार पर, जीडीपी तब क्रिएट होगी जब उसके नागरिक की कार्य क्षमता का विस्तार होगा और उसका नागरिक जो कल बनने वाला है अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस अभियान में और तकलीफ हुई एक दिन मैं समाचार पढ़ रहा था रामपुर मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक विद्यालय है वहां जब बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और अगले दिन डाक्टर का बयान था कि एक विद्यालय में तमाम शत प्रतिशत बालिकाएं एनिमिया की बीमारी से पीड़ित हैं । कोई कल्पना नहीं कि हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं, कहीं खून की कमी है । यह जो घर के दरवाजे से चलकर उसके पास जाकर उसको अवेयरनेस पैदा कर उसके जीवन को सुधारने, संवारने, चिकित्सा उपलब्ध कराने की जो पहल है मैं खुद गया एक स्वास्थ्य परीक्षण के अवसर पर तीसरी चौथी क्लास के बच्चे जिनको पता नहीं कि मैं किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र बावडीखेडा के प्राइमरी स्कूल में जब बच्चों की आंखों का परीक्षण हुआ तो 15 से 20 प्रतिशत बच्चों की आखें कमजोर पाई गई । अध्यक्ष महोदय, अगर इलाज नहीं होता, समय पर उनको चश्में जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती, चिकित्सकीय मार्ग दर्शन नहीं मिलता तो निश्चित रूप से यह बीमारी जाकर बडी बीमारी बनती । अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन सालों से लगातार जब भी इस सदन में चिकित्सा की मांग करता हूं तो दो प्रकार की बातें सामने आती हैं शहरी चिकित्सा और ग्रामीण चिकित्सा । हम शहरी चिकित्सा को सुदृढ करने की बात करते हैं । हम जयपुर के हमारे एसएमएस को सुपर स्पेशलिटी के क्राइटेरिया में लाने की बात करते हैं । निश्चित रूप से करनी चाहिये यह बहुत जरूरी है । लेकिन आज केवल जयपुर के एसएमएस को सुपर स्पेशलिटी में लाने से काम चलने वाला नहीं है । अध्यक्ष महोदय, शायद आज हमने अपने आपको थोडा लिमिटेशन में किया है कि जिन जरूरी चीजों की आवश्यकता स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार को करनी चाहिये चाहे वह संभागीय हैड क्वार्टर पर बाई पास सर्जरी की सुविधा हो या फिर न्यूरोलोजी की यूनिट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर या संभागीय हैड

(श्री प्रहलाद गुंजल)

क्वार्टर में पूरी तरह से स्थापित करने की आवश्यकता हो । कभी-कभी हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में जो निजी क्षेत्र का निवेश हुआ है कोटा में आप चले जाएं तीन-तीन, चार-चार निजी क्षेत्र के अस्पतालों में बाई पास सर्जरी की सुविधा है और कोटा का महाराव भीमसिंह चिकित्सालय जो मेडिकल कालेज से संबद्ध है वहां पर इसकी सुविधा नहीं है । आज हमको कम से कम यह बात तय करनी पड़ेगी कि केवल कार्डोलोजिस्ट लगाने से, फिजीशियन लगाने से काम चलने वाला नहीं है । सर्व सुविधा युक्त एक-एक यूनिट कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर बाई पास सर्जरी की संभव नहीं है तो कम से कम हमको विज्ञान के महाविद्यालय जिन संभाग मुख्यालयों पर कार्यरत हैं वहां पर हमको यह विचार करना पडेगा और ग्रामीण स्वास्थ्य के बारे में जब हम विचार करते हैं अध्यक्ष महोदय, यह बात आती है कि गांवों में डाक्टर नहीं जाते । कई बार यह चिंता सदन के सारे माननीय सदस्यों ने की लेकिन मुझे इस बार बहुत प्रसन्नता है कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने इस बात को समझा कि आखिर गांव में डाक्टर के ठहराव के लिये क्या जरूरी है । मैं हर साल कहता हूं मेरे रामगंज मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बैड के अस्पताल में प्रमोट करो और जवाब आता है कि चूंकि वहां पर हर महीने 100 की क्षमता नहीं होती इसलिए नहीं होता । अध्यक्ष महोदय, मैं हर बार कहता हूं कि उस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आप कैसे 100 लोगों को भर्ती करोगे जिसमें एनेस्थीसिया का डाक्टर नहीं है, जिसमें सर्जरी करने वाला डाक्टर नहीं है, जिसमें गायनोलोजिस्ट नहीं है, जिसमें आर्थोपेडिक्स का कोई सर्जन नहीं है और यह सब है तो जिसमें सर्जरी के लिये आपरेशन थियेटर नहीं है, इक्युपमेंट नहीं है उन अस्पतालों को आप किस प्रकार से कल्पना करोगे कि उसमें इतने-इतने पेशेंट आ जाये और फिर वह क्राइटेरिया फिलअप करने के बाद आप उनको 100 बैड के अस्पतालों में प्रमोट करो । अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है राजस्थान के चिकित्सा मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अब की बार सर्जरी के चिकित्सा लागू करने का प्रयास किया और प्रयास ही नहीं किया डाक्टर वहां रहे और वहां  डाक्टर टिक कर काम करें इसलिए अध्यक्ष महोदय, शायद इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस बात का अनुमान नहीं लगाया होगा, कल्पना नहीं की होगी डाक्टरों को गांव में रहने के लिये, स्टाफ को गांव में रहने के लिये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र पर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रहने के लिये जितने आवासों के निर्माण की स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष में जारी हुई है 50 साल के लोकतंत्र के इतिहास में जितनी स्वीकृति हुई उसके बराबर अकेला एक वित्तीय वर्ष में हुई है । यह इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान कि 1947 के बाद 50 साल के राजस्थान के इतिहास में जितने डाक्टर के और स्टाफ के जितने आवास बने उतने आवासों की स्वीकृति केवल मात्र एक साल में .....

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इतना ही नहीं हम गांव में जाते हैं, गांव में जाते हैं हमेशा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर जाएंगे, उसको उच्चकृत स्वास्थ्य केन्द्र में प्रमोट करने की बात करते हैं। हमारे यहां केवल एक एएनएम है, डाक्टर नहीं है, तो कम से कम एक जीएनएम लगाइये। मैं आज इस मौके पर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने बजट के अंदर राजस्थान के 7502 उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंदर जीएनएम या एएनएम की एक अतिरिक्त पोस्ट सृजित की है, अगले चरण में राजस्थान के दस हजार जो टोटल होते होंगे मैं समझता हूं, उम्मीद करूंगा कि आज इस अवसर पर चिकित्सा मंत्रीजी कहें कि 7502 जो लगभग एडपोस्ट सेंटर के रूप में स्थापित हो जाएंगे, जहां दो-दो का नर्सिंग स्टाफ कायम हो जाएगा। आने वाले वित्तीय वर्ष में सारे राजस्थान के सब सेंटर एडपोस्ट सेंटर के रूप में उच्चकृत स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्थापित हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर चिंकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा। यह सिलसिला लगातार बढ़ना चाहिये इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने कई बार यह बात कही है कि मेरे यहां 100 बैड का अस्पताल होना चाहिये, चेचक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिये लेकिन आज अगर हम ईमानदारी से बात करेंगे तो लोक स्वास्थ्य के सामने हम केवल हमारे कटमोशन की बात है, कटमोशन के माध्यम से सरकार के पास पहुंचती है। हमें यह ईमानदारी से विचार करना पड़ेगा कि हम समूचे राजस्थान को यहां पर चर्चा करके, कोई नीति संगत तरीके से, युक्तिसंगत तरीके से, किस प्रकार से लोक स्वास्थ्य के सामने आने वाली गम्भीर चुनौतियों से निपटने का रास्ता बना रहे हैं और इसलिए इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि लोक

स्वास्थ्य के लिए केवल मौसमी बीमारी नहीं, केवल सामान्यतया आने वाली बीमारियां नहीं, हमें आज इस दिशा में विचार करना पड़ेगा कि आज जिस प्रकार से नशे की प्रवृति नौजवान पीढ़ी में पड़ रही है, नौजवान पीढ़ी में जिस प्रकार से नशे की प्रवृति बढ़ती जा रही है, नशे के आदि होते जा रहे हैं...

**श्री अध्यक्ष:** समाप्त करें। 5.26 पर शुरू किया था और 5.42 हो गए हैं।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): दो मिनिट में समाप्त करता हूं। आज जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार नौजवान में नशे की प्रवृति बढ़ती जा रही है, घायल होता जा रहा है उसके कारण खाली उसके स्वास्थ्य पर ही विपरीत असर नहीं पड़ रहा समाज की व्यवस्था चरमरा रही है। उसकी आदतें खराब हो रही हैं। कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रही है और उसके लिए मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार ने करीब, माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की मदद से 6-7 नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किये गये। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हम नौजवान पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकालें। आज भी हम इन नशामुक्ति केन्द्रों के माध्यम से जो नौजवान चपेट में आ गया है उसको दस प्रतिशत से ज्यादा बाहर नहीं निकाल पा रहे। 80-90 प्रतिशत नौजवान वापिस भागते हैं और नशे की लत को पकड़ लेते हैं। उसको स्थाई रूप से इस खतरे से बाहर निकालने के लिए दीर्घकालीन पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना राजस्थान में की जानी चाहिये और खासतौर से उन जिलों में जो मध्यप्रदेश की सीमा से जुडा हुआ झालावाड़ जिला है उसका असर आज कोटा पर आने लगा है। वहां पर स्मैक और अफीम की तस्करी के कारण चाहे बारां जिला हो, नौजवानों की हालत खराब होती जा रही है।

जिस प्रकार से नशे की लत के कारण व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार नशे पर चर्चा करते समय लोग यह कहते हैं कि अगर किसी देश से बदला निकालना है, किसी देश से कोई दुश्मनी का हिसाब-किताब चुकाना हो तो फौज लेकर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है उस देश की नौजवान पीढ़ी को स्मैक पीने की लत लगा दो, उस देश की नौजवान पीढ़ी को इस प्रकार का कोई घातक नशा करने की लत लगा दो वह देश किसी भी सूरत में नहीं उभर सकेगा। आज इस प्रकार का घातक नशा जो राजस्थान की नौजवान पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है यह

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चुनौती भरा सवाल लोक स्वास्थ्य के सामने खड़ा है। आज हमको भी बहुत गम्भीरता पूर्वक इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। जब यह विचार करेंगे तो कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं का समाधान होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य की, लत के कारण जिस प्रकार की चोरियां, कई प्रकार की सामाजिक गतिविधियां जो समाज में होती है उस पर भी नियंत्रण होता है और लोक स्वास्थ्य में सुधार आयेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर हम इन सारे विषयों पर विचार करके चले, लोक स्वास्थ्य में, जो मिलावट है खान-पीन की, आज किस स्तर की मिलावट हो रही है अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, स्वास्थ्य निरीक्षक के पद राजस्थान में आधे से ज्यादा खाली पड़े हैं, उन पदों को भरने के बारे में आज सदन में आपको निश्चित रूप से यह कहना चाहिये कि हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देना चाहते हैं। बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए उनको किसी प्रकार की खानपान में मिलावटी चीजें नहीं मिले1 बेहतर खानपान की चीजें मिले। अगर कोई मिलावटी चीज मिलती है तो सरकार का दायित्व बनता है इस प्रकार की मिलावटी चीजों पर नियंत्रण करें1 उस पर नियंत्रित करने की ठोस व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि इस दिशा में अगर राजस्थान सरकार कदम उठाएगी तो जिस प्रकार का सकारात्मक आंदोलन चिकित्सा मंत्रीजी आपके नेतृत्व में राजस्थान में चल रहा है चाहे वह नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का मामला हो, चाहे उप केन्द्र खोले जाने का मामला हो, चाहे जीएनएम की भर्ती का मामला हो, चाहे सरकारी आवास बनाने का मामला हो। मैं पिछली बार भी एक निवेदन आपसे कर चुका था। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट में समाप्त करूंगा।

पिछली बार भी मैंने एक निवेदन इस सदन में किया था। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी हर स्वास्थ्य केन्द्र पर जरूरी नहीं कि आप सीमित संसाधनों के चलते हुए एनिथिसिया का डाक्टर लगाओ, जरूरी नहीं कि आप उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर कोई गाइनिकी डाक्टर लगा पाओ लेकिन जो आपका वर्तमान का स्टाफ बैठा है, जितने डाक्टर आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बैठे हैं, जितने डाक्टर आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बैठे हुए हैं आप तय करके किसी को

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एनीथिसिया की ट्रेनिंग दिलाये, आप तय करके किसी को रेडियोलोजिस्ट की ट्रेनिंग दिलाए, तय करके किसी को गाइनिकी की ट्रेनिंग दिलाइये। जब आप इस प्रकार का वातावरण का निर्माण करेंगे, गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर को आप गाइनोलोजिस्ट की तरह प्रशिक्षित करेंगे, आप उसको रेडियोलोजिस्ट की तरह प्रशिक्षित करेंगे, आप उसको एनिथिसिया की तरह प्रशिक्षित करेंगे तो उसकी सेवाओं का लाभ एक तरह से विशेषज्ञ चिकित्सकों की तरह गांव के व्यक्ति को मिलेगा।

भर्तियां कब होंगी, सीमित संसाधनों में कब सारी पूर्तियां होगीं, कब गांव-गांव को डाक्टर मिलेगा लेकिन हम एक सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र जो पंचायत समिति में निश्चित रूप से एक केन्द्र अनिवार्य रूप से होता है उस स्तर पर अगर हम इस प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं क्रियेट कर दें, इस प्रकार की स्पेशलिटी ट्रेनिंग दिलाकर कायम कर दें तो गांव के व्यक्ति को निश्चित रूप से बेहतर चिकित्सा मिल पाएगी, इतना आज आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं।

आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है भ्रूण हत्या। पिछले दिनों जिस प्रकार से वातावरण का निर्माण हुआ मीडिया में, ऐसा लगा सारी मानवता कलंकित हो रही है...

**श्री अध्यक्षः** यह महत्वपूर्ण पहले ही कह देते। आपने समय तो ले लिया कम से कम 25 मिनिट। 5.26 पर बोलने लगे थे अब 5.47....

**श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): आपकी कृपा की जरूरत है।

**श्री अध्यक्षः** महत्वपूर्ण सबसे पहले कहना था ना।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से भ्रूण हत्या के समाचार राजस्थान के पत्रों में छपे, जिस प्रकार के दृश्य पढ़ने को मिले ऐसा लगता है सारी मानवता शर्मा गई, कलंकित हो गई। हमारे पास ठोस कानून है लेकिन उन ठोस कानूनों से हम इस प्रवृति पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे ।

**श्री अध्यक्षः** जिक्र कर दिया आपने भ्रूण हत्या का, बस अब समाप्त करें।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): 21वीं सदी में हम समाज की इस प्रकार की मानसिकता को देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है कि हम किस

दिशा में जा रहे हैं इसलिए इसको कानून के बजाए एक समग्र आंदोलन खड़ा किया जाए। समाज में इस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए सारे सदस्यों को मिलकर एक आंदोलनात्मक भूमिका का निर्माण समाज में करना पड़े .......

**श्री अध्यक्ष:** कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): इस दिशा में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हम राजस्थान के साथ न्याय दिला पाएंगे।

**श्री अध्यक्ष:** आप सदन के साथ भी न्याय करो।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृपा पूर्वक बोलने का समय दिया मैं अपनी बात को विराम देने से पहले आभार व्यक्त करता हूं कि कोटा के मेडीकल कालेज के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रावधान किया है।

**श्री अध्यक्ष:** आगे बढ़ते जा रहे हैं।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): मेरे विधान सभा क्षेत्र पर भी कृपा करेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** अब हो गई कृपा पूरी। चलिये...

**श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): आपने अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री चन्द्रशेखर बैद। स्थान पर बैठा करो।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 के ऊपर आज जो चर्चा चल रही है इस पर मैं सदन का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं1 आपके माध्यम से मैं सर्वप्रथम यह बताना चाहता हूं कि इस बार बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बजट एस्टीमेट रखा गया है 2007-08 का, वह रखा है 1237.61 करोड़ रुपये का और यह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो पिछले साल....

**श्री अध्यक्ष:** 1200 नहीं 1400, 1400 अरब है।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मेम, मैं राजस्थान की तरफ से जो बजट रखा गया है, इसमें सेण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स को शामिल नहीं किया गया है।

**श्री अध्यक्ष:** अच्छा, आज तो आपसे रुपये मांग रहे हैं 14 अरब, सवाल उसका है। सेण्टर का और यहां का नहीं। यह जो मांग रखी गयी है 14 अरब, मोर देन 14 अरब है। उस पर बोलें आप।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): पिछले साल जो इन्होंने बजट रखा था राजस्थान की जनता के लिये वह था 1106.72 करोड़ रुपये। पिछले साल के मुकाबले 132 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान राजस्थान सरकार की तरफ से अपने संसाधनों द्वारा रखा गया। जब यह अपने संसाधनों द्वारा रखा गया तो इसमें देखना यह जरुरी है कि इसमें आपने कौनसी-कौनसी मदों में अधिक पैसा खर्च करने का प्रावधान रखा। जब इसकी तरफ नजर डालते हैं तो मालूम पड़ता है कि नॉन प्लान के अन्दर 105 करोड़ रुपये...

**श्री अध्यक्ष:** यह बजट भाषण की बात है। कटौती प्रस्तावों पर आएं आप।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मेम, मैं थोड़ी भूमिका तो बांध दूं।

तो 105 करोड़ रुपये अधिक रखे। यह 105 करोड़ रुपये तो सिर्फ आपके डाक्टरों की, पैरा मेडिकल स्टाफ की तनख्वाह के अन्दर जो बढ़ोतरी होगी उसी पर खर्च हो जायेगा। और सिर्फ जो दूसरे प्रावधान आपने रखे हैं, 25 करोड़ रुपयों के, उसमें बहुत सारी जो नेशनल स्कीम्स चल रही हैं, सेण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स का पैसा आ रहा है, नेशनल रुरल हैल्थ स्कीम का पैसा आ रहा है उसमें जो 25 करोड़ रुपये अधिक आपको मिल रहे हैं, पिछले साल की बनिस्पत, उनको शामिल किया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वास्थ्य के लिये जो बजट का प्रावधान किया उसमें राजस्थान की गरीब जनता के लिये एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं रखा।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि दवाइयों के लिये, आज जो दवाइयां एक ग्रामीण क्षेत्र में या अरबन क्षेत्र में मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं उस दवाई के लिये आपने टोटल बजट रखा है उसमें एक भी पैसे की आपने बढ़ोतरी नहीं की। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्रीजी का उठाकर देखें। जबकि वास्तविकता यह है कि दवाइयों के दाम में पिछले साल की बनिस्पत 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

**श्री अध्यक्ष:** यस, यस।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): तो जब 20 प्रतिशत की दवाइयों के दाम में बढ़ोतरी हो गयी तो कहने का मतलब यह हो गया कि इस बार राजस्थान की जनता को पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। जब दवाइयों के बजट की तरफ आप देखते हैं तो टोटल प्रावधान आपने रखा है 25 करोड़ रुपये का। इसके अन्दर राजस्थान की पापुलेशन जो आज की तारीख में आंकी जाती है, 6 करोड़ 50 लाख। 6 करोड़ 50 लाख में प्रति व्यक्ति, प्रति साल सिर्फ 3 रुपये 84 पैसे दवाइयों के ऊपर खर्च किये जाएंगे। उसमें भी विसंगति है कि आप रुरल और अरबन के अन्दर डिवाइड करके देखें तो बहुत ही भयावह फिगर आता है। वह इस ग्रामीण जनता के लिये जो कि 4 करोड़ 30 लाख है राजस्थान के अन्दर, सिर्फ 93 पैसे प्रति व्यक्ति, प्रति साल दवाइयों के लिये रखे गये हैं। जो कि सर्वथा अनुचित है। आशा यह की जा रही थी कि इस बार दवाइयों के लिये और दूसरे चिकित्सा संसाधनों के लिये ग्रामीण जनता के लिये ज्यादा प्रावधान किया जाएगा। लेकिन उसमें बढोतरी नहीं करना यह इस चीज को दर्शाता है कि आप अपने संसाधनों से ग्रामीण लोगों को लाभान्वित नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ सेण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं या जो वर्ल्ड बैंक के अनुदान से स्कीम्स चल रही हैं, उसके माध्यम से ही आप लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं।

एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था। 3 साल हो गये उसकी रट लगाते हुए कि राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं, अब आप खुद ही मानते हो कि मिड-डे मील के अन्दर आप एक करोड़ 2 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन करवाते हैं। यह बच्चे जो सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कवर होते हैं, इनकी संख्या एक करोड़ 2 लाख है। और यह है पहली क्लास से लेकर पांचवीं क्लास तक के। अगर आप पहली क्लास से बारहवीं क्लास तक के, जैसे कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि राजस्थान के स्कूल के सारे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, सारे बच्चों को हैल्थ कार्ड इश्यू किया जायेगा और सारे बच्चों के अन्दर अगर कोई बीमारी आती है तो उनका इलाज किया जायेगा। आज तीन साल हो गये लेकिन आज तक स्कूल के अन्दर बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना। और चुनिन्दा स्कूलों को छोड़कर अधिकांश स्कूलों में सिर्फ अध्यापकों ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है जो कि अनुचित है। क्योंकि स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए डाक्टरों के द्वारा। डाक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया। और यह स्थिति इसलिये और ज्यादा इम्पोर्टेण्ट हो जाती है कि आज राजस्थान के अन्दर जो एस.एस.ए. का सर्वे

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

हुआ उसके अन्दर 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाये गये। उनका वेट साधारण वेट से कम था। उनके अन्दर खून की मात्रा एक साधारण हैल्दी बच्चे में जितनी होती है उससे कम थी। इसकी जो ग्रोथ थी, वह कम थी। तो बच्चों के प्रति तो और ज्यादा संवेदनशील होना था। और एक जो कार्यक्रम अच्छा आपने शुरू किया था उसको अंजाम तक पहुंचाते तो राजस्थान के ढाई करोड़ बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। यह उनकी सोच अच्छी हो सकती है लेकिन प्रशासनिक शिथिलता और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण इस कार्यक्रम को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि एक ग्रामीण इलाके के अन्दर जो एक्रेडिटेट सोशल हैल्थ एक्टिविस्ट की पोस्ट, एन.आर.एच.एम. के अन्दर राज्य सरकार को दी गयी उसके अन्दर भी एक तरफ आपको केन्द्र सरकार से इन सुविधाओं के लिये शत-प्रतिशत पैसा उपलब्ध करवाया जा रहा है, इसके बावजूद आप अगर अपने निर्धारित लक्ष्यों को, अपने जो टार्गेट अचीव्ड हैं, उनसे कम्पेयर करें तो मालूम पड़ता है कि जो मिशन 2005 में शुरू किया गया और जिस मिशन को 2012 तक कम्पलीट होना है, 2007 तक आपको इन आशा सहयोगिनियों में 37492 आशा सहयोगिनियों को भर्ती करना था और आपने भर्ती कितनों को किया, 33202 को। मतलब इसमें भी आपने 5 हजार कम आशा सहयोगिनियों को भर्ती किया जबकि इसका सारा पैसा केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाता है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज उभरकर सामने आयी है कि बच्चों को और ग्रामीण इलाके को कौनसा विधायक अपने क्षेत्र को डवलप नहीं करना चाहता। मैं भी करना चाहता हूं, मंत्री महोदय भी करना चाहते हैं, मुख्य मंत्री भी करना चाहती हैं। लेकिन आप इस पूरे राजस्थान का आंकड़ा अगर उठाकर देखें तो झालावाड़ के अन्दर जहां कि इनको भर्ती करनी थी 940, आपने भर्ती 1113 की की। पूरे राजस्थान के अन्दर जितनी भर्ती की जानी थी उनमें से आपने 5 हजार कम आशा सहयोगिनियों को भर्ती दी। यह इस चीज को दर्शाता है कि मुख्य मंत्रीजी का हलका है तो आपने उसमें ज्यादा की। लेकिन वह मुख्य मंत्री सिर्फ झालावाड़ की नहीं हैं, पूरे राजस्थान की हैं। तो राजस्थान के अन्दर चूरु भी आता है, भरतपुर भी आता है। सब जगह जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति की जानी चाहिए थी। एक माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण, 2006 के अन्दर यह घोषणा की कि पंचामृत, मुख्य मंत्री

पंचामृत योजना की शुरूआत करती हैं। बड़ी अच्छी योजना है। योजना क्या थी कि गांवों में जाकर ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण बच्चों को पोषण के हिसाब से पाँच प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और उन्होंने कहा था, अपने पैरा नम्बर 46 में, इसके माध्यम से दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य एवं पोषण की 5 प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। और इन 5 प्रमुख सुविधाओं के अन्दर यह जानकर बड़ा दु:ख हुआ कि इस पंचामृत योजना की शुरूआत की गयी जनवरी, 2005-06 के अन्दर। तीन महीने तक इस अभियान को चलाया गया। इसके लिये पूरे राजस्थान के बजट के अन्दर से एक पैसे का भी प्रावधान नहीं रखा गया। यह आया है, आपने लिखकर दिया है कि इसके लिये एक भी पैसे का प्रावधान नहीं रखा गया। दूसरा, इसमें खर्चा कितना किया, 32 जिलों के अन्दर जिस अभियान को आपने चलाया उसमें सिर्फ 17 हजार रुपये खर्च किये। और वह भी किस लिये कि वह यह कागज छापने के लिये, जिसमें कि वहां का चिकित्सक अपनी रिपोर्ट लिखकर दे सके।

तो यह तो मैं स्थिति तब बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ घोषणा करते हैं। आप सिर्फ यहां पर माननीय मुख्य मंत्री की तारीफ कर करके उनको पोदीने के झाड़ पर चढ़ाते हो और उस योजना का अन्जाम क्या होता है यह भी आपने कभी देखा कि आपके क्या-क्या योजनाएं शुरू की थीं और किसको कहां तक पहुंचाया?

ऐसे ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक पन्ना धाय जीवन बीमा योजना की शुरूआत की और यह योजना यह सोचकर शुरू की गयी कि इंश्योरेंस कम्पनी के माध्यम से, यह लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से ग्रामीण हल्के के अन्दर जो बी.पी.एल. परिवार हैं, उन परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार हो जाता है या किसी परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार की तरफ से बीमा कम्पनी के माध्यम से मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा और इसका हश्र क्या हुआ? इसका हश्र यह हुआ कि यह बिलकुल ताजा जो मेरे प्रश्न के जवाब में आया है कि आज भी, यह योजना शुरू की गयी थी 15 अगस्त, 2006 को और उसके बाद में आपके 1441 प्रकरण अभी भी लम्बित पड़े हैं। लोगों की मृत्यु हो गयी। आकस्मिक मृत्यु हो गयी, राजस्थान के 32 जिलों के अन्दर और आपने आज तक उनको मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया। यह सोच सकते हो कि एक ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जिनको उपलब्ध कराया, उनका भी बता दीजिए।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): उनकी संख्या है 123, 123 ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गलत।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): यह आपके ही द्वारा दिया गया जवाब है। साहब, आप खुद के जवाब को ही गलत कह रहे हो? खैर, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। क्योंकि यह कागज मेरे पास मौजूद है। आप चाहोगे तो मैं टेबल कर दूंगा। आप अपने बगल में बैठे मंत्रीजी से पूछ लीजिए। (व्यवधान)

यह है पन्ना धाय जीवन बीमा योजना और दूसरा, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जब आपने अखबारों में एडवरटाइजमैंट दिया, जब आपने पूरे प्रदेश के अन्दर यह प्रचार किया कि आकस्मिक मृत्यु पर जो मृत्यु पर डिपेंडेंट होगा, उसको 50 हजार रुपये एकमुश्त उपलब्ध कराये जाएंगे और यह जो सूची मुझे मिली है उसके अन्दर आपने सिर्फ 30 हजार रुपये प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराये हैं। कहां गये 20 हजार रुपये? प्रचार तो आपने 50 हजार का किया था। फिर 30 हजार रुपये आपने कैसे उपलब्ध कराये?

मैं आपके माध्यम से एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ जहां सारी सरकार लगातार बार-बार अलग-अलग मंचों से यह प्रचार-प्रसार करती है कि आई.एम.आर. कम करेंगे, एम.एम.आर. कम करेंगे। कैसे कम करेंगे आप? आपने कहा था कि हम आने वाले सालों के अन्दर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों के ऊपर हम यह सेवाएं, प्रसूति की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध कराएंगे और तीन साल से लगातार बार-बार राज्यपाल के अभिभाषण में और अपने मुख्य मंत्री की बजट की स्पीच में आप हमेशा से यह कहते हो कि चिह्नित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हम यह उपलब्ध कराएंगे। आज तक आप इतने विधायक यहां पर बैठे हैं। कोई भी यह बता दें कि उसके विधान सभा क्षेत्र में 24 घंटे डिलीवरी की सर्विसेज उपलब्ध है तो आप जो चाहे वह मैं करने को तैयार हूं। एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 24 घंटे इमरजेंसी टेकल करने के लिए और डिलीवरी सर्विसेज आपने उपलब्ध नहीं करायी जबकि आप ... (व्यवधान) आपका समय आये तो बोल देना। मेरे को बीच में क्यों इंटरप्ट करते हो?(व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह एम.एम.आर. ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एम.एम.आर. इतना ड्रास्टिकली रिड्यूज हुआ है। आई.एम.आर. रिड्यूज हुआ है तो यह वैसे ही हो गया। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आप विराजिये। उसके बाद बताता हूं मैं।

**श्री अध्यक्ष:** आपको समय मिलेगा न, आप बैठिये। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): एम.एम.आर. और आई.एम.आर. जो रिपोर्ट हुआ है, जो अभी रिपोर्ट आयी है नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे के अन्दर, वह पुरानी रिपोर्ट के मुकाबले में आयी है उसमें आधा समय हमारा था, आधा समय आपका था, उसके लिए छाती ठोकने की जरूरत नहीं है। उस पर दोनों का कंटीब्यूशन है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप ठोक लो छाती, क्या दिक्कत है। अब मैंने कहा आप ठोक लो छोती। छाती ठोकने में क्या दिक्कत है?

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): बी.पी.एल. के लिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** तो ठोक लो, क्या बात है? (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): पिछले कई सालों से सवाई मानसिंह चिकित्सालय में और मेडिकल कॉलेज से जुडे हुए अन्य चिकित्सालयों के अन्दर एक सुविधा इन्होंने उपलब्ध करायी थी कि जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग इलाज कराने आएंगे और उन्हें दवाइयां उपलब्ध नहीं होंगी तो दवाइयां लोकल परचेज करके उनको उपलब्ध करायी जाएंगी। पिछले डेढ़ साल से इस सुविधा को बिलकुल बंद कर दिया गया है जो कि बिलकुल गलत है क्योंकि आज आप यह देखें कि कितने वी.आई.पीज. के ट्रीटमैंट में कितना पैसा खर्च होता है और एक गरीब आदमी जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला है उसके इलाज में आप कितना पैसा खर्च करते हो? यह सूची है मेरे पास, जिसमें लाखों रुपये जो अपने सारे के सारे मिनिस्टर्स हैं, विधायक हैं, आई.ए.एस. आफिसर्स हैं, आई.पी.एस. आफिसर्स हैं, उनको उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों में रेफर करने में खर्च किये जाते हैं लेकिन एक एग्जाम्प्ल है ऐसा जहां बी.पी.एल. के मरीज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रेफर किया गया, वह भी मैंने जिद करके करवाया और उसका पैसा अभी तक उपलब्ध नहीं

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कराया गया। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप चाहे दूसरे लोगों की सेवाओं में कितना भी पैसा खर्च करें लेकिन ध्यान उस गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण आदमी की तरफ भी देना निहायत जरूरी है।

आपने यह कहा था कि साहब, हम गरीबों के लिए अलग-अलग प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर कम्युनिटी हैल्थ सेंटर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर लाइफ लाइन स्टोर खोलेंगे जिसमें कि कम दामों के अन्दर दवाइयां उनको उपलब्ध करायी जाएंगी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आज तक आपने कितने ऐसे प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स हैं, जहां फ्लूड स्टोर की स्थापना करके उसकी शुरूआत की है।

एम्बुलेंसेज के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। बहुत प्रशंसनीय काम है। आपने घोषणा की लेकिन आज भी आपके खुद के मापदंडों के आधार पर 168 चिकित्सा केन्द्र ऐसे हैं जहां कि एम्बुलेंसेज होनी चाहिए और एम्बुलेंसेज उपलब्ध नहीं हैं और हर समय यह कहा जाता हैं राजस्थान पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां दूरियां बहुत अधिक है, इतनी अधिक दूरियां होने के बावजूद यदि एम्बुलेंसेज उपलब्ध नहीं हैं तो एक गांव में रहने वाला आदमी तो कहां जाएगा? मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कई विधायक हैं जो अपने प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर एम्बुलेंसेज उपलब्ध कराना चाहते हैं। सरकार को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह कहना चाहिए कि यदि कोई विधायक अपने प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर एम्बुलेंस देना चाहता है तो 50 परसेंट पैसा हम देंगे, 50 परसेंट पैसा विधायक कोष से उपलब्ध होगा, इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स पर इम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। (व्यवधान)

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): मैंने इस वर्ष दो एम्बुलेंस उपलब्ध करवायी हैं। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान)

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): मैंने अपने विधायक कोष से दिलवायी हैं, आप भी यह कर सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** बहुत अच्छी बात है।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आज माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आज 1200 डाक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं। आप कैसे उनको ग्रामीण इलाके में चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे जिसमें से 64 परसेंट, 64 परसेंट गायनोकॉलोजिस्ट की पोस्ट है। आज हर जगह यह शिकायत है, हर विधायक यह कहता है कि हमारे हल्के के अन्दर गायनोकॉलोजिस्ट को भेजो। चाहे वह पुरुष हो, चाहे महिला हो लेकिन इनकी ज्यादा से ज्यादा भर्ती करके इनको कम से कम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और चुनिंदा, आपने ही अपने घोषणा-पत्र में यह कहा है, माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा है कि हर पंचायत समिति के अन्दर एक आइडियल प्राइमरी हैल्थ सेंटर की स्थापना की जाएगी तो ऐसे आइडियल प्राइमरी हैल्थ सेंटर के अन्दर तो आपको एम्बुलेंसेज उपलब्ध करवानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि एक नेशनल रूरल हैल्थ स्कीम के अन्तर्गत जो योजना शुरू की गयी थी, जननी सुरक्षा योजना, इसकी जो शर्मनाक हालत दो साल के अन्दर हुई है और जिसके अन्दर जितना पैसा आपने खर्च किया है और जब आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया, केन्द्र सरकार द्वारा जननियों को मिलने वाले पैसे के अन्दर बढ़ोतरी की गयी तब जाकर यह योजना आगे चलनी शुरू हुई है नहीं तो आपका तो हश्र यह था कि आपने कितने करोड़ रुपये, आपने 3 करोड़ 32 लाख रुपये में से शुरू के दो साल में सिर्फ 3.5 लाख रुपये खर्च किये थे। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता। इस वित्त वर्ष में 5 करोड़ का प्रावधान रखा था, 50 करोड़ रुपया इसमें पेमेंट हो गया, इस वर्ष के अन्दर। 5 के अगेंस्ट में 50 करोड़। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): बीच में खड़े हो जाते हो, रिप्लाई क्या दोगे? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** रिप्लाई देने को बहुत है। बहुत कुछ है। बहुत इश्यूज उठाये हैं। उन पर सब पर देना है जवाब तो, बहुत उठाये हैं। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): एक, आपका जो बेसिक सेंटर है वह प्राइमरी हैल्थ सेंटर है और उस प्राइमरी हैल्थ सेंटर के अन्दर यह आपके माननीय विधायक द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है।

प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर में यह आया है कि 142 प्राइमरी हैल्थ सेंटर ऐसे हैं जिनके अंदर कोई चिकित्सक आज तक उपलब्ध नहीं है तो आपने प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स को खोल क्यों रखा है ? हर बार माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह घोषणा क्यों कराते हो कि यह इतने प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोलेंगे, इतने कम्युनिटी हैल्थ सेंटर खोलेंगे। क्या करेंगे इनको खोलकर ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप जैसे लोग डॉक्टर यहां आ-आकर विधायक बन गये। मजबूरी है कि डॉक्टर्स यहां आ-आकर विधायक बन गये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** यह तो विधायक हैं । (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): डॉक्टर विधायक ही नहीं, डॉक्टर हैल्थ मिनिस्टर भी बन गये। इसलिए भी समस्या पैदा हुई है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** यह विधायक थे, जब ही तो मंत्री बने। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): बिना विधायक के भी बन सकते हैं छह महीने तक।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): इसलिए तो पद रिक्त हो गये। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार पिछले विधान सभा सत्र के अंदर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने यह एडमिट किया था एक प्रश्न के जवाब में, कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कितने उपकरण खराब पड़े हैं और उनको कब तक ठीक करा लिया जायेगा और आज स्थिति यह है कि साल भर व्यतीत हो गया लेकिन अभी भी आपने उनमें से अधिकांश उपकरणों को ठीक नहीं कराया है। आपने 42 उपकरणों की सूची दी थी जिसमें से 35 उपकरण खराब पड़े थे। अब इसका अंदाज इससे लग सकता है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है सवाई मानसिंह हास्पिटल, जिसको कई बार यह कोशिश की जा चुकी है कि इसको ऑल इण्डिया मेडिकल साइंस में कन्वर्ट किया जाये। वहां पर उपकरणों की यह हालत है तो फिर तो कैसे काम चलेगा और फिर तो बाकी इलाके में क्या होगा, यह तो भगवान ही मालिक है।

आपने यह घोषणा की थी कि टेली-मेडिसिन के माध्यम से कम्युनिटी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

हैल्थ सेंटर को जोड़ा जायेगा क्योंकि टेली-मेडिसिन का सबसे ज्यादा लाभ कम्युनिटी हैल्थ सेंटर पर हो सकता है लेकिन आज तक आपने एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को टेली-मेडिसिन के माध्यम से नहीं जोड़ा है। आपने यह घोषणा की थी पिछली बार कि संजीवनी योजना की शुरूआत करेंगे जिससे सीनियर्स डॉक्टर्स को जो डिस्ट्रिक्ट्स पर उपलब्ध हैं उनको प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर ले जाकर जो लोग प्राइमरी हैल्थ सेंटर से डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल पर जाने में असमर्थ हैं, उनको समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। लेकिन आप तो यह गिना दो कि आपने कितने प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर सीनियर्स डॉक्टर्स को ले-जाकर इस तरह की संजीवनी योजना की शुरूआत की है। यह भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी।

पापुलेशन ग्रोथ के बारे में छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा आज यह चीज हर जगह उजागर होती है कि जब तक पापुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जायेगा, तब तक आप कितनी ही सुविधाएं जुटा लें, वह ग्रोथ रहेगी। अब 1991 से लेकर 2001 के सेन्सस तक पापुलेशन ग्रोथ थी 28 प्रतिशत, 2001 का सेन्सस हुआ राजस्थान की पापुलेशन थी 5 करोड़ 65 लाख और आज की तारीख में 2007 में राजस्थान की पापुलेशन है 6 करोड़ 50 लाख और 2010 तक यह पापुलेशन जो होगी, उसके अंदर ग्रोथ आज की तारीख में जो आंकी गयी है, वह 26 प्रतिशत है और सरकार की तरफ से बार-बार कहने के बावजूद कि हम जन मंगल योजना को सुदृढ़ करेंगे लेकिन मंशा वह नहीं है। मंशा इसलिए नहीं है कि ऊपर से सुदर्शनजी का निर्देश आता है कि पापुलेशन बढ़ाओ, हिन्दू कम हो रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं। आपने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पापुलेशन को कंट्रोल किया जाये।

2004 से पहले बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि राजस्थान के अंदर स्वस्थ बच्चे पैदा हों और स्वस्थ जननियों को रखा जाये। इसके लिये दस हजार दाइयों को जो पारम्परिक रूप से काम करती हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई जायेगी। आज तीन साल व्यतीत हो गये, लेकिन आपने सिर्फ पौने तीन हजार दाइयों की ट्रेनिंग करवाई है। यह घोषणा 2004 में की, 2005 में की और कल जो आपने प्रतिवेदन दिया है, उसके अंदर यह लिखा है कि सिर्फ तीन हजार दाइयों की ट्रेनिंग आपने आज दिन तक कराई है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके पास सूचना गलत है।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आपने किताब में गलत लिखा है तो मैं क्या करूं, आपने जो किताब उपलब्ध कराई है, उसी से तो सूचना लेंगे और किससे लेंगे ? आपने यह भी घोषणा की थी कि राज्य सरकार हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर और उप स्वास्थ्य केन्द्र पर धन उपलब्ध करवाने में असमर्थ है इसलिए प्राइवेट पार्टनरशिप में करके इनका उद्धार किया जायेगा और नई निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई जायेगी तो घोषणा तो आपने 2004 में कर दी, नीति तो आज तक बनाई नहीं और वह जो सब सेंटर और प्राइमरी हैल्थ सेंटर जहां थे, वहीं पड़े हैं।

2006-07 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि राजस्थान में अंधे लोगों की संख्या 9 लाख है और हम एक जीरो केटरेक ऑपरेशन शुरू करेंगे जिसका सुझाव मैंने ही दिया और उसके अन्तर्गत हम ऐसा प्रयास करेंगे कि राजस्थान के अंदर इनकी संख्या .34 प्रतिशत हो जाये जिससे कि वह जीरो प्रतिशत हो जाये, लेकिन एक साल के अंदर आपने साढ़े चार लाख की

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

जगह आपने लक्ष्य निर्धारित किया ढाई लाख और ढाई लाख में से भी आपने कितने अंधों का उपचार किया सिर्फ एक लाख साठ हजार। इस तरह से ऑपरेशन जीरो केटरेक का लक्ष्य 2008 तक आप कैसे हासिल कर पायेंगे? यह भी आप बताने की कृपा करें जब आप अपना उत्तर दें।

डॉक्टर्स के लिये आपने घोषणा की थी कि 558 डॉक्टर्स भर्ती करेंगे और इस बार 100 डाक्टर्स बोला है पिछले साल कि 100 डॉक्टरों की भर्ती करेंगे। आप घोषणा कर चुके हैं 458 डॉक्टरों को भर्ती करने की, जबकि भर्ती हुई है सिर्फ 373 डाक्टर्स, तो जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हो, उसको कभी पूरा नहीं कर पाते। यह बात मानने में दिक्कत कहां है? आपके खुद के ही आंकड़े बता रहे हैं कि आप सिर्फ घोषणा करते हो, उसको पूरा नहीं करते। अगर इस तरह से आप करते रहे माननीय मुख्य मंत्री के अधीनस्थ में काम तो इनको पाँच साल पूरे होते-होते नया लेबल लग जायेगा कि यह घोषणा मुख्य मंत्री है, यह सिर्फ घोषणाएं करती हैं, इनको पूरा कभी नहीं करती।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने कई प्रकार से मीडिया के माध्यम से कई

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

चीजें उजागर हुईं और उन चीजों के अंदर जो एक बहुत ही हास्यास्पद चीज उजागर हुई उसके अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसी मंत्री का कान पकड़ रखा है और मंत्रीजी यह कह रहे हैं - "मैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो, तो माखन कुण खायो, फिर माखन कुण खायो" इसका जवाब आज या तो सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये थी, उसका खण्डन करना चाहिये था, न तो आपने स्थिति स्पष्ट की, न उसका खण्डन किया तो आम जनता जो यह जानने को उत्सुक है कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, नीचे सारे अधिकारी, फार्मास्यूटिकल कम्पनी के लोग इन्तजार कर रहे और आप कमरे के अंदर किस आदमी से क्या गुफ़्तगू कर रहे हैं । यह तो मैं कहता हूं कि भला हो उस फार्मास्यूटिकल के मालिक का, जिसने अपने पत्र के अंदर ईमानदारी से सत्य को उजागर करते हुए यह कहा है कि फलाना आदमी जो पहले 15 प्रतिशत मांग रहा था, उसका 15 प्रतिशत हमारा शेयर उसके अंदर नहीं रहा तो अब आपको जो पैसा है 5 प्रतिशत, यह आपको वहन करना पड़ेगा तो इन सब चीजों का जवाब सरकार को देना चाहिये था क्योंकि इससे आम जनता की नजर, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आम जनता की नजर इस बात पर उठती है कि इसका क्या स्पष्टीकरण है। एक तरफ जिस फार्मास्यूटिकल कम्पनी को आप यह कहते हो कि यह फर्जी कम्पनी है, फर्जी दवाइयां बनाती हैं। सरकार केस लड़ती है, सरकार का अधिकारी उसकी पैरवी करता है और वही अधिकारी उस फार्मास्यूटिकल कम्पनी के सारे जो प्रमाण पत्र वह देता है, उसको स्वीकार कर लेता है और जो उस कम्पनी की क्षमता ही नहीं है दवाई बनाने की, वह दवा बनाकर राजस्थान सरकार को तिगुने दाम के अंदर सप्लाई कर दी जाती है, यह कहां तक उचित है। एक तरफ तो बजट में प्रावधान बढ़ाओ मत और दूसरी तरफ जो लोगों को, आम आदमी को दवाइयां उपलब्ध होने वाली हैं, उसके अंदर इस तरह का उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोटा से आने वाले तीन ही है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वह कहते हैं दोनों सचेतकजी हैं। अब जनता तो यह जानने को उत्सुक है कि कौन से सचेतकजी के कहने से आपने इस कम्पनी को क्या कांट्रेक्ट दिया ?

**श्री अध्यक्ष:** सचेतक कहां हैं वह?

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): संसदीय सचिव हैं।

**श्री अध्यक्ष:** सचेतक कहां है, हां, तो संसदीय सचिव बोलो।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मैं आपसे सादर अनुरोध करूंगा इस तरह से जो दवाइयां करोड़ों रुपये का घोटाला अख़बार में उजागर हुआ, उसकी तरफ सरकार या तो कोई स्पष्टीकरण दे या उसका खण्डन करे या जो पत्र उसके अंदर जारी किये गये, उन पत्रों का खण्डन करके जनता के सामने यह स्पष्ट करे कि उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई इस तरह के कुछ चुनिन्दा लोगों की पॉकेट में नहीं जा रही है।

राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी, अब आपको मालूम है आज तो आज अंदाज लगा रहे हो कि एड्स के कितने मरीज होंगे। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर 52 लाख एच.आई.वी. पोजीटिव हैं उसमें राजस्थान के अन्दर जो आंकलन लगाया गया है, डेढ़ लाख एच.आई.वी. पोजीटिव हैं और 2000 मरीजों का इलाज करवा रहे हैं अभी तो इन मरीजों के इलाज के लिए जो पैसा नाको के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है उस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, इसकी तरफ भी आपने ध्यान दिया। आज जो ज्यादातर एड्स की बीमारी हो रही है वो हो रही है मजदूर को, वह हो रही है ग्रामीण महिलाओं को। वो इसलिए हो रही है कि आपका जो एडवरटाइजमेंट है वो शहर तक सीमित है, वह सिर्फ पाँच सितारा होटलों और बड़े-बड़े अखबारों में एडवरटाइजमेंट देने तक सीमित है। आपने इसका पैनेट्रेशन जो है वो ग्रामीण इलाके के अन्दर जो सेक्सुअली एक्टिव परसन्स हैं उनके अन्दर नहीं किया, मजदूरों में नहीं किया, अनपढ़ लोगों में नहीं किया तो आने वाले समय में जो राजस्थान राज्य के अन्दर डेढ़ लाख एच.आई.वी. पोजीटिव हैं और वो जब एड्स की बीमारी में कन्वर्ट होंगे तो स्थिति कितनी भयावह होगी। आप तो चिकित्सक भी हैं और चिकित्सा मंत्री भी हैं तो इस ओर भी जरा वीजन डाल कर देखो और इसको कंट्रोल करने के कुछ साधन अपनाओ जिससे कि जो पैसा, करोड़ों रुपया जो नाको के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाए उसका सदुपयोग किया जा सके।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

आखिर में मैं छोटीसी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जो निविदा के अन्दर पैरामेडिकल स्टॉफ, जो कि आलरेडी ट्रेंड है, जिनका काफी शोषण हो चुका है इसके बावजूद जब यह आन्दोलनरत हैं और आपको नयी भर्तियां करनी है तो क्यों नहीं इन पैरामेडिकल स्टॉफ को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि यह एक्सपीरियंस लोग हैं और इस तरह के एक्सपीरियंस लोगों

को प्राथमिकता दी जायेगी तो इससे स्वास्थ्य का जो पूरा ढांचा है वो सुदृढ़ ही होगा, कमजोर नहीं होगा।

और इसके बाद लास्ट में, मैं इसके पहले कि अपनी बात समाप्त करूं, एक बात और कहना चाहता हूं कि एक बड़ा अच्छा धार्मिक स्थल है चूरू के अन्दर सालासरजी और उसके अन्दर एक ही आपने वहां डाक्टर लगा रखा है और उस डाक्टर के अगेंस्ट में एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी, उसका वहां से ट्रांसफर हो गया। लोगों ने शिकायत कर दी और आज तक उस डाक्टर को एक बार पाँच दिन के लिए ट्रांसफर करके वापस आपने वहीं पदस्थापित कर दिया तो जब लोगों का इतना आग्रह है, वहां पूरे देश के लोग आते हैं ऐसी स्थिति के अन्दर आपको इन छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देकर वहां पर किसी नये, अच्छे डाक्टर को लगाएं जिससे कि राजस्थान की बदनामी दूसरे प्रदेशों में नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** थैंक यू।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन है ...(व्यवधान) समय मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए आपका तो।

**श्री अध्यक्ष:** दूंगी मैं आपको भी समय। श्री अशोक नवलखा।

**श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो मैंने कट मोशन मांग संख्या-26 और मांग संख्या-51 पर दिये हैं उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी और हमारे लोकप्रिय चिकित्सा मंत्रीजी के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षों में जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाये गये हैं उसकी मिसाल आज सदन में जो चर्चा हो रही है उसके माध्यम से सुनने को मिल रही है। पिछले तीन वर्षों में सरकार ने चाहे उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मामला हो चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की दिशा में कदम उठाना हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हों, चाहे चिकित्सालय भवनों के अन्दर भवन निर्माण कराना हो उन सब दिशा के अन्दर सरकार ने चहुमुखी विकास के काम किये हैं।

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

चूंकि आज सदन के अन्दर जो सरकार द्वारा तीन वर्षों में विकास के काम करवाये गये हैं उसके बारे में विस्तारपूर्वक काफी चर्चा हो चुकी है, मैं इस अवसर पर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों के अन्दर जो विकास के काम करवाये उससे हमारा चित्तौड़गढ़ जिला और मेरा विधान सभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा।

आज हमें इस बात की खुशी है कि वर्षों से जिन चिकित्सा भवनों के अन्दर भवन का अभाव था, डाक्टर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रुकते नहीं थे, उन सब की सुध लेकर के हमारे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने जो कार्य किये हैं और उसी का परिणाम है कि आज गांव के अन्दर चिकित्सा की अलख जगी है। जब गांव के अन्दर स्वास्थ्य चेतना यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची और चिकित्सा क्षेत्र में लोगों को जानकारियां मिलीं, यह बात सही है कि कोई भी सरकार सफल होती है तो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को परखने का काम करना पड़ता है और जनता की मूलभूत समस्याओं को परख कर उनको अमल में लाने का यदि किसी सरकार ने काम किया है तो हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधराजी राजे के नेतृत्व में जो सरकार का गठन हुआ है उसी सरकार ने काम किया है।

मैं इस अवसर पर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। एक तो जिस प्रकार से हमारे सड़क के अन्दर नीति बनी है, शिक्षा के अन्दर नीति बनी है कि 500 तक की आबादी के गांव हम सड़क से जोड़ते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय तक स्कूल खोलते हैं तो इसी प्रकार से उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मामले में भी हमें एक नीति बनानी चाहिए क्योंकि आज हमारे इस क्षेत्र के अन्दर ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां तीन-तीन हजार की, ढाई-ढाई हजार की आबादी है, वहां पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं तो इस दिशा में निश्चित रूप से हमें चिन्तन करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा गांव-गांव तक मुहैया हो। मेरा निवेदन है कि कम से कम इसके अन्दर नोर्म्स बना करके एक हजार तक की जो भी आबादी हो उस आबादी के गांव हों, वहां पर निश्चित रूप से उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुलना चाहिए ताकि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में यह चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील मुख्यालय पर जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं, जो वर्तमान में 30 बैड के हैं, 30

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

शय्या के हैं उनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ा कर के 50 शय्या करनी चाहिए क्योंकि जहां पूरी तहसील के अन्दर एक स्वास्थ्य केन्द्र होता है या सामुदायिक केन्द्र होता है और वहां भी 30 बैड की सुविधा रहती है तो यह निश्चित रूप से अपर्याप्त है। एक सामूहिक निर्णय लेकर के पूरे राजस्थान में 30 बैड के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनको 50 बैड के करने चाहिए जिससे कि लोगों को चिकित्सा का लाभ मिल सके।

मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें, क्योंकि अभी सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, यदि समस्त सी.एच.सी. पर यदि सुलभ काम्प्लैक्स की व्यवस्था हो जाए तो यह भी निश्चित रूप से सरकार के लिए हितकारी काम होगा।

मैं इस अवसर पर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनके सख्त निर्देशों के कारण ही हमारे वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सभी डाक्टर्स आज जैनेरिक औषधियां लिखने लगे हैं जिससे वहां आने वाले प्रत्येक मरीज को दवाओं की मार झेलनी पड़ती थी, महंगी दवाइयां जो खरीदनी पड़ती थी वो आज सस्ते रूप में खरीदने को मिल रही हैं। लाइफ लाइन की सुविधा हमारे हास्पीटल में शुरू हुई है। इसी प्रकार से वहां जो अन्य चिकित्सा की इकाइयां हैं वहां पर भी दवाईयां जैनेरिक रूप से शुरू हुई हैं जिससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो भी गरीब लोग हैं उनको दवाइयां सस्ती मिलती हैं।

इस अवसर पर जो मांग संख्या-26 थी उसके अन्दर मैंने इस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं थीं उन समस्याओं की जानकारी मांग के अन्दर दी है। मेरा तो इस अवसर पर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से इतना ही निवेदन है कि निम्बाहेड़ा हमारा तहसील मुख्यालय है, उप-खण्ड मुख्यालय है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहां 70 हजार की आबादी है, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया था, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से भी निवेदन किया है कि यदि वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को, जो वर्तमान में 50 बैड की क्षमता का है यदि 100 बैड की क्षमता का क्रमोन्नत कर दें तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता को आपके इस उपकार का लाभ मिलेगा और अन्य जो भी समस्याएं, जो मैंने अपनी मांगों के माध्यम से उठायी हैं वह आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

मैं इस अवसर पर मांग संख्या-51 के अन्तर्गत जो मैंने बातें रखी हैं उसके अन्तर्गत मैं समाज कल्याण मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में आपने मेरे इस क्षेत्र के अन्दर छोटी सादड़ी जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है उस क्षेत्र के अन्दर समाज कल्याण का छात्रावास नहीं था, आपने 42 लाख रुपये स्वीकृत करके आज भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जिससे आज भवन बन कर खड़ा हुआ है। मैं इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर केवल दोनों तहसील मुख्यालय में...

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, ना तो चिकित्सा मंत्री हैं और ना उनके राज्य मंत्री हैं, दोनों नहीं हैं। अब आप हो गये चिकित्सा मंत्री।

**श्री अध्यक्ष:** शिक्षा मंत्री बैठे हैं न।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): नहीं, रहना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, आपके खुद के निर्देश हैं कि मंत्री को रहना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** आयेंगे, आयेंगे अभी।

**(समय : 18.20 बजे)**

**(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)**

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): जब तक रोक दो न आप इस पर। इस मांग पर विचार रोक दो जब तक आये जब तक।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य समाज कल्याण पर बोल रहे हैं।

**श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा): अभी मांग संख्या-51 पर बोल रहा हूं मैं।

**श्री सभापति:** नौ डिस्कशन ओन दिस पाइण्ट।

कोई भी जोइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है, सीनियर मिनिस्टर यहां मौजूद है उसके बावजूद भी वह पानी पीने गये हैं, अभी आ रहे हैं, मुझे कहकर गए हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): जिस विभाग पर बहस है उस विभाग का मंत्री होना चाहिए, सीनियर मिनिस्टर पर नहीं है, जिस विभाग पर बहस है उस विभाग का मंत्री होना चाहिए ...(व्यवधान)

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा :** माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के कल्याण पर अपनी बात कह रहे हैं, माननीय मंत्रीजी उपलब्ध हैं।

**श्री सभापतिः** अब आप बोलने दीजिए, प्लीज सिट डाउन।

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): सभापति महोदय, सात बजे मंत्रीजी का जवाब होना है मांग पर, होता है तो ठीक है, नहीं आठ बजे से अगर आप विधान सभा आगे चलाना चाहते हैं तो कृपया खाने की व्यवस्था कराएं। मैं आपको साढ़े छह बजे सूचना दे रहा हूं। अगर आप खाने की व्यवस्था करा रहे हैं तो आप चाहे रात को 10-11 बजे तक चलाएं और अगर आठ बजे तक आपको खतम करना है तो भले ही आप खाने का इंतजाम नहीं करें। आठ बजे के बियोन्ड खाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, खाने की व्यवस्था तो हो जाएगी अगर माननीय सदस्य का केवल खाने से काम चल जाए तो।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): तिवाड़ीजी, अब आपको यह तो मानना पड़ेगा कि विष्णु मोदीजी अब आठ बजे खाना खा लेते हैं यह याद दिला रहे हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, खाने की व्यवस्था हो जाएगी यदि केवल खाने से उनका काम चल जाए तो।

**श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं ...

**श्री सभापतिः** एक तो होता है खाना पीना और एक होता है पीना खाना।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ...(व्यवधान) आ ही गए आप सदन में भी कुछ पहुंचाना चाहें तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): नहीं, खाना पीना और पीने खाने की व्याख्या माननीय सभापतिजी आप ही कर सकते हो।

**श्री सभापतिः** आप चाहेंगे तो आपकी व्यवस्था करा दी जाएगी।

**श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन किया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कनेरा, पिनोता, अरनोदा जो कि अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

वहां बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे क्षेत्र में निश्चित रूप से समाज कल्याण के नये छात्रावास खोलने की कृपा कराएं तथा जो छात्रावास निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी में हैं उन छात्रावासों के अन्दर भवन का निर्माण और मरम्मत, उनके अन्दर जो छात्रों की सीट संख्या है वह निश्चित रूप से बढ़ाने का कष्ट करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापतिः** श्री हरीसिंह रावत।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): सभापति महोदय, मेरा भी है।

**श्री हरीसिंह रावत** (भीम): सभापति महोदय, आज के इस आधुनिक और विकसित होने वाले प्रदेश की मांग संख्या-26 के बारे में मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। आज हमारे राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, जल के अन्तर्गत हमारी डायनमिक मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धियाजी ने ऐसे आयाम कायम किए हैं जिनके अन्तर्गत हमारे पूरे विपक्ष को सांप सूंघ गया। इनके पास कोई हथियार नहीं रह गया तो केवल इन्होंने तीन चार दिन हल्ले-गुल्ले के अलावा कोई काम नहीं किया। इसी का परिणाम है कि इनको आज सरेन्डर होना पड़ा और बिना किसी शर्त के आज सामने आकर बैठ गए।

सभापति महोदय, आज से तीन वर्ष पहले जब हमारी भारतीय जनता पार्टी का राज आया और हमारी विजिलैंट मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने पद भार ग्रहण किया उसके पहले पूर्ववर्ती सरकार के जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने पांच साल तक खजाना खाली, खजाना खाली करते हुए निकाल दिया। लेकिन जब हमारी मुख्य मंत्री ने कार्यभार संभाला और उनके कुशल वित्तीय प्रबन्ध के कारण कभी भी यह नहीं जताया कि हमारा खजाना खाली है। कहां कि आओ राजस्थान की जनता और आपको क्या चाहिए जिसमें शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली जो एक आधारभूत सुविधा होती है वह उसको मुहैया करवाई और उसके अन्तर्गत हमारी सरकार ने ऐसे-ऐसे काम किये जो कि आज किसी को याद दिलाने की जरुरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरुरत नहीं है।

सभापति महोदय, जिसका परिणाम है कि प्रत्यक्ष में योजना आयोग द्वारा राज्य की वार्षिक योजना 2007-08 के लिए 11638.86 करोड़ रुपए की

(श्री हरीसिंह रावत)

स्वीकृति दी गई जो कि राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना के कुल आकार की 11500 करोड़ रुपए से अधिक है। यह हमारे वित्तीय प्रबन्धन का एक अच्छा आयाम पैदा हुआ है जिसकी बदौलत आज हमारी सरकार चिकित्सा के अन्तर्गत भी इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई है जिसके फलस्वरूप हमारे गांव की भोली भाली जनता जो गांवों में रहती है, उनको आज तक हमारा देश आजाद हुए 45-46 साल तक राज कांग्रेस ने किया क्योंकि उन्होंने केवल वोट की राजनीति की, कभी हमारी भोली भाली ग्रामीण जनता का भला नहीं किया लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने सब जनता चाहे गरीब हो, चाहे ए. पी. एल. हो, चाहे बी. पी. एल. हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे कोई बड़ा धन्ना सेठ हो हर एक की दुःख-सुख में भागी हुई। इसके अन्तर्गत आज हमारी सरकार के तीन-चार साल ऐसे गुजर रहे हैं जो आज किसी को कहने की जरुरत नहीं है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने चिकित्सा के अन्तर्गत एक स्वास्थ्य कैम्पिंग किया। इसके अन्तर्गत भी हमारी जनता को कई ऐसे लाभ मिले और इसके अन्दर कई ऐसी योजनाएं बनाईं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरुरत नहीं है। एक योजना पन्नाधाय जीवन अमृत योजना जो चालू की है इसके अन्तर्गत अगर बी पी एल परिवार का कोई व्यक्ति, कोई सामान्य मृत्यु होती है तो उसको तीस हजार रुपया और दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 75 हजार रुपया और दुर्घटनावश स्थाई कोई उसको नुकसान होता है 75 हजार और दुर्घटनावश स्थाई किन्तु अशक्त तो 37500 रुपए का, तो यह एक हमारी सरकार की बहुत अच्छी उपलब्धि है जिससे कि गरीबों को एक राहत मिली है।

सभापति महोदय, इसके अलावा हमारी सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सामान्य जन तक पहुंचे इसके अन्तर्गत 1 से लेकर 31 दिसम्बर की अवधि में स्वास्थ्य चेतना अभियान चलाया। इसके दौरान 9205 कैम्पों का आयोजन किया गया जिसमें 53 लाख 21 हजार लोगों ने भाग लिया, 31 लाख 5 हजार व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसमें 19 लाख 2000 रोगी एलोपैथी उपचार एवं 12 लाख 3 हजार रोगी भारतीय उपचार विधियों से लाभान्वित हुए। इन कैम्पों में 2 लाख 85 हजार जांचें हुईं। वर्ष 2007 में भी हमारी सरकार इसी प्रकार फिर योजना चालू करने वाली है तो यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है।

(श्री हरीसिंह रावत)

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने राज्य में प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र पर अभी एक ए एन एम और उप स्वास्थ्य केन्द्र पर एक और ए एन एम के साथ-साथ एक फील्ड विजिट के लिए साथ में जी एन एम का भी प्रावधान रखा है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा, हमारी जनता का भला करने वाला काम हुआ है। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगियों को लाने ले जाने के लिए बड़े अस्पतालों को रैफर करने पर उन्हें वहां ट्रांसफर करने के लिए एम्बुलैंस की आवश्यकता महसूस की जाती थी जिसकी वजह से करीब सौ एम्बुलैंस इस बजट में हमारे पारित की है ताकि जहां-जहां भी किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य कहीं भी पी एच सी में जहां भी जरुरत होगी वहां एम्बुलैंस मुहैया की जाएगी।

सभापति महोदय, बाकी तो हमारी सरकार ने बहुत कुछ बताया है। मैं कुछ समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र भीम है जो कि वहां से करीबन अस्सी- नब्बे किलोमीटर नेशनल हाई-वे नम्बर-8 पड़ता है उस हाइवे के अन्तर्गत मेरे दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं । वैसे तो मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं हमारे मंत्री महोदय पर लेकिन मंत्रीजी भी क्या करें। हमारे कागजों में चिकित्सक आते हैं और चले जाते हैं । कारण कि इसमें हो सकता है हमारी कुछ कमजोरी हो। हमारी जो पद्धति है शायद मैं सोचता हूं इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जो कान्ट्रेक्ट और संविदा बेसिस पर डाक्टर हम लगाते हैं वह अपने आपको स्थाई महसूस नहीं करते और आ जाएं तो एक महीने दो महीने बिना किसी नोटिस के वह चले जाते हैं ।

तो आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं क्यों नहीं आर पी एस सी के थ्रू पहले जैसे डाक्टर्स को लेते थे भरा जाए ताकि वह महसूस कर सकें कि मैं स्थायी हूं और परमानेंट रह सकें। उनको अच्छा वेतन मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे करीबन सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिसमें प्रथम पड़ता है दिबेर वहां पर डाक्टर नहीं है। छापली है वहां पर डाक्टर नहीं है। ताल है वहां डाक्टर नहीं। कुआथल है वहां डाक्टर नहीं है। बार है वहां डाक्टर नहीं है और बरार में दो डाक्टर थे जिसमें एक पोस्ट पहले से ही खाली थी और दूसरा पी जी में चला गया इस वजह से वह भी वैकेंट हो

गयी। तो अब सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जितने भी कांट्रेक्ट बेसिस डाक्टर लगाये थे वह महीने, दो महीने के अन्दर ही चले गये। मेरे यहां जितने भी डाक्टर्स हैं उनको तत्काल वापस आर पी एस सी के थ्रू या और भी कोई लगाएं। मेरे क्षेत्र में आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं जिसकी वजह से अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु से बचाने के लिये मेरे यहां जितने भी डाक्टर्स की वेकेंसीज है वह तत्काल भरी जाए।

मेरे भीम में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां भी आये दिन एक्सीडेंट होते हैं और होने का कारण भी है कि जब से किशनगढ़ से लेकर वाया चित्तौड़, भीलवाड़ा जो एक्सप्रेस हाइवे बन गया है वहां टोल टैक्स ज्यादा होने की वजह से पूरा ट्राफिक भीम से होकर वाया राजसमन्द होकर उदयपुर निकलता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट की बहुतायत हो गयी है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जबकि दो या तीन घटनाएं नहीं होती हो इसलिये मेरा निवेदन है लास्ट बजट में मुख्य मंत्री साहिबा से मैंने निवेदन किया था कि हमारे यहां आये दिन एक्सीडेंट होते हैं तो ट्रोमा यूनिट की स्थापना की जाए। उन्होंने तत्काल ट्रोमा यूनिट की स्थापना की। उसके अन्तर्गत 20-25 लाख के उपकरण भी उपलब्ध हुए लेकिन अफसोस है कि अभी तक न तो आर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर है, न एनेस्थीसिया डाक्टर कोई लगा है अभी तक। हमारे यहां करीब सात कनिष्ठ विशेषज्ञों की जो पोस्ट है भीम में, अभी तक केवल कागजों में ही आते हैं और चले जाते हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां जितने भी कनिष्ठ विशेषज्ञों की पोस्ट जो रिक्त है उनको तत्काल भरा जाए ताकि अकाल मृत्यु में सहभागी होकर बचाया जा सके।

मेरे यहां ब्लड बैंक की भी स्थापना हो चुकी है। ब्लड बैंक के सब उपकरण हैं लेकिन ब्लड बैंक चलाने के लिये उनको सिक्योर करने के लिये स्टाफ नहीं है तो उनकी भी व्यवस्था की जाए।

मेरे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम के अन्तर्गत अभी 50 बैड का हास्पिटल है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको 100 बैड तक का किया जाए। पूर्व में मैंने एक क्वेश्चन लगाया था उसका जवाब आया था मेरे पास कि आपके यहां बहुत ही कम पेशेंटस आते हैं। इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि पेशेंट तो यहां खूब आते हैं। मेरा भीम विधान सभा क्षेत्र

(श्री हरीसिंह रावत)

चार जिलों में पड़ता है। जहां एक तरफ भीलवाड़ा है, एक तरफ पाली है, एक तरफ अजमेर है और स्वयं राजसमन्द है। आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और हमारे यहां जो समस्या है वह रैफर कर दी जाती है। जो भी कोई पेशेंट आयेगा रैफर होगा और केस रजिस्टर नहीं होते। तो हम कैसे बताएं कि हमारे इतने केस रजिस्टर्ड हुए इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां न तो डाक्टर है, न ही वहां दूसरे कोई साधन, सुविधा है इस वजह से जितने भी हमारे यहां केसेज होते हैं उनको रैफर टू ब्यावर, रैफर टू अजमेर, रैफर टू उदयपुर या रैफर टू राजसमन्द कर दिया जाता है। जब तक हमारे यहां डाक्टर्स या अन्य कर्मचारी की व्यवस्था नहीं हो जब तक शायद यह हमारे रैफर ही होते रहेंगे। मेरा निवेदन है कि मेरे यहां करीब 15-16 डाक्टर्स की पोस्ट है लेकिन वहां तीन या चार डाक्टर से ज्यादा नहीं है तो जितनी भी डाक्टर्स की पोस्ट है उनको भरा जाए ताकि हमारी जनता को यहां सुविधा उपलब्ध हो सके।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवगढ़ है। वहां भी दो डाक्टर की कमी है उसको पूर्ण किया जाए। इसके अलावा एम्बुलेंस की सख्त जरूरत है इसलिये मेरा यह निवेदन है इस बजट के अन्दर जो 100 एम्बुलेंस का प्रावधान रखा है, एक मेरे देवगढ़ के लिये भी अलाट की जाए।

सभापति महोदय, हमारे वहां डिप्टी सी एम एच ओ जो थे वह प्रमोशन होकर सी एम एच ओ बनकर चले गये और पोस्ट वैकेंट है इसको भरा जाए। हमारे यहां डाक्टर्स की कमी की वजह से कई ऐसे एपरेट्स हैं, अब जैसे आई स्पेशलिस्ट हमारे डाक्टर है लेकिन आई सम्बन्धी कोई भी सामान नहीं है। ब्लड बैंक के स्टाफ की जरूरत है। इसके अलावा हमने एम पी, एम एल ए लैड से एक डेंटल चेयर और एक आटोलाइजर के हमारी मद से पैसे दिये थे लेकिन अभी तक हमारे वहां पर सामान नहीं आया और आया है तो वह भी अधूरा आया है। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा विभाग को अवगत कराना चाहता हूं कि जो-जो भी हमने सामान की डिमाण्ड की है उनकी तत्काल पूर्ति की जाए। इसी आशा के साथ जय भारत। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** डा. श्रीगोपाल बाहेती।

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब मंत्रीजी जवाब दें, अभी समय है। भीम से आने वाले सदस्य और आप कोई भी माननीय सदस्य जो बोलेंगे,

(श्री विष्णु मोदी)

मैं भी अपने विधान सभा क्षेत्र की बात, राजस्थान में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां डाक्टर्स की कमी नहीं है। तो आप आसन से यह निर्देश देकर कृपया पूछ लें कि राजस्थान में कितने डाक्टर्स की कमी है, कितने टैक्निकल स्टाफ की कमी है और राज्य सरकार कब तक उनको पूरा करने का विचार रखती है ? तो यह अगर बात आ जायेगी तो पूरे इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह मालूम पड़ जायेगा कि जो डाक्टर्स आज नहीं हैं वह कल, परसों या फिर नहीं मिलने वाला है क्योंकि कोई विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें डाक्टर्स की कमी नहीं हो, अस्पताल खाली नहीं पड़ा हो।

**श्री सभापतिः** वह उनके जवाब में वह बतायेंगे।

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): जवाब तो वह जो बनाकर लायेंगे वह देंगे। मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं कि आप मंत्री महोदय को यह ...

**श्री सभापतिः** इस पर बोलेंगे।

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): यह व्यवस्था दे दें कि वह राजस्थान का टोटल फिगर बता दें कि इतने डाक्टर्स उनके पास हैं, इतने कम हैं। इतनी ए एन एम हैं, इतनी कम हैं। इतने कम्पाउंडर हैं, इतने कम हैं। इतना टैक्निकल स्टाफ है, इतना कम है। तो उससे कम से कम राजस्थान की जनता को और इस सदन को यह जानकारी होगी कि यह तो जब नम्बर आयेगा जब ही आयेगा। नहीं तो वहां क्षेत्र में जाने पर जवाब देने की स्थिति नहीं बनती है कि कब डाक्टर आयेगा। तो अगर यह सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को मालूम हो जाए कि राजस्थान में इतने डाक्टर्स की कमी है और यह डाक्टर्स कब-कब, किस-किस साल में कितना राज्य सरकार अपनी मंशा रखती है कि यह उनको कब पूरा करेगी ?

**श्री सभापति :** डा. श्रीगोपाल बोहती।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा था कि अब यह तो अपनी पैतृक पार्टी में लौट कर ही जवाब दें लोगों को तो ठीक रहेगा। डेढ़ साल ही तो बचा है।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर कटमोशन पर जो चर्चा हो रही है उसके लिये आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष के विधायक की पीड़ा यह है तो आप

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

अंदाज़ लगा सकते हैं कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवा का क्या हश्र है। अभी इससे पहले बहुत वक्ताओं ने बहुत गुणगान किया कि हमने यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया लेकिन जो जमीनी हकीकत है वह आपको अभी मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने बतायी कि यह स्थिति पूरे राजस्थान की है। मैं आपको बानगी देता हूं अजमेर के जवाहर लाल हास्पिटल की उसमें 42 पद सैंक्शंड हैं डाक्टर्स के, 16 खाली हैं जो संभाग स्तर का अस्पताल है। जो पद है वह पैरा मेडिकल स्टाफ के हैं पद खाली हैं 63 जो संभाग स्तर का हास्पिटल है जिसमें पूरे संभाग की भीड़ आती है। वहां स्थिति यह है तो आप कल्पना कर सकते हैं बाकी की स्थिति क्या होगी। जबकि गत तीन वर्षों से उच्च शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी सदन में निरन्तर आश्वासन देते रहे कि हम स्टाफ जल्दी लगायेंगे। अजमेर में कैथ लैब लग गयी, कैथ लैब चालू हो गयी लेकिन अकेले कैथ लैब के अन्दर 6 डाक्टर्स की कमी है और चार टैक्निशियंस की कमी है। इतने रुपये लगाकर, 4-5 करोड़ रुपये लगा करके जो कैथ लैब लगायी है उसका उपयोग कैसे होगा यह देखने की बात है और यह स्टाफ तो मैं आपको इसलिये बता रहा हूं कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने तो बहुत विस्तार से बात बतायी कि हमने राजस्थान में यह किया। इतनी हमने पी एच सी खोल दी, हमने इतने उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये। जितनी पी एच सीज हैं उसमें डाक्टर नहीं है। उस हास्पिटल में ए एन एम नहीं हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की कि वह ए एन एम और जी एन एम भर्ती करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बाद शायद गांव को भी वह स्टाफ मिले। पर गांव में जो स्टाफ नहीं मिलता है तो मेरा कहना यह है कि मैं बार-बार इस बात को कहता हूं कि राजस्थान के मायने एस.एम.एस. नहीं है, राजस्थान के मायने झालावाड़ नहीं है। राजस्थान के मायने में वह ढाणी भी है, जिस ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति चिकनगुनिया और मलेरिया के इलाज के लिए आपका इंतजार कर रहा है। चिगनगुनिया ने इस राजस्थान में कैसा तांडव किया वह आपसे छिपा हुआ नहीं है और सरकार बिलकुल मूकदर्शक होकर के देखती रही। चिकनगुनिया के माध्यम से रोगी शरीर से भी पिटा, धन से भी पिटा, चूंकि न तो वहां पी.एच.सी. में डाक्टर्स, न ए.एन.एम., न वहां कोई एस्प्रिन देने वाला, न क्रोसीन देने वाला और व्यक्ति को अपने इलाज के लिए प्राइवेट हास्पिटल में जाना पड़ा और हर व्यक्ति ने कम से कम हजार, दो हजार रुपया अपने शरीर

पर खर्च किया। उसके बाद भी उसका यह हुआ कि आज भी वह भुगत रहा है इस बात को, यह सरकार की फेल्योर है और क्या है।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात को कि टीकाकरण के अंदर हमने टार्गेट पूरे नहीं किये और तो और जो आपका यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है जिसमें आपने लगाने थे 3800 कैम्प और आपने लगाये 1800 कैम्प। यह आपकी क्षमता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम यदि स्वास्थ्य सेवा को लेकर गंभीर नहीं होंगे और उस गांव के व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते तो आपकी स्वास्थ्य चेतना यात्रा का कुछ भी नहीं बनने वाला है। आज भी कहता हूं मैं आपसे कि सरकार के अंर्तविरोध को छिपाने के लिए, सरकार के घोटालों को छिपाने के लिए जो दवाइयां आपने खरीदी हैं एक्सपायरी डेट की, जो दवाइयां खरीदी आपने महंगी वह बचाने के लिए आपने यह यात्रा निकाली। आपकी स्वास्थ्य चेतना यात्रा के अंदर केवल नाच-गान, कठपूतली नाच और आपकी मुख्य मंत्रीजी के फोटो, आपके स्वास्थ्य मंत्रीजी के फोटो, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अभी आप कह रहे थे कि 31 लाख हमने ट्रीटमेंट कर दिये, वह कर दिये। मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रीजी एक चेतना यात्रा में गये। उस गांव का नाम है हटूंडी, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सी.एम.एच.ओ. से कि बुलवाओ लेडी डाक्टर को और शिशु डाक्टर्स को। उसने जवाब दिया कि मैं कहां से लाऊं, मेरे जिले में है ही नहीं, कहां से लाऊं। स्वास्थ्य चेतना यात्रा के माध्यम से आपने क्या किया कि आपने हास्पिटल खाली किये और गांव में डाक्टर्स भेज दिये। आपका जो डाक्टर इलाज कर रहा है पुष्कर में उसको आपने भेज दिया हटूंडी में, जो कर रहा है पीसांगन में वह भेज दिया दांतला में। इस प्रकार से आपने जो लीपापोती की है, यह सारा आपने अपनी सरकार के अंर्तविरोध को छिपाने के लिए और सरकारी पैसे पर मुख्य मंत्रीजी का प्रचार-प्रसार करने के लिए किया है। जो कि नितांत गलत है और यह स्वास्थ्य विभाग के पैसे का क्रिमिनल वेस्टेज है।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय,

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26 एवं मांग संख्या 51 में माननीय मंत्रीगणों की रिप्लाई व दोनों मांगें पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

**श्री सभापति:** क्या सदन की अनुमति है।

**(स्वीकृत)**

सदन की अनुमति से समय बढ़ाया गया।

## मांग संख्या-26 एवं 51 पर विचार

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): सभापति महोदय, जिस स्वास्थ्य चेतना यात्रा में स्वास्थ्य मंत्रीजी जाये, उसके अंदर वहां डाक्टर्स नहीं हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां सिर्फ आपने क्या किया है कि वहां पर केवल विटामिन सी की गोलियां बांटी हैं, आयरन की बांटी हैं। वह बांटना इसलिए आपकी मजबूरी थी कि आपकी वह एक्सपायरी डेट की गोलियां थी। अभी देखिये इसमें, आप इतने निरंकुश हो गये कि एक्सपायरी डेट की दवाइयां उप राष्ट्रपति के किट के अंदर थी, उसके बाद आपके जो विभाग के व्यक्ति थे उन्होंने स्वीकार किया और उसकी हम जांच करा रहे हैं और सैकंड डे ही जांच की रिपोर्ट आयी कि लीपापोती सरकार कर रही है। उप राष्ट्रपति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। उस व्यक्ति के किट में एक्सपायरी डेट की दवाइयां हों। आप देखिये कि आज के अख़बार में न्यूज है कि भवानी भड़के, बाड़मेर के हास्पिटल में जब स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी गये तो उन्होंने देखा कि एक्सपायरी डेट की दवाइयां पड़ी हुई हैं तो यह स्थिति जिस सरकार में हो वह सरकार किस मुंह से स्वास्थ्य की बात करती है। आप शेर पढ़ लें, चाहे कितने ही शेर पढ़ लो। शेर पढ़ने से इलाज नहीं होता है।

**श्री भवानी जोशी** (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): सभापति महोदय, कम से कम इस सरकार के मंत्री सब सेंटर्स तक तो जा रहे हैं और जाकर के देख रहे हैं। पिछली सरकार में आपके मंत्री किसी सब सेंटर पर या पी.एच.सी. पर गये हों तो आप बता दें।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): मैं इसलिए चोर हूं कि मेरा पड़ोसी चोर है, यह कोई जवाब नहीं हुआ ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): बाहेती जी ...(व्यवधान) अफसोस तो इसी बात का है कि सरकार के मंत्री वहां जाते तो हैं लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं होता है।

**श्री भवानी जोशी** (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): हम जहां गये कार्यवाही करके आये ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हम अभी देख लेंगे और दूसरी बात हमारी पूरी सहानुभूति मंत्रीजी आपके साथ है। आपके पास उसके अलावा कोई काम ही नहीं है कि सब सेंटर्स देखते रहें पांच साल में।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): सभापति महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि सरकार स्वास्थ्य को लेकर कितना गंभीर है। चाहे वह दवा की बात हो, चाहे वह स्वास्थ्य केन्द्रों की बात हो। चाहे वह ए.एन.एम. की बात हो और चाहे गांवों की बात हो, आप यह देखिये, मैं इससे आगे और बताता हूं कि आपके एक मेडिकल कालेज में प्रिंसिपल रैंक का आदमी प्राइवेट डायग्नोसिस के आधार पर, आठ साल की एक बच्ची का कैंसर का इलाज करा देवे, बाद में उसकी जब जांच करायी जाये, जब वह होती है काम्प्लीकेटेड तो उसकी जांच में पाया कि कैंसर ही नहीं है। यह कागजात मेरे पास में है। आप चाहें तो मैं टेबल कर सकता हूं ...(व्यवधान) इससे बड़ी दुर्गति आपके स्वास्थ्य विभाग की क्या होगी और उसके बाद भी यदि स्वास्थ्य मंत्रीजी इस पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं तो मैं ऐसी संवादहीनता के लिए आपको कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आप देखिये, आप मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं इसको टेबल करूं। आप देखिये, आशा नाम की बच्ची है। इसका ट्रीटमेंट किया है और गलत इलाज किया है। दुबारा जब उसी कालेज में उसकी जांच करायी तो पता पडा की कैंसर नहीं है। जब कॉलेज में व्यवस्था अवलेबल है फिर बाहर आपने क्यों जांच कराई। बाहर जांच कराई, गलत जांच आ गयी। अब वह आठ साल की बच्ची जिसको आपने कीमोथैरेपी दे दी, मैं इसको समझ सकता हूं चिकित्सक होने के नाते कि आपने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। मैं चाहता हूं कि इसको टेबल करूं। उसकी आप जांच करायें।

**श्री सभापति:** यह क्या कटिंग है क्या अख़बार की।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): कटिंग है।

**श्री सभापति:** तो कोई इसकी जरूरत ही नहीं है। सरकार के पास आती है कटिंग।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): इसमें रिपोर्ट है। इसमें जांच रिपोर्ट भी है सी.एम.एच.ओ. की।

**श्री सभापतिः** बता देना आप।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): नहीं, आप इसको देखिये। बहुत गंभीर मामला है यह क्योंकि जो इलाज करने वाला है वह व्यक्ति प्रिंसिपल रैंक का है कोई आर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। इस पर आप जांच कराकर के एक्शन लेवें ताकि उन लोगों को पता पड़े कि इसका क्या होता है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो इतनी बड़ी बातें करते हो कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, मैं फिर कहता हूं कि सत्ता पक्ष के विधायक ने एक बात कही थी कि आपकी जीडीपी से काम चलने वाला नहीं है। आपके बजट सरप्लस से काम चलने वाला नहीं है। काम चलेगा जब गरीब व्यक्ति को, ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति को आप इलाज दिलवा दें।

सभापति महोदय, डाकटर आपके द्वार की बात मैं आपको बताता हूं, वह एक ही बात है जन चेतना यात्रा दोनों एक ही हैं। आपने पी.एच.सी. खोल करके, सी.एच.सी. खोल करके डाक्टर वहां भेज दिये। मैं तो अजमेर जिले की बात कर रहा हूं, इस तरह से आंखें मत मूंदों। अभी मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, आंखें मत मूंदें इस बात से। सत्य की बात को मानता है यह सदन, जहां हम कहते हैं कि सत्य का सदन है तो सत्य बात होनी चाहिए। मैं बात वह कह रहा हूं जो कि हकीकत है। मैं कोई पालिटिक्स नहीं कर रहा हूं। मैंने धन्यवाद दिया मुख्य मंत्रीजी को ए.एन.एम. भर्ती करने के लिए, मैंने धन्यवाद दिया मुख्य मंत्रीजी को कि वह एम्बुलेंस परचेज कर रही हैं। लेकिन उम्मीद हम यह करते हैं कि बिना किसी प्रकार के भेदभाव के आप ए.एन.एम. को अथवा उन एम्बुलेंस को वहां पहुंचाये जो कि रिमोर्ट विलेजेज हैं। जहां उसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि पांच एम्बुलेंस काम आ रही हैं स्वास्थ्य मंत्रीजी के, पांच एम्बुलेंस काम आ रही हैं सी.एम.एच.ओ. साहब के और पांच आ रही है प्रिंसिपल साहब के। ऐसा आज तक होता आया है। मैं आपको आगे बताता हूं।

**अनेक माननीय सदस्यः** यह तो कांग्रेस के राज में बहुत हुआ है ... (व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): जननी सुरक्षा योजना के अंदर आप

यह देखिये कि आपने भुगतान किया 600 और 1000 रुपये और देय होगा 1400 और 1600 और उसके अंदर आपने क्या किया है कि इसमें आप तीन करोड़ रुपये तो वैसे ही जीम गये कि पता नहीं पडा उस बात का। उसका रजिस्ट्रेशन तो कम है और आपने ज्यादा दे दिया पेमेंट यह स्थिति है।

सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता आपको बता रहे थे कि स्कूल हैल्थ प्रोग्राम में भी घपला, पांच से सात साल के बच्चों के लिए विटामिन की खुराक प्रतिदिन 40 से 60 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं है और आपने कितनी दी 100 मिलीग्राम की।

क्यों दिया आपने? क्योंकि आपने जो दवाइयां पर्चेज की वह खपानी थी और आपकी जो जन चेतना यात्रा थी वह इतने बढ़िया समय में निकाली, आप लोगों ने सोच समझ कर, मैं धन्यवाद देता हूं, जो आपके सलाहकार हैं उनको कि किस प्रकार से पूंजी का आप उपयोग करते हो, मेनिपुलेशन करते हो, आपने सबको मात कर दिया, आपके पास बहुत एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, घोटाला करने वाले, पैसा खा जाओ, कोई पता नहीं पड़ता इस बात का। मैं कहता हूं कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप अपनी रिप्लाई में यह जवाब दें कि जो आरोप लगे हैं डिपार्टमेंट के ऊपर यह 3 करोड़ रुपए के हैं और इस प्रकार जो गोली महंगे भाव पर ली है उसको आपने निकाल दिया टेण्डर से, शोर्ट टर्म टेण्डर कर दिया और उस एक पार्टी को लाभ देने के लिए टर्न ओवर बढ़ा दिया उसको आपने कि दो करोड़ टर्न ओवर होना चाहिए जबकि होना यह चाहिए था कि कम से कम..

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बाहेती साहब, पूरी जानकारी लेकर फिर बोलो प्लीज।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): मैं कहता हूं कि भगवान करे यह न्यूज़ गलत निकले और आप सही निकलें, लेकिन इसकी जांच तो कराएं आप। जांच कराकर सदन को बता देना कि मैं गलत था, जांच में सही निकली। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं आपसे, अब जो आपको कह रहा हूं कि इस प्रकार से माननीय सभापति महोदय कि हमारे अजमेर के अंदर, यह बात छोड़िए आप, यह जयपुर की न्यूज है कि एस एम एस के अंदर डाक्टर मांगे हैं, 25 एसोसिएट प्रोफेसर, 30 रेजीडेंट, 300 नर्सिंगकर्मी, जिसको आप बार-बार कहते हो कि हमारा प्रेस्टीजियस, हमारा एम्स, हमारी नाक एस एम एस है, वहां

स्टाफ की यह स्थिति है तो मैं यह कहता हूं कि किस प्रकार से आप बजट लेना चाहते हैं? जब बजट का आप पूरा उपयोग नहीं कर सकते, जब बजट को आप सही दिशा में खर्च नहीं कर सकते, जो खर्च करो वह घपलों में करो। यह यहीं खतम नहीं होता है। आप देखिए कि आपने जो आशा सहयोगिनी किट खरीदे हैं, आपके पास आशा सहयोगिनियां थीं 26 हजार, किट आपने खरीदे 40 हजार, बाकी किट कहां जाएंगे? जनरेटर सैट जो आपने खरीदे हैं 1 लाख 80 हजार में, उनकी कीमत 40 हजार रुपए है, इसका जवाब कौन देगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपकी सरकार ने एक जांच दल बनाकर इसकी जांच कराई है, उस जांच रिपोर्ट को आप सदन के अंदर रखें। अपने जवाब के अंदर जो जनरेटर में घपला किया, आशा सहयोगिनी किटों में घपला किया, डी डी टी किट में जो घपला किया, फोटो कापी मशीन, और तो और लेप्रोस्कोपिक मशीनों को ठीक करवाने के लिए कितना तो उसका माजना है कितनी उसकी लात, उसमें घपला, वह बिना टेण्डर के, आपने कोई भी जगह छोड़ी हो वह बता दीजिए। एक संवेदनशील मुख्य मंत्री, एक संवेदनशील चिकित्सा मंत्री जो स्वयं चिकित्सक हैं, उनके विभाग में इतनी संवेदनहीनता, उनके विभाग में इतनी घपलेबाजी हो तो कैसे काम चलेगा, आप बता दीजिए मुझे?

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) अपनी तरह का सबको मत समझो। ...(व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो चाहता हूं कि मेरी सब बातें व्यर्थ निकले।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आपके राज में क्या-क्या हुआ है जरा उसके बारे में विचार करो।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): वह आप बोलना।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): हां, वह तो बताऊंगा लेकिन आप ऐसे उपदेश देने की कोशिश मत करो। ऐसे आरोप लगाये जा रहे हो जिसका कोई आधार नहीं है, आपको खुली छूट मिली है इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिस प्रकार चाहे उस प्रकार बोलना शुरू कर दें।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइण्ट आफ आर्डर। इस राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

नियमों में प्रावधान है कि कोई माननीय सदस्य यदि बोलता है तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति व्यवधान नहीं डालता है। यह आपकी आज्ञा से बोल रहे हैं, और वह बिना आपकी आज्ञा से बोल रहे हैं। यह चेयर का कर्तव्य है कि उनको हिदायत दें कि वह बीच में नहीं बोल सकते और व्यवधान नहीं कर सकते।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): थोड़ा आधार सहित बोलो तो समझ में आता है, बिना आधार के अनर्गल बोलते जा रहे हो। यह ठीक नहीं है, बोलो तो कोई आधार के साथ बोलो तो समझ में आता है, आपने चाहे जिस प्रकार से बोलना शुरू कर दिया, यह ठीक बात नहीं है। सभापति महोदय, जरा इस पर रोक होनी चाहिए, वे मर्यादा में रहें यह सदन में बोलते जा रहे हैं, जैसे चाहे बोलते जा रहे हैं, चाहे वैसे बोलते जा रहे हैं, जो मन में आए वह बोलते जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

**श्री सभापति:** आप बैठ जाइए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यह कहावत चरितार्थ कर रहे हैं।

**श्री सभापति:** अब अंकित न हो।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): xxx

**श्री सभापति:** I won't allow. I won't allow like this. आप बोलिए, डिबेट में भाग लीजिए. No, no, I won't allow.

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): xxx

**श्री सभापति:** आसन पांवों पर, आप बैठ जाइए। अब मैं खड़ा हूं, प्लीज सिट डाउन।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): xxx

**श्री सभापति:** आप जो चाहते हैं वह नहीं बोलेंगे। उनको जो बोलना है, मंत्रीजी उसका जवाब दे देंगे। अब आप विराज जाइए।

देखिए, जो व्यवस्था है वह मैं हाउस को बता देता हूं, आप नए सदस्य हैं, केवल अनपार्लियामेंटरी वर्ड या नियमों के विपरीत जो बोलते हैं उन्हीं को रोका जा सकता है। कोई भी मंत्री यहां मौजूद है वह जो बोलेंगे उसका जवाब वह देंगे, मौजूद हैं सदन में इसलिए आप इण्टरफियर मत करिए।

(श्री सभापति)

आपको कुछ बोलना है तो आप चीफ व्हिप को अपना नाम दे दीजिए और उस पर अपने विचार रखिए। कोई बोल रहा है माननीय सदस्य उनके बीच में खड़े होकर इण्टरफियर मत कीजिए प्लीज।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): xxx

**श्री सभापति:** मंत्रीजी जवाब देंगे, सरकार जवाब देने के लिए बैठी है न, आप क्यों बोल रहे हैं? खण्डन करेंगे उस बात का। नो नो, प्लीज सिट डाउन।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): xxx

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): xxx ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** अब मंत्रीजी खडे हैं और आप फिर बोल रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं इण्टरवीन बीच में नहीं करना चाहता, पर माननीय सदस्य यह भूल गए कि आरोप लगाना बड़ा आसान है। पर सारी वस्तु स्थिति की जानकारी इनके सामने आएगी तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह जिस संविदा की बात कर रहे हैं, जिस गोली की बात कर रहे हैं इसका टेण्डर हुआ था 10.03.2003 को, उस समय शासन में कौन था? शासन में ये थे। मतलब इनके समय में जो कुकृत्य हुआ उस कुकृत्य को यह हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे तो एक-एक चीज का खुलासा हो जाएगा और जो आरोप लगा रहे हैं...

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप टेण्डर की बात करते हो, स्वीकृत कब हुआ, वह तारीख भी बता दो न, आपकी सरकार के वक्त में हुआ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, कह रहा हूं, मेरी बात सुन लें। टेण्डर आपने लिया, टेण्डर खोले आपने और स्टोर पर्चेज ...(व्यवधान) इसके समय की थी और आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर।

**श्री संयम लोढा** (सिरोही): अगर आपका दामन साफ है तो आप कहो न पूरी बात। ऑनरेबल मिनिस्टर, अगर आपका दामन साफ है तो पूरे तथ्य रखें आप। यह आधे-आधे मत रखो आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल पूरे तथ्य रखेंगे। अखबारों में कोई चीज छप गई इसका मतलब यह थोड़े हो गया, अखबारों के आधार पर सभापति महोदय, इस सदन में नियम और परम्पराएं

हैं, यहां अखबारों के आधार पर आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं, नोटिस देकर आते, नोटिस देकर लगाते आरोप।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): वह यही तो कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए उन्होंने यही तो कहा है कि ईश्वर करे यह बातें गलत निकले अखबारों की, इन्होंने यही तो कहा कि जांच करा लीजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कहो न, इसकी आप कराओ न, यह बात आपने सही कही, बहुत सेंसिबल बात है।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): मैंने पहले ही बोला है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ऐसी बात किया करो न आप, जरा सीख लो इनसे।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): जांच नहीं, प्रमाणित है, प्रमाणित है, प्रमाणित है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रमाणित नहीं है। वह तथ्य बता रहे हैं, यह आपके समय का कुकर्म है।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): इन्होंने यही कहा है, आप अंदर नहीं थे सदन के, यह बात कही है पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी। ...(व्यवधान) आप बाद में बोल देना।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन इतना ज्यादा इर्रिटेट कर रहे हैं कि मेरे लिए तब तक रुकना भी बहुत मुश्किल होगा। या तो ये तथ्य से बोलें, नहीं तो मैं मुंह तोड़ जवाब अभी दे सकता हूं इनको, इस तरह की तथ्यहीन बातें करने का यहां कोई मतलब नहीं है। ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ... जिस तारीख को टेण्डर खोले गए थे उस तारीख को भी मैं कोट कर सकता हूं, उस समय शासन में कौन बैठे थे, आज हमारे ऊपर कह रहे हैं यह बात।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): किस-किस तारीख को क्या-क्या हुआ, पूरा पढ़ लो आप, सब मालूम पड़ जाएगा राजस्थान की जनता को कि क्या किया आपने।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल एक-एक चीज बता देंगे। इस तरह से आरोपित करने से आरोप लग जाएगा कोई?

**श्री सभापति:** आप जारी रखिए।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी यह भूल गए कि चांद पर दाग नहीं लगता है, आप यदि पाक हैं तो कुछ दाग लगेगा नहीं आप पर। मैंने यह कहा आपसे, आप थे नहीं यहां पर, मैंने कहा कि भगवान करे यह बात गलत निकले।

मुख्य मंत्रीजी संवेदनशील हैं, मंत्रीजी संवेदनशील हैं लेकिन इसकी जांच करवा लें पता पड़ जाएगा। अब आपको मैं एक तुलना दे रहा हूं। फोलिक एसिड और आयरन की गोली खरीदी आपने, मैं उसकी रेट दे रहा हूं। राजस्थान में 15 रुपए प्रति सौ, गुजरात में सात रुपए प्रति सौ, तमिलनाडू में छह रुपए अड़तीस पैसे प्रति सौ, मध्यप्रदेश में चार रुपए प्रति सौ, पश्चिमी बंगाल में चार रुपए अस्सी पैसे प्रति सौ की रेट थी, अलग-अलग। यह भी आपके समय में हुआ है, आप इसकी जांच करवा लें, मैं कहां कह रहा हूं कि आप बेइमान हैं, आप तो बहुत साहूकार हैं और 2003 में जो टेण्डर कांग्रेस के राज में हुआ, वह भी आपकी बात सही है, टेण्डर हुआ, आर्डर आपके समय में मिला, ऑर्डर आपने दिया। इसकी आप जांच करवा लो, कोई बात नहीं है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपने कहा है, आप कह दें कि मैं जांच कराने को तैयार हूं, जांच की घोषणा कर रहे हैं न, जांच कराने की?

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जांच करवा चुके हैं। ...(व्यवधान)

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): पिछले 50 सालों की किस-किस बात की जांच कराओगे आप?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपका दामन साफ है तो जांच की घोषणा करो आप। ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप बाध्य नहीं कर सकते वे जवाब देंगे उस समय बताएंगे। ...(व्यवधान)

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): पिछले 50 साल में आपने इतने कुकर्म किये उसकी किस-किस की जांच कराओगे आप लोग। पिछले 50 साल की सारी जांच कराओ। ...(व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, जांच करा चुके हैं और जवाब नहीं, मुंहतोड़ जवाब इसी सदन में दूंगा। आप थोड़ा इंतजार तो करो। ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** बैठ जाइए। Take your seat please. आपके सदस्य बोल रहे हैं उनको भी टोक रहे हैं। इनका समय समाप्त हो चुका है, मैं उनको रोक दूंगा ..(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं आपका ध्यान कार्यवाहक मुख्य मंत्री की टिप्पणी की ओर आकर्षित कर रहा हूं जिन्होंने कहा कि हमारा दामन साफ है और हम हर तरह की जांच कराने को तैयार हैं। तो कराओ ना जांच।

**श्री सभापति:** अब आप विराज जाइए। वे बोल रहे हैं, आपके ही सदस्य बोल रहे हैं।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं मेरा समय बीच में डिस्टर्ब हो गया है, मेरा समय आप कंसीडर करें।

**श्री सभापति:** आप प्लीज समाप्त करिए।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): कर रहा हूं। आप देखिए..

**श्री सभापति:** You have taken a lot of time .

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, जननी सुरक्षा योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ 14144 का और पेमेंट हुआ 44636 का जिसमें एक करोड़ 83 लाख रुपये कहां गये आप इसकी भी जांच करा लें। मुझे बार-बार टोक रहे हैं तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो घोषणा की वो उसने किया नहीं, जो उसने किया वह उसने बताया नहीं, जो बताया वह जमीन पर था नहीं और जो था वह सब घपले में था हमें पता पड़ा नहीं।

अब मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हुआ यह कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद पर भी ध्यान दिया जाए। मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार आयुर्वेद और एलोपैथी को एक ही मंत्री को दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं एलोपैथी और आयुर्वेद की ज्वाइंट टीम बनाकर उसमें रिसर्च किया जाए ताकि हम राजस्थान की जनता को नहीं, देश की जनता को सस्ता और सुलभ इलाज दिला सकें। यह आपकी नई पहल होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ओर आप ध्यान देंगे। इसके अलावा मैंने जो कटमोशन में कुछ मांगें मंत्री महोदय से की हैं मैं सोचता हूं मेरे पर गुस्सा

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

करके बिना किसी दुर्भावना के और मेरा दण्ड मेरी जनता को दिये बिना वे मांगे पूरी करेंगे यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं, धन्यवाद, जयहिन्द।

**श्री सभापति:** श्रीमती अनिता भदेल।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई की मांग संख्या-26 पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। निश्चित रूप से पिछले तीन सालों में हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य किये हैं उनकी तुलना यदि कांग्रेस के पांच वर्षों के शासन से की जाए तो मेरे प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों को यह ज्ञात हो जाएगा कि चाहे वो चिकित्सकों की भर्ती का मामला हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नये खोलने का विषय हो या चिकित्साकर्मियों की आवास की व्यवस्था हो सभी क्षेत्रों में निश्चित रूप से हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किये हैं और सुदूर ग्राम में बैठे हुए उस व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास किया है जो हमेशा इस अपेक्षा के साथ निगाहें अपनी जमाकर यह देखता रहता है कि मेरे पास भी डाक्टर की सुविधा हो, जब मैं बीमार होऊं तो मुझे नि:शुल्क दवाइयां मिले, मेरे इलाज के लिए सरकार की तरफ से समुचित व्यवस्था की जाए।

हमारी सरकार ने जितने भी प्रयास किये हैं संपूर्ण राष्ट्र और हमारे राज्य में उसकी अपेक्षित परिणाम नहीं निकल रहे और इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या की वृद्धि। इस जनसंख्या की वृद्धि ने हमने जितने भी प्रयास किये हैं उन सभी को इतना छोटा बना दिया है कि हमारे प्रयास गौण नजर आते हैं, हमारे प्रयास दिखायी नहीं देते। परिवार कल्याण के माध्यम से जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है कि इस जनसंख्या वृद्धि को हम किस प्रकार रोकें। हम प्रयास में हैं कि किस प्रकार से मातृ मृत्यु दर को कम किया जाए, शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। इन प्रयासों का यह परिणाम सामने आया है कि हमारा सूचकांक बताता है शिशु मृत्यु दर 75 प्रति हजार से घटकर 67 प्रति हजार हो गई है। इसमें 10.67 प्रतिशत की कमी इन वर्षों में आई है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 677 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर 445 प्रति लाख जीवित जन्म हुई है जिसमें 34 प्रतिशत की कमी हुई है। इसी प्रकार जन्म दर 30.4 से घटकर 29 प्रति हजार थी उसमें 4.29 प्रतिशत की कमी हुई है और आगे यदि मातृ मृत्यु दर की

(श्रीमती अनिता भदेल)

कुल बात करें तो 7.6 कम होकर 7 हो गई जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। यह सूचकांक प्रदर्शित करता है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हुआ है, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक वृद्धि हुई है और यह परिणाम दिया है इस गुणात्मक वृद्धि ने कि निश्चित रूप से परिवार कल्याण के क्षेत्र में जो कदम उठाने चाहते हैं जिस जनसंख्या वृद्धि को हम रोकना चाहते हैं उसके जो लक्ष्य तय किये थे उन लक्ष्यों की ओर हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जननी सुरक्षा योजना, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है के विषय में आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य रामलालजी शर्मा ने कहा था कि यह योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हम सुरक्षित मातृत्व यदि देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से संस्थागत प्रसव को बढ़ाना ही होगा। यदि हम शिशु मृत्यु दर को कम करना चाहते हैं तो हमें संस्थागत प्रसव को बढ़ाना होगा, लेकिन जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा स्टाफ है, जो डाक्टर हमारे पीएचसी में काम करता है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर लगा हुआ है उसकी रुचि इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रति दिखायी नहीं देती और इसी का यह कारण है कि जितना लाभ हमें महिलाओं को देना चाहिए उतना लाभ हम नहीं दे पा रहे हैं। महिलाएं परेशान होती हैं और मैं तो यह कहूंगी इस विषय में यह सुझाव देना चाहूंगी कि यदि प्रसव के सात दिन के भीतर-भीतर महिला को भुगतान नहीं होता है तो उस डाक्टर के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए ताकि महिलाएं उत्साहित होकर प्रसव के लिए हास्पिटल में आएं और हम सुरक्षित मातृत्व की जो कल्पना करते हैं उसको पूरा कर सकें।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से सरकार ने एएनएम की भर्ती के बारे में कहा है और कहा है कि वह प्रत्येक सब सेंटर पर दो एएनएम की व्यवस्था करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की आपने व्यवस्था की है, पर शहरी क्षेत्र में जितने भी होस्पिटल हैं, हमारा जो मुख्य चिकित्सालय है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय वहां पर इतने सारे पद खाली हैं नर्सिंग स्टाफ बहुत कम है और यह एक ऐसा चिकित्सालय है जो संभाग मुख्यालय पर स्थित है जहां पर अजमेर के अलावा भीलवाड़ा, टौंक, नागौर जिलों के अलावा पाली, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बीकानेर, जालौर, राजसमन्द आदि जिलों के समीपवर्ती रोगी भी अपना इलाज कराने के लिए यहां आते हैं। इस

(श्रीमती अनिता भदेल)

चिकित्सालय में कई महत्वपूर्ण बीमारियों के सुचारू इलाज हेतु अलग-अलग यूनिट हैं जैसे कार्डियोलोजी है, न्यूरोलोजी, न्यूरो सर्जरी है, लेकिन न्यूरो सर्जन की स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण से बहुत सारे केसेज जयपुर रैफर किये जाते हैं जिससे वहां लोगों को परेशानी होती है। न्यूरोलोजी, नेफ्रोलोजी, गेस्ट्रोलोजी, प्लास्टिक सर्जरी की भी व्यवस्था यहां उपलब्ध है, लेकिन पद खाली होने के कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार हृदय रोग से संबंधित चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए वहां कैथ लेब लगायी गई है। सरकार का सहयोग रहा है, सभी माननीय विधायकों ने अपने-अपने विधायक फण्ड से उसमें सहयोग दिया है और प्रथम बार इस होस्पिटल में 1985 में हृदय रोग विभाग की घोषणा हुई थी, राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी तभी से इस विभाग की विकास गति इतनी धीमी है कि आज भी उस विभाग में वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जो एसएमएस होस्पिटल या अन्य किसी होस्पिटल में उपलब्ध हैं। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि आप इस कैथ लेब हृदय रोग से संबंधित सर्जरी हो सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके लेकिन यहां जयपुर के एसएमएस के हास्पिटल में इतनी दबाव नहीं बने, अजमेर के इस हास्पिटल में भी इसकी सब सुविधा हो जाए तो शायद हम चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार कर पाएंगे और जो व्यवस्था इस इलाज की कमी के कारण से अकाल मृत्यु हो जाती हैं उनको भी हम बचा पाएंगे। इसी प्रकार मैं माननीय दिगम्बर सिंहजी यहां बैठे हैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पिछले 3 वर्षों से अजमेर शहर में एकमात्र सैटेलाइट हास्पिटल का आरयूआईडीपी में उसके भवन का निर्माण किया है, तीन करोड़ रुपये की लागत से उस भवन का निर्माण हुआ है, बहुत सुन्दर भवन है लेकिन उस तीन करोड़ रुपये का हम इसलिए फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि न तो वहां स्टाफ है, न पैरा-मेडिकल स्टाफ है, न कोई अन्य सुविधाएं हैं। यदि हमको उस तीन करोड़ रुपये का फायदा उठाना है तो निश्चित रूप से मैं आपसे आज आग्रह करती हूं इस बात के लिए क्योंकि कई बार विधान सभा क्षेत्र में जाकर बोलना पड़ता है कि आप क्या लेकर आए तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे इन तीन सालों के प्रयासों को आप इस बार व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इस संबंध में कोई न कोई घोषणा अवश्य करेंगे। इसी प्रकार, मैं आपका ध्यान एक दूसरी बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले आपने एक दानदाता द्वारा

(श्रीमती अनिता भदेल)

दिये गये भवन का उदघाटन किया था, उस दानदाता ने लगभग 20 लाख रुपये की राशि का भवन और अन्य चिकित्सा के उपकरण एक्सरे मशीन और बहुत छोटे-छोटे उपकरण जो चिकित्सा के लिए आवश्यक होते हैं उनको दान में दिया है लेकिन उस हास्पिटल में एक्सरे टेक्निशियन नहीं है, एक्सरे की मशीन दान में मिल चुकी है, वहां वार्ड है लेकिन स्त्री चिकित्सक की वहां व्यवस्था नहीं है, इसके कारण से हम डिलीवरी की सुविधा वहां उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो मेरा आग्रह रहेगा कि जिस दानदाता ने अच्छी मंशा के साथ जो दान किया है उसका हम उपयोग करें और जनता को उन सुविधाओं का लाभ हम दिला पाएं। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आपने जो एनआरएसएम जो स्कीम है उसके तहत अजमेर शहर में स्लम एरिया में डिस्पेंसरियों के प्रस्ताव सरकार ने आमंत्रित किये थे। जिला प्रशासन ने लेकिन मापदण्डों का उन प्रस्तावों में अनदेखी की गई। मेरा आपसे आग्रह है कि जो मापदण्ड स्कीम में उन डिस्पेंसरियों के लिए हैं वह मापदण्डों का ध्यान रखते हुए यदि आप प्रस्ताव तैयार करेंगे तो जो उद्देश्य हमारा है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं, हम उस व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हैं, जहां तक हमारी सेवाएं अभी तक पहुंची नहीं है तो ऐसी सेवाओं के प्रस्ताव मंगाएं और उन लोगों को भी इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस प्रकार से, आप इसकी यदि व्यवस्था करेंगे तो मैं समझती हूं कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, बस दो मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगी। मैं आपसे जैसा कि पूर्व में मेरे साथी सदस्य ने कहा कि रेबीज के जो टीके आते थे, पहले सरकारी स्तर पर जो व्यवस्था होती थी, हमारे जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में वह उपलब्ध होते थे लेकिन अब आए दिन हमारे पास विधान सभा क्षेत्र से लोग आते हैं कि हमको रेबीज के टीके नहीं मिल रहे हैं इसके कारण से आप चिट्ठी लिख दीजिए, हमको वहां निशुल्क मिल जाएंगे तो रोज इस प्रकार से केसेज आते हैं तो यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो लोगों को जो गरीब जनता है, जिनके पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं हैं उनको भी इसका फायदा मिल पाएगा। मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि जिस प्रकार से चिकित्सालय में एक चिकित्सक होता है, वह अपने हास्पिटल की व्यवस्था पूरी भी करता है और अपने चिकित्सकीय दायित्वों का निर्वाह भी करता है तो दो जिम्मेवारियां उसके पास होती हैं। मैं आपसे एक सुझाव देना चाहूंगी कि क्यों न हम जो प्रशासकीय कार्य है उसके लिए अलग पद का सृजन

(श्रीमती अनिता भदेल)

करें और उस पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाएं जिसका चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है और चिकित्सा के लिए हम चिकित्सक को ही रखें ताकि वह अपने ध्यान से और तन्मयता से लोगों का इलाज कर पाएंगे और इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हास्पिटल्स में होती हैं उनसे भी हमको बचा जा सकेगा। एक होम्योपैथिक चिकित्सालय का आपने, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि नये होम्योपैथिक चिकित्सालय की आपने वहां स्वीकृति प्रदान की। जिस जगह वह स्वीकृत हुआ है, वहां की हाउसिंग सोसाइटी उस भवन के निर्माण के लिए उस हास्पिटल के भवन के निर्माण के लिए अपनी जमीन देना चाहती है। यदि आप प्रावधान करेंगे उस भवन के निर्माण में अपने बजट में जब घोषणा की तो निश्चित रूप से वह जमीन हमको नि:शुल्क मिलेगी और हम वहां उस चिकित्सालय का भवन निर्मित कर पाएंगे। इसी प्रकार, एक गढ़ी मालयन क्षेत्र है, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां पर आसपास कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां के लोगों ने दान इकट्ठा करके जमीन लेकर के भवन निर्मित कराया है, वहां लाइट का कनेक्शन दिया है, नल, पानी, बिजली सब की समुचित व्यवस्था की है, सिर्फ अब आवश्यकता है कि अब नये एक शहरी डिस्पेंसरी की घोषणा हो जाए तो निश्चित रूप से हम वहां के लोगों को अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा पाएंगे। मेरा पुन: आपसे आग्रह है सेटेलाइट हास्पिटल के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के लिए कि आप इनकी व्यवस्था करें। इसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पत्रकारों को मेडिकल डायरी की सुविधा पिछले बजट सत्र में घोषणा की थी और उनको सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कुछ पत्रकारों की मांग है कि आप उसमें जो वित्तीय प्रावधान आपने किये हैं उसको बढ़ाया जाए क्योंकि 75 परसेंट पत्रकार इस प्रकार के हैं जो उन डायरियों का उपयोग नहीं करते हैं, पर 25 परसेंट ऐसे हैं जिनको उनकी जरूरत है और वह करना चाहते हैं लेकिन बजट में कम प्रावधान होने के कारण वह उसका उपयोग नहीं कर पाते तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको भी यदि बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उन भाइयों को जिस मंशा से हमने उनको यह सुविधा उपलब्ध कराई है वह निश्चित रूप से उस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे।

**श्री सभापति:** वाइंड-अप करिए प्लीज, समाप्त करिए।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): मेरी बात समाप्त हो गई, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

**श्री सभापतिः** डा. दिगम्बर सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, वाद विवाद का उत्तर देंगे। डा. दिगम्बर सिंह। ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): सभापति महोदय, सुबह से तैयारी करके आये हैं हमारे सदस्य। ...(व्यवधान)

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): सभापति महोदय, हमारे कटमोशन हैं, कटमोशन वालों को नहीं बुलाया जाएगा ? वह नहीं तो हमारे क्षेत्र के सुझाव तो लें। ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** कितने बजे तक बुलाएंगे ?

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): दो मिनट में मेरे को बात कहने का मौका दें। ...(व्यवधान)

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): आप पांच पांच मिनट दे दें। ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): इनको पांच-पांच मिनट दीजिए, मांगीलाल जी गरासिया का सबसे ऊपर लिस्ट में नाम था। ...(व्यवधान) बुलवाया नहीं। ...(व्यवधान)

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, पांच-पांच मिनट दे दें ज्यादा नहीं दें तो चार-चार मिनट दे दो आप।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, नाम इनका बीच में था, किसी कारणवश आसन से पुकारा नहीं गया, मेरा निवेदन है, मांगीलालजी सुबह से बैठे हैं तैयारी करके आए हैं। ...(व्यवधान)

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय आसन से व्यवस्था देकर गई हैं, मुझे बुलवाने के लिए। आप कृपा करें मेरे ऊपर।

**श्री सभापतिः** मेरे पास लम्बी लिस्ट है, यदि मैं सब लिस्ट को बुलाना शुरू करुंगा। ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): सभापति महोदय, समय सीमा बांध दीजिए, आप पांच मिनट से ज्यादा समय मत दीजिए। ...(व्यवधान)

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): सभापति महोदय, पांच मिनट का समय भी नहीं देंगे आप निर्दलीय आदमी को तो ऐसा कैसे होगा? ...(व्यवधान) सभापति महोदय, अपनी बात कहने के लिए तो कुछ समय चाहिए। ...(व्यवधान)

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): सभापति महोदय, कुछ लोकल समस्याएं हैं, वह तो बता दो। ...(व्यवधान) मंत्री महोदय बैठ जाइए, पांच मिनट।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): सभापति महोदय, पांच मिनट में मैं अपनी बात कह दूंगा। ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** जितने सुझाव थे वह सब आ गये, अब आप कोई व्यक्तिगत बात कहनी हो तो वह अलग बात है। ...(व्यवधान)

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): मैंने कटमोशन दिये हैं, मेरा पहला नम्बर था, फिर भी मेरे को समय नहीं दिया। ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): सभापति महोदय, सूची में नाम इनका तीसरे नम्बर पर था, किसी कारणवश मिस हो गया, हमारा आपसे निवेदन है, आसन से कि ये आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, कभी बोले नहीं, अपनी सीधी सी बात कहेंगे, आप इनको अलाउ करिए। ...(व्यवधान) यह तो तारीफ ही तारीफ करेंगे, कोई कायदे की बात प्रतिपक्ष की तरफ से आएगी। ...(व्यवधान) इन्हें तो बस तारीफ ही करनी है और करना क्या है, मंत्री महोदय जवाब दे देंगे। ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** देखिए, बहुत सदस्य हैं बोलने वाले। ...(व्यवधान) प्लीज।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सभापति महोदय, नहीं मुझे टाइम नहीं चाहिए। ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): हमारा आपसे निवेदन है, सभापति महोदय, आप यह मांगीलालजी गरासिया को तो बुलवाइए। ...(व्यवधान) सुबह से तैयारी करके बैठे हैं, आप बढ़ाइए टाइम इसमें क्या बात है। ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): विधान सभा में चिकित्सा और शिक्षा की मांग जिस दिन रखी जाती है सदन कभी 11-12 बजे से पहले उठता नहीं है। यह क्या बात है कि जो माननीय सदस्यों ने कटमोशन दिये हैं, पांच-पांच मिनट बोलना चाहते हैं, बोल लेंगे, ये सत्ता पक्ष के लोग तो ऐसे ही इनके काम, जो बोलना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, बोलने दीजिए। क्या दिक्कत है और जिनको जाना है वह चले जाएं।

**श्री सभापति:** सदन का मूड देखिए।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सदन का मूड हमारा सुनने का है, नहीं तो हम मंत्रीजी को फिर क्यों सुनेंगे? यह कोई जरूरी है क्या? इसलिए आप पांच मिनट आदिवासी क्षेत्र से आते हैं माननीय सदस्य उनको दीजिये। इधर की तरफ से भी कोई बोलना चाहे तो हम उनको सुन लेंगे।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सभापति महोदय, आपसे निवेदन यह है कि आप माननीय सदस्यों को तो बोलने का अवसर प्रदान करें और अगर समय की कमी है तो मंत्रीजी का रिप्लाई पढ़ा हुआ मान लो।

**श्री सभापति:** ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है, आपसे पहले अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देकर के गई हैं मुझे बुलवाने के लिए। आपसे कृपा है कि मेरी बात कहने के लिए मौका दें।

**श्री सभापति:** दूसरी मांग पर बोल लेना आप।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): दो मिनट में खतम कर दूंगा।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): सभापति महोदय, आपने मुझे 5-10 मिनट बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** आपको भी दे देंगे। दो मिनट में बात समाप्त कीजिये प्लीज।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देकर के गई हैं।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है....

**श्री सभापति:** दो मिनट में समाप्त कीजिये।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): मैं बहुत ही आपका आभारी हूं। विशेष तौर से मैं आदिवासी अंचल के उस एरिया की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां ट्राइबल सब प्लान एरिया का जो उदयपुर अंचल का मामला है उसमें सभापति महोदय, आप देख रहे हैं कि जहां पर जिस गांव में हास्पिटल है वहां पर डाक्टर नहीं है, जहां पर डाक्टर है वहां पर नर्स नहीं है और नर्स है वहां पर दवाइयां नहीं हैं। यह बहुत बड़ा ज्वलंत

(श्री मांगीलाल गरासिया)

मामला मेरा ही नहीं सभी माननीय सदस्यों का है। इस प्रकार की समस्या हमारे पूरे एरिया में है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां कुल 6327 पदों के अनुरुप 1202 पद रिक्त हैं विभिन्न श्रेणी के। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो पूरा दूरगामी क्षेत्र कोटड़ा और गोगुन्दा है और इसमें विशेष तौर से कोटड़ा का पूरा एरिया है वह पूरा बिखरी आबादी का क्षेत्र है और बिखरी आबादी के क्षेत्र में कई उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि टेपूर जो उप स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर तीन वर्षों में एक बार भी उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुला। टेपूर जैसा एरिया जो मेपूर की पंचायत में है उसमें तीन वर्षों में एक बार भी यदि उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुलेगा तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर दूर-दराज के एरिया में रहने वाले बच्चों का कभी समय पर टीकाकरण हुआ होगा या नहीं हुआ हो। वहां पर पल्स पोलिया की दवा समय पर मिली होगी या नहीं मिली होगी? उस एरिया के लिए क्या वहां पर समुचित व्यवस्था दवाइयों के रूप में उस एरिया के आदिवासी भाइयों के लिए हुई होगी या नहीं हुई होगी। माननीय सभापति महोदय, उस एरिया में जहां दूरगामी क्षेत्र है, पूरा आदिवासी अंचल है और बच्चों में कुपोषण की बीमारी के रूप में उन लोगों के सामने समस्या व्याप्त है। कुपोषण की बीमारी की वजह से जो बच्चे, आप जानते हैं कि एक वर्ष में 18 लाख बच्चों का जन्म होता है और 18 लाख बच्चों में से सवा लाख बच्चे प्रतिवर्ष बीमारी के शिकार होकर के मौत के मुंह में चले जाते हैं तो आप अंदाजा लगायें। आज जिस तरह से कमी और खामी कुपोषण को लेकर के पूरे एरिया में है उसमें उस कमी और खामी के रूप में जिस तरह विद्यालयों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण के रूप में यदि देखा जाए तो वहां पर बच्चों का ठहराव भी नहीं हो और हैल्थ कार्ड भी उनका नहीं बना है तो क्या उन सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हो पाया होगा या नहीं हो पाया होगा इस गहराई में तो मैं नहीं जाना चाहता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जहां इस राज में 2003-04 में जिस तरह पैसा खर्च होना चाहिए वह उतना नहीं हो पाया। 2005-06 में जिस तरह से पैसा खर्च होना चाहिए था वह भी नहीं हो पाया और यह स्थिति निरन्तर बनती जा रही है और उसमें 26.54 करोड़ रुपये 2004-05 में खर्च करने से वंचित रह गये। इसी तरह से

यदि हर वर्षवाइज समय पर पूरा पैसा खर्च हो गया होता तो मुझे लग रहा है कि उस एरिया में बहुत आमूलचूल परिवर्तन चिकित्सा जगत में हो जाता। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा....

**श्री सभापति:** समाप्त करें। पांच मिनट हो गये, समाप्त करें।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): ...कि नये उप स्वास्थ्य केन्द्र जहां चापा की नाल (मेवाड़ों का मठ) में, भाड़ेल का क्षेत्र ढंखलियात में, माजोड़ा जो भोखाड़ा का एरिया है कुर्रा का, कड़ेच, भूतड़ और जालड़ा, ये जो एरिया है, इतना दूरगामी क्षेत्र है जहां पर यदि उप स्वास्थ्य केन्द्र हो जाता है तो उस एरिया के लिए, उस बिखरी आबादी के उन लोगों के लिए राहत मिल जाएगी। दो मिनट में मेरी बात को खतम करना चाहता हूं, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता माननीय सभापति महोदय।

**श्री सभापति:** दो मिनट तो टोटल मिले हैं। पांच मिनट हो गये।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): मेरे एरिया में रेफरल हास्पिटल पगाड़ा बन जाता है क्योंकि पूरे उस एरिया के लिए क्योंकि दानदाताओं के द्वारा उस हास्पिटल को बनाने में जिस तरह सहयोग किया, यदि वह रेफरल हास्पिटल बन जाता है तो उस एरिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। आज जिस तरह नीम-हकीमों की संख्या बढ़ रही है उससे बहुत बड़ी समस्या उस एरिया के लिए फैली है। नीम-हकीम बढ़ते जा रहे हैं और उन नकली दवाइयों से उस आदिवासी एरिया में उनका जो शोषण हो रहा है यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे ट्राइबल सब-प्लान एरिया में डाक्टर, ए एन एम इस बेसिस पर रह सकते हैं, एम पी डब्ल्यू वहां पर यदि पुरुष वर्ग से लगा दिया जाए क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से वह एरिया पूरा बिखरी आबादी का और पहाड़ी जोन है और वहां पर उनको आवास व्यवस्था मिल जाती है तो यह ठहराव की व्यवस्था हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए वहां पर उनकी आवास व्यवस्था हो सके और आवास व्यवस्था के साथ में वहां पर एम पी डब्ल्यू जैसे व्यक्ति कुछ लग जाएं तब जाकर के उस एरिया के लिए चिकित्सा जगत में एक नया आमूलचूल परिवर्तन होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने बहुत कम समय दिया है। मैं मांग संख्या-51 पर समाज कल्याण मंत्रीजी का दो मिनट में ध्यानाकर्षित करके मेरी

(श्री मांगीलाल गरासिया)

बात को विराम देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो गोगुंदा में हॉस्टल का उदघाटन करके आये पर यदि वहां बच्चे जो आ रहे हैं उन बच्चों के लिए उनमें सीटों की संख्या बढ़ाई जाए तो वहां उस एरिया के लिए बहुत बेहतर रहेगा। माननीय सभापति महोदय, उसके साथ ही मैं मेरे एरिया की समस्या बताकर के मेरी बात को विराम देता हूं। वहां उस एरिया के लिए समाज कल्याण हास्टल के रूप में चित्रावास में गुंदाली में, मादड़ी का छापर जैसा ट्राइबल एरिया है वहां पर अगर हास्टल की व्यवस्था हो जाती है तो वहां पर उस एरिया के बच्चों को लाभ मिल पायेगा। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आप मुझे इशारा कर रहे हैं इसलिए मैं मेरी बात को बहुत जल्दी खतम कर लेता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय चिकित्सा मंत्रीजी और समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति:** धन्यवाद। माननीय श्री सुभाष शर्मा। दो मिनट प्लीज।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई तथा मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना पर मैं अपने विचार रखते हुए सबसे पहले... (व्यवधान) खिलाफ की बात नहीं है, जो अच्छा काम है उसके लिए बधाई देंगा।

**श्री सभापति:** आप उधर मत देखिये। आप आसन को संबोधित करते हुए बोलें, उधर देखकर मत बोलिये।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): खिलाफ और पक्ष का मतलब नहीं है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को तो एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पावटा के अन्दर पंचायत समिति विराटनगर में दिया। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरा, धन्यवाद आपको इस बात का देता हूं कि बी डी एम अस्पताल कोटपूतली के जीर्णोद्धार के लिए आपने दो करोड़ 15 लाख रुपये स्वीकृत करके उसको नये सिरे से करने की जो योजना बनाई। तीसरा धन्यवाद इस बात का देता हूं... (व्यवधान) आप चिंता मत करो, जो बात होगी तो फिर वो भी कहूंगा। तीसरा धन्यवाद मैं इस बात का देता हूं कि बी डी एम अस्पताल में एक ब्लड बैंक की आवश्यकता थी उस ब्लड बैंक की आवश्यकता

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

को आपने पूरा करने का प्रयास जरूर किया लेकिन अभी तक वह ब्लड बैंक अपने फंक्शन में नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस बात के लिए कि जयपुर और दिल्ली के बीच में नेशनल हाइवे पर एक ही अस्पताल है जो बी डी एम अस्पताल है जो 150 बेडेड है, जिला स्तरीय अस्पताल है। उसके लिए ब्लड बैंक का होना अति आवश्यक है। 150 किलोमीटर की दूरी का व्यक्ति जब जयपुर पहुंचता है तो निश्चित रूप से उसको जयपुर पहुंचते-पहुंचते, बहुत-सारी दुर्घटना हैं, जब उसकी दुर्घटना हो जाती है तो उसका ब्लड निकल जाता है और वहां तक पहुंचते-पहुंचते वह मौत के ग्रास तक पहुंचता है। 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग केवल ब्लड निकल जाने के कारण मर जाते हैं....

**(समय : 19.40 बजे)**

**(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि उस ब्लड बैंक को जल्दी से जल्दी चालू करवाने के लिए तुरन्त आप व्यवस्था करवायें।

एक सबसे बड़ा निवेदन करना चाहता हूं, उसके कटमोशन्स भी मैंने दिये हैं और माननीय सदस्यों की तरफ से भी बात उठकर आई है कि पूरे राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र चिकित्सा व्यवस्था से महरूम हो रहा है। जितने भी माननीय सदस्य हैं चाहे वे सत्ता पक्ष से बोले हों चाहे वह प्रतिपक्ष से बोले हों, सबने अपनी बात यह कही है कि चिकित्साकर्मी, डाक्टर गांव के अन्दर उपलब्ध नहीं रहते हैं। हमारी ऐसी योजनाएं होनी चाहिए, हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए, हमारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चिकित्सक शहर की बजाय गांव की तरफ आकर्षित हों और गांव की जनता को चिकित्सा का लाभ मिल सके।

मेरे यहां पर बड़नगर अस्पताल, भोनावास अस्पताल, दांतिल अस्पताल, सुखल्लाबास अस्पताल, नारेहेड़ा अस्पताल, नारेड़ा अस्पताल, पांछोडाला अस्पताल, मैं जो आपको यह अस्पतालों की सूची दे रहा हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्साकर्मियों की ड्यूटी तो है, आपने उनको लगा रखा है, लेकिन वे वहां कार्यरत नहीं हैं। वह प्रतिनियुक्तियों पर अन्यत्र कार्यरत हैं। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पावटा में खोला, पिछले दिनों आपने नियुक्तियां कीं। एक-एक व्यक्ति के तीन-तीन बार स्थानान्तरण हो गये और वे छोड़कर चले गये और जब आपने लास्ट नियुक्तियां कीं, उसके बावजूद

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

भी दो डाक्टर, उसमें से एक डाक्टर है, जो अशोक सोंठवाल है और एक लेडी डाक्टर है कृष्णा, वे अपनी प्रतिनियुक्ति कराकर जयपुर में पदस्थापित हो गये। एक महीने पहले आपने फिर उनकी नियुक्ति की। अब वह यहां पर जयपुर में बैठ गये। ग्रामीण चिकित्सा सुविधा जभी नहीं चल पायेगी मंत्री महोदय, आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, आपकी एक निष्ठा होनी चाहिए। वह है, आप करना चाहते हैं, गांव में डाक्टरों को भेजना चाहते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इस व्यवस्था के अन्दर क्या कमी रही है जिस कारण से वह डाक्टर वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन डाक्टर को हम गांव में भेजना तो चाहते हैं लेकिन उनकी सुविधा का भी हम ध्यान नहीं रखते हैं। आज गांव के अन्दर जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है या अस्पताल है, वहां पर डाक्टरों के रहने की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। उनके पास बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं है, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में वह डाक्टर वहां नहीं रहना चाहते और येन-केन-प्रकारेण चाहे वह किसी तरह के हथकंडे अपनाये, वह अपनी ड्यूटी शहर में लगवा लेते हैं। और तो और माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक स्थिति है कि डाक्टर के पूरे महीने की तनख्वाह नीचे के कर्मचारी, बाबू से लेकर ऊपर तक, जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, उनके यहां पर पहुंच जाती है। डाक्टर को वह तनख्वाह उठाने नहीं जाना पड़ता, केवल साइन करने के लिए वह वहां पहुंचते हैं। बाकी ड्यूटी अपनी शहर के अस्पतालों के अन्दर देते हैं।

मैं आपका ध्यान और पूरे सदन का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव की जनता को अगर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराना है तो हमको इस बात पर प्रतिबद्धता रखनी पड़ेगी, सारे माननीय सदस्यों को प्रतिबद्धता रखनी पड़ेगी और यह स्थानान्तरण, डिजायरों के माध्यम से कि उसको वहां भेज दो, उसको वहां भेज दो, इसकी व्यवस्था यहां कर दो। इसके दोषी हम भी हैं। हम सबको भी इससे ऊपर उठकर और एक ब्यूरोक्रेसी को इस बात का जिम्मेदार ठहराया जाये, उसकी जवाबदेही तय की जाये कि कोई भी अस्पताल अगर खाली रहा, कोई भी चिकित्सक अगर गांव में उपस्थित नहीं रहा तो संबंधित विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी फिक्स करें और सरकार उसमें मोनेटरिंग करे। अगर यह व्यवस्था हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि गांव में चिकित्सक उपलब्ध हो पायेंगे और अगर केवल

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

स्थानान्तरणों में मंत्री और सरकार लगी रही तो मैं समझता हूं कि दबाव और प्रेशर के माध्यम से सारे डाक्टर्स जिस प्रकार से आज गांव के अस्पताल खाली हैं।

मेरे पांछोडाला का अस्पताल तो ऐसा है जो पिछले तीन साल से खाली पडा है। डाक्टर वहां है लेकिन प्रतिनियुक्ति पर कहीं दूसरी जगह है। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आपने मुझे दिया पावटा के अन्दर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चलेगा कैसे? आपका वहां का डाक्टर प्रतिनियुक्ति पर जयपुर में आकर बैठ गया।

इसी प्रकार से बी.डी.एम. अस्पताल का एक चिकित्सक, जिसके खिलाफ शिकायत हुई दो साल पहले, एक हरिजन महिला के साथ अत्याचार करने का, उससे पैसे लेने का आपरेशन में, नौ आपरेशन उस दिन में हुए, नौ आपरेशनों में उसने पैसे लिये, जिसकी जांच जिला कलक्टर और एस.डी.एम. ने की और वह सरकार को भेजी, सरकार ने तुरन्त उस पर एक्शन लिया और उस डाक्टर को वहां से स्थानान्तरित कर दिया और आपने डेढ़-दो महीने पहले उसी डाक्टर को कोटपूतली में, एनेस्थिसिया के डाक्टर को बी.डी.एम. अस्पताल में वापस पदस्थापित कर दिया। इसके क्या कारण हैं। जो भ्रष्ट लोग हैं, वह वापस उन्हीं पदों पर पहुंच जाते हैं। जो बेईमान लोग हैं, जो जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं और यही नहीं, उसमें हस्तक्षेप माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया था, मुख्य मंत्रीजी ने उसको तुरन्त हटाने के आदेश दे दिये। अब यह मुख्य मंत्रीजी बड़ी हैं या आप बड़े हैं या कौन बड़ा है, मैं नहीं समझ पाता। मुख्य मंत्रीजी के हटाये हुए उस एनेस्थिसिया डाक्टर को, जिसकी शिकायत रही है। एस.एम.एस. अस्पताल में भी एक डाक्टर की उसी दिन शिकायत हुई। उस महिला के साथ कोटपूतली में भी अत्याचार हुआ, एस.एम.एस. में भी अत्याचार हुआ और दोनों डाक्टरों को सी.एम. साहब ने खुद बुलाकर, उच्च शिक्षा का सेक्रेटरी था, उसको निर्देश दिये और तुरन्त वहां से उनको सस्पैंड करके वहां से हटाया। आज वह वापस उसी जगह पर स्थानान्तरण से पदस्थापित हो गये। आपको यह व्यवस्था देखनी पड़ेगी, आपको इन बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। इस दबाव की राजनीति से बाहर सरकार को आना पड़ेगा। जब तक हम इस दबाव की राजनीति से बाहर नहीं आयेंगे, हम गांव की जनता को लाभ नहीं दे सकते।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

बजट का प्रावधान हम जो करते हैं, 80 प्रतिशत शहरों के लिए करते हैं और 20 प्रतिशत गांवों के लिए करते हैं। हमारी 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में भी जिस प्रकार की व्यवस्था है, उसको 80 प्रतिशत गांवों में लगायें। मंत्री महोदय, अगर ये डाक्टर गांवों में होंगे, चिकित्सा गांवों में उपलब्ध होंगी तो आपकी सरकार को पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये कांग्रेसी बैठे-बैठे देखते रह जायेंगे और आपकी सरकार दौड़ती हुई चलकर वापस आयेगी और अगर यही हालात रहे तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा आने वाले समय में। मैं सार्वजनिक हित की बात को कहता हूं। बिना किसी पक्ष-विपक्ष के इस बात को कहना चाहता हूं कि जनता की आवाज है यह, गांव में चिकित्सा सुविधा नहीं है, उनको पुन: स्थापित कराने की आप कोशिश करें।

एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, प्रसाविका का पद है, जहां हम गांवों में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं। प्रसाविकाओं की स्थिति यह है कि यह आपका यहां पर मेरे पास में जवाब आया हुआ है। इस जवाब के अन्दर आपने स्वीकार किया है कि गांव मण्ढा, खेलना, बनार, फतेहपुरा खुर्द, राडा, मोहनपुरा, भांकरी, कारोली, पाछोडला, यहां पर प्रसाविका हैं ही नहीं। मण्ढा में आपने प्रसाविका बताई है। अब मण्ढा की प्रसाविका को मरे ही छह महीने हो गये। कैसे आपके अधिकारी जवाब भेज रहे हैं, मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, इस तरह की एक परमानेंट मोनिटरिंग की व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तब तक आप इस व्यवस्था को सुचारू रूप नहीं कर सकते। मेरा निवेदन है, गांवों में हम जननी सुरक्षा योजना चला रहे हैं। प्रसाविका वहां पर है नहीं। उप स्वास्थ्य केन्द्र हम खोलेंगे। उन उप स्वास्थ्य केन्द्र में अगर यह प्रसाविकाएं नहीं होंगी तो हम उन महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं?

तीसरा एक पहलू है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जननी सुरक्षा योजना के तहत जो सहायता राशि राज्य सरकार ने घोषित की है, जो महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल में पहुंचती है, उसको डिलीवरी का पूरा पैसा दिया नहीं जाता है। भारत सरकार की योजना होगी, राजस्थान सरकार की मोनेटरिंग है इसलिए जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की मोनेटरिंग की है। वहां पर तय हो जाता है कि 1400 या 1600 रुपये दिये

जायेंगे, उसमें से 800 या 1000 रुपये तुम्हारे को मिल जायेंगे, 100 उसके होंगे, 100 उसके होंगे और पैरामेडिकल स्टाफ उसमें सम्मिलित हैं इस बात के लिए और मेरे पास कई प्रमाण हैं। मैं सदन में आप चाहें तो इस बात की पुष्टि यहां पर कर सकता हूं, बाकायदा नाम और वह सब दे सकता हूं। उनको यहां पर टेबल भी कर सकता हूं कि उन्हीं प्रसाविकाओं ने जननी सुरक्षा योजना में जो लोग इन्वाल्व हैं, उन्हीं महिलाओं को पूरा पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा इस बात के लिए, पूरे राजस्थान में यह कंट्रोलिंग सिस्टम ऐसा बनायें कि कोई महिला को, जिसको आप जननी सुरक्षा योजना के लिए बधाई देना चाहते हैं, उसको कम से कम इसका मौका मिले और उसकी समुचित राशि उसको मिल सके।

एक निवेदन करना चाहूंगा इस बात के लिए है, बड़नगर जो मेरा गांव है, वहां पर आपने डाक्टर हटा लिया और पैरामेडिकल स्टाफ जो है, दो ए.एन.एम. हैं, नर्स-द्वितीय था, वह माननीय जोशीजी ने हटा दिया। पूरा अस्पताल बन्द हो गया। उस अस्पताल को कैसे चलायेंगे? न आज वहां पर कम्पाउण्डर है, न ही डाक्टर है, वहां पर चिकित्सा की व्यवस्था क्या होगी? यह हमें देखना पड़ेगा इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैंने दो चिट्ठी आपको भी भेजी हैं, दो चिट्ठी माननीय जोशीजी को भी भेजी हैं कि मेरे ये पद खाली पड़े हैं, आप इनको भर दीजिये। स्थानान्तरण भी खूब हुए, लेकिन वे पद नहीं भरे गये। मैं आपसे चाहता हूं कि आप उन पदों को भरने की कृपा करेंगे।

मेरी पंचायत समिति कोटपूतली में 42 पंचायतें हैं और राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक पंचायत समिति में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र....

**श्री अध्यक्ष:** कृपया समाप्त करें।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को कन्क्लूड कर रहा हूं। एक पंचायत समिति में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति कोटपूतली अभी जो आपने खोला है, पंचायत समिति विराटनगर के क्षेत्र में खोला है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पंचायत समिति कोटपूतली का क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। 42 पंचायतों का क्षेत्र खाली पड़ा है। उसमें नारेहड़ा एक ऐसा प्राथमिक

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

स्वास्थ्य केन्द्र है, जिस जगह पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जा सकता है। मेरा आपसे आग्रह है कि डेढ़ लाख की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी आप खुलवाने की कृपा करें। एक बात और विशेष तौर से, जो बहुत गम्भीर है, उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जितने सरकारी बड़े अस्पताल हैं उनके आस-पास में प्राइवेट अस्पताल इतने बढ़ गये हैं चाहे वह कोटपूतली मेरे विधान सभा क्षेत्र हो, मैं वहां की बात कहूं, दूसरी जगह की भी बात कहूं, उसमें प्राइवेट अस्पताल उन डाक्टरों के हो गये हैं जो डाक्टर उसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में पदस्थापित हैं और प्रेक्टिस यह हो गई है कि वहां का पैरा मेडिकल स्टाफ और वहां का डाक्टर मिल करके वहां के मरीज को हरेश करके वह यह कहते हैं कि इलाज कराना है तो बाहर फलाना प्राइवेट अस्पताल में जाकर करा ले वरना तू यहां मर जायेगा, यहां तो व्यवस्था भी नहीं है। इस प्रेक्टिस को वह लोग चला करके कर रहे हैं जिससे प्राइवेट अस्पताल फल-फूल रहे हैं और गरीब लुट रहे हैं, गरीब बरबाद हो रहे हैं। मेरे पास शिकायतें आती हैं कि हमारे पन्द्रह हजार रुपये लग गये, अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, हमारे बीस हजार रुपये लग गये, प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हुआ। मैंने जब उनसे कहा कि आप ले क्यों गये तब उन्होंने कहा कि हमारे को तो डाक्टर साहब ने यहां से रैफर किया था और यह कहा था कि आपको इलाज सही कराना है तो मेरे उस अस्पताल में लेकर आ जाओ। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है इसके लिए आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसी चीजों पर लगाम लगायें और ऐसी चीजों पर लगाम लगाकर के फिर व्यवस्था को सुचारू करें। एस.एम.एस. अस्पताल के बारे में भी एक मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्षः** अब आपने बहुत कह दिया।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्माः** एक निवेदन कर रहा हूं बस। उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यहां पर विराजे हुए हैं, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में एक ही यूनिट आज तक कार्यरत है, कैंसर डिपार्टमेंट में एक ही यूनिट कार्यरत है, उस एक ही यूनिट के हैड आफ द डिपार्टमेंट नहीं चाहते, व्यक्तिगत नहीं चाहते कि वहां पर दूसरी यूनिट खोली जाये। इनके पास चिकित्सक उपलब्ध है, इनके पास एम.ओ. उपलब्ध हैं, सरकार से मैं आग्रह करता हूं और माननीय उच्च शिक्षा

मंत्रीजी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा शिक्षा मंत्रीजी से कि रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में अगर एक अलग यूनिट आप स्थापित करेंगे तो मरीजों को च्वाइस मिलेगी, मरीज उस डाक्टर से इलाज कराना चाहता है या उस डाक्टर से इलाज कराना चाहता है, मरीज का हरेसमेंट होना बंद हो जायेगा, मरीजों को लाभ मिल पायेगा और जो एस.एम.एस. अस्पताल के ऊपर बोझ होने के बजाय जो लोग महावीर कैंसर में जाते हैं, जो प्राइवेट इलाज कराते हैं, जो महंगा इलाज कराते हैं, जिनका शोषण होता है उससे वह बचेंगे और राज्य सरकार की मंशा भी साफ होगी और आम आदमी तक इसका लाभ पहुंचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि सरकार की सोच बहुत अच्छी है, काम करना चाहती है लेकिन उस काम करने के साथ-साथ जब तक इम्प्लीमेंटेशन उसका ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा विचार इस बात के लिए नहीं होगा कि जो योजना बनाई है वह कार्यरूप लें और वह जनता तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे तब तक उसका लाभ निकल करके वापिस नहीं आयेगा। आपने मुझे समय दिया, उसके पहले मांग संख्या-51 पर एक बात और कह देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के विकास की बात हम सब करते हैं...

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, अब कुछ नहीं। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा :** अनुसूचित जाति के विकास की बात हम कहते हैं, अनुसूचित जाति के विकास के लिए हम सब को मिलकर के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे शिक्षा के विद्यालय खोले जाने चाहिए जिससे उन गरीब लोगों को शिक्षा दी जाय...

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये। माननीय सदस्य। श्री सुखलाल मीणा।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, उन गरीब लोगों को शिक्षा दी जा सके और अलग से उनके कोचिंग सेंटर्स बनाकर के उनको उस योग्य बनाने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष:** श्री सुखलाल मीणा। डाक्टर कन्हैया लाल मीणा। (व्यवधान) तगारामजी ऐसे ही थोड़े हो जायेंगे, नाम तो इसमें लिखे हुए हैं वैसे ही बोलूंगी न।

**डा. कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-26 और 51 के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने जो चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये हैं उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने चाहे पीएचसी हो, सीएचसी हो, सभी हास्पीटल्स में एस.एम.एस. की तरह सोच समझ करके जिस प्रकार से जो राशि दी है आपने और वहां पर जो डाक्टर्स के क्वार्टर, नर्सिंग स्टाफ के क्वार्टर बनाने का जो

**(समय : 19.45 बजे)**

**(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)**

पैसा दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान का ही नहीं, बल्कि हरियाणा, मध्य प्रदेश का एकमात्र हास्पीटल एस.एम.एस. एक ऐसा हास्पीटल है जिस हास्पीटल के अंदर यहां चारों तरफ से सब लोगों को यह है कि विशेषज्ञ डाक्टर्स, अच्छे डाक्टर्स अगर कहीं उपलब्ध हैं तो वह एस.एम.एस. में हैं और एस.एम.एस. में आपने इमरजेंसी वार्ड को, ट्रोमा वार्ड को जो एक आधुनिक रूप दिया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं और अन्य जो पूरे हास्पीटल को भी आपने आमूलचूल परिवर्तन करके उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने जो एक करोड़ रुपये की राशि देकर के इस हास्पीटल का विकास करने की मन में जो ललक है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कंटीन्यू बढ़ाओगे तभी जाकर इसमें पार पड़ेगी, नहीं तो इसमें इतने भारी मरीजों की जो संख्या है उसकी और स्टाफ की, डाक्टर्स वही हैं पुराने, आज से बीस साल पहले जो हमने डाक्टर्स लगाये थे, नर्सिंग स्टाफ जो लगाया था वही का वही नर्सिंग स्टाफ है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एस.एम.एस. हास्पीटल को आप अच्छा बजट देकर के, अच्छी राशि देकर के यहां डाक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाय, नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाय जिससे आये दिन होने वाले अड़ौस-पड़ौस के जितने भी एक्सीडेंटल, चाहे न्यूरो सर्जरी का वार्ड हो, काफी व्यवस्था सुधरी है पहले से, लेकिन फिर भी आपके न्यूरो सर्जरी वार्ड के अंदर आज भी स्थिति ठीक नहीं है, जो होनी चाहिए। आये दिन वहां होने वाले एक्सीडेंट्स में नीचे ही, बैड नहीं मिल पाता है, अति सीरियस पेशेंट को भी नीचे ही गैलरी में लिटाया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम न्यूरो सर्जरी वार्ड पर प्राथमिकता से ध्यान देकर के इसमें परिवर्तन किया जाय।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में नेशनल हाइवे 11 दौसा से लेकर के खानियां तक, चूलगिरी पहाड़ी तक इतने एक्सीडेंट्स होते हैं आये दिन, रोजाना एक न एक एक्सीडेंट होता है, कभी तीन एक्सीडेंट हो गये, कभी चार हो गये, कभी एक हो गया, कई बार दस-दस व्यक्तियों के एक्सीडेंट एक साथ हो जाते हैं इसलिए मेरा निवेदन है, ट्रोमा हास्पीटल की पहले भी मांग थी, एक ट्रोमा हास्पीटल इस एरिया के बीच में नियुक्त किया जाय तो यहां पर लोगों को बहुत (व्यवधान) बस्सी में खोला जाय, एक ट्रोमा यूनिट की व्यवस्था की जाय जिससे यहां लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो सके क्योंकि वह व्यक्ति घायल होकर के यहां जयपुर आते-आते या तो उसकी डेथ हो जाती है या उसको बस्सी लेकर जाते हैं, बस्सी से फिर वापिस रैफर किया जाता है तो यहां आते-आते उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। ऐसे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक ट्रोमा हास्पीटल बस्सी में खोला जाय। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बस्सी में वर्तमान में तीस बैड का सीएचसी हास्पीटल है, नौ डाक्टर हैं, आपने करीब एक करोड़ रुपये अभी डाक्टर्स के, स्टाफ के क्वार्टर्स बनाने के लिए, हास्पीटल को बड़ा करने के लिए, पूर्व में भी आपने पैसे, पचास लाख रुपये आपने इस हास्पीटल में दिये हैं, बिल्डिंग आपने सेटेलाइट जैसी बना दी, मैं आपसे यह कहता हूं कि सेटेलाइट नहीं बनायें आप, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप तीस बैड को पचास बैड कर दें क्योंकि वहां की प्रोपर बस्सी की जो चालीस हजार की जनसंख्या है उसके अलावा पूरा क्षेत्र, आधे से ज्यादा जमुआरामगढ़ आ जाता है, लालसोट का हिस्सा काफी आ जाता है, चाकसू और बस्सी का क्षेत्र आ जाता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको तीस बैड से पचास बैड बस्सी सीएचसी को किया जाय, जिससे आने वाले एक्सीडेंट्स वगैरह, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लाभ हो सके। आपको कोई डाक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको कम से कम पचास बैड का कर दें हास्पीटल को, तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कानोता एक इतना बड़ा कस्बा है जिसमें 8900 के करीब जनसंख्या है और उसमें वहां यह हीरावाला रीको एरिया है, इण्डस्ट्रियल एरिया है सो वहां की लेबर, हजारों की संख्या में वहां पर रहती है। साथ ही वहां पर सोसाइटीज के माध्यम से, जेडीए के माध्यम से अड़ौस-पड़ौस में कालोनियां, छोटी-छोटी कालोनियां बस गई हैं और उनके लिए वहां पर आज तक कोई हास्पीटल नहीं है। पूर्व में मैं मांग कर चुका हूं, एक सीएचसी कम से

कम, पीएचसी आप वहां पर दे दें, आपके मापदण्ड में भी खरा उतरता है वह गांव और बस्सी क्षेत्र में सामरिया एक बहुत बड़ा कस्बा है उसमें भी एक एड पोस्ट है उसको क्रमोन्नत करके पीएचसी बनाया जाय, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पीएचसी तूंगा और पीएचसी कोटखावदा, यहां दो-दो डाक्टर हैं और दो-दो डाक्टर होने का मतलब यहां इतने मरीजों की जो संख्या है, उनकी बहुतायत को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम कोटखावदा या तूंगा में से एक को सीएचसी किया जाय, जिससे यहां के मरीजों को ज्यादा लाभ मिल सके ज्यादा डाक्टर्स होने की वजह से। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक मिनट तो बोला ही नहीं अभी।

**श्री सभापति:** बोलो-बोलो। बोलें, समाप्त करें जल्दी। बोलें।

**डा. कन्हैया लाल मीणा :** साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो एड पोस्ट है, जो एड पोस्ट पंचायत हैडक्वार्टर पर थीं और आपने कम्पाउण्डर्स लगा रखे थे उसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा था, इमरजेंसी में रात्रि के वक्त भी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनको आप समाप्त नहीं करें, उन एड पोस्ट पर कम्पाउण्डर्स को यथावत रखा जाये। आपने उस पोस्ट को समाप्त कर दिया वह समाप्त नहीं करके उस एड पोस्ट को यथावत रखा जाय तो बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बस्सी में नौ डाक्टर्स आपने दे दिये, आर्थोपेडिक्स का भी आपने दे दिया एक एनेथिसेसिया का डाक्टर लगा दिया जाए तो वहां पर छोटे-मोटे ऑपरेशन भी वहां हो सकते हैं। एनेथिसेसिया के डाक्टर की आप एक पोस्ट करके वहां पर दे दी जाए तो ठीक रहेगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एस एम एस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक के लिए जब भी कोई ऐक्सीडेंट होता है, मेरे क्षेत्र में तो आये दिन कोई-न-कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ब्लड बैंक में पहले लाइन में लगते हैं और लाइन में लग करके जब वहां से लिखाते हैं कि इतने पैसे जमा कराकर आओ नीचे, फिर वो नीचे वहां आता है, नीचे जमा कराता है, जमा कराने के बाद फिर दूसरी लाइन में लगते हैं जब तक उसको बहुत घंटों तक टाइम व्यतीत करना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नीचे जो कैश काउंटर है उस काउंटर को ब्लड बैंक के बराबर ही लगाया जाए जिससे आम जनता को रोजाना होनी वाली परेशानियों से कम से कम छुटकारा मिल सके, दुबारा उसको लाइन में नहीं लगना पड़े, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

(डा. कन्हैया लाल मीणा)

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वेंटीलेटर की जो व्यवस्था है, वेंटीलेटर के बिना बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है और ये वेंटीलेटर की यहां पर इतनी कमी है उसकी वजह से संतोकबा दुर्लभजी में ले जाना पड़ता है। कल की ही बात है मेरे क्षेत्र का एक सरपंच ऐक्सीडेंट हुआ, वेंटीलेटर की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहां उसको बाद में हम संतोकबा दुलर्भजी में ले गये वहां भी व्यवस्था नहीं हुई, वहां ले जाकर के प्राइवेट सोनी हॉस्पिटल में उसको ले जाना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक वेंटीलेटर की व्यवस्था यहां पर करें, चाहे हम अगर बजट नहीं भी हो तो विधायकों के कोटे से जयपुर शहर के, जयपुर देहात के विधायक कोटे से पैसे देने को तैयार हैं अगर वेंटीलेटर की व्यवस्था करें, इसमें तो यह व्यवस्था आप अवश्य करें कम से कम 5-6 वेंटीलेटर की व्यवस्था और हो जिससे लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा मांग संख्या-51 के बारे में माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी के जो छात्र हैं जिनको दो साल से लगातार छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है उनको छात्रवृत्ति दिए जाने के आदेश जारी करें। भारत सरकार से नहीं आई है या आने के बाद ईश्यू नहीं हुई इसमें प्राथमिकता देकर उन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए। जिससे उन गरीब बच्चों का भला हो सके। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के जो छात्रावास हैं, उन छात्रावासों में वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने के जो पुराने पांच साल पहले आपने जो बिस्तर दे रखे हैं, वह फटे-टूटे बिस्तरों में वो रहते हैं। वहां पर खाना पकाने वाला भी वह बालक ही है, वहां पर खाना पकाता है दूसरा पकाने वाला भी वहां पर नहीं रहता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो उन छात्रावासों में जैसे बस्सी में छात्रावास है, बस्सी प्रोपर में वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, नहाने के लिए दूसरे हैण्डपम्पों के ऊपर अड़ौस-पड़ौस के कस्बों में जाकर के वो बच्चे नहाकर के आते हैं, न उनके पास कोई बाल्टियां हैं, बाल्टियों की व्यवस्था भी वहां पर नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तुंगा और बस्सी दो समाज कल्याण विभाग के ये छात्रावास हैं यहां पर इसकी व्यवस्था की जाए। (व्यवधान) एक सैकिण्ड में, दूसरा मेरा एक निवेदन है, पूर्व में भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है या नहीं है लेकिन ऐसे युवा और युवतियां जो पागल हो गये हैं, मेंटली जो परेशान है जो या तो चौराहे पर नग्न हालत में घूमते रहते हैं, इनकी देखभाल

(डा. कन्हैया लाल मीणा)

करने वाला कोई नहीं है, ऐक्सीडेंट हो जाते हैं, वो फ्रेक्चर हो जाते हैं, उनको उठा के ले जाने वाला कोई नहीं है, उठा के ले जाकर के वहां डाल देते हैं तो वहां कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे सैकड़ों की संख्या में ऐसे व्यक्तियों को कम से कम ऐसी कोई व्यवस्था समाज कल्याण विभाग की तरफ से होनी चाहिए जो ऐसे व्यक्ति या तो, एस एम एस में भी अभी 3-4 ऐक्सीडेंट होकर पड़े हैं उनकी कोई सार-संभाल नहीं है, पड़े-पड़े सुस्त हो गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था करके कोई योजना बनाकर के इन व्यक्तियों की भी मदद करें।

**श्री सभापतिः** धन्यवाद। डा. दिगम्बर सिंहजी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे। डा. दिगम्बर सिंहजी।

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, अब (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** अब बहुत हो गया है। आठ से ज्यादा बज गये हैं।

**श्री अमराराम** (धोद): नहीं, बहुत किसका हो गया है (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** दो मिनिस्टर्स के जवाब आने हैं प्लीज (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): दो मिनिस्टर्स के जवाब तो आयेंगे ही (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): आपने सबको टाइम दिया है (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** दो मिनट का कोई अंत नहीं होता है, दो मिनट बोलने के होते हैं (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): आपने सभी को टाइम दिया है तो दो मिनट में क्या फर्क पड़ता है? (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, ये जो कटमोशन है (व्यवधान) और खासकर के अधिक कटमोशन मेरे हैं और (व्यवधान)

**श्री नवनीत नीनामा** (घाटोल): सभापति महोदय, मैं खाली सुझाव दे रहा हूं, मैं मेरे एरिए का ही सुझाव दे रहा हूं, कोई रद्दी बात नहीं कर रहा हूं।

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** नहीं प्लीज, दिगम्बर सिंहजी, यस।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति

महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): धन्यवाद तो खूब ले लिया आपने, आप तो एक्चुअल सुन लो (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): सभापति महोदय, आपको घर जाने की जल्दी तो नहीं है, सभापति महोदय, कुछ सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बोलना चाहते हैं, बोलने का मौका दिया जाए (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** हो गया, हो गया प्लीज (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): सभापति महोदय, आपका जवाब तो सभी दे रहे हैं, पांच मिनट सबको दिया जाए।

**श्री सभापतिः** आप लास्ट में क्या बोलेंगे? (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): दो-दो मिनट का सब को समय दे दो (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** पहले बोलना चाहिए था (व्यवधान) दस से ज्यादा बजेंगे।

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, आपने व्यवस्था दी इसका मतलब जो मेहनत करता है उसकी व्यर्थ जाए।

**श्री सभापतिः** दूसरी पर बोल लेना ना, क्या फर्क पड़ता है?

**श्री अमराराम** (धोद): दूसरी, इस चिकित्सा की दूसरी कहां आएगी, इस साल तो आयेगी नहीं (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** और डिमाण्ड पर बोल लेना।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, अब आप बैठा दें, इन सबको (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): देखो तैयार की है हमने (व्यवधान) कट-मोशन लगा हुआ है तैयारी की है पूरी (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज देखिए (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): पांच मिनट का टाइम ले रहा हूं (व्यवधान)

**श्री सभापति:** अभी भी दो मिनट सब बोलना चाहते हैं, इधर भी बहुत लम्बी लिस्ट है, इधर बुलाऊंगा तो इधर से भी बुलाना पड़ेगा प्लीज, डा. दिगम्बर सिंह।

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, लम्बी लिस्ट के बाद आपके पास (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** नगर की सीटी डिसपेंसरी जरूर खोलें आप।

**श्री अमराराम** (धोद): लम्बी लिस्ट आपने व्यवस्था दी (व्यवधान) पाँच माननीय सदस्य बोल चुके हैं (व्यवधान)

**श्री सभापति:** पांच कोई नहीं बोला है, इधर से एक, इधर से एक और उधर से एक, तीन ही बोले हैं, इसके बाद नहीं बोले।

**श्री अमराराम** (धोद): तीन तो बोल दिये तो पांच भी बोल लेंगे।

**श्री सभापति:** पांच नहीं, इधर से बहुत लोग बोलना चाहेंगे, इधर से बुलाऊं तो इधर से भी बुलाना पड़ेगा।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): माननीय सभापति महोदय, में आपसे दो मिनट (व्यवधान)

**श्री सभापति:** अब बहुत लेट हो गये हैं दस बज जाएंगे प्लीज, यस डा. दिगम्बर सिंह, प्लीज (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): जिला चिकित्सालय में एक सीटी स्केन खोली जाए, समाज कल्याण मंत्रीजी लावा, सरदारगढ़, केलवा, मोई में छात्रावास खोले जाएं बस।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): माननीय सभापति महोदय, मैं जब नियमों से आता हूं तो आप कहते हो (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मेरा कटमोशन लगा हुआ है जब मैं कटमोशन लगाकर के नियम से आ रहा हूं तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, जब बोलता हूं तो आप कहते हो समय नहीं है।

**श्री सभापति:** नहीं, प्लीज, कोई बात हो तो आप बता दीजिएगा प्लीज (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): माननीय सभापति महोदय, मेरे साथ (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): सभापति महोदय, इन लोगों को पहले बुलवाएगा, आप लास्ट में बुलवाते हो, गलत बात है।

**श्री सभापतिः** दूसरी डिमाण्ड में पहले बुलवा लेंगे आपको प्लीज (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): सभापति महोदय, केवल दो मिनट आपके ले रहा हूं, इससे पहले (व्यवधान) सभापति महोदय, आपसे दो मिनट ले रहा हूं।

**श्री सभापतिः** प्लीज, अब हाउस का मूड देखिए आप प्लीज (व्यवधान) नहीं सारा हाउस देखिए अभी दस बजेंगे, अभी भी दो मंत्रियों के जवाब है प्लीज (व्यवधान) तीन मंत्रियों के जवाब हैं प्लीज।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): सभापति महोदय, दो मिनट आपसे ले रहा हूं, मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैंने कट-मोशन लगाया है (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** नहीं, डा. दिगम्बर सिंह।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि (व्यवधान) जिन्होंने चिकित्सा जैसे संवेदनशील विषय पर अपने विचार सदन में रखकर बहुत ही (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): मैं क्या बोल रहा हूं, दो मिनट आपने सबको दिया है केवल दो मिनट में आपको क्या फर्क पड़ता है?

**श्री सभापतिः** नहीं, फिर और बोलेंगे।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): आपको कोई परेशानी है क्या (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** फिर अमरारामजी भी बोलेंगे, फिर इधर से निनामाजी बोलेंगे।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): आपको मैं यही कह रहा हूं केवल दो मिनट मैं कोई आपका एक घंटा थोड़े ही ले रहा हूं, केवल दो मिनट का टाइम ले रहा हूं।

**श्री सभापतिः** That is no....(व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय केवल दो मिनट आपकी कोई ऐसी, केवल दो मिनट ही तो ले रहा हूं।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा और सरकार का मार्ग प्रशस्त करने का जो प्रयास इस सदन के माध्यम से किया है (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि दो मिनट, दो मिनट में क्या फर्क पड़ता है, मेरा कटमोशन लगा हुआ है (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, कुल 74 माननीय सदस्यों के 252 कटौती के प्रस्ताव मेरे पास आये हैं और मैंने उन सबका अवलोकन कर लिया, सबके जवाब भी मैंने तैयार किये हैं (व्यवधान) अधिकांश कटौती के प्रस्ताव चिकित्सा सेवाओं के विस्तार से संबंधित हैं, कुछ वेकेन्सीज को लेकर के हैं, स्टाफ की वेकेन्सीज को लेकर हैं, कुछ भवन इत्यादि के संबंध में हैं। मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिन-जिन माननीय सदस्यों के कटौती के प्रस्ताव मेरे पास आये हैं उनके लिखित जवाब 48 घंटों के अंदर (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): +++

**श्री सभापति:** ऐसा नहीं है, बिलकुल यह तथ्यों से परे चीज हैं।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उनके पास जवाब पहुंच जाएगा लिखित में, माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद यह ऐसे विषय हैं, ऐसे विभाग हैं जिसका सरोकार राजस्थान की आम आवाम से है और हमारे माननीय सदस्य भी सब वाकिफ हैं कि हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और जिस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है एक तरफ ठेट रेगिस्तानी प्रदेश दूसरी तरफ हमारा पहाड़ी एरिया जहां पर हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, जो अपने जाने-अनजाने में खान-पीन में भी कई बार ऐसी खुद के लिए परेशानी पैदा कर लेते हैं और इधर मरूस्थल पहाड़ी यहां तक कि हमारे चंबल के बीहड़ तक का इलाका हमारे राजस्थान का, इस विषम, भौगोलिक परिस्थितियों में हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हमारे राजस्थान के जो भी वाशिंदे हैं उनको निरोग रखना हमारा पहला कर्तव्य सरकार मानती है।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने शायद मुझे लगा कि जैसे किसी आदमी को जब जलन होती है न तो जिटर-जिटर की आवाज आती है हमारे जो ऐसे पैरामीटर्स हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के जिनमें बहुत अच्छा सुधार हुआ स्वास्थ्य सूचकांकों के ऊपर भी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बड़ा कटाक्ष किया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि स्वस्थ प्रदेश की परिकल्पना के उद्देश्य से पिछले वर्ष मैंने प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमारू

(डा. दिगम्बर सिंह)

राज्य से उबार कर अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाने का संकल्प दुहराया था और मुझे सदन में यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस क्षेत्र में अब सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। कुशल वित्तीय प्रबंधन, प्रभावी मानिटरिंग एवं जनसहयोग के फलस्वरूप राज्य में स्वास्थ्य सूचकांकों में अप्रत्याशित सुधार हुआ है। शिशु मृत्यु दर में जहां 10.67 प्रतिशत की कमी आयी है मातृ मृत्यु दर में 34 प्रतिशत की कमी आयी है और जन्म दर में 4.2 की कमी हुई है तो सभापति महोदय, यह बिना प्रयास के बिना सेवा में सुधार के ये कुछ भी संभव नहीं था।

सभापति महोदय, राज्य के नागरिकों और विशेषकर गरीबों, वृद्ध व्यक्तियों, महिलाओं, शिशुओं तथा दूरदराज के ग्रामीण जन और शहरी कच्ची बस्तियों के निवासियों को सस्ती एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प तो हमारी सरकार की और माननीय मुख्य मंत्री महोदया की यह पहली प्राथमिकता है और मेरा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ा जो अभी मैंने आपको यह हमारे पैरामीटर्स के बारे में जिक्र किया जब हमारा ड्रास्टिक रिडक्शन हमारी मेटरनल मोर्टलिटी, हमारी इंफेंट मोर्टलिटी में हुआ है तो मेरा और ज्यादा इससे मनोबल बढ़ा और मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा जब सफलता मिली मेरी स्वास्थ्य चेतना यात्रा को। मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ स्वास्थ्य चेतना यात्रा के बारे में, भरतपुर में एक कहावत है सभापति महोदय, मुझे पता नहीं सदन में कहनी चाहिए कि नहीं कि गधे को दिया गुलकंद और गधे ने कही कि तेरी तो आंख फोड़ दी। इतना अच्छा करने के बाद भी स्वास्थ्य चेतना यात्रा के बारे में कोई नेगेटिव बोले तो मेरी समझ के बिलकुल बाहर है। सभापति महोदय, मैं अपना यह प्रण जो प्रतिज्ञा है उसको मैं दुबारा एक संकल्प मेरा जो है उसको दुहरा रहा हूं, राजस्थान के गरीब तक, झौपड़ों तक राजस्थान की सेवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से और बेहतर सेवाओं को पहुंचाने का पूरा-पूरा संकल्प मैं सदन में करता हूं। मैं चूंकि कल से क्रिकेट का भी महाकुंभ शुरू होने वाला है और हमारी भारतीय टीम है वो भी बहुत एक दृढ़संकल्प के साथ में वर्ल्ड कप खेलने गयी है। मैं सदन की तरफ से सबसे पहले तो भारतीय टीम की विजय के लिए कामना करता हूं कि वो निश्चित रूप से वर्ल्ड कप जीतकर आये और मैं भी यह अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि अगले वर्ष में हमारा यह सूचकांक हमारे जो मेडिकल पेरामीटर्स हैं इस डिपार्टमेंट के ड्रास्टिकली इनको नीचे लाने का पूरा हम प्रयास करेंगे।

**श्री हीरालाल** (निवाई): सामने तो बेंचें ही खाली हैं सभापतिजी।

**श्री सभापति:** नौ इंटरप्शन प्लीज।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने हमारा आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी योजनाओं और लक्ष्यों का विवरण इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमने चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया है इसमें कोई अगर हमारे प्रतिपक्ष का भी सदस्य कहे इसमें तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। हमने तीन साल में जो काम किया है और आपके पांच साल की विगत सरकार के अगर कार्यकलाप देखें तो उसका कोई कंपेरिजन नहीं है। लगता नहीं कि पिछले पांच साल में आप लोगों ने कोई काम किया था। सभापति महोदय, इस विस्तारीकरण में हमने पिछले तीन वर्षों में 801 नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले जिसके परिणामस्वरूप आज राज्य में एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं बची है मैं यह कहना चाहता हूं कि एक भी ग्राम पंचायत राजस्थान की ऐसी नहीं बची है जिसमें हमारा स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध नहीं है। यह पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर हुआ है।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): ...(व्यवधान) जसवंतगढ़ है। जसवंतगढ़ है गोगुन्दा में जहां अभी तक नहीं बनाया है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इस विस्तारीकरण के ...(व्यवधान) यह हण्ड्रेड परसेंट सही है। आप देख लेना एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं बची है अगर माननीय सदस्य मुझे आकर कहेंगे कि ग्राम पंचायत, जरूरी नहीं कि हैडक्वार्टर पर सब सेन्टर हो ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर न होकर के ग्राम पंचायत के दूसरे गांव में होगा परन्तु ग्राम पंचायत एक भी नहीं बची है और यह पहली बार हुआ है।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): मैं कह रहा हूं कि जसवंतगढ़ है गोगुन्दा में। ...(व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): एक-एक ग्राम पंचायत में दो-दो हैं।

**श्री सभापति:** नौ इंटरप्शन।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इस विस्तारीकरण के क्रम में 2007-08 में राज्य में मुख्य मंत्री महोदया ने अभी अपने बजट भाषण में घोषणा की थी 130 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र, 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के साथ-साथ बाड़मेर, ढंग से सुन लेना पर सामने सुनने वाले तो हैं ही नहीं। डा. बैद साहब नोट कर लें प्लीज। बाड़मेर, आप भी नोट कर लेना ममताजी, बूंदी, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ एवं कोटपूतली के चिकित्सालयों में शैयाओं की संख्या डेढ़ सौ से बढ़ा कर दो सौ की जाएगी। भरतपुर और जयपुर में पचास शैयाओं के सेटेलाइट अस्पताल बनाये जाएंगे तथा हनुमानगढ़ जंक्शन में मैं गया हूं हनुमानगढ़ पहली बार जब गया तो हनुमानगढ़ पूरा शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक हिस्से में अस्पताल खोला हुआ है पूरा और दूसरे हिस्से में करीब चालीस हजार की आबादी वहां पर कोई एक डाक्टर की सुविधा थी। मैं खुद वहां पर जाकर आया और मेरे को लगा कि वहां बहुत इंपोर्टेंट है तो मैं आज यहां घोषणा कर रहा हूं सदन में कि हनुमानगढ़ जंक्शन पर तीन शैयाओं का अस्पताल वहां अलग से खोला जाएगा। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं मालवीयनगर सैक्टर 6 जयपुर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे। मैं आज सदन में जयपुरिया सेटेलाइट अस्पताल जयपुर को जिला अस्पताल बनाने की घोषणा करता हूं। जयपुर के अन्य तीन सेटेलाइट अस्पतालों को भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पहले घोषणा कर दी, उनको सुदृढ़ करने का किया जाएगा ताकि सवाईमानसिंह अस्पताल जो रेफरल हास्पिटल के बतौर अधिक से अधिक कार्य कर सके उसमें लोड इसका कम हो। सभापति महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य वो मेरे ख्याल से चले भी गये दिखते हैं ...

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): नहीं हैं उनके कैंसिल कर दीजिये।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चले भी गये पर मैं बोलूं कि नहीं बोलूं।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): छोड़ो-छोड़ो, क्यों दुःखी हो रहे हो।

**श्रीमती प्रतिभा सिंह:** नवलगढ़ में दो न आप डाक्टर, मैं बैठी हूं। ... (व्यवधान)

**श्री सभापति:** नौ, प्लीज-प्लीज।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): केकड़ी में पचास बैड से 75 बैड का अस्पताल केकड़ी का हम क्रमोन्नत करेंगे और उसमें चरणबद्ध तरीके से भवन निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। सभापति महोदय,

ग्रामीण क्षेत्र की तरफ हमारा बहुत ध्यान है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को हम बहुत अच्छा इंप्रूव भी करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु राज्य में शहरी क्षेत्रों में भी हमारे जो स्लम एरियाज हैं उनमें भी गरीब लोग रहते हैं उनकी चिकित्सा का ध्यान रखते हुए भी राज्य में नगरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 8 शहर जिसमें जयपुर में 8, अजमेर में 5, जोधपुर में 5, कोटा में 4, भरतपुर में 2, उदयपुर में 5, बीकानेर में 5 और अलवर में 2 ये कच्ची बस्तियों में कुल मिलाकर 36 नगरीय स्वास्थ्य इकाइयां अरबन हैल्थ यूनिट्स ये शुरू की जाएंगी। इन स्वास्थ्य इकाइयों पर एक महिला एलोपैथिक डाक्टर होगी और इसके साथ-साथ एक होम्योपैथी का चिकित्सक भी इन स्वास्थ्य इकाइयों में होगा।

सभापति महोदय, वो तो भाग गये क्या डा. बैद साहब? बैद साहब, आप जाना मत प्लीज। हां मेरी बात सुन कर जाना।

**एक माननीय सदस्य:** जो हैं उनके लिए तो बोलें।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक नहीं रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं रहता है, कमी रहती है, इसको मानने में मुझे कोई बिलकुल भी वो नहीं है। हमारे पास शार्टेज है डाक्टर्स की, स्टाफ की इसमें कोई बात नहीं है परन्तु हमने लगातार प्रयास किया है पिछले तीन सालों में इनको भरने का और मैं आज इस सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि हम अलग से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का गठन करेंगे और इस समस्या ...

**श्री युनूस खान:** इसमें क्या होगा ग्रामीण सेवाओं में?

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ग्रामीण सेवाओं में हमें स्टाफ की उपलब्धता होगी, डाक्टर्स की भी उपलब्धता होगी केवल रूरल एरिया में ही लगेंगे। निश्चित रूप से वर्ष 2007-08 में हम स्वास्थ्य सेवाओं का गठन कर के चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में सुनिश्चित करेंगे। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं अभी तक जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थी इसका एक प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जीवन शहरी क्षेत्रों से कहीं अधिक कठिन है संविदा पर नियुक्त चिकित्सक निर्धारित 8000 रुपये प्रतिमाह की तनख्वाह पर जाने व ठहरने के

लिये तैयार नहीं होते थे यह मेन कारण खाली रहने का था और आधे मान से जनता की सेवा करते थे। इस समस्या को माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने वास्तविक रूप में अहसास किया और उनके निर्देश पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों के चिहि्न्त पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने आइडेंटिफाई की है, हर पीएचसी पर संविदा पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी को 8000 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों की पीएचसी पर जो कठिन क्षेत्र है इनके अलावा जो हैं उन पीएचसी पर कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारियों को 8000 रुपये के स्थान पर 12 हजार रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे । दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों के चिहि्न्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत संविदा एएनएम व नर्स ग्रेड द्वितीय को 2500 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त देय होंगे ।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अभी कितना दे रहे हैं ?

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी साढे तीन हजार रुपये मिलते हैं उनको । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर जो डिफिकल्ट एरियाज नहीं है उनमें जो एएनएम और नर्स ग्रेड द्वितीय काम करेंगे उनको डेढ हजार रुपये अतिरक्त दिये जायेंगे । माननीय मुख्य मंत्रीजी का वरिष्ठ नागरिकों के लिये बहुत चिंतन है क्योंकि जितनी प्रोब्लम्स पीडिएट्रिक्स की हैं उतनी प्रोबलम्स आज हमारे देश में, हमारे राजस्थान में जेरिएट्रिक्स की भी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिये हम अपनी तरफ से और क्या कर सकते हैं तो विभाग ने यह तय किया जिसकी घोषणा भी मैं आज यहां करना चाहता हूं हमारी सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की कठिनाई के प्रति सजग व संवेदनशील है । इनके उपचार के लिये राज्य में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क जांच एवं आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराई जायेंगी । इसके लिये उपलब्ध बजट राज्य बजट के अतिरिक्त मैडिकल रिलीफ सोसायटी की आय का 20 प्रतिशत तक की राशि वरिष्ठ नागरिकों के उपचार पर व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2007-08 में, अब ध्यान से सुन लेना, कुल 21790 कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी । इनमें से 937 एलोपेथिक चिकित्सक, 13130 नर्स ग्रेड द्वितीय/एएनएम, 4270

(डा. दिगम्बर सिंह)

आशा सहयोगिनी, 240 हैल्थ मैनेजर स्वास्थ्य प्रबन्धक और 609 डाटा एंट्री ओपरेटर, 1836 अकाउंटेंट और 764 एएनएम होंगी। यह हमारा इस वर्ष में भर्ती का प्रावधान है। जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की माननीय वसुंधराजी ने जो कुछ चुनाव के पहले कहा था कि हम बेरोजगार युवकों को मौका देंगे, उनको रोजगार देंगे और उस कड़ी में मेरे ख्याल से एक वर्ष भी ऐसा नहीं गया है जिसमें एक लाख से कम लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया हो ।

सभापति महोदय, राज्य के इतिहास में आज तक किसी भी सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को न तो एक वर्ष में रोजगार उपलब्ध कराया और न ही चिकित्सा के क्षेत्र में ही एक वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिये इतने व्यापक पैमाने पर चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया है । नये वित्त वर्ष में 575 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति दी, 1980 नर्स ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। सभापति महोदय, राज्य के 325 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चरणबद्ध रूप से दो अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं दो अतिरिक्त फीमेल नर्स ग्रेड द्वितीय नियुक्त किये जायेंगे । प्रथम चरण में सन 2007-08 में 163 सामुदायिक केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । राज्य के सभी 1499 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चरणबद्ध रूप से दो अतिरिक्त फीमेल नर्स ग्रेड द्वितीय उपलब्ध कराई जायेंगी जिससे प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि राज्य के 7502 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्तमान में कार्यरत एक एएनएम के अतिरिक्त एक नर्स ग्रेड द्वितीय की नियुक्ति की जायेगी । इससे उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा कर्मी की उपलब्धता निरन्तर बनी रहेगी । सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह जिस दिन शुरूआत हो जायेगी उस दिन ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में एक आमूलचूल परिवर्तन आयेगा और चिकित्सा के इतिहास में भी यह एक बहुत बड़ा कदम होगा क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले, ग्राम पंचायत के पूरे ग्राम में कम से कम चिकित्सा की पूरी सुविधा मिले, एक ट्रेंड कंपाउंडर या नर्स मिलेगी तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा और जो एक थैला छाप डाक्टरों का

प्रकोप रहता है उन पर भी निश्चित रूप से एक तरह से कंट्रोल होगा । राज्य के शहरी इलाकों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ....

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): मंत्रीजी ग्राम स्वास्थ्य में आपने 2006-07 के बजट की तुलना में 2007-08 में घटाया है या बढाया है, यह बता दीजिए ।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं सारी चीज बता दूंगा । 36 प्रतिशत बढाया है ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): 4 प्रतिशत घटाया है । वर्ष 2006-07 और 2007-08 में ग्रामीण चिकित्सा सुविधाओं में 4 प्रतिशत बजट टोटल घटाया है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको बता दूंगा कितना बढ़ाया है ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप सीएसएस को जोड़कर नहीं देख रहे हैं, जरा जोड लो इसको ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आपने अपने प्लान से 2007-08 में 10 करोड़ 75 लाख रुपये दिये हैं और केन्द्र सरकार ने आपको 204 करोड़ रुपये दिये हैं । अगर सही नहीं है तो मुख्य मंत्रीजी बता दें ।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तो क्या अहसान कर दिया क्या केन्द्र सरकार ने ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आपने 2007-08 के नये बजट में, प्लान बजट में सिर्फ 10 करोड़ 75 लाख रुपये और केन्द्र सरकार से आपको जिसको सेंटर स्पोंसर्ड स्कीम बोलते हैं उसमें 204 करोड़ रुपये मिले हैं ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमारा हक है कोई अहसान किया है क्या ?

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, जिस दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया था उस दिन बैठे-बैठे सबके शून्यपात की बीमारी हो गई थी ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप कहते कि मुख्य मंत्रीजी की क्षमता से मिले हैं लेकिन मिले तो हैं ना ।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, उस दिन सब शून्य हो गये थे और आज भी इनकी स्थिति मुझे ज्यादा कुछ ठीक सी नजर नहीं आ रही है । राज्य के शहरी इलाकों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा सहयोगिनियों की भांति शहरी क्षेत्रों के 4270 आंगन बाड़ी केन्द्रों पर भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा सहयोगिनियों का चयन कर नियोजन किया जायेगा। सभापति महोदय, एक नीचे के स्तर पर इन्वेस्टीगेशन की फैसेलिटी उपलब्ध हो उसकी भी चिंता हमने की है। हमारी सीएचसी पर उपलब्ध हो, हमारी पीएचसी पर उपलब्ध हो । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जटिल प्रसव के मरीजों को गांव में ही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राज्य के 237 पंचायत समिति मुख्यालयों की सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हर एक पर सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध कराई जायेगी और इसके अतिरिक्त 14 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 62 एक्स-रे मशीन 68 डेंटल एक्सरे मशीन, 178 ईसीजी मशीन, 108 कार्डिक मोनीटर, 104 पल्स ओक्सीमीटर, 44 डिफेब्रिलेटर तथा 14 ब्लड गेस एनेलाइजर आदि उपकरण क्रय कर उपलब्ध कराये जाएंगे। (व्यवधान) मैं बात शुरू करना चाहता था पर यह सो न जाए।

सभापति महोदय "उठो आकाश का यह जाल चलकर तोड़ दे,
तूफान की आंधियों की दिशाओं को मोड़ दो,
धरती के दुःख को देखकर भी पिघले नहीं,
उन बादलों को मुट्ठी में कसकर निचोड़ दे।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): हम आपसे क्या कहे, आपके 2006-07 में आपने सिर्फ 37 करोड रुपये लगाया बजट में, मुझे आप करेक्ट कर दीजिए और केन्द सरकार से आपको 151 करोड़ रुपया मिला। केन्द्र सरकार से 151 करोड़ रुपया। आप प्लान और नोन प्लान दोनों में मिलाकर 37 करोड़ रुपये (व्यवधान) अन्याय क्या होगा।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): केन्द्र सरकार कोई दान दे रही है क्या ? यह संघीय व्यवस्था है। यह हमारा राइट है, स्टेट का। जहां से केन्द्र सरकार को वापस... (व्यवधान) उसी में देती है। यह हमारा राइट है।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): वाह-वाही सारी खुद मत लो, कुछ केन्द्र

(श्री जुबेर खान)

सरकार को भी दे दो। आप बता दो, 2007 में आपने प्लान, नोन प्लान दोनों में 37 करोड़ रुपये और केन्द्र सरकार से आपको मिले 151 करोड़ रुपये। (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): यह हमारा अधिकार है।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): कोई दान-दक्षिणा नहीं देती केन्द्र सरकार, हमारा हिस्सा ले रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** बैठिये तगारामजी। आप भी बैठ जाइये।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): बीच-बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** बैठिये-बैठिये।

**एक माननीय सदस्य:** खर्चा नहीं करते थे, हम करते हैं।

**श्री सभापति:** बैठिये, नौ इन्ट्रप्शन प्लीज।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सब सेंटर पर डिलिवरी की सुविधा के लिए हमने पिछली बार भी लेबर रूम बनवाये थे। इस आने वाले वर्ष में 1500 सब सेंटर पर लेबर रूम का निर्माण करवाएंगे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मैं समझता था पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य क्वालिफाइड डाक्टर होंगे, मैं तो यह मानता था पर आज जो कुछ मैंने सुना उससे ...(व्यवधान) आज मुझे कुछ डाउट हुआ उनकी क्वालिफिकेशन पर। स्वास्थ्य चेतना यात्रा के बारे में, कि स्वास्थ्य चेतना यात्रा आप लोगों ने इसलिए करी कि आपको जो एक्सपायरी डेट की दवाईयां थी वह ठिकाने लगाने थी। यह क्या लोजिक हो गया। मैंने इसीलिए कहा आपको कि हमारे भरतपुर में एक कहावत है कि गधे को दिया गुलकंद गधा बोला मेरी तो आंख फोड दी। अच्छा करने को अच्छा न कहो तो बोलो ही मत। स्वास्थ्य चेतना यात्रा ने इतना जबरदस्त मनोबल बढ़ाया है इस डिपार्टमेंट का और मेरा, 31 लाख मरीजों को हमने नि:शुल्क चिकित्सा दी है, उनके इन्वेस्टीगेशन फ्री कराये हैं। उसमें एलोपेथिक चिकित्सा के साथ-साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी की चिकित्सा भी हमने कराई।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं आपको इन्ट्रप्ट नहीं करना चाहता। मैं माननीय मंत्रीजी को करेक्ट करना चाहता हूं उप राष्ट्रपतिजी का जो किट था फर्स्ट एड का उसमें एक्सपाइरी डेट की दवाइयां हैं और अभी भवानीजी भड़के यह बाड़मेर गये थे वहां पर एक्सपाइरी डेट की दवाई मिली थी।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जवाब मिल जाएगा। ऐसा है कल्ला साहब जब तक पूरी जानकारी (व्यवधान) कल्ला साहब आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को तो पूरी जानकारी के बाद ही बोलना चाहिये क्योंकि हमारे भवानीजी जहां गये थे वहां जो उन्होंने देखा उसमें आयोडाइज्ड साल्ट को, टेस्ट किट्स वह जनवरी 2007 में एक्सपायर हो चुकी थी, they were not used. उसको इसमें इतना मत लीजिए, आप जैसा, हम तो आपको मानते हैं बहुत सीनियर हो। (व्यवधान)

सभापति महोदय, वर्ष 2007-8 में यह स्वास्थ्य चेतना यात्रा में इतनी जबरदस्त सफलता हमको मिली और हमने यह तय किया है कि आने वाले वर्ष 2007-8 में भी हम स्वास्थ्य चेतना यात्रा को और अच्छे ढंग से चलाएंगे। हमारा पिछला जो कार्यक्रम हुआ वह दिसम्बर के महीने में हुआ। डाक्टर बैद जानते हैं कि दिसम्बर का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना हेल्दी सीजन माना जाता है। इस बार हमने तय किया है कि हम 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक ब्रिडिंग सीजन होता है, मानसून के जस्ट बाद का सीजन होता है उसमें हम इसको चलाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को निश्चित रूप से उनके घर जाकर उनका मुफ्त इलाज करेंगे यह आपको मैं आज वादा करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फिवर जो था, पिछले वर्ष में उससे हमारे राजस्थान में भी परेशानी हुई। वर्ष 2007-8 में राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पतालों में सम्भावित डेंगू रोग की जांच, सुविधा, रोगी को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

सभापति महोदय, अभी तक पूरे जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रहता है, एक आदमी सीएमएचओ होता है, चीफ मेडीकल हैल्थ आफिसर, हमने तय किया है कि अब हम अपने ब्लाक की स्ट्रेथिंग करेंगे और हर ब्लाक पर एक हम सीएमएचओ ब्लाक का, चीफ मेडीकल हैल्थ आफिसर ब्लाक, हम अभी उसको बनाने जाएंगे और यह सीनियर मेडीकल आफिसर होगा और ब्लाक के सारे जितने भी इन्स्टीटयूशंस है उसके अंडर में आएंगे।

मैं उसमें निवेदन करना चाह रहा हूं कि राज्य में संचालित चिकित्सा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समय पर प्रभावी क्रियान्वयन बेहतर प्रबंधन के लिए सभी 237 पंचायत मुख्यालयों में, ब्लाक में स्थित सभी चिकित्सा संस्थानों का प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी

ब्लाक होगा। इसके अधीन एक एम.बी.ए. जिसको हम, हैल्थ मैनेजर ब्लाक पर रहेगा या इसके समकक्ष योग्यताधारी कोई दूसरा आदमी, एक कम्प्यूटर डेटा एंट्री आपरेटर, एक लेखाकार की नियुक्ति इसमें की जाएगी। संभाग स्तर पर कार्यरत सभी संयुक्त निदेशक के कार्यालय में भी हैल्थ मैनेजर की हम नियुक्ति करेंगे।

सभापति महोदय, राजकीय चिकित्सा संस्थान में रख-रखाव एवं अनआकस्मिक खर्चों के लिए स्वायत्ता के उद्देश्य से जिला अस्पताल से लेकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के चिकित्सा संस्थानों में मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन किया जाएगा। पीएससीज तक हमने एमआरएस का गठन कर दिया है। इस वर्ष राज्य में 1536 एमआरएस का गठन किया गया और 2007-8 में सभी सोसायटीज को पन्दह करोड़, इक्यानवे लाख, पच्चीस हजार रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, एमआरएस का।

जिला चिकित्सालयों की मेडीकल रिलीफ सोसायटी को पांच लाख रुपये की दर से, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सोसायटी को एक लाख रुपये की दर से तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सोसाइटी को 75,000 रुपये की दर से अनुदान राशि दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त राज्य के सभी मेडीकेयर रिलिफ सोसाइटी में जनवरी, 2007 को कुछ सात करोड, सत्ताइस लाख, चौसीस हजार, सात सौ तैरह रुपये बैलेंस राशि उपलब्ध थी। इस राशि का उपयोग यह सोसाइटी स्थानीय स्तर पर संस्थानों के बेहतर रख-रखाव, मरीजों की जांच एवं उपचार एवं आवश्यक औषधियों के क्रय, अन्य आकस्मिक खर्चों आदि के लिए कर सकेगी।

राज्य में मेडीकल रिलीफ सोसायटी के प्रभावी संचालन के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन कर इसे अधिक जनोपयोगी बनाया गया है जो 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

राज्य के सभी 10,512 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पिछले दो वर्षों की भांति 2007-8 में भी 10,000 रुपये प्रति केन्द्र की दर से 10 करोड, 51 लाख रुपये रिवाल्विंग फण्ड के बतौर उपलब्ध कराए जाएंगे। पिछले दो सालों में 10-10 हजार करा चुके, एक सब सेंटर तक 30,000 रुपये हमारे पहुंचे हैं जो पहली बार राजस्थान में रिकार्ड है। सब सेंटर पर कभी सफेदी कराने के लिए कोई फण्ड उपलब्ध नहीं हुआ करता था।

(डा. दिगम्बर सिंह)

सभापति महोदय, जननी सुरक्षा के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्ष के हमारे पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो बहुत ज्यादा एक तरह से नेगेटिव बोला। उन्होंने कितना रजिस्ट्रेशन बताया कितना सब रजिस्ट्रेशन और पेमेंट इतना को हो गया, कहां से लेकर आये हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए जननी सुरक्षा के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 2006-7 में जनवरी माह तक करीब जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 2006-07 में जनवरी माह तक करीब 4 लाख गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हुआ, वे कितना बता रहे थे, 4 लाख महिलाओं का पंजीकरण हुआ और 2 लाख 59 हजार 885 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये, शहरी क्षेत्रों में एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में योजना की सफल क्रियान्विति के परिणामस्वरूप, इसको ध्यान से सुनना डाक्टर बेद साहब, इसमें 5 करोड़ रुपये आबंटित राशि के मुकाबले 50 करोड़ रुपये तक की नगद राशि वितरित किये जाने की सम्भावना है, इस मार्च के अन्दर। 5 करोड़ की जगह पर 50 करोड़ रुपये पर हम पहुंचेंगे। परिणामस्वरूप इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य में संस्थागत प्रसव पर पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की सम्भावना है इंस्टीट्यूशनल। सभापतिजी, मैं कुछ भवन निर्माण के बारे में भी सदन को बताना चाहूंगा, राज्य में लम्बे समय के बाद ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों की आधारभूत सरंचना की ओर ध्यान दिया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा राज्य के वर्तमान चिकित्सा संस्थानों में नवीन भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों में जीर्णोद्वार कार्य हाथ में लेने के साथ वर्षों से लम्बित समस्या का समाधान करते हुए चिकित्सा संस्थानों में आवासीय सुविधा बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिये प्रारम्भ में 135 करोड़ का प्रावधान रखा था। कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए विश्व बैंक से विचार-विमर्श उपरान्त इस प्रावधान को 135 की जगह 175 करोड़ रुपये बताया गया है। अब तक परियोजना में 104 स्थानों पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है जिसमें से 34 स्थानों पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इनमें जो पूरे हुए हैं काम उसमें, करौली, टोंक, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, आहोर, सोजत, रेवदर, झाड़ोल, रेलमगरा, आसपुर, कोटड़ा, फलौदी, बनाड़, तारानगर,

(डा. दिगम्बर सिंह)

मनोहरथाना, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, शाहबाद, नैनवां, बायाना, कुम्हेर एवं नगर प्रमुख हैं। वर्ष 2007-08 में सौ अतिरिक्त अस्पतालों के जीर्णोद्वार का कार्य प्रारम्भ करने का एवं वर्तमान में शेष चल रहे 70 कार्यों में से 60 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, चूरू, नोखा, डूंगरगढ़, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, झालरापाटन, सुजानगढ़, रतनगढ़ व खानपुर प्रमुख हैं। जिला अस्पताल बांसवाड़ा, चूरू, हनुमानगढ़ व भरतपुर के भवनों के जीर्णोद्वार पर 2 करोड़ से ज्यादा व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार वर्ष 2007-08 के अन्त तक कुल 94 अस्पतालों के जीर्णोद्वार का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। राज्य के 1325 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुल 1748 आवासों के निर्माण के लिये, इसको ठीक से सुन लेना एक बार डाक्टर साहब, राज्य के 325 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुल 1748 आवासों के निर्माण के लिये 113 करोड़ 28 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर निर्माण कार्य आरम्भ कराया जा चुका है। इन आवासों के निर्माण के उपरान्त राज्य के 325 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 4 चिकित्सकों के आवास, 4 पैरा-मेडिकल के आवास और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवास की व्यवस्था हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा कि राज्य सरकार की यह उपलब्धता उल्लेखनीय है क्योंकि इससे पूर्व राजस्थान सरकार, राज्य में अब तक की राज्य सरकारों ने जो टोटल सरकारें अब तक रही हैं, जब से राजस्थान की सरकार बनना शुरू हुई है, तब से अब तक की सरकारें जो बनी हैं, कुल 1779 आवासों का निर्माण किया था और हमने एक वर्ष के अन्दर 1748 आवासों के निर्माण की स्वीकृति जारी की है।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): डाक्टर साहब, थोड़ा धीरे बोलें, इनकी तो सांसें रुकी हुई हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आई.सी.यू. में भेजें, रिजर्व कर रखा है ना।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): रिजर्व करा रखे हैं, 2 आई.सी.यू.।

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): आप ही के व्यवहार से लग रहा है, सांसें रुकी हुई हैं।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): आई.सी.यू. में दवाइयां तो वही हैं ना जो उप राष्ट्रपतिजी के लिये रखी हुई थीं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): हां, वही हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): देखिये सन 1998 में जहां आपको केन्द्र का मिलता था 1964 करोड़, आज आपको 8002 करोड़ मिल रहा है, साहब। कितना फर्क है। तो स्वाभाविक है, जितना पीछे इतने दिनों में नहीं मिला, अब 2-3 साल में ही मिल गये।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार): केन्द्र सरकार हमारा हिस्सा देती है, कोई खेरात में देती है क्या? वह हमारे हिस्से में ही देते हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): जो कुछ आता है, करों का हिस्सा, डिवोल्यूशन का, ग्राण्ट इन एड आ रही है। आप अपनी पाकेट से कुछ नहीं कर रहे हो।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): राजसमन्द पंचायत समिति में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। आपके नार्म्स हैं कि राजसमन्द में हर ब्लाक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दिया जाए।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): केन्द्र सरकार भी भारत की सरकार है, वह इटली नहीं है। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): कालीचरणजी, बाप-दादाओं की कमाई पर मत करो। कुछ कमाकर लगाओ तो पता चलेगा। (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): राजसमन्द पंचायत समिति में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): अपना खुद का कमाकर क्या लगा रहे हो, यह बताओ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): केन्द्र सरकार आपके समय में नहीं थी क्या। आप इधर बैठे हुए थे, तब केन्द्र सरकार नहीं थी क्या? मेहनत है हमारे चिकित्सा मंत्रीजी की।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): केलवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए, राजसमन्द पंचायत समिति में।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वर्ष 2007-08 में, आप सुनें, वर्ष 2007-08 में राज्य में 128 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 40

(डा. दिगम्बर सिंह)

करोड़ रुपये की लागत से एवं सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 20 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्वार कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 12 करोड़ रुपये की लागत से नये आवास निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। राज्य में हमारे पास 10 जिलों में स्वास्थ्य काम्पलेक्स हैं। जहां हमारे सी.एम.एच.ओ., डिप्टी सी.एम.एच.ओ. के आफिस एक जगह हो जाते हैं। हमने यह तय किया है कि हम इस वर्ष 2007-08 में 10 जिलों में और स्वास्थ्य काम्पलेक्स बनायेंगे। एक काम्पलेक्स पर 80 लाख रुपये का खर्चा इसमें आयेगा। इस तरह से 8 करोड़ रुपये इसमें नगरीय सहभागिता योजना के अन्तर्गत हम इस कार्य को करवाएंगे। जिला चिकित्सालय, झालावाड़ के नवीन भवन का निर्माण कार्य 2007-08 में पूर्ण कर दिया जाएगा। 5 जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त औषधि भण्डार जो हमारे ड्रग वेयर-हाउसेज, 5 जिलों में नहीं थे, उनमें निर्माण कार्य चल रहा है और इससे मेरे ख्याल से राजस्थान के सारे जिलों में यह ड्रग वेयर-हाउसेज बन जाएंगे, इन 5 जिलों में पूरे होते ही। हमने प्रशिक्षण पर भी काफी जोर इसमें दिया है और 2007-08, आने वाले वर्ष में हम 3 हजार क्रमिकों को प्रशिक्षण इसमें दिलायेंगे। राज्य के सभी, एक बहुत इम्पोर्टेण्ट चीज है, राज्य के सभी सम्भाग मुख्यालयों पर निजी क्षेत्र में कम से कम एक एम.एससी. कालेज खुलेंगे, हम इस बार खोलेंगे। एम.एससी. नर्सिंग जो राजस्थान में एम.एससी. नर्सिंग थे ही नहीं। हम गवर्नमेंट कालेज तो चालू कर रहे हैं और हर अपने जो सम्भाग स्तर के जो शहर हैं, कम से कम एक सम्भाग में एम.एससी. नर्सिंग का कालेज खुले। राज्य में गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण संस्थान में बेहतर प्रबन्धन एवं अनुसंधान कार्य के लिये एक करोड़ रुपये के कोष से राज्य स्तरीय हैल्थ रिसोर्सेज सेण्टर का भी गठन किया जायेगा। पी.सी.पी. एण्ड टी. एक्ट में, गुणवत्ता पर भी काफी लोगों के विचार हमको सुनने को मिले थे तो इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक सेल का गठन पी.सी.पी. एण्ड टी. एक्ट में कर रहे हैं और इसमें एक हैल्थ मैनेजर, एक विधि विशेषज्ञ और डाटा एण्ट्री आपरेटर इसमें होंगे। इसमें प्रभावी तरीके से राजस्थान के अन्दर एक तरह से कण्ट्रोल पूरी तरह से हो, यह प्रयास हम पूरी तरह से आने वाले वर्ष में करेंगे।

एडस कण्ट्रोल के बारे में भी कई बार चर्चा हुई। मैं तो इतना बताना

(डा. दिगम्बर सिंह)

चाहूंगा कि एडस रोगियों के उपचार एवं सुविधा के विस्तार के तहत राज्य में नये वित्तीय वर्ष में 2 नये ए.आर.डी. सेण्टर, 2 कम्युनिटी केयर सेण्टर तथा 2 नये ड्रापिंग सेण्टर खोलने का प्रावधान है। इसके साथ ही गंगानगर, अजमेर, जयपुर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 84 एच.आई.वी. जांच व परामर्श केन्द्र तथा सौ नये एस.टी.डी. क्लिनिक प्रारम्भ करने का प्रस्ताव भी है। चालू वित्तीय वर्ष में एडस के रोगियों की चिकित्सा स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिये जोधपुर में ए.आर.डी. सेण्टर स्थापित किया गया। सरकार के द्वारा सफल संचालन का परिणाम है कि राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान पिछले तीन वर्ष में 14.17 प्रतिशत से बढ़कर 26.74 प्रतिशत हुआ। वालंटरी ब्लड डोनेशन का रेट इतना इन तीन वर्ष के अन्दर बढ़ा है।

अभी एक माननीय सदस्य ने चर्चा अपने टी.बी. कण्ट्रोल प्रोग्राम के बारे में की थी तो मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया अगी टी.बी. कण्ट्रोल प्रोग्राम है तो राजस्थान का माना जा रहा है और आज डॉट्स की जो पद्धति है इसके तहत जो 86 पहले हमारी क्योर रेट थी वह 88 परसेंट हो गयी है और निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत अच्छा हमारा यह टी.बी. नियंत्रण का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम अभी कमला नेहरू, यह कहा है, मल्टी ड्रग रेसिसटेंट टी.बी. रोगियों के लिए कमला नेहरू प्रादेशिक क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर में नि:शुल्क कल्चर सेन्सिविटी जांच की सुविधाएं भी इस आने वाले वित्तीय वर्ष में हम अजमेर में देंगे। हां, वही दे रहा हूं। ...(व्यवधान)

गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक डॉट्स सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चयनित आशा सहयोगिनियों का सहयोग लिया जाएगा तथा इसके लिए उन्हें प्रति केस क्षय रोगी के उपचार पूर्ण करने के उपरान्त 250 रुपये का नकद उनको मानदेय होगा।

कुपोषण जो हमारा (माल न्यूट्रिशन) का है, इसमें मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के सात जिलों में यह कुपोषण जो माल न्यूट्रिशन ट्रीटमैंट सेंटर्स संचालित हैं, इसी क्रम में आने वाले वित्त वर्ष में राजस्थान के शेष 25 जिलों में इन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी और इसमें खास बात जो हमने रखी है वह यह है कि कुपोषित बच्चे की मां जो अस्पताल में रहेगी उसको भी खाने-पीने के लिए 30 रुपये रोज का हम नकद पेमेंट उस मां को भी करेंगे।

(डा. दिगम्बर सिंह)

इसी प्रकार इंटिग्रेटेड मेनेजमैंट आफ नियो-नेटल एण्ड चाइल्डहुड इलनेस (IMNCI) सेवाओं में, यह पूर्व में 9 जिलों में थी। कोटा, बारां, करौली, बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ व टोंक, इसका विस्तार करके अब 18 जिलों में संचालन करेंगे और यह जो बाकी जो नये जिले इसमें शामिल होंगे, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, सिरोही, जालौर, पाली व भीलवाड़ा।

पी.पी.पी. के अन्तर्गत अभी डाक्टर बैद ने भी चर्चा की थी तो इसमें भी हमारा प्रारूप पूरा तैयार है सब कमेटी का और जल्दी ही हम इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप पर अपनी या तो रूरल एरिया के कुछ हास्पिटल्स में जहां भी वे लेना चाहेंगे इंवेस्टिगेशंस को, पार्टली लेना चाहेंगे, फुल लेना चाहेंगे, इस पर हम विचार-विमर्श कर रहे हैं और जल्दी ही इसका हम शुभारम्भ भी करेंगे।

वर्ष 2007-08 में आर.एच.एस.डी. परियोजना के माध्यम से 154 करोड़ रुपये आधारभूत सुविधाओं, औषधियों, उपकरण एवं प्रशिक्षण इत्यादि पर व्यय किये जाएंगे।

राज्य के 2 जिलों में शिशु स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन हेतु होम बेस्ट नियो-नेटल सेवाएं प्रारम्भ की जाएंगी। यह परियोजना नार्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव के तहत आशा सहयोगिनियों द्वारा नवजात शिशुओं की देखभाल संबंधी प्रशिक्षण पर आधारित होगी।

राज्य में टेली-मेडिसन का प्रोजेक्ट, हमारे 10 जिला अस्पताल इसमें जुड़ चुके हैं और बाकी का कार्य चालू है क्योंकि इसरो से कुछ उपकरण आने हैं, उसके बाद हमारे सारे जिले के अस्पताल मेडिकल कालेज से जुड़ जाएंगे।

केन्द्र सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाये जा रहे साफ्टवेयर ई-मोनेटरिंग के लिए राजस्थान सहित देश के दो राज्यों, राजस्थान और तमिलनाडु का पायलट हेतु चयन किया है, यह भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है।

ग्राम तथा ब्लाक स्वास्थ्य में, एवं स्वच्छता समितियों का क्षमता संवर्द्धन किया जाना है और इस वर्ष 50 हजार पंचायती राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों को ग्राम तथा ब्लाक स्तर पर स्वास्थ्य विषयक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राज्य की सभी 9189 ग्राम पंचायतों के विलेज हैल्थ एण्ड सेनिटेशन

कमेटी को 10 हजार रुपये प्रति कमेटी संबंधित पंचायत की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में किये जाने वाले कार्य के लिए हम उपलब्ध कराएंगे और इस पर 9 करोड़ 18 लाख 90 हजार रुपये इसमें व्यय होंगे।

अगले वर्ष में चिकित्सा स्वास्थ्य में आयुर्वेद विभाग की गतिविधियों को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 20 करोड रुपये की राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में प्रत्येक बुधवार को, इनका हमने डेज फिक्स कर दिया, प्रत्येक बुधवार को महिला नसबंदी, शनिवार को पुरुष नसबंदी, इसी तरह के दिवस आयोजित किये जाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर द्वितीय तथा चतुर्थ मंगलवार को महिला व पुरुष नसबंदी दिवस रहेंगे। इन दिवसों पर नियमित नसबंदी शिविर आयोजित किये जाएंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके नोट करने लायक तारीख है।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप तो आपस में ही ... (व्यवधान) पड़े हुए हैं। सुदर्शनजी को भी तो कुछ समझाएंगे या नहीं समझाएंगे तिवाड़ीजी और कटारियाजी कि वह भी कुछ अंकुश लगायें। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अबके सुदर्शनजी को रामगढ़ भेज देंगे, आपको समझाने के लिए। (व्यवधान)

ड्रग एण्ड इक्विपमैंट प्रक्योरमैंट के लिए एक कारपोरेशन का तमिलनाडु की उस पर, हम गठन करेंगे ताकि दवाइयों व उपकरणों के केन्द्रीय क्रय के साथ-साथ चिकित्सा केन्द्रों पर समय पर इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

राज्य के निजी क्षेत्र में औषधि निर्यात में भी हमने इसमें बहुत ड्रास्टिकली प्रोग्रेस की है। इन तीन वर्षों में 106 करोड़ रुपये से बढ़कर हमारा एक्सपोर्ट जो है मेडिसन में वह 220 करोड़ रुपये हो गया है।

परीक्षण के तौर पर 100 व इससे अधिक शैय्याओं के जो 38 हमारे चिकित्सालय हैं उनमें हमने पेशेंट काउंसलर अपाइंट किये थे। मरीजों की सुविधा के लिए जिसका परिणाम उत्साहवर्धक रहने पर आगामी वर्ष में शेष चिकित्सालयों में इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा।

(डा. दिगम्बर सिंह)

अगले वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि 100 एम्बूलेंस व 52 मेडिकल मोबाइल यूनिट उपलब्ध कराने की घोषणा कर चुकी हैं और इससे डाक्टर आपके द्वार यह एक इतनी अभिनव योजना की आपने शुरूआत की है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के गरीब, राजस्थान के ग्रामीण किसान, मजदूर के लिए इससे और कोई आकर्षक योजना चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं हो सकती।

मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में बात करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह सामने बैठे हैं हमारे प्रतिपक्ष के भाई, इन्होंने पाँच साल के अन्दर कुछ किया नहीं था। आयुर्वेद के अन्दर वह केवल टोपी बदलने के काम के अलावा कुछ नहीं किया था। हमने इसमें बहुत बड़ा काम किया और राज्य में परम्परागत चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लम्बे अरसे से इन सेवाओं का कोई विस्तार नहीं हुआ था। हमने एक छत के नीचे लाने का और जो एक तरह से आयुर्वेद का और होम्योपैथी का एक हमने इनको और सुविधाएं उपलब्ध हो और लोगों में इसकी जो बढ़ती हुई एक तरह से आज जो डिजायर है, इस ट्रीटमैंट के लिए उसके हिसाब से उपलब्धता भी इनकी हो। परम्परागत चिकित्सा पद्धति के विस्तार के तहत एलोपैथिक के साथ-साथ एक छत के नीचे आयुष की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी 1499 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एलोपैथिक चिकित्सक के साथ, यह भी इम्पोर्टेंट है, राजेन्द्रजी, एक एलोपैथिक चिकित्सक के साथ एक आयुष चिकित्सक, एक पी.एच.सी. पर हम और लगाएंगे। जिससे निश्चित रूप से वहां पर हमारे स्टाफ की जो अवेलिबिलिटी है वह सुनिश्चित होगी और एक कम्पाउंडर भी आयुष का वहां पर पी.एच.सी. पर हम लगाएंगे, यह भी हमने एक निर्णय लिया है।

आयुर्वेद के 'अ' व 'ब' श्रेणी के हमारे जितने भी औषधालय हैं, इनमें ऐलोपैथिक की तर्ज पर मेडिकल रिलीफ सोसायटीज का गठन किया जाएगा, इस आने वाले वर्ष में।

माननीय सभापति महोदय, विगत तीन वर्षों में हमने आयुर्वेद के 65 औषधालय, होम्योपैथिक के 35 औषधालय, यूनानी के 14 औषधालय, कुल 114 हमने आयुष के औषधालय खोले और 22 हमने 'ब' श्रेणी के औषधालयों को क्रमोन्नत किया और इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने और आयुर्वेद

(डा. दिगम्बर सिंह)

विभाग को बहुत दिल खोलकर इन घोषणाओं में बताया और 30 आयुर्वेद के, 30 होम्योपैथिक के और 10 यूनानी, 10 यूनानी, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के इलाज के लिए, इन्होंने पाँच साल में एक यूनानी नहीं खोला, हमने 24 यूनानी अब तक खोले हैं। आयुर्वेद के, माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद के 319, होम्योपैथिक के 47 और यूनानी के 30 चिकित्सकों तथा 219 नर्स-कम्पाउंडरों की इस वर्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी।

राज्य में आयुष ग्रामीण सेवा, जिस तरह से एलोपैथिक में हम रूरल हैल्थ सर्विसेज का गठन कर रहे हैं, उसी तर्ज पर ही आयुर्वेद में भी आयुष ग्रामीण सेवा का हम इसमें गठन करेंगे और जिसका लाभ तीन वर्ष से अधिक अवधि तक ग्रामीण क्षेत्र में संविदा पर काम करने वाले आयुष के चिकित्सक, चाहे नर्स-कम्पाउंडर हो, को निश्चित रूप से उनको मिलेगा।

पहले प्रति औषधालय 3500 रुपये से 5000 रुपये तक की दवाइयां आयुर्वेद के इसमें आयुष में मिलती थी, अब इसके अलावा अब ग्रामीण क्षेत्र के प्रति औषधालय 25 हजार रुपये अतिरिक्त राशि की औषधियां हमने इनको मुहैया करवायी हैं।

एक आयुष मोबाइल यूनिट, एक रसायनशाला, एक वन औषधि एवं जड़ी-बूटी उद्यान का विकास किया जायेगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 200 आयुर्वेदिक औषधालय के भवनों की मरम्मत पर कुल 2 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे । आयुष चिकित्सकों के लिये 322 सी.एच.सी., पी.एच.सी. पर तीन लाख रुपये प्रति केन्द्र की दर से व्यय कर भवन का विस्तार किया जायेगा। पी.एच.सी., सी.एच.सी. पर आयुर्वेद के जो बैठेंगे, उनकी बिल्डिंग के लिये तीन लाख रुपये का बजट हमने दिया है।

सभापति महोदय, इस तरह चिकित्सा विभाग में कुल नियुक्तियां हुई उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा देना चाह रहा हूं। चिकित्सा विभाग में चिकित्सक 937 होंगे, नर्स ग्रेड-2 13,130 होंगे, 244 स्वास्थ्य प्रबन्धक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्स 609, लेखाकार 1836, आशा सहयोगिनी 4,270, इस तरह से 21,026 एलोपैथी में और इसके साथ-साथ आयुर्वेद विभाग में 919 आयुर्वेद चिकित्सक, 223 होम्योपैथी चिकित्सक, 40 यूनानी चिकित्सक और 969 नर्स-कम्पाउण्डर हैं।

**श्री युनूस खान :** कल्ला साहब, कुछ बोलो। यूनानी चिकित्सालय तो

(श्री युनूस खान)

अपने दोनों को एक-एक मिल जायेगा, यह तो तय हो गया क्योंकि अपन दो ही माइनोरिटी के बैठे हैं। अब कल्ला साहब के लिये यह कुछ न कुछ बोलेंगे।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कुछ ऐसे सवाल उठाये थे । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधूरी जानकारी में और कोई बात सदन में कह देना, मैं उसको उचित नहीं मानता। तारानगर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि पिछली बार मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा की थी कि हम 500 चिकित्सकों को 2006-07 में अपाइंट करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि हमने 369 चिकित्सक आर.पी.एस.सी. से चयन किये और उनमें से 343 को नियुक्ति दे चुके हैं। 318 चिकित्सकों को वर्ष 2006-07 में संविदा पर नियुक्ति दी। इस तरह से 500 के खिलाफ हमने 661 डाक्टरों को नियुक्ति दी।

आपने कहा दाई ट्रेनिंग के बारे में। दाई ट्रेनिंग के बारे में भी आप जोर से बोले कि दाइयों की ट्रेनिंग नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005-06 में हमारा लक्ष्य था दस हजार दाइयों को ट्रेण्ड करने का, हमने 11,607 दाइयां ट्रेण्ड कीं। 2006-07 में अभी 6,258 दाई ट्रेण्ड हो चुकी हैं और इस तरह से 34,375 फरवरी तक ट्रेण्ड हो चुकी हैं।

आपने ऑपरेशन जीरो कैटरेक्ट में भी पता नहीं कहां से आप आंकड़े लेकर आये। वह भी मेरी समझ से बाहर है, जबकि यहां पर दो प्रोग्राम टी.बी. कंट्रोल प्रोग्राम और जीरो कैटरेक्ट प्रोग्राम, जो हमारा ब्लाइंडनैस कंट्रोल प्रोग्राम है, वह राजस्थान में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में बहुत अग्रणी माना जा रहा है और मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाह रहा हूं कि इस बार 2006-07 के दौरान कैटरेक्ट के 2 लाख 20 हजार 280 ऑपरेशन किये गये, जो हमारा टार्गेट का 95 प्रतिशत हो चुका है। यह आपकी जानकारी के लिये थोड़ा बता रहा हूं। आप इस बात को ध्यान में रख लें। आपने कहा संजीवनी कैम्प, आपने घोषणा की थी कि हम विशेषज्ञों को ले जायेंगे संजीवनी कैम्प में और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ दिया जायेगा। उसके लिये भी आपकी जानकारी में बता देना चाहता हूं संजीवनी कैम्पों में 2004-05 में स्पेशलिस्ट, जो हमारे संजीवनी कैम्प थे, उसमें 01 लाख 01 हजार 550 लोग लाभान्वित हुए। 2005 -06 में 1 लाख 27 हजार 133 लोग लाभान्वित हुए और इस वर्ष दिसम्बर तक की जो फीगर मेरे पास है 46 हजार 483 लोग इसमें लाभान्वित हुए।

(डा. दिगम्बर सिंह)

इसके अलावा मैं आपको निवेदन करूंगा वैकेन्सीज की बात आई। हमारे माननीय विष्णु मोदीजी ने भी कहा था। इसमें वैकेन्सीज है। इसमें मैंने बता भी दिया कि किस तरह वैकेन्सीज भरी जायेगी।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि "मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो" सभापति महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं। भैंस घर में हमेशा रही है और रोज दूध भी पीता हूं, रोज मक्खन भी खाता हूं और भरतपुर से जब जयपुर आया था तब अपनी भैंस साथ लेकर आया था। अपनी भैंस का दूध पीता हूं, अपने खेत का गेहूं खाता हूं और अपने खेत की सब्जी खाता हूं। इसलिए किसी बात को केवल आरोप लगाने के लिये कह देना, मैं समझता हूं इससे बुरी बात इस सदन के लिये कुछ नहीं हो सकती। मैं आपको इसमें पूरी जानकारी देना चाहूंगा कि माइक्रो न्यूट्रीशन प्रोग्राम के तहत कुल 6 दवाइयों में से 3 दवाइयां आर एन फोलिक एसिड लार्ज, आर एन फोलिक एसिड स्मॉल और विटामिन सी इसके लिये जो टेण्डर बेचे गये, वह 10.3.2003, 10 मार्च और इसकी निविदायें दिनांक 12.3.2003 से 26.3.2003 तक खोली गयीं। मैं आपको इतना निवेदन करूं जो भी इनके टेण्डर खुले, उसमें तीन दवाइयां मैसर्स एल्डोक फार्मा कोटा के पक्ष में अनुमोदित की गयीं। अब जो टेण्डर पास करते हैं, यह किस स्तर के लोग हैं, वह भी मैं बता दूं आपको। इसमें चाहे मिनिस्टर मैं रहा हूं, चाहे मिनिस्टिर कोई और रहा हो, चाहे मिनिस्टर आपकी पार्टी का उस समय रोल था, वह रहा हो । परन्तु इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक बहुत हाई लेबल की कमेटी है, जिसका चेयरमैन स्पेशल सेक्रेट्री होता है, जिसमें डायरेक्टर पब्लिक हैल्थ होता है, जिसमें डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर होता है, जिसमें डायरेक्टर आई.ई.सी. होता है, डायरेक्टर एड्स कंट्रोल होता है, एफ.ए. होता है, प्रिंसिपल एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल जे.एल.एन. अजमेर, ड्रग कंट्रोलर और रिप्रजेन्टेटिव इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट और चीफ अकाउंट्स आफिसर, यह 11 अधिकारी इस हमारी जो पर्चेज कमेटी है, उसके मैम्बर होते हैं। यह मैम्बर्स पूरी तरह उनके सामने निविदायें खोली जाती हैं। ओपन टेण्डर्स होते हैं और उसमें जो लोएस्ट रेट होती है, उनको देखने के बाद टैक्निकली क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद उनकी बिड होती है, उनका रेट कान्ट्रेक्ट हो जाता है। अब मेरी बात सुन लीजिये, मेरी मजबूरी है कि मैं रेट कान्ट्रेक्ट के

अलावा दूसरी फर्म से नहीं खरीद सकता। मैं ही नहीं, कोई भी नहीं खरीद सकता। जिस फर्म का रेट कान्ट्रेक्ट है, यह तो चांस की बात थी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गरीबों के मालनरिश बच्चों के लिये मल्टीन्यूट्रिन का प्रोग्राम चलाया और इसमें यह और जानकारी आपके ध्यान में ला दूं कि यह जो बजट था इसका, यह पंचायती राज विभाग के पास था। यह बजट अलॉट हुआ जिला परिषदों को। हमारे पास केवल सी.एम.एच.ओ. को इसकी इन्फोर्मेशन, कि मालनरिश बच्चे कितने हैं, इसका एस्टीमेट करो। सी.एम.एच.ओ. ने पूरा एस्टीमेट करके हमें उसकी रिपोर्ट दी। हमने बकायदा उसके आर्डर प्लेस किये और उसके बाद यह तीन कम्पनियां थीं एडोल्क, आर.डी.पी.एल. और तीसरी बंगाल केमिकल्स थी। इन तीनों कम्पनियों ने सीधा सी.एम.एच.ओ. के यहां पर माल सप्लाई किया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। सी.एम.एच.ओ. ने बिल वैरीफाई किये। बिल वैरीफाई कराने के बाद बजट चूंकि जिला परिषदों में गया था, जिला परिषदों को उन बिलों को वैरीफाई करने के बाद भेज दिया गया और आज तक भी दु:ख की बात यह है कि अभी तक भी बंगाल कैमिकल्स का साढ़े तीन करोड़ रुपये पेमेन्ट नहीं हुआ है। आर.डी.पी.एल. का कम से कम साढ़े तीन करोड़ रुपये का जो पिछली साल मल्टीन्यूट्रिन सप्लाई किये थे, उसका पेमेन्ट भी अभी तक नहीं हुआ है। आर.डी.पी.एल. हमारे .. (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आर.डी.पी.एल. गवर्नमेंट होल्ड कम्पनी है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इस तरह के फालतू के आरोप लगा देना तो मैं समझता हूं केवल हंसने के लिये कही है। इस तरह की बात को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिये। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा -

"नई धरती, नया आकाश पैदा किया,

तुमने भी देखा, एक मधुमास पैदा किया

जहां भी जाते हैं, उमड़ जाते हैं लोग,

देख लो, किस तरह विश्वास पैदा किया।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप चुटकले तो अच्छे कहते थे।

**श्री सभापति:** श्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय मंत्री। उत्तर देंगे।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): मंत्री महोदय, भैंस की जगह गाय रखो और गाय का दूध पीया करो।

**श्री सभापति:** श्री मदन दिलावर।

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघठक योजना मांग संख्या-51 पर सदन के लगभग 13 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और 93 कट मोशन्स हमें प्राप्त हुए हैं, 93 कट मोशन्स के जवाब हमने बना लिये हैं और हम माननीय सदस्यों को भिजवा देंगे।

सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से जो सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से विपन्न लोग हैं और जो एक संतुलन है आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों में और आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अगड़े लोगों में असंतुलन है इस संतुलन को पूरा करने के लिए एक समरसता की गंगा बहाने के लिए ओर इस विभाग का एक निर्माण किया गया है ताकि यह असंतुलन पूरा हो।

आप भी जानते हैं कि जो भी इस भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं वो सब भाई हैं और भाइयों में ना तो कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ना कोई जाति से ऊँचा होता है न कोई जाति से नीचा होता है, हम सब बराबर हैं लेकिन कालान्तर में किसी कारण से इस प्रकार का असंतुलन हुआ जिसके कारण से आज समाज में यह परिस्थितियां पैदा हुई। हम चाहते हैं और हमारी सरकार चाहती है कि यह असंतुलन संतुलन में बदले और हम सब एक जाजम पर बैठें, एक साथ उठें, एक साथ बैठें, एक साथ खाएं और इसीलिए सामाजिक दृष्टि से बराबर लाने के लिए यह भी आवश्यक है होगा कि इनको आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ किया जाए और इसीलिए हमने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलायी हैं।

आप जानते हैं कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो लोग हैं वे शैक्षणिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आवश्यक यह है कि शिक्षा के विभिन्न आयामों के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाए और इसलिए विभिन्न छात्रावासों का निर्माण करके हमने एक अच्छी शिक्षा सस्ती दर पर या नि:शुल्क देने के लिए इस प्रकार के प्रयास किये हैं और इसलिए आज हम लगभग 602 सरकारी छात्रावास राजस्थान भर में चला

(श्री मदन दिलावर)

रहे हैं और 97 हम अनुदानित छात्रावास चला रहे हैं। इनके दोनों के माध्यम से, सरकारी और गैर-सरकारी के माध्यम से हम लगभग 28 हजार अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को लाभान्वित कर रहे हैं।

अब आप देखें कि इतने सारे छात्रों को सरकार की तरफ से राहत देने पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसको सरकार इसलिए वहन कर रही है कि हमारे सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से विपन्न भाई हैं, जो वंचित लोग हैं वो हमारे बराबरी में आ सकें। यही नहीं, अच्छी शिक्षा देने के लिए हम लोगों ने आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है। राजस्थानभर में हम 12 आवासीय विद्यालय चला रहे हैं। एक आवासीय विद्यालय के भवन का निर्माण औसतन 6 करोड़ रुपया है और यह इसलिए बनाये थे और यह योजना इसलिए चलायी थी कि जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोग थे वो तो बहुत अच्छी पब्लिक स्कूलों में पढ़ कर अपनी प्रतिभा को ठीक प्रकार से निखार लेते हैं लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं वो अपनी प्रतिभा को आर्थिक अभाव में नहीं निखार पाते हैं, अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ पाते हैं और इसलिए हमने आवासीय विद्यालयों की स्थापना की थी। और मुझे गर्व है यह कहते हुए कि आवासीय विद्यालयों के हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। यानि यह एवरेज लगभग हमारे 85 परसेंट बोर्ड की परिक्षाओं के रिजल्ट हैं जो मैं समझता हूं अपने आप में एक शिक्षा में बहुत मील का पत्थर साबित हुआ है।

यही नहीं, हमने सम्भागीय स्तर पर बालिकाओं के कॉलेज स्तरीय छात्रावास प्रारम्भ किये हैं। सब जगह लगभग हमारे भवनों की स्वीकृति जारी कर दी है, अधिकांश जगहों पर भवन निर्माण प्रारम्भ हो गये हैं और आने वाले शैक्षणिक सत्र में हम यहां कुछ में तो सरकारी छात्रावास, हमारे भवन बन कर तैयार हो गये हैं, उन्हें प्रारम्भ कर देंगे और कुछ में हम किराये के भवन में प्रारम्भ कर देंगे लेकिन सभी मुख्यालयों पर कॉलेज स्तरीय बालिकाओं के छात्रावासों को प्रारम्भ कर देंगे और एक-एक छात्रावास की जो क्षमता होगी वह 75-75 छात्राओं की होगी। यह पहली बार हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, अभी तक 10+2 तक ही हमारे छात्रावासों में रन करते थे, पहली बार हम कॉलेज स्तरीय बालिकाओं के लिए छात्रावास रन करने के लिए जा रहे हैं।

यही नहीं, जैसा मैंने कहा पहले कि 602 सरकारी छात्रावास हम चला रहे हैं, आपको यह जानकर के दुःख होगा, कष्ट होगा कि पिछले तीन वर्ष

(श्री मदन दिलावर)

पहले की बात करें, जो पाँच साल का कार्यकाल रहा था पूर्ववर्ती सरकार का तो छात्रावासों की स्थिति बहुत दयनीय हो गयी थी। जितने भी सामान थे, गद्दा, तकिया, पलंग सारे के सारे अनुपयोगी हो गये थे और उसके कारण छात्रावासों की स्थिति हो गयी थी। एक भी भवन का निर्माण नहीं किया। माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार ने, जितना उस समय की सरकार ने निर्माण किया था वही हुआ उसके बाद पाँच सालों में कोई भवन निर्माण नहीं होने से छात्रों के सामने रहने का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था। मैं कह सकता हूं कि हमने लगभग 133 भवनों का निर्माण किया है और हम इस 133 भवनों को आने वाले दो-तीन महीने के अन्दर हम सरकारी भवनों में, जो बन गये हैं हमारे उसमें शिफ्ट कर देंगे और लगभग हमारे 85 भवन ऐसे रह जायेंगे जो नहीं हैं, उनको भी आने वाले दो वर्षो में हम यह कह सकते हैं कि अभी जो छात्रावास 602 हैं, आने वाले दो वर्षो में 602 के 602 छात्रावासों में हमारे सरकारी भवन होंगे, अब कोई भी किराये के भवन में हमारा छात्रावास नहीं रहेगा।

यही नहीं, सभापति महोदय, हम इस प्रकार की योजनाएं भी लाये हैं जो राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में एक यूनिक योजना है, जिसकी पूरे भारतवर्ष के सभी प्रदेशों की सरकार ने प्रशंसा की है। हम 'पालनहार योजना' ला रहे हैं। 'पालनहार योजना' हमने सबसे पहले प्रारम्भ की थी। अनुसूचित जाति के ऐसे बालक जो अनाथ हैं, जिनके मां-बाप मर चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं उनके लिए प्रारम्भ की थी। फिर हमारी सरकार ने उनको सब जाति के लिये प्रारम्भ की और अब इसका विस्तार कर दिया है, इसका विस्तार करके हमने ऐसे-ऐसे बच्चों के लिए भी इसको लागू कर दिया है जिसकी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि जिनकी माताएं बच्चों को छोड़ कर जिन्होंने दूसरा विवाह कर लिया है या जिन्होंने दूसरा नाता कर लिया है, उनको भी इसमें प्रारम्भ कर दिया है। और यही नहीं, जो पेन्शन पाने की पात्रता रखने वाली ऐसी महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं उनको भी इस योजना को लागू कर दिया है जिसके कारण से राजस्थान के बहुत सारे ऐसे निराश्रित बच्चों को उसका लाभ मिलने वाला है। यह हमारी एक यूनिक योजना है, बहुत अच्छी योजना है।

'अनुप्रति योजना' के बारे में आप जानते हैं, 'अनुप्रति योजना' में जो आई.ए.एस., आर.ए.एस. की प्रारम्भिक परीक्षा में पास हो जाते हैं, ऐसे छात्रों को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे, जो

(श्री मदन दिलावर)

प्रतिभावान हैं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए और आई.ए.एस., आर.ए.एस. बनाने के लिए प्रारम्भिक परीक्षा में पास होने पर एक लाख रुपये आई.ए.एस. की परीक्षा में पास होने पर और आर.ए.एस. की प्रारम्भिक परीक्षा में पास होने पर हम 45 हजार उपलब्ध कराते हैं ताकि वो मुख्य परीक्षा की तैयारी ठीक प्रकार से कर सकें। यह एक हमारी यूनिक योजना है।

सभापति महोदय, पशुपालकों के बच्चों के लिए भी जालौर में हम लगभग 6 करोड़ की लागत से एक आवासीय विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। अभी उस आवासीय विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम प्राइवेट भवन लेकर अध्ययन करा रहे हैं और इनका आने वाला जो शैक्षणिक सत्र रहेगा, कोशिश हमारी यह रहेगी कि हमारा भवन ज्यों ही पूर्ण होता है हम उसमें शिफ्ट कर देंगे और यह पशुपालकों के बच्चों की शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

यही नहीं, सभापति महोदय, जो भिक्षावृत्ति करते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए कोई पढ़ाई का साधन नहीं है ऐसे बच्चों के लिये भी हम कोटा में मण्डाणा क्षेत्र में एक आवासीय विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं और आने वाले शैक्षिक सत्र में भी हम उसमें बच्चों की पढ़ाई प्रारम्भ कर देंगे, काफी निर्माण कार्य उनका पूरा हो गया है।

यही नहीं, सभापति महोदय, अभी जो चर्चा यहां आयी थी कि 'पन्नाधाय जीवन अमृत योजना' में अभी तक 123 लोगों को राहत दी गयी है और 1441 आवेदन लम्बित हैं। इसमें कुछ समस्या थी एल.आई.सी. के सामने। एल.आई.सी. के अधिकारियों को, पंचायत राज के अधिकारियों को और स्वायत्त शासन के अधिकारियों को बुलाकर हमने बातचीत की है। उनमें कुछ यह भ्रम हो रहा था कि जो जिले में हमारी बी.पी.एल. सूची है उसके क्रमांक अलग हैं और जो स्टेट लेवल पर हमारी बी.पी.एल. सूची है उनके क्रमांक अलग हैं। हमने उनको समझाया कि बी.पी.एल. सूची के क्रमांक अलग होने से और नहीं होने से कोई अन्तर नहीं आता है, आपके पास गांव का नाम है उसमें, आपकी जो सी.डी. बनी हुई है जिसमें सूची दी है, पंचायत का नाम है, तहसील का नाम है और जिले का नाम है, आप तो कम्प्यूटर में डालिये, वो डालने पर जो निकलता है बी.पी.एल. सूची में तो उसको आपको देना होगा। यह सब समझाने के बाद वो मान गये हैं कि इस एक महीने के अन्दर, यानी 30 दिन

(श्री मदन दिलावर)

के अन्दर सब लम्बित 1441 हमारे आवेदन हैं उन सब का भुगतान हो जायेगा, एक भी भुगतान बाकी नहीं रहेगा। यह मैं आश्वस्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, छात्रवृत्ति के बारे में कहा गया है कि छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति देरी से मिलती है और बच्चे भटकते रहते हैं। इस बात से मैं आंशिक रूप से काफी सहमत हूं क्योंकि जो भारत सरकार है वह हमको काफी विलम्ब से छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाती है।

जो शैक्षणिक सत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कभी-कभी तो लास्ट यानि अन्तिम तारीख को हमको प्राप्त होती है इसलिए हमको दूसरे वर्ष भी उसको डालकर के उसका भुगतान करना पड़ता है। पर मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि वित्तीय वर्ष 2005 और 2006 की छात्रवृत्ति हम लगभग दो महीने के अन्दर सभी छात्रों को दे देंगे। कोई भी छात्र बकाया नहीं रहेगा, सबकी छात्रवृत्ति का भुगतान हो जाएगा।

मैं आपको भी जानकारी दे दूं अभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पच्चीस करोड़ रुपए की जो छात्रवृत्ति है वह हमें भारत सरकार से प्राप्त नहीं हो रही है। हम लगातार सम्पर्क कर रहे हैं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही हमें छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। माननीय सभापति महोदय, मुझे डर लग रहा है उस डर से भी आपको अवगत करा देता हूं कि भारत सरकार लगातार हमको प्रेशर यह डाल रही है कि प्राइवेट कालेजेज में या संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अभी तक हम छात्रवृत्ति पूरी, उनका शिक्षण शुल्क का भुगतान कर रहे हैं जितनी उनकी छात्रवृत्ति लगती है, जितनी उसकी शुल्क लगती है। अब वह यह करने जा रही है उन्होंने टी ए डी की जो छात्रवृत्ति है उसमें तो यह कर दिया है कि प्राइवेट कालेजेज में या प्राइवेट इन्सटीट्यूट में जितने भी बालक अध्ययनरत हैं उनकी छात्रवृत्ति सरकारी कालेजेज के बराबर दी जाए। यदि सरकारी कालेजेज के बराबर छात्रवृत्ति दी जाएगी तो हमारे गरीब बालक किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ पायेंगे।

आप जानते हैं मेडिकल कालेज की जो शुल्क लगती है वह लगभग एक लाख सत्तर हजार रुपए प्रतिवर्ष होती है और सरकार के बराबर देंगे तो मुझे एग्जेक्ट ध्यान नहीं है लेकिन शायद तीन हजार रुपए लगती है। अब यदि तीन हजार रुपया देते हैं और उसका जमा एक लाख सत्तर हजार रुपया होता है तो बालक किस प्रकार से पढ़ पाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि टी.ए.डी.

(श्री मदन दिलावर)

में भारत सरकार ने कर दिया है और हमारी जो अनुसूचित जाति की योजनाएं हैं उनमें भी यह करने जा रही है इसलिए बहुत बड़ा डर लग रहा है ।

ओ. बी. सी. के छात्र मैं समझता हूं कि लगभग पाँच छह लाख लोगों को छात्रवृत्ति देनी चाहिए जो पात्रता रखते हैं लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने उनको केवल तेईस हजार में समेट दिया है कि आप तेईस हजार से ज्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे सकते हैं। यह एक दुविधा का विषय है कि हम किस प्रकार से दे पायेंगे। भारत सरकार से सभी ओ बी सी के छात्रों को छात्रवृत्ति मिले इसलिए निवेदन करता हूं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय यहां नहीं हैं परन्तु कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान बी. डी. कल्लाजी उनसे निवेदन करूंगा कि उनकी केन्द्र में सरकार है, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की छात्रवृत्ति या शिक्षण शुल्क में कटौती न करवाएं और ओ बी सी के छात्रों को भी पूरी छात्रवृत्ति मिले, ऐसा केन्द्र से आग्रह करें, हम सब लोग मिलकर के आग्रह करें क्योंकि राजस्थान के लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है अन्यथा फिर गरीब आदमी का बेटा कभी भी इंजीनियर, डाक्टर नहीं बन पाएगा। इस बात को हमको गम्भीरता से सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अनेक प्रकार के संकट हमारे ऊपर आ रहे हैं, धर्मान्तरण की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है और धर्मान्तरण की समस्या होने के कारण से आप सब जानते हैं कि हमारे भारत के जो सेवन स्टेट सिस्टर्स हैं इनमें पूर्वांचल के जितने भी हैं चाहे नागालैण्ड हो चाहे मिजोरम हो चाहे और प्रदेश हो उनमें स्थिति यह हो गई है कि हम वहां जाते हैं तो हमको पूछने लगे हैं कि आप भारत से आए हैं क्या, क्या आप भारतीय हैं क्या। यानि धर्मान्तरण के कारण से स्थिति यह हो गई है कि वहां से धर्मान्तरण केवल मतान्तरण नहीं होता, धर्मान्तरण में केवल पूजा पद्धति नहीं बदलती। धर्मान्तरण होते ही अलगाववाद की भावना पैदा की जाती है, राष्ट्रद्रोह की भावना पैदा की जाती है और इस देश के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा किया जाता है और इसीलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार मिलकर के धर्मान्तरण विरोधी बिल लाई थी लेकिन अभी किसी कारण से महामहिम राज्यपाल महोदय ने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। फिर भी हम चाहेंगे कि राजस्थान में धर्मान्तरण जोर जबर्दस्ती न हो और इसलिए हमने कहा कि जो इस प्रकार के अनाथालय चलाते हैं, जो इस प्रकार के होम्स चलाते हैं ऐसे सब

(श्री मदन दिलावर)

होम्स को या अनाथालयों को राजस्थान सरकार से अनुमति लेनी होगी अन्यथा भारत सरकार का भी एक विधेयक पास हो गया है उस आधार पर उनको दण्ड मिलेगा। वह किसी भी प्रकार से इस प्रकार के अनाथालय या चिल्ड्रन होम्स नहीं चला पायेंगे। इसकी हम पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं कि इस प्रकार से कोई नहीं चला पाये। हम चाहते हैं कि राजस्थान में किसी प्रकार से जोर जबर्दस्ती और प्रलोभन के आधार पर धर्मान्तरण न हो । यहां बहुतों ने इस प्रकार का धंधा करके राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश की है उस बदनामी से पूरी तरह बचाने की कोशिश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो विशिष्ट संगठन योजना राजस्थान में लगभग 96 लाख यहां की जनसंख्या है अनुसूचित जाति की और जिसमें 17.16 प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है और उसके लिए सभी विभागों में हमने बजट हैड खोलने का निवेदन किया है कि अलग बजट हैड खोले जाएं। चौंतीस विभागों ने बजट हैड खोल लिया है शेष भी बजट हैड खोल रहे हैं और उसके कारण से सब विभागों का दायित्व हो जाएगा कि इस तरह से अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ कम से कम 17.16 प्रतिशत राशि को खर्च करें। इसलिए विभिन्न डिपार्टमैंट्स का मैं वर्णन नहीं करना चाहता परन्तु सभी विभागों ने इस प्रकार का दृढ़ निश्चय किया है कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए इनको हम साधन सम्पन्न बनाने के लिए, बराबर लाने के लिए हम एक साथ चलने के लिए हम सबका कल्याण करेंगे।

इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।

**श्री सभापति:** श्री घनश्याम तिवाड़ी।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप तो धर्मान्तरण रोक दो उससे ही काम हो जाएगा बोल दिया इन्होंने।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज माननीय दिगम्बर सिंहजी ने और दिलावर साहब ने अपनी बात कही तो दिगम्बर सिंहजी ने चिकित्सा के क्षेत्र में इक्कीस हजार लोगों की नियुक्ति की बात कही है तो मैं भी एक सूचना के साथ अपना संक्षिप्त कथन प्रारम्भ करूंगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से अभी समाचार मिला है कि जिन

अध्यापकों की परीक्षा हुई थी, अभी 25 फरवरी को उन सब का रिजल्ट घोषित कर दिया है और आज सारा रिजल्ट उनका आ गया है। अड़तीस हजार अध्यापकों की नियुक्ति का काम अब शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा शिक्षा का अलग से विभाग माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गठित किया और गठित करते समय यह प्रश्न बार बार उठा, इसको गठित करने से क्या लाभ है। मैं इस पर बताना चाहता हूं इस गठित करने से तीन वर्ष में जो लाभ हुआ सबसे पहला कि कुल मिलाकर दो करोड़ सतहत्तर लाख रुपए का बजट इस उच्च शिक्षा की चिकित्सा शिक्षा के लिए था जो आज बढ़कर चालीस करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। बीस गुना वृद्धि तीन साल में। इसमें भारत सरकार का कोई पैसा नहीं इसलिए हमारे माननीय सदस्यों को जो बार-बार यह तकलीफ होती थी ...(व्यवधान) कोई बात नहीं, यह भी अपना है और वह भी अपना है इसलिए यह एक सबसे बड़ा काम इसमें हुआ है ।

माननीय सभापति महोदय, यह जो विभाग हमारे जो सभी मेडिकल कालेज उन मेडिकल कालेजों में पचास लाख, उनके अस्पतालों में पचास लाख आउट डोर पेशेंट प्रतिवर्ष आए हैं । इस साल सात लाख इण्डोर पेशेंट रहे हैं और 10,235 जो हमारी सीटें हैं, शैय्याएं हैं लेकिन हमारी तेरह हजार से अधिक का औसत इनमें रहा है। यह हमारी स्थिति है मेडिकल कालेजों की चिकित्सा की इसलिए हमने इस पर ध्यान देने के लिए सबसे पहले मास्टर प्लान बनाया कि सभी मेडिकल कालेजों का मास्टर प्लान बनाया जाए और उनके जो अस्पताल हैं और उस मास्टर प्लान के अन्तर्गत हम इस कार्यवाही को प्रारम्भ करें और जब हम एक बार बात करते हैं अब यह बार-बार चर्चा आई, यह कहा गया कि सवाई मानसिंह अस्पताल पूरा राजस्थान नहीं है, मैं कहता हूं नहीं है लेकिन सवाई मानसिंह हास्पिटल केवल जयपुर के लोगों के लिए नहीं है आज सवाई मानसिंह हास्पिटल में सम्पूर्ण राजस्थान भर के लोग आते हैं । राजस्थान के नहीं बाहर के अन्य प्रान्तों के लोग भी यहां पर आते हैं और चिकित्सा का एक बहुत बड़ा केन्द्र आज सवाई मानसिंह अस्पताल बन गया है। एक सवाई मानसिंह अस्पताल नहीं चाहे आप जे के लोन ले लें चाहे महिला ले लें चाहे आप जनाना अस्पताल ले लें चाहे डेंटल हास्पिटल ले लें चाहे बीकानेर के अस्पताल पी बी एम को ले लें चाहे आप जवाहर लाल नेहरू

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अजमेर को ले लें, चाहे महात्मा गांधी उम्मेद जोधपुर को ले लें, चाहे कोटा को ले चाहे अजमेर को लें। सभी का हमने एक नियोजित ढंग से विकास करने का मास्टर प्लान बनाया और मास्टर प्लान बनाने के बाद मैं आग्रह करना चाहता हूं आज कई कांग्रेसी माननीय सदस्य नहीं हैं मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन करके उन्होंने कहा जिस-जिस की आवश्यकता पड़ी कि हम सवाई मानसिंह अस्पताल में गये, हम जे के लोन में गये, हम इस अस्पताल में गये यह तीन साल में इनका काया कल्प हो चुका है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इस बात की गवाह हैं । जब 8 दिसम्बर को सरकार के तीन वर्ष पूरे हुए, एक साल पूरा हुआ फिर दूसरा साल पूरा हुआ तीसरा साल पूरा हुआ जितने उदघाटन इन अस्पतालों के अवसर पर हुए हैं उतने शायद अन्य किसी विभाग में नहीं हुए होंगे । यह इसका प्रमाण है और इस बार जब माननीय मुख्य मंत्रीजी उदघाटन करने गयीं तो मैंने उनको वहां पर एक बोर्ड दिखाया था उनका कायाकल्प कैसे हुआ तो 120 करोड़ रुपए के काम सवाई मानसिंह अस्पताल और उससे संबंधित अस्पतालों में इन तीन साल में हुए हैं। यह इतना बड़ा काम हुआ उसका नक्शा बदल गया। हम तो एक फिल्म बना रहे हैं और बैद साहब आप उस फिल्म से संतुष्ट होंगे। सवाई मानसिंह हास्पिटल तब जब आप थे तब और सवाई मानसिंह हास्पिटल अब जब आप यहां हो तब। तो उसका जो फर्क आप देखोगे तब आपको पता लगेगा तब क्या था और अब क्या है..

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): सवाई मानसिंह स्टेडियम तक ही रखना उस फिल्म को आगे मत पहुंचा देना कहीं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): आगे तो मैं ठेठ तक पहुँचा दूंगा। रुक जाओ अभी थोड़ी सी तो अभी बाकी है। इतना काम किया है...

**श्री सभापतिः** उस फिल्म का नाम क्या होगा अब और तब।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां यह नाम अच्छा ढूंढा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): जब इस प्रकार बना वह 69 करोड़ रुपये ... (व्यवधान) अब और तब होगा और तब यह यहां नहीं होंगे क्योंकि इनको तो इस बात का भ्रम बार-बार हो रहा है कि बाहर क्या हो रहा है

इसलिये आपने देखा नहीं सारे विभागों की जब चर्चा होती है तब एक चर्चा आम तौर पर थी। आज मैं ईमानदारी से, एक बात का सर्वे किया जा रहा है राजस्थान में कि तीन साल में सरकार ने किन-किन विभागों में नौकरियां दी लोगों को तो एक बड़ा पाइंट है जिसको ले करके भारतीय जनता पार्टी जायेगी चुनाव में तो आपके पैर नहीं टिकेंगे मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं ...

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): मैं तो आ जाऊंगा ना।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): आपका तो पक्का है क्योंकि हम आयेंगे तो आप आओगे और हम नहीं आते तो आप नहीं आते। आपका इंटरेस्ट भी इसी में है कि हम आएं। जब-जब भारतीय जनता पार्टी का राज आता है जुबेर खान आते हैं। तो इनकी दुआ के कारण से भी यह काम होने वाला है। तो मैं कह रहा था कि अभी बार-बार एक बात उठायी गयी। मैं मानता हूं कि बहुत सी जगह डाक्र्स की कमी है। है कमी। जब आप आये थे तो सभी मेडिकल कालेजों में कमी थी। एम सी आई के नोटिस आ गया इस बात के लिये कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल कर दिया जाए ? हमने 161 की वैकेंसी निकाली और 55 लोगों को उनमें से अभी तक नियुक्ति मेडिकल कालेज में दे चुके हैं डाक्टर्स को। यह काम किया बाकी आरपीएससी को भेजे हुए हैं। उसका सारा काम पूर्ण हो रहा है। तीन वर्ष के कार्यकाल में 130 से अधिक डाक्टर्स को जिनके प्रमोशन बाकी थे, बैद साहब, आप तो प्रमोशन लेकर यहां आ गये। बाकी साथियों को छोड़ आए आप। तो उनका भी तो प्रमोशन करना था। आपके साथ तो मैं ला नहीं सकता उन्हें लेकिन उनका प्रमोशन किया और 130 से अधिक डाक्टर्स का प्रमोशन हुआ।

सभापति महोदय, मैं एक बात आज दावे से कहना चाहता हूं डाक्टर्स में एक भय का वातावरण था हमने प्रमोशन के अन्दर किसी भी प्रकार से एक सीधा नीति सम्वत् आदेश दे दिया कि प्रमोशन करिये 12 साल से अधिक जिन डाक्टर्स को हो गये हैं। प्रमोशन जिस अस्पताल में वह काम करते हैं अगर वहां उनकी वैकेंसी है तो वहीं उनको प्रमोशन दे दीजिये। हमने किसी भी प्रकार से उनमें भय पैदा करने की कोशिश नहीं की और इसी का परिणाम है कि आज डाक्टर्स में पहली बार साहस का काम हुआ है। उन्होंने काम प्रारम्भ किया है। विभागों में बदलाव की स्थिति आयी है। आज सवाई मानसिंह हास्पिटल के अन्दर जाकर आप प्रवेश करोगे कौनसा बरामदा है, आप पूछोगे कौनसी स्टाल में आ गये। मैं समझता हूं कि जयपुर का कोई बढ़िया से बढ़िया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्राइवेट हास्पिटल भी होगा तो आज इस प्रकार का लुक और प्रवेश करने के बाद वह इस प्रकार दिखाई नहीं देगा। आज मैं दावे से यह बात कह सकता हूं। यह काम चेंज किया है। उसमें काम करने वाले हमारे जो लोग हैं वह इस काम में लगे हैं और आज मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार वहां पार्किंग की जगह बनी है। सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। टपरे-सी लगती थी वह टपरे-सी सामने पूरा उसके लॉन लगाकर इस प्रकार का व्यू आ गया है कि लोगों को देखने पर पता लगता है कि वास्तव में यह अस्पताल ही है। स्वच्छता भी है, सफाई भी है और रहने की व्यवस्था भी है। इस प्रकार का अस्पताल का हमने गठन किया है।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह तो बैदजी भी मानते हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): मानते हैं, मुझे तो कई बार कहा भी है। मैं भी उनको मानता हूं, यह भी मुझे मानते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपसे कहना चाहूंगा कि हमने बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई नीति घोषित की उस नई नीति के अन्तर्गत दो हजार करोड़ रुपये के निवेश के 17 प्रस्ताव हमने अब तक मंजूर कर दिये हैं। वह मंजूर हो गये हैं। इनके अन्तर्गत 3 डेंटल कॉलेज और दो नये मेडिकल कॉलेज राजस्थान में आ रहे हैं। 2008 में इन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रारम्भ हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 साल बाद कोटा के मेडिकल कॉलेज में 50 की संख्या छात्रों की हमने बढ़ाई है। इस प्रकार से मेडिकल और डेंटल में प्रवेश करने वाले छात्रों की संख्या भी लगातार राजस्थान में बढ़ेगी जयपुर में । बाकी घोषणाएं तो दिगम्बर सिंहजी ने कीं। मानसरोवर में साढ़े तीन सौ बैड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल चालीस करोड़ रुपये की लागत से, आजादी के बाद आज तक चालीस करोड़ रुपया किसी अस्पताल पर सरकार ने खर्च करके बनाया हो यह पहली बार खर्च करके चालीस करोड़ रुपये में उस अस्पताल का निर्माण हो रहा है। उस अस्पताल के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में सुपर स्पेशिलिटीज का वह वार्ड बन रहा है। इसके अलावा भी मेडिकल शिक्षा को विस्तार देने के लिए सबसे पहले हमने राजस्थान में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की। स्थापना हो गयी। स्थापना करके छोड़ नहीं दिया उसे। स्थापना करने के बाद उसको बजट दिया। उसके प्रशासनिक भवन का काम पूरा हो चुका है। उसके साथ सुपर स्पेशिलिटी का 200 बैड का नया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अस्पताल मेडिकल यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध होने वाला प्रताप नगर में 21 एकड़ जमीन देकर उसका निर्माण का काम भी हो रहा है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है, यह माइल स्टोन है, जो मेडिकल चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़कर आये हैं। 30 साल तक लिखते रहे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। मेडिकल यूनिवर्सिटी का गठन नहीं हुआ है। मेडिकल यूनिवर्सिटी गठित हो गयी, प्रशासनिक भवन बन गया और अस्पताल बनाने की स्थिति में है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार और भी बहुत से काम हैं जो किये हैं लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर दो-तीन विषयों की बहुत बड़ी चर्चा की गयी। एक हमारे मित्र डाक्टर बैद साहब ने कहा कि एस.एम.एस. हॉस्पिटल में जीवन रक्षक सारी मशीनें खराब पड़ी रहती हैं। सारी नहीं रहती, डाक्टर साहब। मशीनें खराब होती हैं। वेंटिलेटर हैं 32, 27 काम कर रहे हैं। डिफेब्रीलेटर हैं 30 और 27 काम कर रहे हैं। कार्डिक मॉनिटर पल्स 125 हैं और उसमें से 100 काम कर रहे हैं। कुछ मशीनें खराब होती हैं तो उनको ठीक करने की भी कार्यवाही करते हैं। उनका काण्ट्रेक्ट भी होता है लेकिन हम इस पर सजग हैं। कन्हैयालालजी मीणा ने बात की वेंटिलेटर्स की कमी है। मैं चाहूंगा कि हम भी प्रयत्न करेंगे। हमारे डाक्टर जो प्रयत्न कर रहे हैं। हमने एम.पीज. से भी काण्ट्रेक्ट किया है। आपने एम.एल.एज. ने भी देने के लिए कहा है अगर 10-15 वेंटिलेटर और आएंगे तो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में उसकी आवश्यकता है। हमने नया ईमरजेंसी पर डाक्टर साहब, आपने देखा होगा कि जो वार्ड बनाया है वह वार्ड अपने आप में एक अदभुत वार्ड है। उस वार्ड में ईमरजेंसी में ही वही पास में सीटी स्केन की एक मशीन भी और लगाना चाहते हैं ताकि सवाई मानसिंह अस्पताल में सीटी स्केन की मशीन खराब होने से बाहर चले गये तो छोटी सी भी खबर छप जाती है। वहीं सीटी स्केन की मशीन थी, तब हमने लगायी थी तो बहुत जबरदस्त विरोध किया गया। आज राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में वह एक मॉडल बन रही है। उसके आधार पर हमने एम.आर.आई. की मशीन भी लगायी। अब सीटी स्केन की एक मशीन ईमरजेंसी के नीचे और लगा देंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि जितने भी पेशेंट आते हैं एक बार उनको तुरन्त अटेंड करके फ्री चिकित्सा करने का काम उत्तर भारत में सवाई मानसिंह अस्पताल के अलावा दूसरा कोई अस्पताल नहीं है जिसमें इस प्रकार फ्री इतने चार सौ लोग ईमरजेंसी में आते हैं, हम उनकी फ्री चिकित्सा करते हैं। यहां पर यह भी कहा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गया कि जो बी.पी.एल. के लोग आये थे, बी.पी.एल. के लोगों को किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी 2005 और 2006 में। 2006 में 9430 लोग भर्ती हुए बी.पी.एल. के उनकी मुफ्त में चिकित्सा की गयी एक अस्पताल में। इसी प्रकार आउट डोर में 75843 बी.पी.एल. लोगों की चिकित्सा की गयी। इसी प्रकार 2005 में 8675 लोगों को भर्ती करके चिकित्सा की गयी और 62033 लोगों की आउट डोर में चिकित्सा की गयी तो यह कहना गलत है। बी.पी.एल. परिवार का जो भी हमारे पास आएगा हर कीमत पर मुफ्त चिकित्सा की जाएगी। चाहे कितने ही रुपये इन मेडिकल कॉलेजों में लगे। व्यवस्था करके हम व्यवस्था करेंगे यह दृढ निश्चय है। हमने तो नारा दिया, मैं वह शेर तो नहीं सुनाता जो शेर-शायरी आपने सुनाई। जो शेर-शायरी की परम्परा मुख्य मंत्रीजी ने डाल दी। मैं तो एक श्लोक कहना चाहता हूं। हम कल्चर शो विकसित करना चाहते हैं।

न त्वम कामये राज्यम्, तो राज्य को तो मैं हटा रहा हूं। न त्वम कामये सुखम्, न स्वर्गम्, न पुनर्भवम्, प्राणी नाम दु:ख तप्तानाम, कामये दु:ख तप्तानाम, प्राणीनाम, आर्तनासी। यह उपनिषद का यह वाक्य है कि न मुझे राज्य की कामना है लेकिन मैं इससे अपने आप को विद्-ड्रा करता हूं क्योंकि मुझे राज्य की कामना है। इस श्लोक में मैं संशोधन कर रहा हूं। न त्वम कामये सुखम, सुख नहीं चाहिए। न स्वर्ग चाहिए। न पुनर्जन्म चाहिए। केवल जो दु:ख से त्रस्त प्राणी हैं उनके आर्त का नाश करके उनको सुख प्रदान करें। यह हम पैदा करना चाहते हैं मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र में। हमारे डाक्टर, हमारे नर्सिंग स्टाफ के लोग और सारे लोग इसी काम में लगे हुए हैं। इसी प्रकार विपक्ष के तीन माननीय सदस्य डाक्टर हैं। एक के बारे में तो डाक्टर दिगम्बर सिंहजी ने शंका पैदा कर दी। मुझे पता नहीं है। बाहेतीजी के बारे में वह कह रहे हैं कि एम.बी.बी.एस. नहीं हैं। वह कह रहे हैं कि वह एम.बी.बी.एस. नहीं हैं, वह मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन बैदजी को मैं जानता हूं। वह भी हैं और बेनीवाल जी भी हैं। बेनीवाल जी चले गये ...(व्यवधान) डाक्टर नहीं हैं क्या वह ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): डॉ. समरजीत सिंह।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): बेनीवाल जी ने पी.बी.एम. हास्पिटल के बारे में तीन बातें कही थी, मैं बिना कागज देखे बता देता हूं, एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो उन्होंने कहा था कि ब्लड सेपटेयर की जो मशीन है वह मशीन वहां उपलब्ध नहीं है। इस कारण से मरीजों को परेशानी होती है। बात बिलकुल ठीक है उसके लिए हमारे सांसद श्रीमान् धर्मेन्द्रजी ने पहले 23 लाख उपलब्ध कराये थे। हमने आदेश दिया लेकिन रुपये कम पड़े। उसके बाद उन्होंने 16 लाख रुपये उपलब्ध कराये, 49 लाख में वह मशीन आ गयी। उसका इंसपेक्शन हो गया, ड्रग इंसपेक्टर की एप्लीकेशन हो गयी। प्राइमरी चैकिंग हो गयी, दोनों चैकिंग हो गयी। लाइसेंस मिल गया और अब वह काम चालू होने वाला है, इसलिए उनकी समस्या का समाधान हो गया। कल्ला साहब के तो काम की चीज है ...(व्यवधान) इसी प्रकार से आई.सी.यू. के बारे में बताया, यह बात बिलकुल ठीक है, एक बार आई.सी.यू. बंद कर दिया था, दो बैड का आई.सी.यू. रखा था। छत के गिरने के बारे में कहा है कि जितनी छत है वह गिरने वाली है इसलिए उसको बंद किया गया। सारी छतों को ठीक कर दिया। अब आई.सी.यू. चालू कर दिया है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से लाइफ सेविंग ड्रग स्टोर के बारे में कहा था, वह काम भी चालू हो गया है। माननीय विधायक बेनीवाल जी ने एक रोगी बच्ची के प्रकरण पर चर्चा की। इस प्रकरण में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है और मेडिकल कौंसिल द्वारा उसकी जांच की जा चुकी है और इन जांचों में पी.बी.एम. में कार्यरत किसी भी चिकित्सक को दोषी नहीं पाया गया है और इस प्रकार से उसकी जांच भी परिपूर्ण हो गयी है। यह तीन बातें यहां पर प्रमुख रूप से उठायी गयी थी।

सभापति महोदय, इन बातों के अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिये हैं उनके जवाब तो मैं भेज ही रहा हूं। कुछ प्रमुख काम हैं वह इस साल में हम करना चाहते हैं। वह मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं। जयपुर में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस स्टेशन की स्थापना होगी। प्रथम चरण में तीन क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, एक डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध करायी जायेगी। सवाई मानसिंह अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग में लेजर सर्जरी हेतु 1.5 करोड़ की लागत से मशीन उपलब्ध करायी जायेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्रीजी और हम भी नोरसे हास्पिटल गये थे। उनसे बातचीत की थी। उनका प्रतिनिधि मंडल भी यहां आया था। इस बातचीत के बाद हमारा आपस में समझौता होगा। व्यापक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एम.ओ.यू. पर साइन होने वाले हैं। इसके अंतर्गत जिस प्रकार से उन्होंने न्यूयार्क में व्यवस्था कर रखी है इमरजेंसी की, उसी प्रकार की इमरजेंसी की व्यवस्था हम जयपुर में करना चाहते हैं। उसी के पहले चरण के रूप में यह क्रिटिकल इमरजेंसी के तीन वाहनों को हम खरीद रहे हैं और आगे चलने के बाद यह भी एक आदर्श और मॉडल व्यवस्था इमरजेंसी की राजस्थान में होगी।

सभापति महोदय, बीकानेर में योजनान्तर्गत कार्डियाथोरोसिक सेंटर की स्थापना की पहल हो गयी है। डायबिटिक केयर रिसर्च सेंटर का लोकार्पण भी 30 मार्च को कल्लाजी हो जायेगा। 31 मार्च, 2007 को मेडिकल योजना से वंचित जिलों में उपकरण लगाये जाने के बाद टेली मेडिसिन से हमारे सभी जिले जुड़ जायेंगे। जयपुर एवं उदयपुर में निजी क्षेत्र के सहयोग से लिनियर एक्सिलरेटर की स्थापना होगी और इसके साथ ही हम अन्य स्थानों पर भी इस योजना को बढ़ावा देंगे ताकि कैंसर पेशेंट को और अधिक लाभ मिल सके और उनको बाहर नहीं जाना पड़े। इसमें हमने यह भी रखा है कि जो महावीर कैंसर चिकित्सालय में जितना पैसा लगता है उससे 25 प्रतिशत कम पैसा लगेगा, 20 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को फ्री होगा। इस शर्त के आधार पर होगा जिस शर्त के आधार पर हमने सी.टी. स्केन और एम.आर.आई की मशीन लगायी थी उसी के आधार पर यह मशीन भी लगाने का काम अब स्टेज पर है और इससे लाभ मिलेगा ...(व्यवधान) कई बन जायेगी, जिस-जिसका कराना है वह करा देंगे। एम.ओ.यू. इसका तैयार किया जा रहा है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं उन उपलब्धियों का यहां बार-बार जिक्र नहीं करूंगा लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बातें कही थी, एक तो पातंजलि आरोग्य योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके कारण से प्रदेश में गैर संक्रामक बीमारियों यथा मधुमेह, रक्त चाप, हृदय रोग, कैंसर आदि से निपटने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित होंगे। इसी प्रकार से अन्य जो कार्यक्रम हैं वह भी हम इसमें लागू करेंगे। एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बार-बार यह चर्चा होती है कि उपकरण कहां-कहां खरीदे गये। 11 करोड़ 21 लाख के पिछले साल में हमने उपकरण विभिन्न अस्पतालों में खरीदे थे। इस साल भी हमने 11 करोड़ के उपकरण खरीदने का प्रावधान इसमें रखा है।

सभापति महोदय, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बात सब जगह सुनाई देगी, शिक्षा के क्षेत्र में हम आये तो भर्ती का काम हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में आये तो भर्ती का काम शुरू किया। पटवारियों की भर्ती की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की। राजस्थान में एक माहौल बना है इन तीन सालों में कि आज तक पुलिस की भर्ती की इतनी बड़ी घोषणा माननीय गृह मंत्रीजी ने की है जितनी आज तक नहीं हुई है। दो हजार मांगी और छः हजार इनको मिली। इस प्रकार का जो भर्ती का, एक हजार की वन विभाग में भर्ती हो रही है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भर्तियों का काम प्रारंभ नहीं हो रहा है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें विकास का काम नहीं हो रहा हो। राजस्थान में विकास की और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की एक व्यापक योजना बनी है, मैं इस पर लंबा नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आलोचना करते समय कम से कम इस बात का ध्यान रखें। समाचार-पत्र बहुत बड़े माध्यम हैं सूचना प्राप्त करने के लेकिन समाचार-पत्र के माध्यम के आधार पर किसी माननीय मंत्री या विधायक का ट्रायल नहीं करना चाहिए। एक बार उसका ट्रायल होने के बाद में वह अपने आपको निर्दोष साबित नहीं कर सकता है।

सभापति महोदय, अभी गोलियों के बारे में, किस समय गोलियों का टेंडर निकला, किस समय गोलियां खरीदी गयी, वह डा. दिगम्बर सिंहजी को कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया गया। इस बात की अगर पहले ताइद कर लेते अख़बार का कागज लेकर के पढ़ने से पहले तो इनके मन को क्लेश नहीं होता। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर हमारी गलती है तो हम आपके पोस्टमार्टम पर हैं, हमारा पोस्टमार्टम करिये, हमारी गलतियों को निकालिये। लेकिन बिना किसी आधार के आरोप लगाकर के चित्रण नहीं करें। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम यहां पर बैठने के लिए तैयार हैं। हम सब बात आपकी सुनने के लिए तैयार हैं। आपका आदर करने के लिए तैयार हैं। हम भेदभाव भी नहीं करना चाहते। हम यह नहीं करना चाहते कि आपके क्षेत्र में यह करेंगे कि नहीं करेंगे। कम, अधिक हो सकता है, इतने बड़े राज्य में अगर इतना सा भेदभाव हो जाये तो उसकी कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब राजस्थान का विकास करें। जब सभी सी.एच.सी. की पी.एच.सी. की बात करते हैं, जब सभी मेडिकल कॉलेजों की बात करते हैं तो बीकानेर की मेडिकल कॉलेज भी आती है, जयपुर की भी आती है। हमारे विकास में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदय, मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से कि एक तो बोलने के बाद, सभापति महोदय आप यह व्यवस्था कर सकते हैं, एक सामान्य नियम है वाद-विवाद का, मुझे दु:ख है पहले सब कांग्रेस के लोग और हम भी इस बात की पालना करते थे कि जब हम किसी विषय पर बोलते थे तो उसका उत्तर सुनने के लिए हम सदन में रहते थे। आज यह परंपरा टूट गयी। हम बोल कर चले जाते हैं। हमको बोल कर नहीं जाना चाहिये, यह व्यवस्था होनी चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जब हम किसी बात पर बोल कर चले जायें, बाहेतीजी बोल कर चले गये। अगर आज वह होते यहां तो इस समय मैं उनको जवाब देता कि किस तारीख को टेंडर निकला, किस तारीख को खोला गया, किस तारीख को आर्डर दिया गया और क्यों डा. दिगम्बर सिंह को उसमें मिलान किया गया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो बोलने वाले रूकें और एक बोलने वाले सुनें। आज सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और जिस प्रकार का वातावरण माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद में सदन का बना है, मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार का वातावरण बजट सत्र में चलेगा ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष बैठे तो हमारा बोलने का मन भी करेगा।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ऐसा नहीं है, कल से तीन दिन की छुट्टियां थी। लोगों की गाड़ियों का टाइम था। ऐसा नहीं कहो आप ...(व्यवधान) एक तिहाई लोग बैठे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप तो वन, टू, थ्री हो, वन, टू और थ्री ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): हमने अभी तक व्हिप जारी नहीं किया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): आप तीन लोग बैठे हैं इसके लिए आपसे और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ...(व्यवधान) मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दो या तीन बस और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): मंत्रीजी आपने कहा ना कि मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण बना, लेकिन आपके श्लोक में जो आपने पहले वाला कह दिया न, कि मैं उसको नहीं मानता हूं उससे जरूर बैचेनी हो गयी है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): उसकी पूर्ति कर देंगे हम।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): राज की इच्छा है और मैं राज कर रहा हूं इस समय।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): यह जो बैचेनी है, कटारिया जी तो उठे ही उसके बाद में ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): आपकी यह बैचेनी और बढ़ेगी ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पास कराओ सभापति महोदय।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (शिक्षा मंत्री): यह हमारी मेडिकल की जो डिमांड है उसको पारित करें।

**श्री सभापति:** जो आपने कहा अभी कि बोलने के बाद सुनने के लिए रूकना भी चाहिए। नियमों में प्रावधान ऑलरेडी है। लेकिन माननीय सदस्य कई बोलने के बाद चले जाते हैं वह नियमों का पालन नहीं करते हैं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आधे से ज्यादा मंत्री अनुपस्थित हैं।

**श्री सभापति:** नियमों में प्रावधान यह है कि ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, जो रूकते हैं उनको आप बोलने नहीं देते हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): हम चार में से तीन को आपने बोलने नहीं दिया। आपने मुझे कहा ना कि मत बोलिये, मैंने कहा नहीं बोलेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, पारण कराओ।

**श्री सभापति:** कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, इसकी सूची भी आप ही भेजते हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): हमने तो दी थी, आपने कहा मत बोलें तो नहीं बोले।

## मांग संख्या 26-का पारण

**श्री सभापति :** 'प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने

(श्री सभापति)

वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 14,54,61,55,000/- (चौदह अरब चौवन करोड़ इकसठ लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?'

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या-51 का पारण

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51– अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3,04,83,43,000 (तीन अरब चार करोड़ तिरासी लाख तैतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?'

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2007 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 21.51 बजे मंगलवार, 20 मार्च, 2007 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# परिशिष्ट-1

## नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

### पाली जिले में पारम्परिक तरीके से बनाये जा रहे ईंट कजावा व मिट्टी के बर्तन के लिए हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

महोदय,

प्रदेश के पाली जिले में गरीब, मजदूर तथा पिछडे वर्ग (प्रजाजत, मोईल्ला जाति) द्वारा अपना पुश्तेनी कार्य मिट्टी के बर्तन तथा ईंट बनाना है। ये लोग गांवों के आसपास नाड़ी, तालाब अथवा वेस्ट लेण्ड सरकारी भूमि पर पंचायत अथवा राजस्व विभाग की अनुमति से ईंट, कजावा बनाते हैं। ये लोग तालाब नाडी को खोदकर उसमें ईंट इत्यादि बनाते हैं तथा इसके साथ तालाब नाडी को गहरा कर जल सग्रंहण के कार्य में भी सहयोग करते हैं।

सरकार एक तरह तालाब, नाड़ी खोदने पर राहत के नाम पर करोड़ों रूपये खर्च कर रही है वही उक्त लोग सार्वजनिक तालाबों को अपनी मेहनत से मुफ्त में खोद रहे हैं उनको सहायता दी जानी तो दूर की बात रही उन्हें अपना पुश्तेनी रोजगार से सरकार द्वारा वंचित किया जा रहा है। राजस्व विभाग पूर्व में (1999 से 2003 तक) इनसे ईट कजावा लगाने हेतु 500 रूपये किराये के रूप में ले रहे थे वही 2003 से इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति ईंट कजावा कर दिया गया। यह सरासर इनके साथ अन्याय है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन लोगो को जो पारम्परिक तरीके से ईंट बनाते हैं उन्हें नहीं रोका जावे तथा इनसे मनमाने रूप से वसूल की जा रही राशि पर रोक लगाई जावे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो चन्द दिनो के बाद प्रदेश से मिट्टी के बर्तन, ईंट बनाने की यह कला भी लुप्त हो जायेगी जिसके जिम्मेदार हम होंगे।

पारम्परिक रूप से मिट्टी की ईट बनाना कोई लघु उद्योग नहीं है यह मात्र इन लोगों के लिए रोजगार व जीवीकोपार्जन का साधन हैं जहां इनको ऋण व सरकारी अनुदान मिलना चाहिये वहीं ये गरीब, मजदूर व पिछड़ों से व सरकार टैक्स वसूल कर रही हैं जिसे रोका जाना नितान्त ही आवश्यक है।

इस वर्ष पाली जिले में व विशेषकर विधान सभा क्षेत्र खारची में बेमोसम बरसात व ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के साथ-साथ मिट्टी से बनी कच्ची ईट भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मेरा सरकार से अनुरोध है

कि किसानों के फसलों में हुए नुकसान के साथ-साथ जिन कच्ची ईंट कजावों को नुकसान हुआ है उसका भी आकलन कर उचित मुआवजा दिया जावे तथा भविष्य में इन्हें भी बीमा योजना में सम्मिलित किया जावें।

अधिकांश स्थानों पर राजस्व रिकार्ड में गोचर दर्ज हैं उस गोचर में नाडी व तालाब भी हैं जो रिकार्ड में कहीं भी दर्ज नहीं हैं। उन तालाबों व नाडियों में इन्हें ईट कजावा बनाने की स्वीकृति प्रदान कर राहत प्रदान करावें।

आदर सहित ।

**खुशवीर सिंह**
(खारची)

## बामनवास विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क व लिंक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में

जिला सवाईमाधोपुर की तहसील बामनवास व बौंली में कई मार्ग पूर्व निर्मित सड़कों से बाधित व अवरूद्ध हो रहे हैं जिनके कारण अनावश्यक समय की बर्बादी, दूरी व अत्याधिक ईंधन का अपव्यय हो रहा हैं । आम जनता को गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अनावश्यक कई किमी. का चक्कर लगाकर ईंधन व समय की बर्बादी कर पहुंचना पड़ रहा है। अतः राज. सरकार का ध्यान निम्नलिखित सम्पर्क व लिंग सड़कों के निर्माण हेतु आकर्षित करना चाहता हूं। कृपया निम्नलिखित सड़कों के निर्माण करवाने से आम जनता को ईंधन व समय की बहुत भारी बचत होगी :-

1. बैराडा से बाबा का तिबारा बिछौछ – 2 किमी
2. बाबा का तिबारा से सासाली – 2 किमी
3. टिगरिया से निमोद – 4.5 किमी
4. बिन्जारी से आरामपुरा – 2 किमी
5. कोहली प्रेमपुरा से लिवाली – 5 किमी
6. श्री टोली से नैनेटा – 2 किमी
7. मुकुन्दपुरा रोड से उदगांव रोड – 3.5 किमी
8. जटलाव से वपुई – 4.5 किमी
9. वपुई से लाखनपुर – 3.5 किमी
10. मेडोली से बीज गोदाम घाटा नैनावाड़ी – 1 किमी
11. मोगल गटा से मोरेल नदी घाटा नैनावाड़ी – 1 किमी

12. झन्डून से दतुंली – 4 किमी
13. करेल से पडसावटा – 3 किमी
14. टिगरया से सांचोली – 3 किमी
15. जाहिरा से ठीकरया – 2 किमी
16. बिछौछ से शेकरपुरा – 1.5 किमी

क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना के नियमानुसार हालांकि उक्त सड़क जुडे हुए हैं लेकिन इन जुड़े हुए ग्रामों के बीच में थोड़ा-थोड़ा अन्तर रहने से एक गांव के साधन को दूसरे गांव में पहुंचने में कई कि.मी. का अनावश्यक चक्कर लगाना पड़ता है थोड़ी-थोड़ी देर में इधर से उधर जाना इसमें काफी समय और ईंधन का अपव्यय होता है थोड़ी-थोड़ी दूरी को कृषि विपणन व मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना, कृषि विपणन व सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा इनके बीच की दूरियों को सड़क निर्माण कर समस्या से निजात दिलाने का कष्ट करें।

**हीरालाल**

(बामनवास)

## बाड़मेर जैसलमेर में चिकित्सों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने बाबत

महोदय,

सर्वप्रथम मैं मुख्य मंत्रीजी एवं चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सतारूढ़ होते बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में 570 ए.एन.एम. का विशेष पैकेज दिया एवं बड़ी संख्या में सी.एच.सी.पी.एच.सी. एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं तथा बजट में डाक्टर आपके द्वार योजना से सीधा बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की दूरदराज की गरीब ग्रामीण जनता को फायदा मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहता हूं पैरामैडिकल स्टाफ को बाड़मेर-जैसलमेर में कमी को देखते हुये स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित करने का प्रावधान बजट में तथा इस हेतु बाड़मेर में अलग से नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

मैं सदन का ध्यान बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की चिकित्सा सेवाओं का तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि डाक्टरों की कमी को गम्भीर समस्या से जुझ रहे बाडमेर जिले में हाल ही लगाए गए दस में से आठ डाक्टरों के

आपने तबादले रद्द करवा दिये हैं एवं एक डाक्टर का तबादला जिले से बाहर कर दिया है इस प्रकार से ले देकर वही स्थिति यह रही जो पूर्व में थी ।

बाड़मेर जिले में वरिष्ठ विशेषज्ञ के 18 कनिष्ठ विशेषज्ञ के 38 व चिकित्सा अधिकारियों के 94 पद स्वीकृत हैं। ये स्वीकृत पद भी जिले की मौजूदा आबादी की जरूरत से काफी कम हैं लेकिन हालात ये हैं कि इस कुल 148 पदों में से 86 खाली पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के आश्वासनों की पालना में दस चिकित्सक हाल के तबादलों में बाड़मेर में लगाये गये लेकिन उनमें से कई ने अपने तबादले रद्द करवा दिये हैं। जिले में मात्र दो नये आये।

अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला सीमान्त जिला है जहां पर स्थित पी.एच.सी.सी.एच.सी. में अधिकांश डाक्टरों के पद रिक्त हैं मुख्यालय पर निम्नानुसार डाक्टरों की कमी है।

| | रिक्त पद |
|---|---|
| 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ | 4 |
| 2. वरिष्ठ विशेषज्ञ | 1 |
| 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 3 |
| 4. चिकित्सा अधिकारी | 18 |

| बाडमेर जिला में रिक्त पद | स्वीकृत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ | 38 | 24 |
| 2. वरिष्ठ विशेषज्ञ | 10 | 8 |
| 3. चिकित्सा अधिकारी | 94 | 23 |

ऐसी ही हालत जैसलमेर की भी है। बाड़मेर मुख्यालय पर स्थित अस्पताल में 150 बैड का अस्पताल है जिन्हें 200 का क्रमोन्नत होना चाहिये महोदय जी सीमान्त जिले में खोले गये अस्पतालों में अधिकांश पद रिक्त चल रहें हैं ऐसी दशा में जिला मुख्यालय के अस्पताल पर मरीजों की पूरी भरमार रहती है।

बाड़मेर में केयर्न ऐनर्जो का बहुत बड़ा नेटवर्क हैं। थर्मल पॉवर जिन्दल राजवेस्ट पावर प्रोजेक्ट लिग्नाईट आर.एस.एस.एम. ट्रास्फार्म करीब 20,000 मजदूर कार्यरत हैं। ऐसी दशा है जिला मुख्यावास का अस्पताल महत्वपूर्ण है जिन्हें क्रमोन्नत कर रिक्त पद पूर्ण भरने का कष्ट करें। मंत्रीजी यह मानवता का मामला है एवं सीमा का भी नहीं है। दिल्ली कलकता नेशनल हाईवे होने के

कारण ट्रोमा यूनिट की स्वीकृति जारी करावें। जोधपुर संभाग में मात्र जोधपुर में ही सी.टी. सक्रिय मशीन है यह मशीन बाड़मेर मुख्यावास पर आवश्यक रूप से होवे ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि बाड़मेर जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा आधारित चिकित्सकों लगाये जाते रहे हैं उनको 8000 रुपये के स्थान पर कम से कम 15000 रुपये मासिक वेतन देने पर है ये चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों की अस्पतालों में अपनी सेवाऐं दे सकेंगे तथा बाडमेर एवं जैसलमेर के जिला मुख्यालयों के रिक्त पदों पर भी संविदा आधारित चिकित्सकों को लगाया जावे।

**जालम सिंह रावलोत**

(शिव)

**रींगस (सीकर) में ट्रोमा हास्पिटल की स्थापना बाबत**

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के कस्बा रींगस नेशनल हाईवे रोड़ नं. 11 पर स्थित है। रींगस सीकर एवं जयपुर मध्य में स्थित है। जहां पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तत्काल समय पर उनको राहत नहीं मिल पाती हैं। जिनके कारण घायल व्यक्तियों की मौके पर उनकी मृत्यु भी हो जाती हैं। घायल व्यक्तियों को तत्काल राहत देने बाबत रींगस नेशनल हाइवे रोड नं. 11 पर एक ट्रोमा होस्पीटल इस वित्तीय वर्ष में खोला जाये।

अत: मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा उपरोक्त चिकित्सालय खोलने की अनुमति प्रदान की जाये तथा मुझे सदन में इस बाबत चर्चा करने की अनुमति प्रदान करावें।

**हरलाल सिंह खर्रा**

(श्रीमाधोपुर)

# परिशिष्ट–2

## मांग संख्या-26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाय-

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) :

1. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम उरसेवा, कोरसीना में चिकित्सालय खोलने एवं दूदू चिकित्सालय में ब्लड बैंक की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र दूदू के चिकित्सा विभाग के सभी रिक्त पद भरने तथा प्री.पी.जी. परीक्षा में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र क तहत नेगेटिव मार्किंग नहीं कर अनुसूचित जाति/जनजाति के अभयर्थियों को चयनित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र दूदू में रेफरल हास्पिटल खोलने तथा प्रत्येक राजस्व गांव में सब सेन्टर खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
4. विभाग द्वारा संविदा चिकित्सा कर्मियों को स्थायी नहीं करने से कर्मचारियों में बढ़ रहे असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. कल्याण अस्पताल, सीकर की अव्यवस्थाओं से आम जनता को लपका गिरोहों के दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. विधान सीभा क्षेत्र धोद में चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लम्बे समय से रिक्त पदों को नहीं भरने से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम मून्डवाड़ा एवं धोद तथा सांवलोदा पुरोहितान में प्रवासी राजस्थानियों द्वारा प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर भवन हेतु प्रस्ताव देने के बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
8. विभाग द्वारा विटामिन की टेबलेट एवं अन्य दवाइयों की खरीद में हुए घोटाले एवं ब्लेक लिस्टेड कम्पनियों से खरीद में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) :

9. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

सुदृढ़ करने एवं चिकित्साकर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा के लिये ।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) :

10. तहसील लूणकरणसर के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम एवं पंचायत मुख्यालय खिमेरा/सुई तथा राजासर ऊर्फ करणीसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

11. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम सेटेरा/रूणिया बडाबास, कलरीमातर/रामसर/मालासर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र अर्जुनसर/दन्तोर/नाल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महाजन बम्बलू व छतरगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने व महिला चिकित्सक नियुक्त करने एवं आवश्यक उपकरण मय स्टाफ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर में नेत्र रोग व अस्थि रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर व नापासर में एम्बूलेन्स मय आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने तथा विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों मे रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

14. पी.बी.एम. हास्पिटल बीकानेर की व्यवस्थाओं में सुधार एवं हीमोफीलिया रोगियों को उपचार सुविधा हेतु चर्चा के लिये।

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़) :

15. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के विभिन्न चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं में सुधार करने एवं नये सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा क लिये ।

**श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) :

16. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालयों में सुधार करने की आवयकता पर चर्चा के लिये।

17. जिला जैसलमेर में बाबा रामदेव मंदिर के पद यात्रियों को मार्ग में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री केसर देव बाबर)

18. तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में नये सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

19. लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के ग्राम बहेवा एवं गनेडी, लक्ष्मणगढ शहर के अस्पतालों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

20. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के ग्राम बलारा, काछवा, जसरासर, जाजोद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़) :

21. विधान सभा क्षेत्र सुरजगढ़ के क्षेत्र डमोली खुर्द व भालोट, कलवा आदि आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में वैद्य व अन्य स्टाफ की कमी के संबंध में चर्चा के लिये ।

22. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के चुड़िना, सोली, कारवास, सावंलोद, मचेरी कलां, सिंघाना आदि के चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी के संबंध में चर्चा के लिये ।

23. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के पी.एच.सी. केन्द्र भुआना और उदामांडी आदि में स्टाफ की कमी के संबंध में चर्चा के लिये ।

24. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के माकडो, सांतोर, थली, डमोली आदि में चिकित्सालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रणवीर सिंह गुढ़ा** (गुढ़ा) :

25. विधान सभा क्षेत्र गुढ़ा के ग्राम पंचायत पोंख मे चिकित्सालय की व्यवस्था दुरूस्थ करने एवं महिला चिकित्सालय चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

26. उदयपुर वाटी कस्बे में चिकित्सालय में उचित व्यवस्था एवं चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

27. झुंझुनूं जिले में चिकित्सा केन्द्रों की खराब स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये ।

28. झुंझुनूं जिले के अन्तर्गत गुढ़ा में स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री रामचन्द्र सराधना** (जमुआरामगढ़) :

29. ग्राम ताला (जमवारामगढ़) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्दवाजी (आमेर) में महिला चिकित्सक का

(श्री रामचन्द्र सराधना)

पद सृजित करने एवं जमवारामगढ़ में रिक्त ए.एन.एम. के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) :

30. पी.एच.सी. सेतरावा व भामू को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने व एडपोस्ट खिरजा, भाबा, बेलवा, खजिया, खुडियाला, बस्तवा को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

31. सामुदायिक चिकित्सालय बालेसर की क्षमता 30 से 50 शैय्याएं करने, सी.एच.सी. बालेसर, शेरगढ़ व देचू में रिक्त चिकित्सकों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी) :

32. सरकारी चिकित्सालयों के रिक्त पद भरने व रात्रि को डाक्टर व नर्सों का गांवों में ठहराव करवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री हरीसिंह रावत** (भीम) :

33. चिकित्सालयों में चिकित्सकों, कर्मचारियों एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) :

34. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धवा का भवन निर्माण, पी.एच.सी. लूणी, झंवर व धवा को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करवाने, सब सेन्टर मोगडा कलां को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करवाने, आयुर्वेद अस्पताल लूणी व धुन्धाड़ा को ''अ'' श्रेणी का दर्जा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) :

35. ग्राम खेरखटा तहसील हिण्डौली में पी.एच.सी. खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

36. राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डौली को ट्रोमा अस्पताल बनाने अथवा ट्रोमा अस्पताल की सारी सुविधाएं देने के संबंध में चर्चा के लिये ।

37. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली मे उपयुक्त स्थानों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध मे चर्चा के लिये ।

38. ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डौली में पी.एच.सी. खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

39. चिकित्सा विभाग में की जा रही खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

40. विभाग द्वारा राज्य में बीमारियों की रोकथाम के लिये कारगर उपाय निमित सार्थक प्रयास के संबंध में चर्चा के लिये ।

41. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्साकर्मियों, दवाइयों एवं चिकित्सा सुविधाओं से सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई) :

42. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कुटी (बांदीकुई) में सिटी डिस्पेंसरी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

43. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में ग्राम बैजूपाड़ा एवं ग्राम गुढलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

44. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम पंचायत मुख्यालय हिगोंटा, झाझीरामपुरा, मुंडषिस्या एवं रलावता में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री नवनीत नीनामा** (घाटोल) :

45. जिला बांसवाड़ा तहसील घाटोल के गांव सेनावासा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. जिला बांसवाड़ा के तहसील घाटोल के गांव गरनावट में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

47. जिला बांसवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घाटोल में एक्सरे टेकनीशियन के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

48. जिला बांसवाड़ा में तहसील घाटोल के गांव नावन में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

49. जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल में समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेल नर्स के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) :

50. विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्राम पाटोली में पी.एच.सी. खोलने के संबंध पर चर्चा के लिये ।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) :

51. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम पिचौलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व पुष्कर में सेटेलाइट अस्पताल के निर्माण एवं अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये। विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रिक्त पदों भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी) :

53. बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत नोसर के ग्राम दानाणियों की ढाणी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

54. बाड़मेर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरा की ग्राम पंचायत मुख्यालय अरणियाली स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. बाड़मेर जिले में ग्राम नोसर में परिवार कल्याण केन्द्र खुल जाने से वहां पर पूर्व में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र को केरलीनाडी में पंचायत के प्रस्तावनुसार स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर) :

56. रिक्त पदों पर भर्ती हेतु डाक्टरों, नर्सो को जैसलमेर में नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा) :

57. पीलीबंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरने पर चर्चा के लिये ।

58. ग्रामीण क्षेत्रों में ए.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

59. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में बिजली पानी व चार-दीवारी की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सी.डी. देवल** (रायपुर) :

60. विधान सभा क्षेत्र रायपुर में डाक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पद भरने पर चर्चा के लिये ।

61. राजकीय चिकित्सालय, बर को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(श्री सी. डी. देवल)

62. विधान सभा क्षेत्र रायपुर में ग्राम श्यामपुरा, रूपनगर, देवनगर, सीरमा, सिंधपुरा इत्यादि गांवों में सब सेन्टर खोलने व सेन्दड़ा को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने तथा रामपुराकलां को एडपोस्ट में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

63. विधान सभा क्षेत्र रायपुर के बर गांव में ट्रोमा हास्पिटल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

64. विधान सभा क्षेत्र रायपुर में ए.एन.एम. के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) :

65. विधान सभा क्षेत्र खारची में ए.एन.एम. के रिक्त पद भरने एवं दो नये उप स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः गुड़ा जेतावतान (पंचायत मगर तालाब) व गुड़ा देवड़ा मेडतीयान (पंचायत बागोल) में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

66. विधान सभा क्षेत्र खारची के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर के रिक्त पद भरने तथा एक मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खारची में डाक्टर के रिक्त पद भरने के संबंध मे चर्चा के लिये ।

67. विधान सभा क्षेत्र खारची के मगरा क्षेत्र स्थित जोजावर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

68. विधान सभा क्षेत्र खारची में खिवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल चिकित्सा केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) :

69. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में ऐडपोस्ट एवं सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

70. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के रिक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये ।

71. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के रेफरल चिकित्सालय में आंख एवं दन्त चिकित्सक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

72. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रेफरल चिकित्सालय में ऑर्थोपेडिशियन चिकित्सक का पद सृजित करने की आवश्यका पर चर्चा के लिये ।

73. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रेफरल चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) :

74. जयपुर के विद्याधर नगर में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

75. बनीपार्क सेटेलाइट अस्पताल, जयपुर में स्थानाभाव के कारण अन्यत्र पास ही में सिन्धी कालोनी स्थित राजकीय मातृ शिशु चिकित्सा केन्द्र में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

76. न्यू कालोनी, जयपुर स्थित राजकीय गोदावरी देवी जाजू चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

77. गरीबी रेखा से ऊपर के रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. राज्य के प्रत्येक सेटेलाइट अस्पतालों में एक ही छत के नीचे आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार) :

79. राज्य के जयपुर एवं बीकानेर की तरह ही अन्य मेडिकल कालेजों में भी फिजिकल मेडिसिन एवं रिहेबिलिटेशन इकाई खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

80. जयपुर में वार्ड 28 में स्थित माडल टाउन क्षेत्र एवं मालवीय नगर के वार्ड नं. 25 में डिस्पेन्सरी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

81. एकल विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं, जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में नहीं है उनको भी बी.पी.एल. को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये

82. जयपुरिया हास्पिटल, जयपुर को क्रमोन्नत कर जिला अस्पताल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल) :

83. कस्बा बहादरपुर विधान सभा क्षेत्र खैरथल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

84. ग्राम भजेड़ा, चिकानी, मूण्डिया खेड़ा तहसील किशनगढबास में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

85. ग्राम घासौली तहसील किशनगढबास (अलवर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा) :

86. बांसवाड़ा में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना करने एवं उदयपुर मेडिकल कालेज की सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

87. विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में अरथूना में लम्बे समय से स्थापित पी.एच.सी. केन्द्र को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

88. विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के अधिकांश पी.एच.सी. में स्टाफ व डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

89. बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की पी.एच.सी. व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों के लम्बे समय से रिक्त पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) :

90. उप स्वास्थ्य केन्द्र चित्रावास (गोगुन्दा) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

91. पंचायत समिति कोटडा, पंचायत सामोली में क्यारला, गोगरूद एवं झालरा में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व पालछा में ए.एन.एम. बी.एच.डब्लू. लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

92. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के पंयायत चित्रावास में स्वास्थ्य केन्द्र पर ए.एन.एम. व एम.पी.डब्लू. को लगाये जाने एवं तरपाल चित्रावास स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत तथा बाउण्ड्रीवाल नयी कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

93. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में चापा की नाल (मेवाडो का मठ) कोटडा में नया स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध मे चर्चा के लिये।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) :

94. राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

95. राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में खराब उपकरणों को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

96. बी.पी.एल. मरीजों को प्राथमिकता से समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

97. दवाई खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को दण्ड दिलवाकर व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

98. आपातकालीन प्रसव सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) :

99. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शैय्याओं की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 करने एवं एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों में जांच सुविधाओं में विस्तार एवं खराब पड़े चिकित्सा उपकरणों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

101. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के हरसोली गांव में भवन बने होने के बावजूद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

102. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त चिकित्सकों व पैरामेडिकल पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये ।

103. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने एवं भादवा में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (नागौर) :

104. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मेडता में ग्राम जारोडा में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

105. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय सामुदयिक चिकित्सालय मेड़ता में सौ बैड तक का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

106. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

107. विभाग द्वारा मेड़ता व मूंडवा विधान सभा क्षेत्र के राजकीय चिकित्सालय मेड़ता रोड को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेडा) :

108. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

109. विभाग द्वारा नव क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनेरा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में भवन, वार्ड निर्माण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

110. विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बम्बोरी पंचायत समिति छोटी सादड़ी के क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

111. निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी तहसील क्षेत्रों में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

112. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बाहेड़ा व बैगू को 50 से 100 बेड सामान्य चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी सादड़ी में 30 शैय्याओं से 50 शैय्याओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**डा. एन.एस. गुर्जर** (टोडारायसिंह) :

113. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में नये उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

114. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में उप स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की मरम्मत एवं नव निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

115. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में डाक्टर, कम्पाउण्डर व ए.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) :

116. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर तहसील मुख्यालय पर आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

117. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में गंगापुर व रायपुर में राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

118. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में डाक्टरों, कम्पाण्डर तथा नर्सों के रिक्त पदों को भरने तथा जांच उपकरणों से जांच करने वाले तकनीकी कर्मचारियों के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

119. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

120. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बैड्स की संख्या बढ़ाने तथा नये सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ए.एन.एम. उप स्वाथ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) :

121. आयुर्वेद चिकित्सालय कालानला तहसील नैनवा (बूंदी) में चिकित्सक आवास निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

122. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड जिला बूंदी में मुर्दाघर के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

123. चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मेडिकल छात्रों को समय पर छात्रवृति स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

124. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड जिला बूंदी के लिये एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

125. भीतरी ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम रायथल जिला बूंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार) :

126. जयपुर स्थित बाइजी की कोठी झालाना डिस्पेन्सरी में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) :

127. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अस्पतालों में रोगियों के लिए आवश्यक सुविधाओं में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये । विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के चिकित्सालयों के भवनों में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं बड़े अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) :

130. किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में डाक्टर्स/ए.एन.एम./मेलनर्स के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

131. खण्डेला ग्राम में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

132. सुमेरपुर में सहायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

133. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में आवश्यकतानुसार गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृतियां दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

134. सुमेरपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री देवीशंकर भूतड़ा** (ब्यावर) :

135. अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर में बर्न यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

136. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ढढालिया, सरूपा, बुजारेल, बनजारी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर) :

137. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भवनों हेतु आवश्यक प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

138. राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में चर्चा के लिये ।

139. जिला बाड़मेर में ग्राम निम्बाणियों की ढाणी ग्राम पंचायत माडपुरा बरवाला पंचायत समिति बायतु, ग्राम जोगासर ग्राम पंचायत बायतु भोपजी पंचायत समिति बायतु में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

140. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाटाडू पंचायत समिति बायतु जिला बाड़मेर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

141. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विशाला पंचायत समिति बाड़मेर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हीरालाल** (निवाई) :

142. विधान सभा क्षेत्र निवाई में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये ।

143. निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर ट्रोमा हास्पिटल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

144. विधान सभा क्षेत्र निवाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दतवास एवं झिलाय को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खरेड़ा, सिरोही, नटवाटा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) :

145. विधान सभा क्षेत्र बाली के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

146. नव क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेडा में, एम्बुलेंस, आपरेशन थियेटर, वार्ड रूम, स्टाफ क्वाटर्स व अन्य आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवयकता पर चर्चा के लिये ।

147. राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फालना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कराने एवं राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाली में 100 रोगी भर्ती शैय्या एवं फालना में 50 रोगी भर्ती शैय्या संख्या स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

148. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम काकराडी व भीटवाड़ा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने तथा फालना नगरपालिका क्षेत्र की कच्ची बस्ती में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

149. राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमाणा तहसील बाली के जीर्ण-क्षीर्ण भवन की मरम्मत तथा डाक्टर्स एवं नर्सिंग क्वाटर्स निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) :

150. विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व में स्थित कस्तूरबा परिवार कल्याण केन्द्र को वार्ड संख्या 37 या 36 के मध्य स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

151. विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व में स्थित सेटेलाइट अस्पताल को 50 से

(श्रीमती अनिता भदेल)

100 बिस्तर व आवश्यक चिकित्सा स्टाफ तथा उपकरण की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

152. विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व में स्थित गुलाबबाड़ी सिटी डिस्पेन्सरी के भवन निर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

153. विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व में स्थित कुन्दननगर क्षेत्र वार्ड संख्या-47 में नई सिटी डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व में स्थित गढी मालीयान वार्ड संख्या-14 में नवीन शहरी चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) :

155. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र पांच्यावाला में राजकीय एलोपैथी चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

156. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के मुरलीपुरा क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

157. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के खातीपुरा वार्ड नं. 9 में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

158. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के झोटवाड़ा क्षेत्र में राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

159. राजकीय चिकित्सालय वैशानीनगर की क्रमोन्नति तथा जयपुरिया अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा एवं सुविधा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री प्रभुलाल वर्मा** (पीपल्दा) :

160. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

161. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में ए.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा) :

162. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के राजकीय चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किये जाने एवं वार्ड में शैय्याएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

163. विधान सभा क्षेत्र तिजारा स्थित राजकीय हास्पिटल कोटकासिम, तिजारा, टपूकड़ा, भिवाड़ी में डाक्टर, नर्स, लेब ब्वाय, महिला चिकित्सक, रेडियोलोजिस्ट आदि के रिक्त पद तुरन्त भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

164. विधान सभा क्षेत्र तिजारा तहसील के भिवाड़ी क्षेत्र के समथल चौक पर स्थित सी.एच.सी. हास्पिटल के विकास हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन द्वारा स्वीकृत 40 लाख रुपये की राशि का उपयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

165. तिजारा क्षेत्र के भिवाड़ी, टपूकड़ा अस्पतालों में ब्लड बैंक व एक्स–रे मशीन को चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

166. तिजारा क्षेत्र के टपूकडा अस्पताल में एम्बुलेंस की दुर्घटना के बाद मरम्मत नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी) :

167. बूंदी में पं. बृजसुन्दर शर्मा चिकित्सालय में डाक्टर्स के पदों को भरने एवं जिला मुख्यालय का अस्पताल होने के कारण ''अ'' श्रेणी घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) :

168. चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित परिवार कल्याण एवं अन्य कैम्पों हेतु चिकित्सकों के अलग से पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

169. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

170. राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाजवास को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

171. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परबतसर को रेफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) :

172. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगंजमण्डी को 100 शैय्याओं के रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने, चेचट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में क्रमोन्न्त करने, रानपुर, अलोद, बोराबास, केवलनगर सहरावदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) :

173. विभाग द्वारा आबू रोड़ में कार्यरत चिकित्सक डा. अग्रवाल की मृत्युपरांत उनकी पत्नी को नियमानुसार नियुक्ति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

174. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में नये प्राथमिक व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

175. राज्य में अपात्र चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये ।

176. सिरोही जिले में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये ।

177. राजकीय चिकित्सालय शिवगंज (जिला सिरोही) की शैय्या क्षमता बढ़ाकर 50 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) :

178. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगरार, राशमी व बस्सी में शैय्याओं (बेड) की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

179. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राशमी में रोगी वाहन उपल्ब्ध कराने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राशमी, गंगरार, बस्सी में आपरेशन थियेटर के लिये सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

180. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी में मानदण्डों के अनुरूप पदों के सृजन करने एवं नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूद, बूढ, सोनियाना, सिंहाना में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

181. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में भवन रहित सब सेन्टर पर भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंना में भवन एवं आवास निर्माण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगरार के रोगी वाहन के लिये चालक का पद सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन) :

182. विधान सभा क्षेत्र कपासन में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने जर्जर भवनों का पुनरूद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

183 विधान सभा क्षेत्र कपासन में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण व नये चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र कपासन स्थित चिकित्सालयों में चिकित्सकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

185. उपखण्ड मुख्यालय कपासन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने व नये बैड तथा भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

186. विधान सभा क्षेत्र कपासन में चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) :

187. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित ट्रोमा यूनिट के नवीन भवन निर्माण एवं इसके सुचारू संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

188. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित वाई.एन. अस्पताल में आई.सी.यू. की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

189. किशनगढ़ शहर स्थित सिटी डिस्पेन्सरी में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं महिला चिकित्सक के नये पद सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

190. किशनगढ़ स्थित वाई.एन.अस्पताल में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के आवास की रिपेयर एवं नये आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

191. अजमेर स्थित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में हार्ट की बाइपास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री कालूराम यादव** (हिण्डौन) :

192. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन जिला करौली में ग्राम पीपलहेड़ा, श्यामपुर मुंडरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) :

193. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कानोता तथा सांभरिया में नये पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

194. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के पी.एच.सी. तुंगा व कोटखावदा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

195. पी.एच.सी. बड़वा तहसील बस्सी (जयपुर) में लम्बे समय से डाक्टर के अनुपस्थित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

196. मरीजों की संख्या को देखते हुये सी.एच.सी. बस्सी में 30 बेड से 50 बेड किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

197. एस.एम.एस., जयपुर में राज्य एवं पड़ौसी राज्यों के मरीजो की बढ़ती भीड़ को नियंत्रण करने व प्रति मरीज शुल्क लगाकर अच्छी सुविधा देने पर चर्चा के लिये ।

**श्री प्रमोद जैन** ''भाया'' (बारां) :

198. विधान सभा क्षेत्र बांरा के अन्ता राजकीय चिकित्सालय में मरीजों के बढ़ते दबाव को कारण इसे 100 बेड के अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

199. बारां शहर के चिकित्सालय को ''अ'' श्रेणी में घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) :

200. बाड़मेर जिले में विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

201. संविदा पर नियुक्त चिकित्सकों का मानदेय (वेतन) बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) :

202. विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के ग्रामीणों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

203. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम नथावड़ा में पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

204. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों के कारण समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

205. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के चिकित्सालयों एवं पी.एच.सी. में उचित साफ-सफाई की व्यवस्था करवाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

206. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम सांजू में पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**डा. सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा) :

207. नाथद्वारा राजकीय चिकित्सालय को 200 शैय्याओं के चिकित्सालय के आवश्यक बजट आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति तथा रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) :

208. पंचायत समिति पंसागन जिला अजमेर के गांव लीडी में अपग्रेडेड सब सेन्टर पर कम्पाउण्डर का पद नियमित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

209. पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर के गांव तिहारी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियमित डॉक्टर के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

210. नसीराबाद जनरल चिकित्सालय में ई.एन.टी. विशेषज्ञ, चिकित्साधिकारी व पैरामेडिकल स्टाफ के पद वर्षो से रिक्त होने पर भी उन्हें नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

211. नसीराबाद जनरल चिकित्सालय में ट्रोमा वार्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) :

212. केपसूल एण्डोस्कोपी लीवर पर वायरल लोड आदि कई प्रकार की जांच की सुविधा एस.एम.एम. सहित सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केन्द्र प्रत्येक जिले में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

213 चिकित्सकों, नर्स-।।, ए.एन.एम. आदि के रिक्त पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

214. यूनानी एवं आयुर्वेद के चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के नये पद सृजित करने तथा रिक्त पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

215. नगर व पहाड़ी (जिला भरतपुर) के अस्पतालों को रेफरल अस्पताल का दर्जा देने तथा नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को नई एम्बुलेंस व सीकरी के अस्पताल में एक्स-रे मशीन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

216. सरकारी चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट अस्पतालों मे जाकर आपरेशन व इलाज कर मोटी रकम कमाने व अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

**श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी) :

217. रावतसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल बनाने या 30 बेड से 60 बेड का क्रमोन्नत करने व टिब्बी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

218. ग्राम तलवाड़ा तहसील टिब्बी, ग्राम थालड़का तहसील रावतसर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व रावतसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन लगाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़) :

219. रामगढ़ (अलवर) में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

220. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्रामों में उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़) :

221. जैतसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने, बीरमाना व पतरोडा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

222. श्रीविजयनगर सी.एच.सी., अनूपगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावला पी.एच.सी. में डाक्टर के रिक्त पद भरने के संबंध मे चर्चा के लिये ।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) :

223. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पी.एच.सी. कालाडेरा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

224. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम पंचायत ढोढसर में पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम पंचायत सामोद में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

226. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित सी.एच.सी. चौमूं को क्रमोन्नति के संबंध में चर्चा के लिये ।

227. विधान सभा क्षेत्र चौमू के ग्राम पंचायत किशनपुरा में पी.एच.सी. खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) :

228. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में सारोला सी.एच.सी. भवन निर्माण एवं सभी खाली पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री लालचन्द मेघवाल** (रायसिंहनगर)

229. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के उप स्वास्थ्य केन्द्र बाजूवाला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिड़मलसर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसिंहनगर में रिक्त पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये ।

230. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री महीपाल सिंह यादव** (बानसूर)

231. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के निम्न गांवों में नई डिस्पेंन्सिरियों यथा- ग्राम मौठूका, भूपसेडा, चतरपुरा लाडपुर में खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

232. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में वर्षो से उप स्वास्थ्य केन्द्रों क्रमश: लाडपुर, डांगीवास, शेरपुर तथा चतरपुरा, बुढवाल, रिवाली, बुटेरी, मौठूका, भांखरवाला गुढा को ऐडपोस्ट में क्रमोन्नत करने के सं्बंध में चर्चा के लिये ।

233. ग्राम भीटेडा (पंचायत समिति बहरोड़) तथा हाजीपुर गांव की डिस्पेन्सरियों के भवनों की आबंटित राशि से भवन निर्माण में हो रहे विलम्ब के संबंध में चर्चा के लिये ।

234. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में उप स्वास्थ्य केन्द्र नालोता, जयसिंहपुरा, रसनाली, बहराम का बास, मुण्डली, रघुनाथपुरा, तलवाड़, गोकलपुर, इन्द्रोड़ा, मंगलवा, कांजीपुरा, नरसिंहपुरा गांवों में खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

235. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बर्डोद एवं बानसूर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरेल हास्पिटल में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये ।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर) :

236. विधान सभा क्षेत्र आहोर के विभिन्न चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

237. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आहोर में स्त्री रोग एवं आंखों के रोगों के विशेषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

238. विधान सभा क्षेत्र आहोर में नोसरा, शंखावाली, साकरना में नवीन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र आहोर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

240. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आहोर में 30 शैय्याओं से 70 शैय्याओं में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना) :

241. विधान सभा क्षेत्र मकराना में बौरावड़, मकराना सी.एच.सी. में रिक्त डाक्टरों की नियुक्ति एवं 8 जगह पर रिक्त ए.एन.एम. की नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा) :

242. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) :

243. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम बबइचा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री प्रभुलाल वर्मा** (पीपल्दा) :

244. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढीबरी चम्बल में रिक्त पदों को भरने के संबंध मे चर्चा के लिये ।

245. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम विनायका के उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की रिपेयर करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री कालूराम यादव** (हिण्डौन) :

246. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डौन में चिकित्सकों एवं उन्य कर्मचारियों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये ।

247. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के ग्राम पीपलहेड़ा में सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री सुरेद्र गोयल** (जैतारण) :

248. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतारण, रास, लाम्बिया व नीमाज में एम्बुलेंस नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

249. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतारण को 100 बैड्स का करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

250. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नीमाज में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

251. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नीमाज को 50 बैड्स में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

252. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आनंदपुरकालू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

## मांग संख्या-51 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–51 मुख्य शीर्षक अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संगठक योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) :

1. सरकारी भूमि पर वर्षो से निवास कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों के आवासीय भवनों का नियमितीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
2. कृषि भूमि की रजिस्ट्री को डी.एल.सी. रेट में अनुसूचित जाति के परिवारों को स्टाम्प ड्यूटी सामान्य दर से आधी करने के संबंध में चर्चा के लिये ।
3. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सरकारी सेवा में सीधी भर्ती व पदोन्नति में रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में चर्चा के लिये ।
4. विशेष भर्ती द्वारा सभी विभागों के बैकलाक के पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।
5. केन्द्र सरकार के नियमों के तहत पदोन्नति में जोन आफ कन्सिडरेशन की शर्त समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री अमराराम धोद** (धोद) :

6. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ सवर्ण जाति द्वारा अत्याचार करने पर देय आर्थिक सहायता समय पर नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये ।
7. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण हेतु कार्यशाला निर्माण करने के बाद भी समय पर भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति में संबंध में चर्चा के लिये।
8. राज्य में समाज कल्याण छात्रावासों की दयनीय व्यवस्था एवं हो रहे अनियमित कार्यो के संबंध में चर्चा के लिये ।
9. अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति हर महीने नहीं मिलने और साल भर की छात्रवृत्ति एक साथ मिलने से छात्रवृत्ति का सही उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) :

10. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य योजना सुचारू ढंग से लागू करने पर चर्चा के लिये ।

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़) :

11. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कल्याण एवं उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़, सीकर) :

12. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषि कनेक्शन में बिलों की दर में छूट देने पर चर्चा के लिये ।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा) :

13. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाया जाकर भूमि आबंटन हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये ।

14. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति को निगमों और बोर्ड एवं ठेके में भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

15. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति को निजी क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्योगों आदि में महत्वपूर्ण विभागों में भागीदारी सुनिश्चित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

16. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार को रोकने के लिये कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी) :

17. अनुसूचित जाति व गरीब व्यक्तियों को बी.पी.एल. व अन्य सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) :

18. ग्राम नंदवान में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना करने, ग्राम-सालावास पालासनी, धवा, गुड़ा में समाज कल्याण छात्रावासों की स्थापना व विधान सभा क्षेत्र व तहसील मुख्यालय ग्राम लूणी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) :

19. हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के लिये उपयुक्त धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

20. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के नागरिकों में अपने व समाज के उत्थान के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा पहल करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(श्री मदन राठौड़)

21. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा देने, स्वावलम्बी व आत्मविश्वास का संचार करने के नियिमत्त कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री मुरारीलाल मीणा** (बांदीकुई) :

22. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम अलियापाड़ा में समाज कल्याण विभाग का छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा) :

23. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यक्रमों हेतु आवश्यक पहल करने पर चर्चा के लिये ।

24. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं में अधिक राशि का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) :

25. विधान सभा क्षेत्र खारची के राणावास में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास खोलने पर चर्चा के लिये ।

26. विधान सभा क्षेत्र खारची में मारवाड़ जंक्शन स्थित समाज कल्याण छात्रावास के क्षत-विक्षत स्थिति को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) :

27. राजगढ़ (चुरू) पंचायत समिति में इंदिरा आवास का बकाया भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री जीतमील खांट** (बागीडोरा) :

28. विभाग द्वारा बांसवाड़ा–डूंगरपुर जिलों में एस.सी. के वर्ग के बैकलाग को शीघ्र भरवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

29. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु चलायी जाने वाली योजनाओं की कार्यरूप में परिणीति में देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

30. बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिलों में अनुसूचित जाति के छात्रावास स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) :

31. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं/कार्यक्रमों पर चर्चा के लिये ।

**श्री चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) :

32. अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
33. अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाओं की क्रियान्विति न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
34. अनुसूचित जाति की योजनाओं में जातिगत आधार पर भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।
35. अनुसूचित जाति की विभिन्न योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।
36. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लिये केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के सुचारू संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (नागौर) :

37. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मेड़ता में समाज कल्याण भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
38. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में समाज कल्याण छात्रावास भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**डा. एन.एस. गुर्जर** (टोडारायसिंह) :

39. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु योजनाओं की उचित क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) :

40. विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये प्राप्त होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता के दुरूपयोग को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
41. राजकीय/अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के अनेकों छात्रों के छात्रवृत्ति प्राप्त करने से वंचित रहने पर सरकार द्वारा ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
42. भू-संरक्षण कार्य हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शत-प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
43. अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम धानुगांव (नैनवां) जिला बूंदी में

(श्री रामनारायण मीणा)

भू-संरक्षण कार्य प्रारम्भ करके लाभान्वितों को अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

44. अनुदानित छात्रावासों की सहायता राशि में मंहगाई के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त राशि बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) :

45. एस.सी. कार्पोरेशन बारां में वाहनों के आबंटन का लक्ष्य बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. विभाग द्वारा किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में छात्रावास के अधीक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये ।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर) :

47. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अनुसूचित जाति के लोगों के खेतों व घरों में पेयजल हेतु टांके निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत भीमड़ा पं.स. बायतु जिला बाड़मेर में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति छात्रावास के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

49. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अनुसूचित जाति के लोगों के खेतों में एनिकट निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

50. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अनुसूचित जाति के कृषकों की भूमि (मिट्टी) का नि:शुल्क परीक्षण करवाकर अच्छी उपज के लिये विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

51. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अनुसूचित जाति के पशुपालनों को अच्छी किस्म की गायें/भैंसे क्रय करने हेतु अनुदानित ऋण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हीरालाल** (निवाई) :

52. विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास एवं झिलाय में बालक छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):

53. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में स्थित एस.सी., एस.टी. छात्रावास जो किराये के भवन में चल रहे हैं उनके स्थान पर सरकारी भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा) :

54. अनुसूचित जाति के शिक्षित युवकों को रोजगार हेतु क्षेत्र में विशेष योजना प्रारम्भ करने व उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) के कस्बा कनेरा, बिनोता, अरनोदा में अनुसूचित जाति के नये छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

56. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी में स्थित समाज कल्याण छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाने व आवश्यक निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) :

57. अनु. जाति/जनजाति के भूमिहीन किसानों को कृषि योग्य भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

58. अनु. जाति के किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में चर्चा के लिये ।

59. अनु. जाति के किसानों को कृषि कार्यों में दिये जाने वाले ऋण की ब्याज कटौती के संबंध में चर्चा के लिये ।

60. अनु. जाति की लड़कियों की शादी में दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने के संबंध में ।

61. अनु. जाति के छात्रावासों में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाये जाने के संबंध में ।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) :

62. समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) :

63. सिरोही में अनुसूचित जाति की लड़कियों का छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. अनुसूचित जाति के छात्रावासों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों को छात्रवृत्ति में से भुगतान करने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

65. भारत सरकार द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण के संबंध में प्रदत्त राशि के दुरूपयोग के संबंध में चर्चा के लिये ।

(श्री संयम लोढ़ा)

66. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के अनु. जाति के छात्रावासों में छात्र क्षमता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

67. सिरोही जिले में समाज कल्याण छात्रावासों की बदहाल स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) :

68. अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने व अधिक अनुदान दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

69. अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के रोजगार हेतु आवश्यक साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

70. विभाग द्वारा संचालित छात्रावास साडास, गंगरार, राशमी, बस्सी में छात्रों के प्रवेश की वर्तमान संख्या को दोगुनी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

71. उच्च माध्यमिक विद्यालय रूद, उ.मा.वि. बूठ, उ.मा.वि. बोरदा, उ.मा.वि. पहुंना में छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) :

72. छात्रावासों में वर्षो से कार्यरत अंशकालीन रसोइयों एवं चौकीदार को नियमित करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

73. विभागीय छात्रावासों में एक छात्र के लिये दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन) :

74. विधान सभा क्षेत्र कपासन में कपासन, सिंहपुर, आकोला व भादजोडा में छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

75. अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने व अधिक अनुदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

76. मेवदा कालोनी (ग्राम पं. मुगाना, तह. कपासन) में अनु. जाति के लोगों के लिये विशेष रोजगार हेतु उद्योग व रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) :

77. जयपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति बालिका छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. जिला जयपुर में अनु. जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति लगातार दो वर्ष से नहीं दिये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

79. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पेंशनशुदा विकलांगों, विधवाओं व बुजुर्गों को समय पर भुगतान नहीं मिलने एवं पेंडिंग पेंशन के संबंध में चर्चा के लिये ।

80. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में समाज कल्याण द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों के भवनों की दुर्दशा एवं पानी, बिजली की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**डा. सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा) :

81. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में छितराई जनसंख्या के लिये अनुसूचित जाति को भवन तथा संभागीय आयुक्त जनजाति द्वारा प्रस्तावित सड़कों हेतु राशि आबंटन कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) :

82. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का सम्पूर्ण उपयोग नहीं करने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

83. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु लागू योजनाओं में भ्रष्टाचार समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

84. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं पर्याप्त मोनिटरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) :

85. अनुसूचित जाति के लिये ग्रा.पं. ढोढ़सर में रोजगार के लिये प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

86. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम उदयपुरिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति का छात्रावास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री रामलाल शर्मा)

87. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में अनुसूचित जाति के लिये ग्राम किशनपुरा में सामुदायिक केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

88. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम मलिकपुर के गांव नृसिंहपुरा में सामुदायिक केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

89. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में अनु. जाति के लिये ग्राम पं. हस्तेड़ा में सी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) :

90. विधान सभा क्षेत्र खानपुर (झालावाड़) के सारोला कलां में अनुसूचित जाति का छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना) :

91. मकराना क्षेत्र में अनूसूचित जाति के छात्रों के लिये बोरावड बूड़सू में छात्रावास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।